DIKSHANT | दीक्षांत Education Centre

दीक्षांत समसामयिकी

जून 2023

क्या है खास....

- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
- मणिपुर की अशांति के कारण
- जल्लीकट्टू कानून वैध: सुप्रीम कोर्ट
- तेलंगाना-आंध्र प्रदेश जल विवाद
- वाशिंगटन घोषणा
- तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन
- माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी
- मशीन लर्निंग मॉडल
- पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के कुछ प्रमुख बिन्दु
- 'आदर्श कारागार अधिनियम'
- विश्व जैव विविधता दिवस 2023
- यूपीएससी प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट

करेंट अफ़ेयर्स की बेहतर तैयारी हेतु
दीक्षांत एप पर निःशुल्क करेंट अफ़ेयर्स क्लास
में अवश्य भाग लें।

दीक्षांत ऐप डाउनलोड
करने के लिए
QR Code स्कैन करें।

VISIT US: DIKSHANTIAS.COM | 9312511015 8851301204 | FACEBOOK.COM /DIKSHANT.IAS.7 | YOUTUBE.COM /DIKSHANTIAS | TWITTER.COM /DIKSHANTIAS | INSTAGRAM.COM /DIKSHANTIAS | T.ME/ DIKSHANTIAS

DIKSHANT

दीक्षांत

19 वर्षों से ईमानदार प्रयास

समाजशास्त्र

वैकल्पिक विषय

Dr. S.S. Pandey Sir

ऑनलाइन ऑफलाइन

Attend 3 days Free Demo

DOWNLOAD

दीक्षांत DIKSHANT IAS EDUCATION APP

नामांकन प्रारंभ / सीमित सीटें

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP

नया बैच प्रारंभ

6 JUNE @ 9 AM

ADD: 704 ,GROUND FLOOR, MAIN ROAD, FRONT OF BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

दीक्षांत समसामयिकी

जून, 2023

मुख्य संपादक

डॉ. एस एस पाण्डेय

डायरेक्टर

शिप्रा पाण्डेय

कार्यकारी संपादक

राकेश पाण्डेय

सह-कार्यकारी संपादक

साकेत आनंद

प्रबंधन परामर्श

शंकर भारती, मरीना

सम्पादन सहयोग

नीरज, मो. शोएब, सुधीर प्रसाद, अभिजीत,
प्रकाश जायसवाल, मनोज सिंह

टाइप सेटिंग व डिज़ाइनिंग

सूर्यजीत, पूजा, सुनील
संजय, प्रवीण

****

- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाइटों से गैर-व्यवसायिक एवं शैक्षणिक उद्देश्य से लिये गये हैं और हम इसके लिये उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

प्रधान कार्यालय

289, ढाका जौहर, दशहरा ग्राउन्ड के नजदीक, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

संपर्क कार्यालय

704, बत्रा सिनेमा के सामने, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
मोबाइल: 7428092240, 9312511015, 8851301204
ई-मेल: dikshantias2011@gmail.com, वेबसाइट: www.dikshantias.com

अनुक्रम

करेंट अफेयर्स

शासन एवं राजव्यवस्था

- मन की बात के 100 एपिसोड पूरे 7
- तलाक के लिए अब 6 माह का इंतजार नहीं : सुप्रीम कोर्ट 8
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 में 161वें स्थान पर 9
- मणिपुर की अशांति के कारण क्या है? 9
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन से अयोग्य ठहराए गए सदस्य 10
- चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में चेहरे कि पहचान आधारित चुनाव का परीक्षण 11
- भ्रामक विज्ञापनों और दावों के 32 नए मामले चिन्हित 12
- स्वच्छ भारत मिशन-II द्वारा 50 प्रतिशत गांव शौच मुक्त 13
- दिल्ली सरकार के पास होगी प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां : सुप्रीम कोर्ट 14
- विधायकों कि अयोग्ता पर फैसला करेंगे स्पीकर : सुप्रीम कोर्ट 14
- महिला सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर खामियाँ : सुप्रीम कोर्ट 16
- ज्ञानवापी मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग हो : हाई कोर्ट 16
- जल्लीकट्टू कानून वैध, सुप्रीम कोर्ट 17
- चुनावों में मुफ़्त प्रसारण का औचित्य 18
- आंध्र प्रदेश डॉटेड लैंड को निषिद्ध सूची से मुक्त कराना प्रारंभ किया 19
- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायलय से दिल्ली सरकार के शक्तियों पर पुनर्समीक्षा की मांग की 20
- दिल्ली में सेवाओं को लेकर खींचतान 21
- सीजेआई ने फोरम शॉपिंग की निंदा की 22
- तेलंगाना-आंध्र प्रदेश जल विवाद 23
- अध्यादेशों का पुनःर्प्रख्यापन 24

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- वाशिंगटन घोषणा 25
- जापान, दक्षिण कोरिया संबंधों को आगे ले जाने पर सहमत 26
- नॉर्वे ने रूस से आर्कटिक काउंसिल की अध्यक्षता संभाली 27
- भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में पहला व्यापार और तकनीकी परिषद 27
- दीव में जी20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 28
- जी 7 में पीएम मोदी ने दिया 10 प्वाइंट का एक्शन प्लान 28
- पापुआ न्यू गिनी में तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन 29

अर्थव्यवस्था

- जम्मू-कश्मीर में 'शिताके' मशरूम की व्यावसायिक खेती 30
- डी-डॉलरीकरण प्रक्रिया में तीव्रता 31
- विनिर्माण के क्षेत्र में कर्नाटक प्रथम नवोन्मेषी राज्य 31

- व्यक्तियों, उद्योगों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए भारत की पहली ग्रीन क्रेडिट योजना 32
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 साल पूरे 33
- 'हरित सागर : हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 का शुभारंभ 34
- नए जीएसटी अनुपालन उपाय 35
- एसडीजी को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भोपाल पहला भारतीय शहर बन गया है 36
- वित्तीय नियामक लिबोर से अवस्थांतर क्यों कर रहे हैं? 36
- ग्रीन डिपॉजिट पर आरबीआई द्वारा नियामक ढांचा तैयार 37
- S&P स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर भारत की सॉवरेन रेटिंग 38
- डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क 39

सुरक्षा

- आईईडी से होने वाले खतरे को कम करना 39
- ब्रिगेडियर और उच्च रैंक के अधिकारियों की होगी समान वर्दी 41
- ब्रिटेन, यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देगा 42

सामाजिक मुद्दे

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 42

स्वास्थ्य

- वैज्ञानिकों ने भारत में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सिनेशन आवश्यक बताया 43
- दुर्लभ विकार के इलाज के लिए डॉक्टरों ने अजन्मे बच्चे के मस्तिष्क की अपनी तरह की पहली सर्जरी की 44
- यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने वृद्ध वयस्कों के लिए पहले आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी 45
- ड्रग रिकॉल 45
- जहरीली शराब से मृत्यु की बढ़ती घटनाएँ 46
- भारत डेंगू के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका विकसित करने के करीब 47
- बीमारियों की जानकारी के लिए डब्लूएचओ का नवीनतम वैश्विक नेटवर्क 48

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- ईयू का नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम 49
- चीन ने पहली जीन-संपादित फसल सुरक्षा की मंजूरी 50
- वैज्ञानिकों ने नई तरह की आणविक मोटर खोजा 51
- ब्लूस्की नवीनतम माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 52
- यूके द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सफलता 52
- माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट द्वारा एक बच्चे के तीन माता-पिता 53
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेनदेन मॉडल 54
- मशीन लर्निंग मॉडल 55
- रेडियोमेट्रिक डेटिंग में कैल्शियम 41 की स्वीकार्यता 56
- स्पेसएक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा निजी मिशन लॉन्च 56

पर्यावरण

- भारत एवं चीन ने कार्बन ट्रांजिशन का रोडमैप पेश किया 57

- पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के कुछ प्रमुख बिन्दु 58
- क्या भूमि पुनर्स्थापन पृथ्वी की सुरक्षा कर सकता है? 59
- पश्चिमी घाट उत्तर-दक्षिण प्रजातियों में जैव-भौगोलिक विभाजन 60
- तितलियों के प्रवास अध्ययन से उनका संरक्षण : रिपोर्ट 61
- समुद्री तितलियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील 61
- वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण 80 प्रतिशत तक कम : संयुक्त राष्ट्र 62
- यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र 63

संस्कृति

- शिलाभट्टारिका (ताम्रपत्र) का पुर्नअध्ययन 63

विविध

- सबाल्टर्न स्कूल और दक्षिण एशियाई अध्ययन में गुहा का योगदान 64
- एशिया-प्रशांत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं: एस्केप (ESCAP) 65

प्रीलिम्स फैक्ट

शासन एवं राजव्यवस्था

- आवारा कुत्ते और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या 67
- सरकार द्वारा फांसी के विकल्प पर समिति पर विचार 67
- समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना कुछ अधिकार देने पर विचार करेगी: केंद्र सरकार 68
- देश की 62 सैन्य छावनियां समाप्त 68
- 'आदर्श कारागार अधिनियम' 69

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- भारत रूसी तेल के शोधन और इसे यूरोप को बेचने में सबसे आगे, रिपोर्ट 70
- जासूसी विरोधी कानून में संशोधन : चीन 70
- भारत ने मालदीव को दो युद्धपोत सौंपें 71
- भारत-इजराइल के बीच औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में समझौता 71
- सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय और आसियान जहाजों को पार करती चीनी नौकाएं 72
- कैलिफोर्निया में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध 72
- एसजी 9 सम्मलेन : दूर संचार क्षेत्र को गति 73
- यूएस, पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा सहयोग समझौता 73
- शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्यकारी दल का वर्चुअली शुभारंभ 74
- भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किया 74

अर्थव्यवस्था

- महाराष्ट्र में रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ विरोध 75
- राजस्थान में लिथियम भंडार मिला 76
- भारतीय डाक करोड़ों कारोबारियों का लॉजिस्टिक्स साझेदार 76
- अमेरिकी ऋण सीमा पर गतिरोध 77

- रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को नवरत्न का दर्जा 78
- बैंक बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने और उसका निपटान करने के लिए 100 दिन का अभियान : आरबीआई 78
- केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर' का शुभारंभ 78
- मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को स्वीकृति 79
- आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट का संचालन बंद किया 79
- छत्तीसगढ़ के गेवरा में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनाने की योजना : केंद्र 80

सुरक्षा

- सेना की कई ऑटोमेशन पहलों का रियल टाइम, ऑपरेशनल तस्वीर जारी 80
- रोल ऑफ ऑनर 81
- आईएनएस मगर सेवामुक्त 81
- भारत-थाईलैंड कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल (इंडो-थाई कॉर्पेट) का 35वां संस्करण 82
- भारत और इंडोनेशिया के बीच नौ-सैन्य अभ्यास 82
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण 83
- रोहिंग्या शरणार्थियों को जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं 83

सामाजिक मुद्दे

- इसरो द्वारा पीजी एवं यूजी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 84
- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 84

स्वास्थ्य

- COVID महामारी अब एक आपात स्थिति नहीं है : WHO 85
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ 86
- नॉन शुगर स्वीटनर्स पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन 86

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- ऑफ-द-शेल्फ घटकों से विकसित नए कम लागत वाले स्टार सेंसर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च 87
- ऑप्टिकल ट्वीजर्स का उपयोग करके मृदु कोलाइड्स (सॉफ्ट कोलाइड्स) में कणों को ट्रैक करने की नई विधि जो लक्षित औषधि वितरण करेगा 87
- नई तकनीक जो सरल यांत्रिक कंपन को बिजली में परिवर्तित करती है 88
- वैज्ञानिकों चंद्रमा के भीतर का अवलोकन करेंगे 88
- बिट्स-पिलानी (हैदराबाद) ने सेंसर के साथ बीमारी का पता लगाने वाला मास्क विकसित किया 89
- इसरो ने तमिलनाडु महेंद्रगिरि में नई केंद्र में रॉकेट इंजन का परीक्षण शुरू किया 89
- पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रारंभ 90
- गगनयान के लिए री एंट्री कैप्सूल पैराशूट बेंगलुरु में इसरो सुविधा के लिए भेजे गए 90
- हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ 91
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे धूमकेतु को देखा है, जिसके आसपास पानी है। 91
- भारत के हिमालयन टेलीस्कोप अध्ययन में ब्रह्माण्ड की सबसे ऊर्जावान पिंडों में से एक का अवलोकन किया 92
- वैज्ञानिकों को भारत में भेड़िया कुत्तों के संकरण का पहला प्रमाण मिला 93
- सीमित आर्सेनिक एक्सपोजर भी संज्ञानात्मक क्षमता को खराब कर सकता है: अध्ययन 93
- इसरो न्यू जेनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा 94

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

- कूनो में पांच और चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा 94
- विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलकर डीकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेंगे 95
- भूजल दोहन से जमीन के धँसने की प्रवृति देखी गई 95
- विश्व जैव विविधता दिवस 2023 96
- जन जैव विविधता रजिस्टर का राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ 97

संस्कृति

- संसदीय समिति द्वारा विरासत की चोरी पुरावशेषों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की 97
- 'नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट' के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 98

प्रैक्टिस सेट

- प्रारम्भिक परीक्षा 99
- मुख्य परीक्षा 111

शासन एवं राजव्यवस्था

मन की बात के 100 एपिसोड पूरे

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' ने 100 एपिसोड पूरे किए।
- पिछले लगभग नौ वर्षों में, प्रसारण प्रयोग जिसका वैश्विक इतिहास था, लेकिन कोई महत्वपूर्ण भारतीय उदाहरण नहीं था, प्रधान मंत्री की संचार रणनीति में एक सफल तत्व बन गया है, एक नेता जो जनता से सीधे बात करने में विश्वास करता है।

रेडियो प्रसारण के समान वैश्विक उदाहरण

फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट:

- किसी राष्ट्रीय नेता द्वारा रेडियो प्रसारण के उपयोग का सबसे पहला उदाहरण "फायरसाइड चैट्स" है, जो 30 रेडियो संबोधनों की एक श्रृंखला है, प्रत्येक आमतौर पर 20-30 मिनट लंबा होता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 और 1944 के बीच संबोधित किया था।
- इनके चैट लोकप्रिय थे, और एक ऐसे समय में कई मुद्दों पर अमेरिकी जनता की राय को आकार देने में भूमिका निभाई जब अमेरिका महामंदी से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के संकटों से जूझ रहा था।
- उन्होंने रूढ़िवादी मीडिया की आलोचनाओं का मुकाबला करने और मध्यस्तों के बिना अपनी नीतियों को अमेरिकी जनता के सामने लाने के लिए भी चैट का उपयोग किया।

रोनाल्ड रीगन:

- रोनाल्ड रीगन ने भी एक दैनिक रेडियो कमेंट्री का उपयोग किया जो 1975 से 1979 तक "जन संचार" के रूप में प्रतिष्ठा बनाने और 1980 में अपने सफल राष्ट्रपति पद के लिए जमीन तैयार करने के लिए चलाया।
- इन्होंने 1,027 संबोधन दिए, हर हफ्ते 20-30 मिलियन श्रोताओं तक पहुँचे।
- रेडियो कमेंट्री ने रीगन को एक राष्ट्रीय सार्वजनिक शख्सियत से बदलने में सहायता की, जिसे एक गंभीर राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनकी राजनीतिक कौशल की तुलना में उनकी अभिनय क्षमता के लिए अधिक सराहा गया।

एससी बोस:

- इससे पहले, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी, जिसका पहला प्रसारण 7 जनवरी, 1942 को हुआ था।
- यह कार्यक्रम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत मातृभूमि में रहने वाले लोगों के साथ विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच संबंध बनाने के लिए था।

वे मुद्दे/थीम जिनका पीएम ने बार-बार जिक्र किया

- अक्टूबर 2014 में मन की बात शुरू होने के बाद से योग, महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल, युवा और स्वच्छता सबसे अधिक चर्चित विषय रहे हैं।
- प्रधानमंत्री ने अक्सर भारत के सैनिकों के शौर्य और बलिदान, देश की सांस्कृतिक विरासत की बात की है और पद्म पुरस्कार विजेताओं और अन्य प्राप्तकर्ताओं के जीवन और कार्यों की कहानियों को दोहराया है। उन्होंने विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दों पर भी बात की है।
- एपिसोड के प्रतिलेख दर्शाते हैं, प्रधान मंत्री ने खादी पर विस्तार से बात की है। कार्यक्रम के पहले एपिसोड में उन्होंने लोगों से खादी पहनने को कहा था।

क्या मन की बात पीएम का राजनीतिक/चुनावी प्रचार का साधन रही है?

- इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में से एक सामाजिक मुद्दों के प्रति इसका गैर-पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। इसने अपनी पहुंच को व्यापक और गहरा करने में सहायता की है, और पीएम को अपने विचारों को व्यापक लोगों तक पहुंचाने में समर्थ बनाया है।
- यह कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दो वर्षों के दौरान, लगभग सभी प्रकरणों में स्वास्थ्य संबंधी कैप्सूल था।
- पीएम ने बार-बार सामाजिक रूप से जिम्मेदार और कोविड-उपयुक्त व्यवहार, और व्यापक टीकाकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया, क्योंकि देश कोरोनोवायरस से जूझ रहा है।
- पीएम ने सरकारी योजनाओं और पहलों, निर्यात, ई-मार्केटप्लेस पहल, प्रधान मंत्री संग्रहालय, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न, और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर मंच का उपयोग किया है।

मन की बात के कौन-सी तार श्रोताओं को लुभाते हैं?

- मन की बात सतर्क रूप से प्रधानमंत्री का एकालाप नहीं है। कार्यक्रम का डिजाइन सहभागी है, और इसमें नागरिकों की भागीदारी शामिल है।
- इसके माध्यम से पीएम से लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़ रहे हैं और जनता की रुचि इस कार्यक्रम में बढ़ी है।
- लगभग हर शो में भारत की कला, शिल्प, लोक संस्कृति और नायकों आदि के बारे में कुछ नई और दिलचस्प अल्पज्ञात जानकारी शामिल होती है, जो सूचित और शिक्षित करती है, और श्रोताओं की रुचि को जगाती और बनाए रखती है।

तलाक के लिए अब 6 माह का इंतजार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ:

- सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यदि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश ना बची हो तो संविधान के आर्टिकल 142 के तहत वह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए तलाक को मंजूरी दे सकता है।
- ऐसी स्थिति में मामले को फैमिली कोर्ट भेजना और 6 से 18 महीने का वेटिंग पीरियड भी अनिवार्य नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फेक्टर्स भी तय किये है, जिसके आधार पर शादी को सुलह से परे माना जाएगा।

तलाक के क्या प्रावधान हैं?

- उल्लेखनीय है कि हिंदू मेरिज एक्ट, 1955 के सेक्शन 13बी में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है।
- सेक्शन 13बी (1) में कहा गया है कि पति-पत्नी तलाक के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इसका आधार यह होना चाहिए कि दोनों साल भर या इससे ज्यादा वक्त से अलग रह रहे हों, या साथ रहना संभव न हो, अथवा दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया हो।
- इसी तरह हिंद मैरिज एक्ट के सेक्शन 13बी (2) में कहा गया है दोनों पक्षों को तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से 6 से 18 महीने के बीच इंतजार करना होगा। यह वक्त (कूलिंग पीरियड) इसलिए दिया गया है, ताकि यदि दोनों पक्ष यदि राजी हो या इस बीच मन बदल जाए तो अपनी अर्जी वापस ले सकें।
- निर्धारित वेटिंग पीरियड बीतने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि कोर्ट को लगता है तो वह जांच कर तलाक को मंजूरी दे सकती है। हालांकि यह प्रावधान तभी लागू होता है, जब विवाह को कम से कम एक साल बीत चुका हो।

किस आधार पर ले सकते हैं तलाक?

- हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के मुताबिक पति-पत्नी में से कोई तलाक की अर्जी दाखिल कर सकता है। इसके लिए एडल्ट्री (व्यभिचार), घरेलू हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, परित्याग, कुष्ठ रोग, यौन रोग और मृत्यु की संभावना जैसे ग्राउंड हो सकते हैं।

क्या कुछ मामलों में प्रक्रिया जल्दी हो सकती है?

- हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि किसी असाधारण स्थिति या कठिन परिस्थिति में विवाह के साल भर के अंदर भी तलाक की अर्जी दी जा सकती है। इसके लिए धारा 14 में प्रावधान किया गया है।
- इसी तरह असाधारण परिस्थितियों में धारा 13बी (2) से छूट (कूलिंग अथवा वेटिंग पीरियड से छूट) के लिए भी फैमिली कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है।
- साल 2021 के बहुचर्चित 'अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल' केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "यदि किसी रिश्ते में दोबारा समझौते की जरा सी भी गुंजाइश बची हो तो तलाक की अर्जी दाखिल करने की तिथि से अगले छह महीने का कूलिंग पीरियड अनिवार्य है। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि समझौते की जरा सी गुंजाइश नहीं है, तब कूलिंग पीरियड को लागू करना दोनों पक्षों के लिए पीड़ादायक है"।
- इस प्रकार, यदि विवाह असाध्य रूप से टूट गया है, पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं और अपने मतभेदों को सुलझाने में असमर्थ हैं, और फिर उन्होंने पारस्परिक रूप से अलग होने का फैसला किया, तो दोनों पति-पत्नी को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए विवाह को समाप्त करना बेहतर है।

वह मामला जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता अख्तियार किया?

- 2014 में, सुप्रीम कोर्ट में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन नामक एक मामला दायर किया गया था, जहां पार्टियों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक मांगा था, जिसमें कहा गया था कि उनकी शादी अपरिवर्तनीय रूप से टूट गई थी। यह तलाक के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त आधारों में से एक है, जो पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध है।
- श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले में, अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के तहत क्रूरता के आधार पर "विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना" पढ़ा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- अदालत ने अपने अनुच्छेद 142 शक्तियों का उपयोग करते हुए पक्षकारों को तलाक की अनुमति दी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि क्या यह अनुच्छेद 142 के तहत पार्टियों को पारिवारिक अदालत में संदर्भित किए बिना सीधे तलाक दे सकता है या नहीं। यह एक ही प्रश्न पर शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित कई समान याचिकाओं के आलोक में किया गया था।
- वर्ष 2021 में, अदालत ने कहा कि वह निर्धारित करेगी कि सीधे अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को भंग करते समय किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
- न्यायालय का उद्देश्य यह भी स्पष्ट करना है कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत इसकी शक्ति का प्रयोग सभी तलाक के मामलों पर लागू होगा; और क्या इसका उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां एक पक्ष तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा है।

➲ इसके लिए अदालत ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह, मीनाक्षी अरोड़ा और वी.गिरि को न्यायमित्र नियुक्त किया।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 में 161वें स्थान पर

How India, neighbours fare in press freedom

Country	Ranking
Nepal	95
Pakistan	150
Sri Lanka	135
India	161
Myanmar	173

Source : World Press Freedom Index

Indian media landscape has more than **100,000** newspapers, including **36,000** weeklies and **380 TV channels.**

Mukesh Ambani owns more than **70 media outlets** that are followed by at least **800 million Indians**

चर्चा में क्यों?

➲ वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) दुनिया भर के देशों में प्रेस की स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

➲ आरएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 11 पायदान गिरकर 161वें स्थान पर पहुंच गया। आरएसएफ ने पिछले साल 180 देशों के एक सर्वेक्षण में भारत को 150वां स्थान दिया था।

भारत के पड़ोसी:

➲ भारत कि तुलना में, पाकिस्तान ने मीडिया स्वतंत्रता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि इसे 150वें स्थान पर रखा गया था, जो पिछले वर्ष की 157वीं रैंक से बेहतर था।

➲ श्रीलंका ने 2022 में 146वें स्थान की तुलना में इस वर्ष 135वें स्थान पर रहते हुए सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

टॉप/बॉटम स्कोरर:

➲ नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा किया, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया नीचे के तीन स्थानों पर रहे।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में:

➲ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) हर साल प्रेस की स्वतंत्रता की वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। आरएसएफ एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना है।

➲ इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी दर्जा प्राप्त है।

➲ विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का उद्देश्य, जिसे वह हर साल जारी करता है, "पिछले कैलेंडर वर्ष में 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करना है"।

➲ आरएसएफ प्रेस की स्वतंत्रता को "राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र सार्वजनिक हित में और उनकी शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए खतरों की अनुपस्थिति में समाचारों का चयन, उत्पादन और प्रसार करने के लिए व्यक्तियों और सामूहिक रूप से पत्रकारों की क्षमता" के रूप में परिभाषित करता है।

चिंताएं:

➲ इंडियन वुमन्स प्रेस कोर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने सूचकांक में देश के स्थान में गिरावट पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया।

➲ इसी तरह अनुबंध बहाली जैसी अस्थिर कामकाजी परिस्थितियां भी प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां हैं। जो असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां कभी भी स्वतंत्र प्रेस में योगदान नहीं दे सकतीं।

मणिपुर की अशांति के कारण क्या है?

चर्चा में क्यों?

➲ जब से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी तब से एक विशिष्ट जनजातीय समूह के लिए बेदखली अभियान शुरू किया।

➲ इस अभियान के कारण विरोध हुआ, लेकिन 3 मई को होने वाले अभियान जितना बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य को गैर-आदिवासी मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की 10 वर्ष पुरानी सिफारिश को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। ।

मणिपुर की जातीय संरचना क्या है?

➲ इम्फाल घाटी, जिसमें मणिपुर का लगभग 10% भूभाग शामिल है, गैर-आदिवासी मेइतेई समुदाय का प्रभुत्व है, जो राज्य की 64% से अधिक जनसँख्या के लिए जिम्मेदार है और राज्य के 60 विधायकों में से 40 यहाँ से आते हैं। 90% भौगोलिक क्षेत्र वाली पहाड़ियों में 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का निवास है, लेकिन विधानसभा में केवल 20 विधायक भेजते हैं।

➲ जबकि अधिकांश मैतेई हिंदू हैं, जिनके बाद मुस्लिम आते हैं, 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां, जिन्हें सामान्य तौर पर 'एनी नागा ट्राइब्स' और 'एनी कुकी ट्राइब्स' में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से ईसाई हैं।

क्या है मेइती समुदाय का तर्क?

➲ मीतेई (मीतेई) जनजाति संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए, मणिपुर उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल को

राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मेइती समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 10 वर्ष पुरानी सिफारिश प्रस्तुत करे।

- न्यायालय ने मई 2013 में मणिपुर सरकार को भेजे गए मंत्रालय के पत्र का उल्लेख किया जिसमें नवीनतम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ विशिष्ट सिफारिश मांगी गई थी।
- यह पत्र मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति (STDCM) द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिनिधित्व के बाद आया, जिसने 2012 में मीतेई के लिए जनजातीय स्थिति की मांग शुरू की।
- याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय को बताया कि 1949 में भारत संघ के साथ राज्य के विलय से पहले मेइती को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि समुदाय को "संरक्षित" करने और "पैतृक भूमि को बचाने" के लिए एसटी स्थिति की आवश्यकता है। मैतेई लोगों की परंपरा, संस्कृति और भाषा"।

आदिवासी समूह मेइती को एसटी दर्जा देने के खिलाफ क्यों हैं?

- मेइती लोगों को अकादमिक और अन्य पहलुओं में उनसे अधिक उन्नत होने के कारण जनसांख्यिकीय और राजनीतिक लाभ प्राप्त है। उन्हें लगता है कि मेइती को एसटी का दर्जा मिलने से नौकरी के अवसरों का नुकसान होगा और उन्हें पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को बाहर धकेलने की अनुमति मिलेगी।
- मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन जैसे समूह बताते हैं कि मैतेई लोगों की भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है और उनमें से कई की एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस स्थिति से जुड़े लाभों तक पहुंच है।

किस वजह से अशांति हुई?

- मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का दावा है कि कुछ जनजातीय समूह अपने निहित स्वार्थों के लिए ड्रग्स के खिलाफ मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन सिंह के धर्मयुद्ध को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।
- नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के क्रम में अफीम के खेतों को नष्ट करने और इस सिद्धांत के साथ शुरू हुआ कि अफीम और भांग उगाने के लिए जंगलों और सरकारी जमीनों को साफ करने के पीछे म्यांमार के "अवैध निवासी" हैं।
- 10 मार्च को पहला हिंसक विरोध एक कुकी गांव के निवासियों को बेदखल करने के खिलाफ था। इसने राज्य सरकार को प्रदर्शनकारियों को उकसाने के आरोपी दो कुकी चरमपंथी समूहों के साथ संचालन के निलंबन से वापस ले लिया।
- 3 और 4 मई को कम से कम एक व्यक्ति के जीवन का दावा करने वाली बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा ने एसटी सूची में मेइती को शामिल करने के कथित कदम के खिलाफ "आदिवासी एकजुटता रैली" का पालन किया।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन से अयोग्य ठहराए गए सदस्य

संदर्भ:

- हाल में लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के बाद एक अधिनियम के प्रावधान सुर्खियों में आ गए हैं, जिसके तहत 1988 से अब तक 42 सांसद सदस्यता गंवा चुके हैं।
- इनमें सबसे ज्यादा सदस्य 14वीं लोकसभा में अयोग्य करार दिए गए। प्रश्न पूछने के बदले धन लेने के मामले और 'क्रॉस वोटिंग' के संबंध में 19 सांसदों को अयोग्य करार दिया गया।
- सांसदों को राजनीतिक पाला बदलने, सांसद के तौर पर अशोभनीय आचरण करने तथा दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने समेत विभिन्न आधारों पर अयोग्य करार दिया गया है।

नवीनतम अयोग्यताएं:

- हाल ही में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मोहम्मद फैजल पी पी, और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता अफजाल अंसारी को अदालतों द्वारा उनकी दोषसिद्धि के बाद दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा के कारण अयोग्य करार दिया गया। इन्हें जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया।
- जन प्रतिनिधित्व कानून किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर सांसदों और विधायकों की स्वत: अयोग्यता से संबंधित है।
- लोकसभा में लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व करने वाले फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा के बाद सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा रद्द किए जाने के बाद सदस्यता बहाल कर दी गई।
- गांधी ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में राहत पाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।

पूर्व अयोग्यताएं:

- वर्ष 1985 में दल-बदल विरोधी कानून लागू होने के बाद लोकसभा की सदस्यता से सबसे पहले कांग्रेस के लालदुहोमा को अयोग्य करार दिया गया था, जिन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मिजो नेशनल यूनियन के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस पार्टी का गठन लालदुहोमा ने ही किया था।
- नौवीं लोकसभा के समय जब जनता दल के तत्कालीन नेता वी पी सिंह ने गठबंधन सरकार बनाई थी, लोकसभा के नौ सदस्यों को दल-बदल विरोधी कानून के उल्लंघन का दोषी माना गया, जिसके कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया।

- हालांकि, 14वीं लोक सभा में सदन से सबसे ज्यादा सदस्यों ने अपनी सदस्यता गंवाई। इस दौरान 10 सदस्यों को संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत स्वीकार कर अशोभनीय आचरण के लिए और नौ को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार के विश्वास मत के दौरान 'क्रॉस-वोटिंग' के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। जुलाई 2008 में वाम मोर्चे ने अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण सरकार को विश्वासमत का सामना करना पड़ा था।
- वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के छह सदस्यों, बसपा के दो और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के एक-एक सदस्य को 'प्रश्न पूछने के लिए धन लेने के' मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। बसपा के एक राज्यसभा सदस्य को भी सदन से निष्कासित कर दिया गया था।
- लोकसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह असवाल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "निष्कासन के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था। इनमें से किसी भी मामले को निष्कासन की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया, क्योंकि विधायिका स्वयं ऐसा करने के लिए सक्षम है।"
- दसवीं लोकसभा में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव ने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था, चार सदस्यों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

राज्यसभा से अयोग्यताएं:

- दल-बदल विरोधी कानून के तहत राज्यसभा में भी सदस्यों ने अपनी सदस्यता गंवाई। इनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद (1989), सत्यपाल मलिक (1989), शरद यादव (2017) और अली अनवर (2017) शामिल हैं।
- झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता शिबू सोरेन और समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्य जया बच्चन को क्रमशः 2001 और 2006 में लाभ का पद संभालने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सोरेन जहां झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे, वहीं जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष थीं।
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की अध्यक्ष के लाभ का पद धारण करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अयोग्यता संबंधी याचिका निष्फल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

2006 संशोधन और उसके बाद:

- संभावित राजनीतिक उथल-पुथल से बचने के लिए, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 को 2006 में 4 अप्रैल, 1959 से पूर्व प्रभाव के साथ संशोधित किया गया था और इसी तरह की याचिकाएं निष्फल हो गईं।
- लिली थॉमस मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय ने कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया कि कोई भी दोषसिद्धि जिसमें दो साल या उससे अधिक की सजा हो, निर्वाचित प्रतिनिधि स्वत: ही सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा।
- लोकसभा सचिवालय को केवल एक अधिसूचना जारी करके रिक्ति को अधिसूचित करना होता है ताकि निर्वाचन आयोग उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सके।
- फैसले के परिणामस्वरूप, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य, रशीद मसूद को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
- चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद और जनता दल (यूनाइटेड) सदस्य जगदीश शर्मा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में चेहरे कि पहचान आधारित चुनाव का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारत के चुनाव आयोग ने कर्नाटक में मतदाताओं के लिए सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका निकाला है।

विवरण:

- चुनाव आयोग (ECI) कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र में चेहरे की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा।
- कर्नाटक में होने वाले मतदान में फर्जी वोटिंग पर अंकुश लगाने और लंबी लाइन से छुटकारा पाने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी की है। इस नई तकनीक को पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा।
- कर्नाटक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के पास राजकीय रामनारायण चेलाराम कॉलेज पेलेस रोड पर स्थित मतदान केंद्र पर इस नए सिस्टम को लगाया गया है।

यह कैसे काम करेगा?

- इस प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए, मतदाताओं को चुनाव आयोग के चुनाव मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना होगा, जिसके बाद वे अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर, और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और उनके पंजीकृत नंबरों पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इसके बाद मतदाताओं को एप पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी।
- इस पंजीकरण प्रक्रिया के बाद, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद चेहरे की पहचान करने वाले स्कैनर से गुजरेंगे।
- यदि फोटो चुनाव आयोग के डेटाबेस से मेल खाती है, तो उन्हें अब दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अपना वोट डालने के लिए मंजूरी दे दी जाएगी।

लाभ:

- यह मतदान के लिए कतार/प्रतीक्षा समय को कम करेगा।

- इसके लिए कम जनशक्ति की जरूरत है। उदाहरण के लिए, एक बूथ पर चार मतदान अधिकारियों के बजाय केवल तीन को ही तैनात किया जा सकता है क्योंकि इस चेहरे की पहचान तकनीक के कारण आगे की जाँच/सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।
- एसआरएम यूनिवर्सिटी के कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज विभाग के छात्रों द्वारा मतदान की उदासीनता से निपटने के लिए 30 घंटे का ऑफ़लाइन हैकाथॉन जीतने के बाद यह नया विचार सामने आया।
- लंबी प्रतीक्षा लाइनों से बचने के अलावा, चुनावाना मोबाइल एप्लिकेशन मतदाताओं को मतदान केंद्र के पास उपलब्ध पार्किंग स्थलों के बारे में भी बताएगा। वे रीयल-टाइम में ऐप पर कतार की स्थिति भी देख सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों और दावों के 32 नए मामले चिन्हित

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की विज्ञापन निगरानी समिति ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) के भ्रामक दावों और विज्ञापनों के 32 नए मामलों को चिह्नित किया।
- नियामक के अनुसार, पिछले छह महीनों में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है।

क्या हैं नियम?

- भ्रामक विज्ञापनों और दावों से निपटने के लिए विभिन्न नियम हैं, कुछ व्यापक हैं, जबकि अन्य उत्पाद विशिष्ट हैं।
- उदाहरण के लिए, एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उपयोग करता है जो विशेष रूप से भोजन (और संबंधित उत्पादों) से संबंधित है, जबकि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के नियम वस्तु, उत्पादों और सेवाओं को कवर करते हैं।
- इसके अलावा, केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएँ निर्धारित करती हैं कि विज्ञापनों को यह नहीं कहना चाहिए कि उत्पादों में "कुछ विशेष या चमत्कारी या अलौकिक संपत्ति या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।"
- एफएसएसएआई चाहता है कि विज्ञापन और दावे "सच्चे, स्पष्ट, अर्थपूर्ण, भ्रामक न हों और उपभोक्ताओं को प्रदान की गई जानकारी को समझने में मदद करें"।
- इस दावे के आधार होने वाले संघटक या पदार्थ को चिह्नित करने या मात्रा निर्धारित करने के मान्य तरीकों द्वारा दावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
- किसी बीमारी, विकार या विशेष मनोवैज्ञानिक स्थिति की रोकथाम, उपशमन, उपचार या इलाज का सुझाव देने वाले उत्पाद के दावे प्रतिबंधित हैं, जब तक कि एफएसएस अधिनियम, 2006 के नियमों के तहत विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।

किसी उत्पाद को 'प्राकृतिक' और 'ताज़ा' कब कहा जा सकता है?

- एक खाद्य उत्पाद को 'प्राकृतिक' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है यदि यह एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त एकल भोजन है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है। इसे केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए संसाधित किया जाना चाहिए था। पैकेजिंग भी रसायनों और परिरक्षकों के बिना की जानी चाहिए।
- समग्र खाद्य पदार्थ, जो अनिवार्य रूप से पौधे और प्रसंस्कृत घटकों का मिश्रण हैं, खुद को 'प्राकृतिक' नहीं कह सकते, इसके बजाय, वे 'प्राकृतिक अवयवों से बने' कह सकते हैं।
- 'फ्रेश' का उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जा सकता है जिन्हें धोने, छीलने, ठंडा करने, ट्रिमिंग करने, काटने या 1 kGy से अधिक आयनकारी विकिरण द्वारा विकिरण या किसी अन्य प्रसंस्करण के अलावा किसी भी तरह से संसाधित नहीं किया जाता है, जैसे कि यह बुनियादी के साथ खपत के लिए सुरक्षित रहता है विशेषताएं अपरिवर्तित।
- एडिटिव्स वाले (शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए) इसके बजाय 'फ्रेश फ्रोजन', 'फ्रेश फ्रोजन', या 'फ्रेश से फ्रोजन' का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि यह फ्रेश होने के दौरान जल्दी फ्रोजन था।

'शुद्ध' और 'मूल' के बारे में क्या?

- 'शुद्ध' का उपयोग एकल-घटक खाद्य पदार्थों के लिए किया जाना चाहिए जिसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और जो सभी परिहार्य संदूषण से रहित हैं, जबकि अपरिहार्य संदूषक निर्धारित नियंत्रण के भीतर हैं।
- 'ओरिजिनल' का उपयोग एक फॉर्मूलेशन में बने खाद्य उत्पादों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसका पता लगाया जा सकता है जो समय के साथ अपरिवर्तित रहता है।
- उनमें किसी भी प्रमुख सामग्री के लिए प्रतिस्थापन शामिल नहीं है। इसी तरह इसका उपयोग एक अनूठी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है जो समय के साथ अपरिवर्तित बनी हुई है, हालांकि उत्पाद बड़े पैमाने पर उत्पादित हो सकता है।

'पोषण संबंधी दावों' के बारे में क्या?

- पोषण संबंधी दावे या तो किसी उत्पाद की विशिष्ट सामग्री या किसी अन्य खाद्य पदार्थों से तुलना के बारे में हो सकते हैं।
- तुल्यता के दावे जैसे "(भोजन) के समान (पोषक तत्व) शामिल हैं" या "(भोजन) जितना (पोषक तत्व)" लेबलिंग में उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि यह संदर्भ भोजन के बराबर पोषण मूल्य देता हो।
- भ्रामक विज्ञापनों की अधिकांश शिकायतें किसी उत्पाद के पोषण, उसके लाभों और संघटक मिश्रण के पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित नहीं होने से संबंधित थीं।

स्वच्छ भारत मिशन-II द्वारा 50 प्रतिशत गांव शौच मुक्त

चर्चा में क्यों?

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश के कुल गांवों में से आधे गांवों (50 प्रतिशत) ने मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत ने खुले में शौच मुक्त (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) का दर्जा हासिल कर लिया है।

विवरण:

- खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है।
- अब तक 2.96 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। यह 2024-25 तक एसबीएम-जी चरण-II लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:

- खुले में शौच मुक्त गांवों के प्रतिशत की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं - तेलंगाना (शत-प्रतिशत), कर्नाटक (99.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (97.8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (95.2 प्रतिशत) और गोवा (95.3 प्रतिशत) और छोटे राज्यों में सिक्किम (69.2 प्रतिशत) हैं।
- केंद्रशासित प्रदेशों में - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप में शत- प्रतिशत खुले में शौच मुक्त आदर्श गांव हैं।
- इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुले में शौच मुक्त का दर्जा हासिल करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और यह उपलब्धि हासिल करने में उनके प्रयासों की प्रमुख भूमिका रही है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को कुल 83,938 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वर्ष 2023-24 52,137 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निधियों के अतिरिक्त स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग की निधियों ने स्पष्ट रूप से अगल आवंटन किया है। इन निधियों का उपयोग स्वच्छता संपत्तियों के निर्माण, व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए किया गया है।
- इस साल स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे हो गए हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों ने 50 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है यह स्वच्छता के क्षेत्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सिर्फ शौचालयों के निर्माण और उपयोग से आगे बढ़कर पूर्ण और पूर्ण स्वच्छता यानी खुले में शौच मुक्त से, खुले में शौच मुक्त प्लस तक जा रहा है।

प्रमुख घटक:

- खुले में शौच मुक्त स्थिति स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-ग्रामीण, ठोस (जैव-निम्नीकरणीय) अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम), तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम), मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), गोबरधन, सूचना शिक्षा और संचार/व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी/बीसीसी) और क्षमता निर्माण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण-II के प्रमुख घटक हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और रहन-सहन को बेहतर बनाने में सहायक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में आई कई रिपोर्टों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के प्रभाव की प्रशंसा की गई है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 831 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां और 1,19,449 अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण शेड स्थापित किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक को साफ करके, टुकड़े करके सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल सीमेंट कारखानों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है।

सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण

- घरेलू स्तर पर जैव-निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोगों को सामुदायिक स्तर पर कंपोस्टिंग के लिए स्रोत पर ही अपने सूखे और गीले (जैविक) कचरे को अलग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज तक 3,47,094 सामुदायिक खाद गड्ढों का निर्माण किया गया है।
- गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज-धन)। अपशिष्ट प्रबंधन कचरे को संसाधनों में बदलने और स्वच्छ और हरित गांव बनाने के लिए एक पहल है। यह एक 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल है, जिसमें गांवों में उत्पन्न कचरे का उपयोग बायो-गैस/सीबीजी के साथ-साथ बायो-स्लरी/बायो-फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किया जाता है। यह भारत सरकार की सर्कुलर इकोनॉमी और मिशन लाइफ पहल के अनुरूप है।

धूसर पानी के प्रबंधन के लिए

- गंदे पानी के प्रबंधन के लिए - गांवों में रोजमर्रा के घरेलू कामों- सफाई, खाना पकाने, नहाने आदि से उत्पन्न अपशिष्ट जल है, जिसमें जल निकासी व्यवस्था नहीं है।
- इन स्थानों पर एक विशेष अभियान सुजलाम चलाया गया और धूसर पानी के प्रबंधन के लिए लगभग 2.2 मिलियन (22 लाख) सोक पिट्स (सामुदायिक और घरेलू गड्ढे) बनाए गए।
- अब सुजलाम 3.0 को समग्र रूप से और सम्मिलित ग्रेवाटर प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है।

आगे की राह:

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) इस तथ्य का एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं तो कितना विलक्षण परिणाम हासिल किया जा सकता है।

➲ पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके योगदान के लिए शुभकामनाएं देता है और इस कार्य की सराहना करता है।

दिल्ली सरकार के पास होगी प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां : सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

➲ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच आठ साल की लंबी कानूनी लड़ाई पर पर्दा डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।

➲ भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सर्वसम्मत निर्णय ने कहा कि निर्णय "संघवाद की मूल संरचना" को आगे बढ़ाएगा।

कोर्ट के सामने क्या था मामला?

➲ वर्ष 2015 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर "सेवाओं" पर नियंत्रण रखेंगे। दिल्ली सरकार ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने 2017 में अधिसूचना को बरकरार रखा। अपील पर, सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस मुद्दे को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया।

➲ वर्ष 2018 में, तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में दिल्ली और केंद्र के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून को निर्धारित किया। फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में था।

➲ 2019 में, दो न्यायाधीशों, (जो 2018 में 5-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच का भी हिस्सा थे), जस्टिस अशोक भूषण और एके सीकरी ने "सेवाओं" के विशिष्ट मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया। खंडित फैसला तब तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ और अंततः पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास गया, जिसने अब अपना फैसला सुनाया है।

विवाद की जड़ क्या थी?

➲ अदालत को यह तय करना था कि राजधानी की नौकरशाही पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण दिल्ली सरकार का है या केंद्र सरकार का।

➲ अदालत को संविधान के अनुच्छेद 239एए (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) के खंड (3)(ए) की व्याख्या करनी थी।

➲ इसमें कहा गया है, 'इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला संबंधित मामलों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है...'

क्या थी केंद्र की दलील?

➲ केंद्र का तर्क था कि 2018 के फैसले में, अदालत ने अनुच्छेद 239एए(3)(ए) में दो महत्वपूर्ण वाक्यांशों का विश्लेषण नहीं किया था। पहला था "इस तरह का कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" और दूसरा "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन था।"

➲ केंद्र ने तर्क दिया कि चूंकि किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास सेवाओं पर अधिकार नहीं है, इसलिए दिल्ली भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। अनिवार्य रूप से, दिल्ली केवल उन मुद्दों पर कानून बना सकती है जिन पर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट रूप से कानून बनाने की अनुमति है।

कोर्ट ने क्या फैसला किया?

➲ इस संदर्भ में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि संवैधानिक योजना के तहत दिल्ली एक सुई जेनरिस (या अद्वितीय) मॉडल है, और किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के समान नहीं है। आगे कहा कि दिल्ली अनुच्छेद 239AA के तहत एक विशेष संवैधानिक स्थिति प्रस्तुत करती है।

➲ इसने 2018 के फैसले का हवाला दिया, जहां जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि "इतिहास की पृष्ठभूमि को देखते हुए, एनसीटी को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान दर्जा देना मौलिक रूप से अनुचित होगा।"

➲ दूसरे वाक्यांश पर, "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन," अदालत ने कहा कि यह अनुच्छेद 239एए के लिए अद्वितीय नहीं है और दिल्ली सरकार पर एक सीमा नहीं हो सकती है।

अब क्या है दिल्ली की शक्तियों का दायरा?

➲ अनुच्छेद 239AA विशेष रूप से दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के दायरे से भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर करता है। अदालत ने स्वीकार किया कि इन तीन मुद्दों में "सेवाओं" के साथ कुछ ओवरलैप भी हो सकते हैं।

➲ अदालत ने माना कि प्रविष्टि 41 (सेवाओं) पर दिल्ली की विधायी और कार्यकारी शक्ति सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित सेवाओं तक विस्तारित नहीं होगी। हालांकि, ऐसी सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, या सेवाओं का संयुक्त कार्ड, जो नीतियों के कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक हैं और क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के संदर्भ में दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दृष्टि दिल्ली के पास रहेगी।

विधायकों कि अयोग्ता पर फैसला करेंगे स्पीकर : सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

➲ जून 2022 में शिवसेना में विभाजन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कड़ी टिप्पणियां कीं।

- अदालत ने हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से परहेज किया।

मुख्य विचार:

अयोग्यता पर फैसला करेंगे स्पीकर:

- इस कार्यवाही में हस्तक्षेप न करते हुए, SC ने कहा कि अयोग्यता के मुद्दे को कानून में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार तय किया जाना चाहिए और संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष इसके लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं, जो दल-बदल विरोधी कानून का पालन करता है।
- खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, "कोई असाधारण परिस्थितियाँ" नहीं थीं, जो इस मामले में अदालत का फैसला कर रही थीं।
- इसने यह भी स्पष्ट किया कि अयोग्यता के लिए किसी भी याचिका के लंबित होने की परवाह किए बिना एक विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।

स्पीकर को शिवसेना के संविधान पर विचार करना चाहिए

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करते समय, अध्यक्ष को शिवसेना के संविधान पर विचार करना चाहिए, जिसे दोनों गुटों की सहमति से चुनाव आयोग (ईसी) को प्रस्तुत किया गया था। इसमें कहा गया है कि चूंकि दसवीं अनुसूची के तीसरे पैराग्राफ को हटा दिया गया है, पार्टी में 'विभाजन' अब कार्यवाही का सामना कर रहे विधायकों के लिए उपलब्ध बचाव नहीं होगा।
- दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 3 ने तब तक दलबदलुओं को संरक्षित किया जब तक कि एक राजनीतिक दल के एक-तिहाई सदस्यों ने एक अलग समूह का गठन किया।
- इसे संविधान (91वें संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया, जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुआ। कोर्ट ने स्पीकर से पहले यह निर्धारित करने के लिए कहा कि कौन सा गुट राजनीतिक दल का गठन करता है और उस संबंध में ईसीआई के आदेश से प्रभावित हुए बिना कॉल करें।
- खंडपीठ ने कहा कि अध्यक्ष को यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन सा गुट विधानसभा में किस समूह की बहुमत वाली "अंधी प्रशंसा" पर राजनीतिक दल का गठन करता है।

राज्यपाल ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया:

- अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का 30 जून, 2022 को फ्लोर टेस्ट का आह्वान करना उचित नहीं था, क्योंकि उनके पास यह दिखाने के लिए वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी कि मौजूदा सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है।
- अदालत ने कहा कि राज्यपाल ने इस अनुमान पर कार्रवाई की थी कि शिवसेना का एक वर्ग सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहता है, भले ही कुछ विधायकों द्वारा संचार ने केवल महा विकास अघडी गठबंधन के बारे में असंतोष व्यक्त किया हो।
- इसने कहा कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य करने की राज्यपाल की शक्ति एक असाधारण प्रकृति की है, और कानून की सीमाओं के भीतर सावधानी के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।
- इसने यह भी कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर या पार्टी के भीतर के विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है।

उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था

- ठाकरे समूह ने 29 जून, 2022 से पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की थी, ताकि उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल किया जा सके। हालांकि, अदालत ने कहा कि ठाकरे ने 30 जून को शक्ति परीक्षण का सामना नहीं किया और इस्तीफा दे दिया।
- SC ने कहा कि राज्यपाल के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण नहीं होने के बावजूद कि ठाकरे ने सदन का विश्वास खो दिया है, वह स्वेच्छा से प्रस्तुत इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि अगर ठाकरे ने इस्तीफा देने से परहेज किया होता, तो वह उनकी सरकार को बहाल करने के उपाय पर विचार कर सकते थे।

शिंदे गुट के व्हिप की नियुक्ति अवैध

- 21 जून, 2022 को पार्टी के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने एक व्हिप जारी कर सभी विधायकों को सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर एक बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया। उपस्थित लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपने विधायक दल के समूह नेता के रूप में हटाने का प्रस्ताव पारित किया।
- शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने तब अपना प्रस्ताव जारी किया, जिसमें प्रभु को व्हिप के रूप में हटा दिया गया और उनकी जगह भरत गोगावाले को नियुक्त किया गया। कार्यभार संभालने के बाद अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गोगावले को सचेतक के रूप में मान्यता दी।
- SC ने कहा कि अध्यक्ष ने यह पहचानने का प्रयास नहीं किया कि राजनीतिक दल द्वारा दो व्यक्तियों में से किसे अधिकृत किया गया था, अध्यक्ष को पार्टी के नियमों के आधार पर एक स्वतंत्र जांच करनी चाहिए थी।
- गोगावले को व्हिप के रूप में मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को अवैध माना गया, क्योंकि उन्होंने यह सत्यापित नहीं किया था कि यह राजनीतिक दल का निर्णय था या नहीं।

विधायक दल, राजनीतिक दल अलग:

- जबकि शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने तर्क दिया कि विधायक दल और राजनीतिक दल आपस में जुड़े हुए हैं, अदालत ने कहा कि दोनों को मिलाया नहीं जा सकता।
- कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खुद को राजनीतिक दल बताने वाले व्यक्तियों के संघ को चुनाव आयोग के पास पंजीकृत कराना होता है।

- अदालत ने कहा कि संसद ने एक विधायक दल के स्वतंत्र अस्तित्व को राजनीतिक दल के विधायकों के कार्यों की रक्षा प्रदान करने की सीमित सीमा तक मान्यता दी थी। उदाहरण के लिए, सदन में विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या पार्टी के भीतर असहमति, दल-बदल विरोधी कानूनों के दायरे में नहीं आ सकती है।
- कोर्ट ने कहा कि व्हिप राजनीतिक दल के निर्देशों को बताने के लिए विधायक दल के सदस्यों के साथ बातचीत करता है। इसने कहा कि "यह राजनीतिक दल है न कि विधायक दल जो व्हिप और सदन में पार्टी के नेता की नियुक्ति करता है"।
- इसलिए, यह कहा गया कि अध्यक्ष को केवल व्हिप और नेता को पहचानना चाहिए जो राजनीतिक दल द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हो।

स्पीकर और चुनाव आयोग मुद्दों पर समवर्ती निर्णय ले सकते हैं

- अदालत ने कहा कि वह ठाकरे समूह के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकती है कि चुनाव आयोग को पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद पर तब तक फैसला करने से रोक दिया गया था जब तक कि अध्यक्ष उनके सामने अयोग्यता याचिकाओं का फैसला नहीं कर लेते।
- अदालत ने कहा कि यह "अनिश्चित रूप से चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने" के बराबर होगा, क्योंकि स्पीकर के फैसले को उनके फैसले के खिलाफ अपीलों के निस्तारण के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

नबाम रेबिया मामले को बड़ी बेंच को रेफर करना:

- पांच-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नबाम रेबिया मामले में अपने 2016 के फैसले से संबंधित कुछ मुद्दों को एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया। मुद्दों में से एक यह है कि क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी करने के लिए स्पीकर की शक्तियों को प्रतिबंधित करेगा।

महिला सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में गंभीर खामियाँ : सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा (पीओएसएच) अधिनियम के कार्यान्वयन में "गंभीर खामियां" हैं, जिससे कई कामकाजी महिलाओं के पास अपनी नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामला:

- बॉम्बे हाई कोर्ट के 15 मार्च, 2012 के एक फैसले के खिलाफ दायर एक अपील में यह फैसला आया, जिसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों के आधार पर उसे नौकरी से बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक अधिकारियों के फैसले के खिलाफ गोवा विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।
- मामला शिकायत समिति को वापस भेज दिया गया है।

निर्णय की प्रमुख बातें:

- न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोधी कानून को लागू किए जाने के एक दशक बाद भी "स्थिति ख़राब" और "चिंताजनक" थी, और यह केंद्र और राज्यों के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का समय था।
- कामकाजी महिलाएं यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने में अनिच्छुक थीं, या तो इस बारे में अनिश्चितता के कारण कि किससे संपर्क किया जाए या इस प्रक्रिया और इसके परिणामों में विश्वास की कमी के कारण।
- यह अधिनियम चाहे कितना भी कड़ा क्यों न हो, यह महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मान और गरिमा प्रदान करने में तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि प्रवर्तन शासन का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है और सभी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा एक सक्रिय दृष्टिकोण नहीं होता है। यदि काम का माहौल शत्रुतापूर्ण, असंवेदनशील और महिला कर्मचारियों की जरूरतों के प्रति अनुत्तरदायी बना रहता है, तो अधिनियम एक खाली औपचारिकता बनकर रह जाएगा।
- इसने एक अखबार के सर्वेक्षण का हवाला दिया जिसमें पता चला कि देश में 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 ने 2013 के अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया था।

निर्देश:

- इसमें न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए एक समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया कि क्या मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी), स्थानीय समितियों का गठन किया था। (LCs) और आंतरिक समितियाँ (ICs) अधिनियम के तहत।
- इन निकायों को आदेश दिया गया है कि वे अपनी-अपनी समितियों का विवरण अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करें। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामे का पालन करने और दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया था।

ज्ञानवापी मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग हो : हाई कोर्ट

संदर्भ:

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक आदेश को दरकिनार करते हुए वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग सहित एक 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' का आदेश दिया है।

पृष्ठभूमि:

- मई 2022 में, एक स्थानीय अदालत द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद का एक अदालत-आदेशित वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया गया।
- सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, एक संरचना - जिसे हिंदू पक्ष द्वारा "शिवलिंग" और मुस्लिम पक्ष द्वारा "फव्वारा" होने का दावा किया गया - मस्जिद परिसर के अंदर पाया गया।
- उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने "कार्बन डेटिंग द्वारा वैज्ञानिक जांच करने या अन्यथा आयु, प्रकृति और शिवलिंगम के अन्य घटकों को निर्धारित करने का अनुरोध किया था।"

कार्बन डेटिंग क्या है?

- कार्बन डेटिंग व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है जिसे कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ यानी ऐसी चीजें जो कभी जीवित थीं।
- दरअसल जीवित वस्तुओं में विभिन्न रूपों में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन का एक विशेष समस्थानिक होता है, जिसे C-14 कहा जाता है।
- इस C-14 का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और यह रेडियोधर्मी होता है। रेडियोधर्मी होने के कारण इस कार्बन परमाणु का द्रव्यमान समय के साथ जैविक शरीर में घटता जाता है। यह रेडियोधर्मिता का एक गुण होता है। इसे रेडियोएक्टिव विघटन कहते हैं।
- ऐसे में जब कोई जीवित वस्तु जैसे कि कोई पौधा या जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में कार्बन -12 से कार्बन -14 का अनुपात या उसके अवशेष बदलना शुरू हो जाते हैं।
- इस परिवर्तन को मापकर यह पता लगाया जा सकता है कि अमुक कार्बनिक वस्तु कितना पुराना है यानी उसके उम्र का पता लगाया जा सकता है।

लेकिन निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या, जैसे वाराणसी में कथित शिवलिंग?

- इसका उपयोग चट्टानों जैसी निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिए।
- कार्बन डेटिंग से 40,000-50,000 वर्ष से अधिक पुरानी चीजों की आयु का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्ध-जीवन के 8-10 चक्रों के बाद, C-14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता नहीं चल पाती है।
- लेकिन निर्जीव चीजों की उम्र की गणना करने के लिए अन्य तरीके भी हैं, जिनमें से कई कार्बन डेटिंग के समान सिद्धांत पर आधारित हैं। इसलिए, कार्बन के बजाय, सामग्री में मौजूद अन्य रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय काल निर्धारण पद्धति का आधार बन जाता है। इन्हें रेडियोमीट्रिक कालनिर्धारण विधियों के रूप में जाना जाता है।
- इनमें से कई में अरबों वर्षों के अर्ध-जीवन वाले तत्व शामिल हैं, जो वैज्ञानिकों को बहुत पुरानी वस्तुओं की आयु का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं।

कार्बन डेटिंग पद्धति के लिए तरीके:

- चट्टानों के काल-निर्धारण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो विधियाँ पोटेशियम-आर्गन काल-निर्धारण और यूरेनियम-थोरियम-लेड काल-निर्धारण हैं। पोटेशियम का रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्गन में क्षय हो जाता है, और उनका अनुपात चट्टानों की उम्र के बारे में एक सुराग दे सकता है।
- यूरेनियम और थोरियम में कई रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं, और ये सभी स्थिर सीसा परमाणु में क्षय हो जाते हैं। सामग्री में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है और उम्र के बारे में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह निर्धारित करने के भी तरीके हैं कि कोई वस्तु कितनी देर तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रही है। ये विभिन्न तकनीकों को लागू करते हैं, लेकिन फिर से रेडियोधर्मी क्षय पर आधारित होते हैं और विशेष रूप से दफन वस्तुओं या टोपोलॉजी में परिवर्तन का अध्ययन करने में उपयोगी होते हैं।
- इनमें से सबसे आम को कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड डेटिंग या सीआरएन कहा जाता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों में आइस कोर की उम्र का अध्ययन करने के लिए नियमित रूप से इसका उपयोग किया जाता है।

तो ज्ञानवापी मामले में यह सब कैसे फिट बैठता है?

- ज्ञानवापी मामले में, हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी।
- कथित "शिवलिंग" को हिंदू द्वारा मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जा रहा है। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि यह स्थापित हो जाता है कि 1669 में मस्जिद के बनने से पहले उस जगह पर "शिवलिंग" मौजूद था।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार संरचना को उखाड़ा या बाधित नहीं किया जा सकता है।

जल्लीकट्टू कानून वैध, सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जल्लीकट्टू को एक "गोजातीय खेल" करार दिया है जो एक सदी से तमिलनाडु में मौजूद है।
- इसने राज्य विधायिका के उस प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं किया कि सांडों को काबू करने की घटना लोगों की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का हिस्सा है।

मुख्य विचार:

- न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 2017 के पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम और 2017 के पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (जल्लीकट्टू का संचालन) नियमों की वैधता को बरकरार रखा।
- उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के बैलगाड़ी दौड़ और भैंसों की दौड़ से संबंधित खेल 'कंबाला' को भी मंजूरी दी।
- पिछली सुनवाई में सरकार ने हलफनामे में कहा था कि जल्लीकट्टू केवल मनोरंजन का काम नहीं है, बल्कि महान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाला कार्यक्रम है। इस खेल में सांडों पर कोई क्रूरता नहीं होती है।
- पीठ ने कहा, "हम विशेष रूप से निर्देश देते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकारी नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन के बाद बनाए गए कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।"

याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा:

- जल्लीकट्टू को 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए. नागराजा मामले में प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसे "क्रूर" कहा गया था। लेकिन इससे पहले राज्य ने 2017 में संशोधन अधिनियम पारित किया था, जिसमें भाग लेने वाले सांडों या मानव जीवन के नुकसान को रोकने के लिए कई उपाय किए गए थे।
- खंडपीठ ने कहा कि राज्य को 2017 के कानून को लागू करने का अधिकार है।

निष्कर्ष:

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू और इसी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराज और अन्य मामले में राज्य सरकारों द्वारा संशोधन पारित किए गए थे।
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 17 के अनुसार इन संशोधनों को करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास विधायी शक्ति थी।
- इसमें कहा गया है कि कानून जानवरों के प्रति क्रूरता और दंड के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। चूंकि इन संशोधित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी थी, इसलिए इन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता था।

चुनावों में मुफ़्त प्रसारण का औचित्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान सार्वजनिक संचार तंत्र, ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) और दूरदर्शन पर मुफ्त प्रसारण प्रदान किया गया था।

विवरण:

- यह आवंटन छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी), आम आदमी पार्टी (एएपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) तथा एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) के लिए उपलब्ध था।
- पार्टियों को 45 मिनट का आधार समय और पिछले चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त स्लॉट आवंटित किए गए थे। इस आवंटन के अंतर्गत कुल 630 मिनट का मुफ्त एयरटाइम जारी किया गया था।

योजना का औचित्य क्या है?

- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में 2003 के संशोधन के माध्यम से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त एयरटाइम प्रदान करने की सुविधा को वैधानिक आधार दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रसिद्ध निर्णय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड एएनआर, 1995) में कहा कि एयरवेव्स सार्वजनिक संपत्ति हैं और इसका उपयोग व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाना चाहिए।
- चुनाव लोकतंत्र की जीवनरेखा होते हैं, अनुचित चुनावी लाभ हासिल करने के लिए हवाई तरंगों का दुरुपयोग या कुप्रयोग विश्व भर की सरकारों की एक प्रमुख नियामक आशंका है।

वैश्विक प्रथाएं:

- अमेरिका में, उदाहरण के लिए, संघीय संचार आयोग, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रित करता है, ने निष्पक्षता सिद्धांत को एयरवेव्स पर चुनाव प्रचार को न्यायसंगत रखने के लिए तैयार किया।
- अब निष्क्रिय निष्पक्षता सिद्धांत प्रसारकों पर एक सकारात्मक दायित्व डालता है जो चुनावी मैदान में एक उम्मीदवार की राजनीतिक सामग्री को अपने कार्यक्रम में दूसरे उम्मीदवार के लिए विस्तारित करने के लिए ले जाते हैं।
- यू.के. में भी, राजनीतिक दलों को लोगों को महत्वपूर्ण राजनीतिक जानकारी देने के लिए संसद द्वारा नामित स्लॉट आवंटित किए जाते हैं, जिसे पार्टी राजनीतिक प्रसारण (पीपीबी) कहा जाता है।
- ब्रिटिश संचार प्रहरी, ऑफकॉम, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक सेवा टेलीविजन चैनल और वाणिज्यिक रेडियो सेवाओं में पीपीबी शामिल हैं।

- सिंगापुर, ब्राजील और जापान में समान आवश्यकताओं को अपनाया गया है।

योजना का कार्य क्या है?

- कर्नाटक चुनाव में, भाजपा को डीडी और आकाशवाणी दोनों पर 167 मिनट का प्रसारण समय मिला, जबकि कांग्रेस को 174 मिनट और जनता दल (एस) को 107 मिनट का समय मिला।
- टाइम वाउचर प्राइमटाइम स्लॉट प्राप्त करने में किसी भी तरजीही उपचार को खत्म करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा एक लॉटरी प्रणाली द्वारा वितरित किए जाते हैं।
- राजनीतिक दलों के प्रतिलेखों की जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक संहिताओं का पालन करते हैं। ये कोड ऐसी किसी भी सामग्री का निषेध करते हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण है, धर्मों या अन्य समुदायों पर हमला करती है या हिंसा और व्यक्तिगत हमलों को उकसाती है।
- सार्वजनिक प्रसारक द्वारा स्क्रिप्ट की सामग्री पर किसी भी असहमति के मामले में, इसे आकाशवाणी और डीडी के सदस्यों वाली एक शीर्ष समिति के पास भेजा जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है।
- भारतीय मीडिया परिदृश्य में, मीडिया घरानों के स्वामित्व के पैटर्न के कारण, आम तौर पर जनता एक ब्रॉडकास्टर की पहचान एक या दूसरे राजनीतिक दल से संबद्ध होने के रूप में करती है। इस संबंध में, राज्य प्रायोजित एयरटाइम चुनावी प्रक्रिया को अधिक विविधता और रंग प्रदान करता है।
- भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार आकाशवाणी और डीडी द्वारा अधिकतम दो पैनल चर्चाओं का प्रसारण भी आवश्यक है।
- ये चर्चाएँ बड़े और छोटे दोनों पक्षों को एक-दूसरे की नीतियों और घोषणापत्रों पर बहस करने और उनकी आलोचना करने और आम तौर पर एक सूचित नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती हैं।

परिचालन चुनौतियां क्या हैं?

- तथ्य यह है कि योजना राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियों के लिए उपलब्ध है, यह तर्क आकर्षित कर सकता है कि यह वास्तव में न्यायसंगत नहीं है।
- नेशनलिस्ट पीपल्स कोएलिशन (NPC) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में वापस लेने के आलोक में, यह अवलोकन महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि, ईसीआई व्यावहारिकता के विचारों और इस तथ्य से विवश है कि एयरवेव्स एक अनंत संसाधन नहीं हैं।
- सर्वोच्च समिति में आकाशवाणी और डीडी के अधिकारी शामिल हैं और प्रतिलेख की सामग्री पर राजनीतिक दल के साथ संघर्ष के मामले में अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। यह हितों के टकराव की गुंजाइश छोड़ देता है और इसलिए, एक अधिक प्रतिनिधि समिति का गठन किया जा सकता है।
- यू.एस. के निष्पक्षता सिद्धांत के समान निजी प्रसारकों को कवर करने के लिए प्रावधान का विस्तार करने की भी मांग की जा रही है।
- निजी चैनलों को समान रूप से सामग्री प्रसारित करने और छोटे दलों और उम्मीदवारों के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक निर्दिष्ट स्लॉट अनिवार्य किया जा सकता है। राजनीतिक प्रसारण को नियमित समाचार प्रसारण और कार्यक्रमों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है।

आगे की राह:

- 2024 के आम चुनाव मीडिया में अभूतपूर्व स्तर के चुनावी प्रचार के गवाह बनेंगे।
- शांत, निष्पक्ष, सुविचारित और विचारशील बहस के लिए स्थान ध्यान आकर्षित करने के लिए एक उन्माद में सिमट जाते हैं, यह अनिवार्य है कि भारतीय लोकतंत्र को पोषण और समृद्ध करने और अन्य चुनावी लोकतंत्रों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए हवाई तरंगों का उपयोग किया जाए।

आंध्र प्रदेश डॉटेड लैंड को निषिद्ध सूची से मुक्त कराना प्रारंभ किया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में "डॉटेड लैंड्स' को निषिद्ध सूची से हटाना शुरू कर दिया है, इन जमीनों को बेचने या उन किसानों को गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार बहाल कर दिया है, जो उनके मालिक हैं।
- ब्रिटिश काल की इन डॉटेड लैंड में से 2 लाख एकड़ से अधिक भूमि को स्थायी रूप से गैर-अधिसूचित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

डॉटेड लैंड किस प्रकार की होती है?

- डॉटेड लैंड्स (बिंदीदार भूमि) विवादित भूमि होती है जिसके लिए कोई स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ-साथ सरकार का राजस्व विभाग भूमि पर दावा करता है।
- इन भूमियों को "बिंदीदार भूमि" के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि जब, ब्रिटिश काल के दौरान, भू-स्वामित्व सर्वेक्षण और भू-अभिलेखों का पुनः बंदोबस्ती किया गया, तो स्थानीय राजस्व अधिकारी जिन्हें सरकारी और निजी स्वामित्व वाली भूमि की पहचान करने का काम सौंपा गया था उसे यदि एक से अधिक व्यक्ति द्वारा स्वामित्व का दावा करते मिला, या यदि स्वामित्व स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता था, तो स्वामित्व कॉलम में डॉट्स लिख दिया।
- इन भूमियों को बंदोबस्ती रजिस्टर या भूमि अभिलेख रजिस्टर में भी विवादित भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। भूमि दस्तावेजों पर डॉट्स ने उनका विवादित भूमि के रूप में संकेत किया।

ये स्वामित्व विवाद किस प्रकार उत्पन्न हुए?

- यह तब हो सकता है जब भूमि के मालिक अपने वारिसों या बच्चों को ज़मीन देने के लिए स्पष्ट वसीयतें न छोड़ें, और अगर ज़मीन पर एक से अधिक वारिसों का दावा होने के कारण विवाद पैदा हो जाए। इसके अलावा, भूमि को सरकार द्वारा राज्य से संबंधित माना जा सकता है, लेकिन निजी पार्टियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
- विचाराधीन कुछ भूमि अभिलेख 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं, और उन्हें प्रतिबंधित सूची और रजिस्टरों में बंद कर दिया गया था।
- बाद के सर्वेक्षणों के दौरान, सरकारी अधिकारियों ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 22ए के अनुसार अपनी विवादित स्थिति का संकेत देते हुए स्वामित्व वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया।

चिन्हित भूमि:

- राज्य सरकार ने अब तक 2,06,171 एकड़ भूमि को चिन्हित भूमि के रूप में चिन्हित किया है, और उन्हें निषिद्ध सूची से हटाने का निर्णय लिया है।
- राज्य में 10 लाख एकड़ से अधिक डॉटेड भूमि हो सकती है।
- नेल्लोर जिले में डॉटेड लैंड पार्सल (43,000 एकड़) की सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद प्रकाशम जिले (37,000 एकड़) का स्थान है।

इस कदम से भूस्वामियों/किसानों को किस प्रकार लाभ होगा?

- मार्च में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान, सरकार ने 12 वर्षों से अधिक समय से बिंदीदार भूमि पर खेती करने वाले किसानों को टाइटल देने के लिए राजस्व अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया।
- भूमि रजिस्टरों में बिंदुओं और प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा और इन किसानों को स्पष्ट भूमि स्वामित्व दस्तावेज दिए जाएंगे। कम से कम 97,000 किसानों को 2,06,171 एकड़ विमुक्त बिंदीदार भूमि के लिए भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज मिलेंगे।
- जब ये किसान भूमि का उपयोग कर रहे थे, तब वे भूमि को संपार्श्विक के रूप में रखकर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे। वित्तीय संस्थान स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेजों के रूप में बिंदीदार भूमि दस्तावेजों को नहीं पहचानते हैं।
- भूमि को अब निषिद्ध सूची से हटा दिए जाने के साथ, भूस्वामियों/किसानों को भूमि पर पूर्ण अधिकार मिल जाएगा, और भूमि मालिकों के रूप में सभी सामान्य अधिकारों का आनंद लेंगे।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे फसल सहायता, बीज और उर्वरक की खरीद और कृषि उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भू-स्वामी/किसान अपने परिजनों या रिश्तेदारों को भूमि या उपहार भी बेच सकते हैं।

राज्य सरकार ने यह कवायद क्यों शुरू की?

- मुख्य भूमि सीमा आयुक्त (सीसीएलए) को विगत वर्षों में भूमि विवादों को हल करने के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
- शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से बिंदीदार भूमि को बेच दिया गया है और घरों का निर्माण किया गया है, जिस पर कर नहीं लगाया जा सकता है। लाखों एकड़ जमीन पर विवाद होने से सरकार को स्टांप ड्यूटी राजस्व का भी नुकसान होता है।
- 2,06,171 एकड़ का पंजीकरण मूल्य 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि भूमि का मूल्य 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

चालू योजना:

- बिंदीदार भूमि को मुक्त करने की कवायद वाईएसआर जगन्नाथ शाश्वत भु हक्कू और भू रक्षा योजना को लागू करके वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा ली गई भूमि के व्यापक पुनर्सर्वेक्षण का भाग थी।
- योजना के अंतर्गत, सरकार ने पहले चरण में 2,000 गांवों में किसानों को 7,92,238 स्थायी शीर्षक विलेख प्रदान किए हैं।
- कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले महीने से शुरू होगा।

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायलय से दिल्ली सरकार के शक्तियों पर पुनर्समीक्षा की मांग की

चर्चा में क्यों?

- केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं पर कानून बनाने और नियंत्रण करने की दिल्ली सरकार की शक्ति को बरकरार रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की मांग की है।

केंद्र द्वारा समीक्षा याचिका:

- केंद्र ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ पर दिल्ली को "पूर्ण राज्य" घोषित करने का प्रभाव था, जबकि यह वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश है।
- केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली को कभी भी राज्य के स्तर तक ऊंचा नहीं किया गया है। केंद्र ने कहा कि निर्णय स्व-विरोधाभासी था, यह कहते हुए कि दिल्ली के पास एक विशिष्ट या विशेष दर्जा है, जबकि उसी समय में इसे 'राज्य' के रूप में माना जाता है।
- केंद्र ने तर्क दिया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए, संसद एकमात्र विधायी निकाय है।
- निर्णय, हालांकि दिल्ली पर संसद के श्रेष्ठ विधायी अधिकार को स्वीकार करते हुए, दिल्ली मंत्रिपरिषद और विधान सभा को व्यापक विधायी और कार्यकारी शक्तियों को मान्यता देने के लिए चला गया था।
- समीक्षा याचिका में कहा गया है कि विधायी शक्तियां संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच वितरित की जाती हैं, न कि संसद और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के बीच।

विरोधाभास:

- याचिका में आगे कहा गया है कि पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय फैसला नई दिल्ली नगर निगम बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट

के 1997 के नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ के फैसले का खंडन करता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 69वें संशोधन के बावजूद विधान सभा की शुरुआत की गई थी। दिल्ली, दिल्ली का एनसीटी एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

- केंद्र ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 309 स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सेवाओं के बीच अंतर करता है। केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवाएं स्पष्ट रूप से केंद्र से संबंधित थीं।
- अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लेफ्टिनेंट-गवर्नर (एलजी) के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित केंद्रीय भर्ती नियमों के अनुसार दिल्ली प्रशासन में नियुक्तियां और स्थानान्तरण किए जाते हैं।

कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई किस प्रकार होती है?

- संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश का कानून बन जाता है। हालाँकि, संविधान, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति देता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम अधिकार से इस प्रस्थान को विशिष्ट, संकीर्ण आधारों के तहत माना जाता है। इसलिए, जब कोई समीक्षा होती है, तो कानून यह है कि उसे मामले का ताजा जायजा लेने की अनुमति नहीं है, बल्कि उन गंभीर त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।
- न्यायालय के पास "पेटेंट त्रुटि" को ठीक करने के लिए अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है न कि "अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियों" की।
- 1975 के एक फैसले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि एक समीक्षा को "केवल वहीं स्वीकार किया जा सकता है, जहां एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक चूक से हुई हो"।

याचिकाकर्ता किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की मांग कर सकता है?

- 2013 के एक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए तीन आधार निर्धारित किए:
  a) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, याचिकाकर्ता के ज्ञान से परे थी या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी;
  b) गलती या त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है;
  c) या कोई अन्य पर्याप्त कारण। बाद के निर्णयों में, अदालत ने निर्दिष्ट किया कि "किसी भी पर्याप्त कारण" का अर्थ एक ऐसा कारण है जो अन्य दो आधारों के साथ तुलनीय है।
- 2013 के एक अन्य निर्णय (भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड) में, न्यायालय ने नौ सिद्धांतों को निर्धारित किया कि समीक्षा कब की जा सकती है। एक समीक्षा किसी भी तरह से भेष में अपील नहीं है जिससे एक गलत निर्णय को फिर से सुना जाता है और सही किया जाता है लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए होता है। इसमें कहा गया है कि इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं हो सकती है।

समीक्षा याचिका विफल होने पर क्या होता है?

- न्याय के अंतिम द्वार के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिणाम न्याय की विफलता नहीं हो सकता है।
- रूपा हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा (2002) में, अदालत ने स्वयं एक उपचारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित की, जिसे इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक समीक्षा खारिज होने के बाद सुना जा सकता है।
- उपचारात्मक याचिका पर भी समीक्षा याचिका की तरह बहुत संकीर्ण आधार पर विचार किया जाता है, और आम तौर पर मौखिक सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाती है।

दिल्ली में सेवाओं को लेकर खींचतान

चर्चा में क्यों?

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने 11 मई को कहा कि दिल्ली सरकार कानून बना सकती है और राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं का संचालन कर सकती है।
- न्यायालय ने राजधानी में नौकरशाहों पर उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका को तीन विशिष्ट क्षेत्रों - सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि तक सीमित कर दिया।
- हालांकि, 19 मई को, राजधानी में सेवाओं पर सत्ता का एक नया दावा करने के लिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया है।

अध्यादेश क्या कहता है?

- सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी मूल स्थिति में लौटने के लिए अध्यादेश के रास्ते का प्रयोग किया है, जिसे उसने 21 मई, 2015 को गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से लिया था।
- अधिसूचना, जिसने पिछले आठ वर्षों से आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और केंद्र के बीच विवाद की जड़ का निर्माण किया, ने उपराज्यपाल (एलजी) को सेवाओं पर शक्ति प्रदान की। इसके लिए एलजी को अपने "विवेक" पर ही मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता थी। अधिसूचना ने दिल्ली सरकार की शक्तियों के दायरे से राज्य सूची की प्रविष्टि 41 (सेवाओं) को बाहर कर दिया था।

एनसीसीएसए:

- अध्यादेश एक "स्थायी" राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) बनाता है जिसमें मुख्यमंत्री क्रमशः अध्यक्ष और मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव क्रमशः सदस्य और सदस्य सचिव होते हैं।

- एनसीसीएसए सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी विभागों में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों पर अधिकार का प्रयोग करता है।
- यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से दिल्ली सरकार के विभागों में प्रतिनियुक्त सिविल सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, अभियोजन स्वीकृति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सतर्कता मुद्दों आदि का निर्णय करेगी। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- यह एक ऐसा परिदृश्य खोलता है जिसमें एनसीसीएसए के नौकरशाह संभवतः मुख्यमंत्री को वीटो कर सकते हैं। अध्यादेश बताता है कि मुख्य सचिव "जीएनसीटीडी के अधिकारियों की इच्छा" (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) का प्रतिनिधित्व करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तटस्थ मार्ग:

- सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रिपरिषद के दिन-प्रतिदिन के निर्णयों को पूरा करने के लिए एक "तटस्थ सिविल सेवा" की परिकल्पना की थी। एनसीसीएसए सिविल सेवा अधिकारियों को निर्वाचित मंत्रियों के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर लाने का प्रयास करता है, जो लोगों की इच्छा को मूर्त रूप देते हैं, और उन्हें एक शक्तिशाली लॉबी में बदल देते हैं।
- अध्यादेश, एनसीसीएसए बनाकर, दिल्ली के शासन में "ट्रिपल चेन ऑफ कमांड" पर दिए गए निर्णय में दिए गए जोर को कम कर देता है। अदालत ने माना था कि सिविल सेवाएं निर्वाचित सरकार के मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हैं, जिनके अंतर्गत वे कार्य करते हैं।
- अध्यादेश राष्ट्रपति के स्वयं के कार्य संचालन नियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 1993 का भी पालन नहीं करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कहा था कि "नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (एनसीटीडी) के कार्यकारी कार्यों के दायरे में आते हैं, उन पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद"। यह दृष्टिकोण को 11 मई, 2023 को दृढ़ता प्राप्त हुआ।

के. बालकृष्णन समिति:

- न्यायालय ने के. बालाकृष्णन समिति की विशिष्ट सिफारिश को भी खारिज कर दिया था कि "सेवाओं" को एनसीटीडी के विधायी और कार्यकारी दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- अदालत ने माना कि समिति की रिपोर्ट प्रासंगिक नहीं थी क्योंकि यह अनुच्छेद 239AA को सम्मिलित करने से पहले थी - वह प्रावधान जो 69वें संविधान संशोधन, 1991 में दिल्ली की शासन संरचना से संबंधित है।

क्या अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाता है?

- अध्यादेश इस तर्क पर आधारित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं राष्ट्रीय राजधानी के लिए कानून बनाने के लिए संसद के श्रेष्ठ अधिकार को स्वीकार किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली एक "पूर्ण राज्य" नहीं है, बल्कि केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केंद्र का विस्तार है। संसद दिल्ली की सच्ची विधायिका है, केंद्र ने तर्क दिया है।
- हालांकि, 11 मई के फैसले ने इस विवाद को स्वीकार करते हुए संबोधित किया कि हालांकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसकी विधान सभा को संवैधानिक रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सौंपी गई है।
- सर्वसम्मत निर्णय में कहा गया है कि हालांकि दिल्ली संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत एक राज्य नहीं है, इसे "एनसीटीडी के लोगों की आकांक्षाओं को प्रभावित करने के लिए" विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है जो एनसीटीडी के लोगों के प्रति जवाबदेह है।
- अनुच्छेद 239एए(3) में परिकल्पित संवैधानिक योजना के अंतर्गत, एनसीटीडी को विधायी शक्ति दी गई थी, जो हालांकि सीमित है, कई पहलुओं में राज्यों के समान है। उस अर्थ में, अनुच्छेद 239AA को जोड़ने के साथ, संविधान ने केंद्र में भारत संघ और क्षेत्रीय स्तर पर एनसीटीडी के साथ एक "असममित संघीय मॉडल" बनाया।

एलजी की शक्तियों के बारे में अध्यादेश और निर्णय क्या कहते हैं?

- अध्यादेश ने सेवाओं के संबंध में एनसीसीएसए द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति देकर एलजी को चालक की सीट पर वापस रख दिया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि एलजी की शक्तियों को 2018 में एक अन्य संविधान पीठ के निर्णय से कम कर दिया गया था।
- 11 मई को, अदालत ने 2018 में अपने निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त की थी कि एलजी अनुच्छेद 239AA (4) के तहत एनसीटीडी की विधान सभा के विधायी डोमेन के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं।
- अदालत ने माना था कि एलजी को दी गई "सीमित विवेकाधीन शक्ति" का भी "राष्ट्रीय हित और वित्त के मामलों जैसे दुर्लभ परिस्थितियों में सावधानीपूर्वक तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर हर मामले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं"।

आगे क्या निहित है?

- कोई भी अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यदि 2023 के अध्यादेश को अलग से चुनौती दी जाती है, तो संघ को "असाधारण या आकस्मिक स्थिति" को साबित करना होगा, जिसके कारण संविधान पीठ द्वारा कानून का निपटारा करने के कुछ ही दिनों बाद अध्यादेश को लागू करना आवश्यक हो गया।
- डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य मामले में एक संविधान पीठ ने कहा था कि अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की शक्ति को "राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत" नहीं किया जाना चाहिए।

सीजेआई ने फोरम शॉपिंग की निंदा की

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI) ने फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा की। उल्लेखनीय है कि एक वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसी मामले का उल्लेख किया गया जिसका उल्लेख उसने एक दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष भी किया था।

क्या है फोरम शॉपिंग?

- 22 मार्च, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, 'फोरम शॉपिंग' शब्द को किसी भी भारतीय क़ानून में एक विशेष परिभाषा नहीं दी गई है।
- जब कोई वकील अथवा वादी अपने केस को जानबूझकर किसी विशेष जज या न्यायालय में ट्रांसफर कराने का प्रयास करता है, और उन्हें लगता है कि इससे जजमेंट उनके अनुकूल हो सकता है तो कानून की भाषा में इसे फोरम शॉपिंग' कहा जाता है।
- वेबस्टर्स डिक्शनरी के मुताबिक फोरम शॉपिंग का मतलब ऐसी अदालत का चुनाव है, जहां से एडवोकेट अथवा वादी के पक्ष में फैसला आ सकता है।
- कोई भी एडवोकेट मुकदमा दायर करने से पहले एक रणनीति बनाता है और तय करता है कि याचिका दायर करने का सबसे सही मंच कौन सा होगा।
- उदाहरण के लिए कई बार संबंधित वकील हाईकोर्ट न जाकर PIL के जरिये सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, ताकि उसकी याचिका और हाईलाइट हो सके। यह 'फोरम शॉपिंग' के दायरे में आता है।

वैश्विक संदर्भ:

- फोरम शॉपिंग' को लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन जैसे देशों में लंबे समय से बहस चल रही है। तमाम देशों ने फोरम शॉपिंग से बचने के लिए "forum non-conveniens" सिद्धांत अपनाया है।
- इसके तहत न्यायालय को ऐसी शक्ति दी गई है कि वह किसी ऐसे केस में, जिसे किसी और उचित फोरम या न्यायालय में सुना जा सकता है, वहां अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है।
- उदाहरण के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई मामला हाईकोर्ट में जाना चाहिए तो इसका निर्देश दे सकता है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए न्याया लय, न्याय और याचिकाकर्ता के हित को ध्यान में रखते हुए मामले को उचित पीठ को आवंटित करते हुए खारिज कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने साल 1988 के बहुचर्चित 'चेतक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम ओम प्रकाश (Chetak Construction Ltd. vs. Om Prakash) मामले में साफ कहा था कि किसी भी याचिकाकर्ता को किसी सूरत में फोरम शॉपिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इस तरह के किसी भी प्रयास से कड़ाई से निपटना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की राय:

- अदालत के फैसले के अनुसार, 'फोरम शॉपिंग' को अदालतों द्वारा एक विवादित प्रथा करार दिया गया है और कानून में इसकी कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है।
- फैसले में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तरदाताओं में से एक ने तीन शिकायतें दर्ज कीं, दो दिल्ली में और एक कोलकाता में। दायर की गई शिकायतों की समय-सीमा को देखते हुए, अदालत ने कहा कि उसने प्रतिवादी के दुर्भावनापूर्ण इरादे को निर्दिष्ट किया था, जो याचिकाकर्ताओं को परेशान करना था और "उन पर निवेश करने के लिए दबाव डालना था।"
- अपने 2022 के फैसले में, अदालत ने 'भारत संघ और अन्य बनाम सिप्ला लिमिटेड' मामले में 2017 के एक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें फोरम शॉपिंग के लिए "कार्यात्मक परीक्षण" को अपनाने के लिए निर्धारित किया गया था।

उच्च न्यायालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाई:

- इसी साल 28 मार्च को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने 'डॉ. खेरुन्निसा व अन्य बनाम जम्मू कश्मीर सरकार व अन्य मामले में याचिकाकर्ता को फोरम शॉपिंग का दोषी मानते हुए 10,0000 का जुर्माना लगा दिया था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के अलग-अलग विंग्स में अर्जी दायर की थी।
- इसी तरह, पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने धनवंतरी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज वर्सेस राजस्थान सरकार मामले में एक पार्टी को फोरम शॉपिंग का दोषी मानते हुए 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था।

तेलंगाना-आंध्र प्रदेश जल विवाद

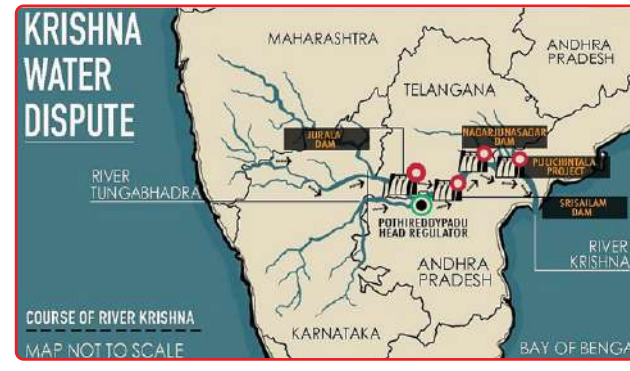

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राज्य के विभाजन के नौ साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अनसुलझा है।

कृष्णा जल विवाद का मूल क्या है?

- यह विवाद नवंबर, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन से पहले का है। आंध्र प्रदेश के गठन से पहले, रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना क्षेत्र सहित आंध्र के विभिन्न क्षेत्रों के चार-चार वरिष्ठ नेताओं ने 20 फरवरी, 1956 को एक सज्जन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- अन्य बातों के अलावा, समझौते के प्रावधानों में से एक विश्व स्तर पर पालन की जाने वाली संधियों के आधार पर न्यायसंगत वितरण के साथ

जल संसाधनों के उपयोग के संबंध में तेलंगाना के हितों और जरूरतों की सुरक्षा थी।

- हालांकि, सिंचाई सुविधाओं के संबंध में संयुक्त व्यवस्था का ध्यान आंध्र पर था, जिसमें पहले से ही तेलंगाना में इन-बेसिन सूखाग्रस्त क्षेत्रों की कीमत पर अंग्रेजों द्वारा विकसित प्रणालियां थीं, एक तथ्य जो बाद के क्षेत्र के नेताओं द्वारा शुरू से ही तर्क दिया गया था।

बच्चावत न्यायाधिकरण:

- इसके अलावा, 1969 में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश (विभाजन से पहले) के तटीय राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को निपटाने के लिए बचावत ट्रिब्यूनल (KWDT-I) का गठन किया गया था। न्यायाधिकरण ने आंध्र प्रदेश को 811 टीएमसीएफटी भरोसेमंद पानी आवंटित किया।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने बाद में इसे क्रमशः आंध्र (रायलसीमा के कुछ हिस्सों सहित, जिसमें कृष्णा बेसिन शामिल हैं) और तेलंगाना के बीच 512:299 tmcft अनुपात में विकसित कमांड क्षेत्र या तब तक स्थापित उपयोग तंत्र के आधार पर विभाजित किया।
- ट्रिब्यूनल ने तुंगभद्रा बांध (कृष्णा बेसिन का एक हिस्सा) के पानी को तेलंगाना के सूखा-प्रवण महबूबनगर क्षेत्र में ले जाने की भी सिफारिश की थी।
- हालांकि, इसका पालन नहीं किया गया, जिससे लोगों में असंतोष पैदा हुआ। तेलंगाना ने बार-बार दोहराया है कि जल संसाधनों के वितरण के मामले में आंध्र प्रदेश में उसके साथ किस तरह अन्याय हुआ है।

विभाजन के बाद जल बंटवारे की क्या व्यवस्था थी?

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में पानी के हिस्से का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि KWDT-I अवार्ड, जो अभी भी लागू था, ने क्षेत्रवार कोई आवंटन नहीं किया था।
- 2015 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक बैठक में, दोनों राज्यों ने तदर्थ व्यवस्था के रूप में 34:66 (तेलंगाना: आंध्र प्रदेश) अनुपात में पानी साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि इसकी समीक्षा की जानी है प्रत्येक वर्ष।
- अधिनियम में व्यवस्था केवल दो बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) की स्थापना करके जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए थी।
- तेलंगाना के विरोध के बावजूद KRMB ने साल दर साल इसी अनुपात को जारी रखा। अक्टूबर 2020 में, तेलंगाना ने पानी के बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने तक समान हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाई।
- इस महीने की शुरुआत में हुई बोर्ड की बैठक में, तेलंगाना ने समान हिस्सेदारी के लिए अपना कदम पीछे खींच लिया और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने से इनकार कर दिया। सदस्य राज्यों को समझाने में असमर्थ, नदी बोर्ड ने मामले को जल शक्ति मंत्रालय (MoJS) को भेज दिया है।

प्रत्येक राज्य क्या दावा करता है?

- तेलंगाना अपने गठन के पहले दिन से ही केंद्र से पानी के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए कह रहा है। नदी के पानी को साझा करने में विश्व स्तर पर हुई संधियों और समझौतों का हवाला देते हुए, तेलंगाना तर्क दे रहा है कि बेसिन मापदंडों के अनुसार, वह 811 tmcft के आवंटन में कम से कम 70% हिस्सेदारी का हकदार है।
- इसके अलावा, यह इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि आंध्र प्रदेश कैसे तेलंगाना में बेसिन के भीतर फ्लोराइड प्रभावित और सूखा-प्रवण क्षेत्रों से लगभग 300 tmcft पानी बेसिन के बाहर के क्षेत्रों में मोड़ रहा है।
- दूसरी ओर, आंध्रप्रदेश भी पहले से विकसित कमांड क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए पानी के अधिक हिस्से का दावा करता रहा है।

केंद्र का रुख क्या है?

- केंद्र ने इस मुद्दे से निपटने का कोई प्रयास किए बिना 2016 और 2020 में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की शीर्ष परिषद की दो बैठकें बुलाई हैं।
- 2020 में एमओजेएस द्वारा दिए गए एक सुझाव के बाद, तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अपनी याचिका वापस ले ली है क्योंकि मंत्रालय ने पानी के शेयरों के मामले को ट्रिब्यूनल को भेजने का आश्वासन दिया था।
- हालांकि, केंद्र दो साल से अधिक समय से इस मुद्दे पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों राज्यों के बीच दिन-रात इस मामले पर मतभेद जारी है।

अध्यादेशों का पुनःर्प्रख्यापन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत निर्णय को रद्द कर दिया, जिसने 11 मई को दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT), सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंध को छोड़कर अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर नियंत्रण दिया था।

विवरण:

- राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को, जिन्हें केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, सेवाओं पर अधिकार दिया।
- इसने एक "राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण" की स्थापना की जिसमें मुख्यमंत्री और दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल थे, जो "उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से" मामलों को तय करेंगे, अनिवार्य रूप से एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे जिसमें निर्वाचित मुख्यमंत्री की राय हो सकती है संभावित रूप से खारिज किया जा सकता है।

संविधान में अध्यादेश:

- संविधान के अनुच्छेद 123 (संसद के मध्यावकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति) के अंतर्गत, "अगर किसी भी समय, संसद के दोनों सदनों के सत्र को छोड़कर, राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं तत्काल कार्रवाई करें, वह ऐसे अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है क्योंकि परिस्थितियाँ उसे आवश्यक प्रतीत होती हैं।"
- एक अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव "संसद के अधिनियम के समान होगा"। लेकिन सरकार को अनुसमर्थन के लिए संसद के समक्ष एक अध्यादेश लाने की आवश्यकता है और ऐसा करने में विफलता "संसद की पुन: बैठक से छह सप्ताह की समाप्ति पर" समाप्त हो जाएगी।
- यदि राष्ट्रपति इसे वापस लेते हैं, या यदि दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। (हालांकि, एक अध्यादेश की अस्वीकृति का अर्थ यह होगा कि सरकार ने बहुमत खो दिया है।)
- इसके अलावा, यदि कोई अध्यादेश ऐसा कानून बनाता है कि संसद संविधान के अंतर्गत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसे शून्य माना जाएगा।
- चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, इसलिए प्रभावी तौर पर सरकार ही अध्यादेश लाने का फैसला करती है। राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट की सिफारिश वापस कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए; यदि इसे वापस (पुनर्विचार के साथ या बिना) भेजा जाता है, तो उसे इसे प्रख्यापित करना होगा।
- अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश को लागू करने/वापस लेने के लिए राज्यपाल की मोटे तौर पर समान शक्तियों से संबंधित है।
- कोई अध्यादेश अगला सत्र शुरू होने की तारीख से छह सप्ताह या 42 दिनों के लिए वैध होता है। यदि दोनों सदन अलग-अलग तिथियों पर अपना सत्र शुरू करते हैं, तो बाद की तारीख पर विचार किया जाएगा, इसे अनुच्छेद 123 और 213 की व्याख्या कह सकते हैं।

अध्यादेश का पुन: प्रख्यापन:

- अगर, किसी भी कारण से, कोई अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो सरकार के पास इसे फिर से जारी करने या फिर से लागू करने का एकमात्र विकल्प होता है।
- वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले की जांच की जहां बिहार राज्य ने विधानमंडल के समक्ष रखे बिना कई बार एक अध्यादेश को फिर से लागू किया। (कृष्ण कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य)
- अदालत की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ, जिसमें अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं, ने दोहराया कि कानून सामान्य रूप से विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए, और एक अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति एक आपातकालीन शक्ति की प्रकृति में है .
- अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो एक अध्यादेश को फिर से जारी करने की अनुमति देती हैं, हालांकि, उसने कहा, अध्यादेश को विधायिका में लाए बिना बार-बार फिर से जारी करना विधायिका के कार्य को बाधित करेगा, और असंवैधानिक होगा।
- अदालत ने उस मामले में कार्रवाई को "संवैधानिक शक्ति पर धोखाधड़ी" घोषित किया, और कहा कि डॉ डी सी वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1986) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए अध्यादेशों को फिर से लागू किया गया था।

डीसी वाधवा मामला:

- डी.सी. वाधवा में, 1967 और 1981 के बीच 256 अध्यादेशों को प्रख्यापित किए जाने के बाद, बिहार में विभिन्न अध्यादेशों को फिर से लागू करने की राज्यपाल की शक्ति के खिलाफ चुनौती दी गई थी, जिनमें से 69 को कई बार फिर से प्रख्यापित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति से जीवित रखा गया।
- तत्कालीन सीजेआई पीएन भगवती की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि "एक आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के फिर से शुरू होने के छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रभाव में नहीं रहेगा।"
- यदि सरकार चाहती है कि अध्यादेश छह सप्ताह की अवधि से अधिक समय तक लागू रहे, तो उसे "विधायिका के समक्ष जाना होगा", जो संवैधानिक प्राधिकरण है जिसे कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए अध्यादेशों के माध्यम से अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को विनियमित करना जारी रखते हुए यह "निश्चित रूप से सरकार के लिए विधायिका की उपेक्षा करने" और "अध्यादेश को फिर से लागू करने" के लिए शक्ति का एक रंगहीन अभ्यास होगा।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

वाशिंगटन घोषणा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल अमेरिका-दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय संबंधों की 70 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अमेरिका पहुंचे।
- यात्रा का एक मुख्य आकर्षण परमाणु निरोध रणनीति के रूप में "वाशिंगटन घोषणा" पर हस्ताक्षर करना था।

अमेरिकी यात्रा को किसने प्रेरित किया?

- उत्तर कोरिया की ह्वासोंग-8 ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM), जो परमाणु हथियार वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, के सफल प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा को गति प्रदान की है।

- उन्होंने उत्तर कोरिया के क्षेत्रीय आक्रमण के खिलाफ एक विस्तारित परमाणु निवारक योजना पर एक गठबंधन बनाकर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा।

क्या कहता है वाशिंगटन डिक्लेरेशन?

- घोषणा के अनुसार,
  a) कोरियाई प्रायद्वीप में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैनात की जाएगी;
  b) संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति के सिद्धांतों को तैयार करने के लिए एक परमाणु परामर्शदात्री समूह का गठन किया जाएगा;
  c) परमाणु प्रगति के संबंध में दक्षिण कोरिया को अमेरिका से इंटेल प्राप्त होगा; और
  d) अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एक वार्षिक अंतर-सरकारी अनुकरण के माध्यम से दक्षिण कोरिया की परमाणु निवारक क्षमताओं को मजबूत करेगा।

निवारण:

- घोषणा ने अप्रसार संधि की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि दक्षिण कोरिया अपनी स्वतंत्र परमाणु क्षमताओं के निर्माण में उद्यम नहीं करेगा और इसके बजाय गठबंधन-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से निवारक उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- यह अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु टकराव की स्थिति में अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए एकमात्र 'एकमात्र प्राधिकरण' के रूप में भी अनिवार्य करता है।
- जबकि समझौते का अस्तित्व दक्षिण कोरिया की सुरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित है, नीति बड़ी शक्ति की राजनीति को दर्शाती है जहां बड़ी शक्ति (यू.एस.) के हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमेरिका दक्षिण कोरिया के पास परमाणु शस्त्रागार होने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है?

- पूर्व राष्ट्रपति पार्क चुंग ही द्वारा समर्थित दक्षिण कोरिया का परमाणु विकास कार्यक्रम अमेरिकी दबाव के कारण बाधित हुआ। 1990 के दशक में, अमेरिका ने अपनी "रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि" के हिस्से के रूप में दक्षिण कोरिया से एक सौ परमाणु हथियार वापस ले लिए।
- अमेरिका ने एक गलत धारणा बना ली कि वह दक्षिण कोरिया की परमाणु क्षमता को निकालकर उत्तर कोरिया के हथियारों के उत्पादन को रोक सकता है।
- द न्यूक्लियर पॉश्चर रिव्यू 2022 अमेरिकी आख्यान में एक बदलाव को दर्शाता है जहां वह अब उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमताओं के बारे में चिंतित है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया "संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों और साझेदारों के लिए निवारक दुविधा" पैदा करता है, और यह कि "कोरियाई प्रायद्वीप पर एक संकट या संघर्ष में कई परमाणु-सशस्त्र अभिनेता शामिल हो सकते हैं, जो व्यापक संघर्ष के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।"
- और अंत में, अमेरिका वैश्विक परमाणु हथियारों के उत्पादन को नियंत्रित करना चाहता है। यह दक्षिण कोरिया को अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार विकसित करने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक रहा है क्योंकि यह दुनिया में परमाणु उत्पादन को नियंत्रित करने के लंबे प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा।
- यह आश्वासन कि अमेरिका और उसके परमाणु हथियार क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बनकर अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे, अप्रसार के बड़े लक्ष्य के साथ संरेखित है।

जापान, दक्षिण कोरिया संबंधों को आगे ले जाने पर सहमत

चर्चा में क्यों?

- जापान और दक्षिण कोरिया हाल ही में संबंधों को आगे ले जाने और लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक विवादों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, एक ऐसे संबंध को बदलने का वचन दिया है जिसका क्षेत्र के लिए व्यापक प्रभाव हो सकता है।
- जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा 12 वर्षों में सियोल का दौरा करने वाले पहले जापानी नेता बने। यह यात्रा मार्च में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल द्वारा जापान की यात्रा के बाद हुई।

शटल कूटनीति:

- जिसे "शटल डिप्लोमेसी" करार दिया गया है, वह दो अमेरिकी सहयोगियों के बीच संबंधों को बदलने का वादा करता है जो ऐतिहासिक मुद्दों पर आधारित हैं, मुख्य रूप से जापान द्वारा अपने कब्जे के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगने की अनिच्छा अनिच्छा को दर्शाता है।
- हालांकि, दोनों को न केवल उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर बल्कि चीन की क्षेत्रीय ताकत पर साझा चिंताओं के कारण एक साथ लाया गया है।

मार्च समझौता:

- जापान के युद्धकालीन कार्यों पर मतभेदों के बावजूद, जो दक्षिण कोरिया और चीन में एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने आगे बढ़ने के लिए एक मामला बनाकर घरेलू राजनीतिक गिरावट का जोखिम उठाया है और तर्क दिया है कि जबकि ऐतिहासिक मुद्दों को हल किया जाना जारी है, संबंधों को अभी भी भविष्य की ओर देखने की आवश्यकता है।
- उस अंत तक, मार्च में दोनों पक्ष दक्षिण कोरियाई लोगों को मुआवजा देने के लिए एक कोष के साथ आने पर सहमत हुए, जो जापानी मजबूर श्रम कार्यक्रमों के तहत पीड़ित थे।
- मार्च के समझौते के तहत, मुआवजे का भुगतान एक संयुक्त कोष द्वारा किया जाएगा, न कि, जैसा कि दक्षिण कोरिया में कई लोगों ने मांग

की थी, पूरी तरह से जापानी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिनमें से दो ने 2018 में अपने रिकॉर्ड को लेकर दक्षिण कोरिया में कानूनी कार्रवाई का सामना किया था। 1910-45 के कब्जे के दौरान। जापानी सेना द्वारा हजारों कोरियाई महिलाओं को भी यौन गुलामी के लिए मजबूर किया गया था।

आगे की राह:

- दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मार्च यात्रा ने एक ऐसे मेल-मिलाप को आगे बढ़ाया जिसका दोनों नेताओं ने पुरजोर समर्थन किया है।
- वर्तमान यात्रा ने दोनों पक्षों को घनिष्ठ आर्थिक और रक्षा संबंधों का पता लगाने के लिए देखा है। जापानी नेता ने मई 2023 में टोक्यो में आयोजित होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया, जिसकी हाल के दिनों में संभावना नहीं थी।

नॉर्वे ने रूस से आर्कटिक काउंसिल की अध्यक्षता संभाली

चर्चा में क्यों?

- जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित ध्रुवीय क्षेत्र की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता के बारे में बढ़ते सवालों के बीच नॉर्वे ने रूस से आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता संभाली।
- रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच आर्कटिक परिषद का भाग्य खतरे में रहा है जिसने पश्चिमी देशों को रूस के साथ सहयोग निलंबित करने के लिए प्रोत्साहित किया था।

यूक्रेन युद्ध का प्रभाव:

- रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित आर्कटिक परिषद के आठ सदस्य देशों ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और सामाजिक विकास पर सहयोग किया है।
- आर्कटिक परिषद, जो सुरक्षा के मुद्दों से सम्बंधित नहीं है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर बाध्यकारी समझौते करती है और आर्कटिक क्षेत्र के स्वदेशी लोगों की आवाज बनती है, उन कुछ सेटिंग्स में से एक थी जहां पश्चिमी देशों और रूस ने मिलकर काम किया।
- सभी सात देश; संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फ़िनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने फरवरी 2022 में मास्को द्वारा पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने के तुरंत बाद परिषद में रूस के साथ अपने काम को रोक दिया था। इसका प्रभाव यह था कि जलवायु परिवर्तन से लेकर ध्रुवीय भालू तक के मुद्दों पर शोध को रोक दिया गया था, और वैज्ञानिकों ने रूसी आर्कटिक में महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंच खो दी थी।
- एक अप्रभावी आर्कटिक परिषद के क्षेत्र के पर्यावरण और इसके 4 मिलियन निवासियों के लिए भयानक प्रभाव हो सकते हैं जो समुद्री बर्फ के पिघलने के प्रभावों और क्षेत्र के अधिकतर अप्रयुक्त खनिज संसाधनों में गैर-आर्कटिक देशों के हित का सामना करते हैं।

आर्कटिक परिषद की भूमिका:

- अतीत में आर्कटिक परिषद ने पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पर बाध्यकारी समझौते किए हैं। यह क्षेत्र के स्वदेशी लोगों को आवाज देने वाला एक दुर्लभ मंच भी है।
- आर्कटिक शेष विश्व की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है। जैसे ही समुद्री बर्फ गायब हो जाती है, ध्रुवीय जल नौवहन और अन्य उद्योगों के लिए खुल रहा है, जो इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें तेल, गैस, और धातु जैसे सोना, लोहा और दुर्लभ पृथ्वी शामिल हैं, का दोहन करने के लिए उत्सुक हैं।

आगे की राह:

- नॉर्वे ने अब परिषद के काम को आगे बढ़ाने की कसम खाई है क्योंकि इसने रूस से दो वर्ष की अध्यक्षता संभाली है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में पहला व्यापार और तकनीकी परिषद

चर्चा में क्यों?

- ब्रुसेल्स में भारत-यूरोपीय संघ टीटीसी की पहली बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच महत्वपूर्ण डोमेन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र:

- विदेश मंत्री (ईएएम), वाणिज्य और उद्योग मंत्री और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय पक्ष की सह-अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सामरिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल प्रशासन और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- दो व्यापार भागीदारों द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ जलवायु परिवर्तन सहित चुनौतियों का समाधान करने में सहायता करने के लिए मात्रा और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर सहयोग करेंगे।
- दोनों क्षेत्र भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग लेने और एक समर्पित समझौता ज्ञापन के माध्यम से रणनीतिक अर्धचालक क्षेत्र के संबंध में अपनी नीतियों का समन्वय करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

- वे डिजिटल कौशल अंतर को पाटने और डिजिटल प्रतिभा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- दोनों भागीदार 5जी, टेलीकॉम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मानकीकरण पर काम करेंगे, जो उनके संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की अंतरसंचालनीयता को बढ़ाएगा।
- वे अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें प्लास्टिक कूड़े और अपशिष्ट से हाइड्रोजन; पूर्व-मानक अनुसंधान के माध्यम से ई-वाहनों और मानकों के लिए बैटरियों का पुनर्चक्रण शामिल हैं।

व्यापार:

- व्यापार पर, दोनों देश लचीला मूल्य श्रृंखलाओं पर अपने सामान्य काम को गहरा करने, द्विपक्षीय बाजार पहुंच के मुद्दों को हल करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्क्रीनिंग पर एक दूसरे के तंत्र पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए हैं।
- वे विश्व व्यापार संगठन पर विशेष जोर देने के साथ वैश्विक और बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों को भी संबोधित करेंगे।
- दोनों पक्षों ने कार्बन सीमा उपायों पर अपने संबंधों को तेज करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

भारत के बारे में- यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी):

- टीटीसी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने अप्रैल 2021 में अपनी भारत यात्रा के दौरान की थी।
- इसने टीटीसी वर्किंग ग्रुप ऑन स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, वर्किंग ग्रुप ऑन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स के तहत तीन वर्किंग ग्रुप्स का निर्माण किया।

आगे की राह:

- संयुक्त कथन में, यह घोषणा की गई है कि टीटीसी वर्ष में कम से कम एक बार होगा, जिसका स्थान यूरोपीय संघ और भारत के बीच वैकल्पिक होगा।
- भारत में 2024 की शुरुआत में अगली मंत्रिस्तरीय बैठक की योजना है।

दीव में जी20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर जी20 रिसर्च इनोवेशन एंड इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी) सम्मेलन में स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति मॉडल को साझा करने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- भारत के पास तटीय क्षेत्र के विकास के लिए एक बहु-आयामी योजना है जिसमें नीली अर्थव्यवस्था को बदलना, तटीय बुनियादी ढांचे में सुधार करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना शामिल है।
- भारत ने बताया कि महासागर और इसके संसाधन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को नहीं पहचानते हैं और उन्होंने सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया कि वे समुद्री संसाधनों की रक्षा, संरक्षण और सतत उपयोग करें।
- राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में भारत की पहलों जैसे कि डीप ओशन मिशन और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर प्रकाश डाला।

हितधारक:

- सम्मेलन में कुल 35 विदेशी प्रतिनिधियों और 40 भारतीय विशेषज्ञों और भारत सरकार के विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/संगठनों के आमंत्रित लोगों ने भाग लिया।
- भारतीय प्रेसीडेंसी ने बैठक के दौरान चर्चा के लिए अनुसंधान मंत्रियों की घोषणा का पहला मसौदा भी प्रस्तुत किया। 5 जुलाई 2023 को मुंबई में होने वाली अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाया जाएगा।

रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी)

- रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (आरआईआईजी) जी20 फोरम की एक नई पहल है, जिसे 2022 में इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी के दौरान शुरू किया गया था।
- भारत 2023 में अपनी जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान आरआईआईजी पहल को "समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार" के मुख्य विषय के तहत आगे बढ़ा रहा है।

जी 7 में पीएम मोदी ने दिया 10 प्वाइंट का एक्शन प्लान

संदर्भ:

- 49वां जी7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा, हिरोशिमा प्रीफेक्चर, जापान में आयोजित किया गया था।

प्रतिभागियों:

- जी7 में वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं, साथ ही यूरोपीय संघ "गैर-गणना सदस्य" के रूप में शामिल है, लेकिन मंच ने वर्षों से भारत, पोलैंड और स्पेन जैसे गैर-सदस्य देशों द्वारा भागीदारी को आमंत्रित किया है।
- 2023 में, 16 देशों के नेताओं, साथ ही यूरोपीय संघ ने तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- जी7 सदस्यों और यूरोपीय संघ के अलावा, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और कोमोरोस और कुक द्वीप समूह के नेता भाग ले रहे हैं । बाद के दो क्रमशः अफ्रीकी संघ और प्रशांत द्वीप समूह मंच का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में।

पीएम मोदी की 10 सूत्रीय कार्ययोजना:

- समावेशी खाद्य प्रणालियां जो सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करती हैं: अपने संबोधन में, उन्होंने एक समावेशी खाद्य प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो दुनिया भर में सबसे कमजोर आबादी, विशेष रूप से सीमांत किसानों को लक्षित करती है।
- वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अराजनीतिकरण: किसी देश का नाम लिए बिना, उन्होंने उर्वरक संसाधनों के आसपास विस्तारवादी मानसिकता की जांच करने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने में राजनीतिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- उर्वरकों के लिए एक वैकल्पिक मॉडल विकसित करें: प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
- खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भोजन की बर्बादी रोकें: उन्होंने भोजन की बर्बादी को रोकने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि एक स्थायी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बर्बादी को रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- ग्लोबल साउथ की जरूरतों से प्रेरित विकास मॉडल: उन्होंने विकास और लोकतंत्र के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण की वकालत की। उन्होंने एक ऐसे विकास मॉडल की वकालत की जो विकासशील देशों के लिए बाधा पैदा करने के बजाय उन्हें सुविधा प्रदान करे।
- समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना: उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली शामिल है।
- बाजरा को अपनाना: उन्होंने चर्चा की कि कैसे बाजरा एक साथ पोषण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करता है। उन्होंने बाजरा अपनाने के लाभों के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने का मामला बनाया।
- लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: उन्होंने अपनी 10 सूत्री कार्य योजना में विश्व स्तर पर एक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली विकसित करने के महत्व को उठाया।
- डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना: उन्होंने विश्व स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गतिशीलता सुनिश्चित करें: समग्र स्वास्थ्य देखभाल विकास और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता के साथ, उन्होंने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए बेहतर गतिशीलता की भी वकालत की।

पापुआ न्यू गिनी में तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री जेम्स मारपे के साथ तीसरे भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (FIPIC) शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया।
- प्रशांत द्वीप समूह (PIC) के 14 देशों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

FIPIC क्या है?

- नवंबर 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) के लिए फोरम लॉन्च किया गया था.
- एफआईपीआईसी में 14 द्वीप देश शामिल हैं - कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु - जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित हैं।

FIPIC के पीछे क्या विचार था?

- अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार और भारत से काफी दूरी के बावजूद, इनमें से कई द्वीपों में बड़े विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) हैं।
- ईईजेड वह दूरी है जिस तक एक तटीय राष्ट्र का समुद्र पर अधिकार क्षेत्र है, जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों संसाधन शामिल हैं। यह आम तौर पर किसी देश के प्रादेशिक समुद्र से 200 समुद्री मील या 230 मील (लगभग 370 किमी) तक जाता है।
- भारत का बड़ा ध्यान हिंद महासागर पर है जहां उसने एक प्रमुख भूमिका निभाने और अपने सामरिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने की मांग की है। FIPIC पहल तब प्रशांत क्षेत्र में भी भारत के जुड़ाव का विस्तार करने के लिए एक गंभीर प्रयास का प्रतीक है।
- 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, खनिज ईंधन और अयस्क जैसी वस्तुओं में भारत और प्रशांत द्वीप देशों के बीच कुल वार्षिक व्यापार $570 मिलियन का है। उनमें से पापुआ न्यू गिनी मूल्य के मामले में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।

FIPIC शिखर सम्मेलन:

- FIPIC-I, 2014 में, फिजी की राजधानी सुवा में आयोजित किया गया था। भारत ने जलवायु परिवर्तन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलीमेडिसिन और टेलीएजुकेशन, आईटी, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विकास सहायता पहलों और अन्य सहयोग परियोजनाओं की घोषणा की।
- जयपुर में 2015 में FIPIC-II में, भारत ने फिर से इसी तरह की पहल की घोषणा की। भारत ने "दोनों श्रेणियों में विस्तारित और संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए समर्पित सीट" की मांग करते हुए, एक बड़े कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इस कार्यक्रम का रुख किया।
- 2019 में, भारत-प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (PSIDS) नेताओं की बैठक (14 प्रशांत द्वीप समूह देशों में से 12 के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं) 24 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर आयोजित की गई थी। .
- तब भारत सरकार ने उनकी पसंद के क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाली विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए $12 मिलियन अनुदान (प्रत्येक पीएसआईडीएस के लिए $1 मिलियन) के आवंटन की घोषणा की।
- इसके अलावा, प्रत्येक देश की आवश्यकता के आधार पर सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएसआईडीएस द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली $150 मिलियन की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई।

FIPIC शिखर सम्मेलन 2023 के मुद्दे

- तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
- अपने समापन भाषण के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री ने पहलों की घोषणा की जैसे:
  - फिजी में एक सुपर स्पेशियलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल की स्थापना। भारत सरकार इस मेगा ग्रीनफील्ड परियोजना की पूरी लागत वहन करेगी।
  - सभी 14 प्रशांत द्वीपीय देशों को समुद्री एंबुलेंस प्रदान की जाएगी।
  - उन्होंने कहा कि 2022 में, फिजी में एक जयपुर फुट कैंप आयोजित किया गया था, जहां 600 से अधिक लोगों को कृत्रिम अंग मुफ्त में प्रदान किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2023 में पापुआ न्यू गिनी में इसी तरह का एक और शिविर लगाया जाएगा और 2024 से शुरू होकर प्रशांत द्वीप देशों में हर साल ऐसे दो शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री ने प्रत्येक प्रशांत द्वीप देश के लोगों के लिए अलवणीकरण इकाइयां प्रदान करने का भी संकल्प लिया।

अर्थव्यवस्था

जम्मू-कश्मीर में 'शिताके' मशरूम की व्यावसायिक खेती

चर्चा में क्यों?

- जम्मू-कश्मीर में मशरूम की खेती में लगे किसान केंद्र शासित प्रदेश में व्यावसायिक खेती के लिए सबसे महंगे मशरूम में से एक 'शिताके' की पेशकश की सरकार की घोषणा से उत्साहित हैं।
- जापानी मूल के इस मशरूम किस्म की खेती के सफल खेत परीक्षण के बाद कृषि विभाग सितंबर में 'शिताके' मशरूम की व्यावसायिक खेती की शुरुआत करेगा।

विवरण:

- जम्मू और साथ ही खेतों में स्पॉन उत्पादन प्रयोगशाला में स्पॉन उत्पादन और शियाटेक मशरूम की खेती के लिए खेती का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया।
- यह मशरूम अनुसंधान निदेशालय (आईसीएआर), सोलन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पॉलीप्रोपाइलीन बैग में चौड़ी पत्तियों के बुरादे पर किया गया था।
- इस मशरूम के पहले फलन निकायों के विकास और पूर्ण विकास के साथ सभी परीक्षण सफल रहे।

शिताके मशरूम

- 'शिताके' मशरूम (लेंटिनस एडोड्स), मूलत: जापान की उपज है। इसमें लेंटिनन नामक रसायन होता है, जिसका उपयोग कुछ चिकित्सा पेशेवर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए करते हैं।
- इसे जम्मू-कश्मीर में मशरूम की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- ताजा मशरूम बाजार में 1,500 रुपये प्रति किलो बिकता है। अगर हम इसे सुखाते हैं, तो यह बाजार में 15,000 रुपये प्रति किलो बिकता है।
- मशरूम की तीन किस्में – बटन, डिंगरी और मिल्की मशरूम उगाने के अलावा उनकी खेती को विविधतापूर्ण बनाया जाएगा। चौथा, शियाटेक मशरूम पेश किया जाएगा।
- यह फसल के साथ-साथ कृषि प्रणाली में विविधता लाएगा। इससे सभी को यहां तक कि छोटे मशरूम उत्पादकों को भी आर्थिक रूप से लाभ होगा।
- इसमें कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, जिनका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है।

आगे की राह:

- छोटे किसानों को समर्थन देने के उद्देश्य से, जम्मू-कश्मीर सरकार टिकाऊ और लाभदायक फसलों के लिए पूरे साल मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों में 42 करोड़ रुपये की लागत से एक पूर्ण परियोजना लागू करने जा रही है।

डी-डॉलरीकरण प्रक्रिया में तीव्रता

संदर्भ:

- विभिन्न कारणों से कई दशकों से देशों ने वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर को हटाने का प्रयास किया है। लेकिन हाल ही में, 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद डी-डॉलरीकरण के प्रयासों में तेजी आई है।
- वर्तमान में, चीनी युआन को चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति के कारण अमेरिकी डॉलर के प्राथमिक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

डी-डॉलराइजेशन क्या है?

- डी-डॉलराइजेशन वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अन्य मुद्राओं द्वारा अमेरिकी डॉलर के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है।
- एक आरक्षित मुद्रा किसी भी मुद्रा को संदर्भित करती है जो व्यापक रूप से सीमा पार लेनदेन में उपयोग की जाती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में आयोजित की जाती है।

पृष्ठभूमि:

- ब्रिटिश पाउंड और फ्रेंच फ्रैंक जैसी अन्य मुद्राओं ने अतीत में अंतरराष्ट्रीय आरक्षित मुद्राओं के रूप में काम किया है।
- यह आर्थिक महाशक्तियों की मुद्राएं हैं जो आमतौर पर वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में उपयोग की जाती हैं। जैसे-जैसे इन देशों का आर्थिक दबदबा कम होता गया, उनकी मुद्राओं को भी इसी तरह की गिरावट का सामना करना पड़ा।
- यह मामला था, उदाहरण के लिए, ब्रिटिश पाउंड के साथ जो धीरे-धीरे अमेरिकी डॉलर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था क्योंकि ब्रिटेन ने 20वीं शताब्दी के पहले छमाही में वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति खो दी थी।

आरक्षित मुद्रा के लाभ:

- जब किसी देश की फिएट मुद्रा को आरक्षित मुद्रा का दर्जा प्राप्त होता है, तो यह देश को केवल नई मुद्रा बनाकर शेष दुनिया से सामान और अन्य संपत्ति खरीदने की शक्ति देता है। हालांकि, पैसे की आपूर्ति के इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना विस्तार से मुद्रा की दुर्बलता हो सकती है और अंततः आरक्षित मुद्रा के रूप में इसकी स्थिति को खतरा हो सकता है।
- लेकिन यू.एस. फेडरल रिजर्व दुनिया का एकमात्र केंद्रीय बैंक नहीं है जो कई दशकों से विस्तारवादी मौद्रिक नीति में शामिल होकर अपनी मुद्रा को कमजोर कर रहा है।
- अन्य देश भी अपनी घरेलू आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी संबंधित मुद्रा आपूर्ति का विस्तार कर रहे हैं।
- जब तक यू.एस. अन्य देशों की तुलना में अपनी मुद्रा को तेज गति से कम नहीं करता है, तब तक डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले अपने मूल्य को बनाए रखने का प्रबंधन कर सकता है और इसलिए इसकी आरक्षित मुद्रा स्थिति गंभीर खतरे में नहीं आ सकती है।

अमेरिकी डॉलर की लोकप्रियता:

- अमेरिकी डॉलर का अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि लोग वास्तव में विभिन्न आर्थिक कारणों से दूसरों की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का उपयोग करना पसंद करते हैं। अन्य मुद्राएं जिन्होंने यू.एस. डॉलर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की है, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करने के लिए ग्रीनबैक के रूप में लोकप्रिय नहीं हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत और रूस द्वारा दोनों देशों के बीच अमेरिकी डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में व्यापार करने के हालिया प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई है क्योंकि रूस से भारत के आयात का मूल्य देश में इसके निर्यात से कहीं अधिक है।
- इससे रूस के पास हाथ में अतिरिक्त रुपये रह गए, जिसे वह भारतीय वस्तुओं या संपत्तियों पर खर्च करने को तैयार नहीं था, और अमेरिकी डॉलर में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान के लिए रूसी मांगों को जन्म दिया।

अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्वीकार्यता:

- अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्वीकार्यता को मुख्य रूप से निवेशकों के बीच अमेरिकी संपत्तियों की लोकप्रियता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- अमेरिका दशकों से लगातार व्यापार घाटा चला रहा है (वास्तव में पिछली बार जब अमेरिका ने 1975 में व्यापार अधिशेष चलाया था)। अर्थात्, लंबे समय तक इसके आयात का मूल्य शेष विश्व में इसके निर्यात के मूल्य से अधिक रहा है।
- यू.एस. के व्यापार घाटे के कारण शेष विश्व में जमा होने वाले अतिरिक्त डॉलर को यू.एस. की संपत्तियों में निवेश किया गया है, जैसे कि यू.एस. सरकार द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में।
- अमेरिकी वित्तीय बाजारों में वैश्विक निवेशकों का उच्च स्तर का विश्वास, शायद अमेरिका में 'कानून के शासन' के कारण, एक प्रमुख कारण माना जाता है कि क्यों निवेशक अमेरिकी संपत्ति में निवेश करना पसंद करते हैं।

युआन का मामला:

- यह आवश्यक नहीं है कि किसी देश को अपनी मुद्रा को आरक्षित मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए व्यापार घाटा चलाना पड़े।
- चीन जो दुनिया को भारी मात्रा में माल की आपूर्ति करता है और व्यापार अधिशेष चलाता है, युआन को एक आरक्षित मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है।
- हालांकि, चीनी सरकार द्वारा चीन के वित्तीय बाजारों तक विदेशी पहुंच पर लगाए गए प्रतिबंधों और चीन में 'कानून के शासन' पर संदेह ने युआन की वैश्विक मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

विनिर्माण के क्षेत्र में कर्नाटक प्रथम नवोन्मेषी राज्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे (NMIS) 2021-22 जारी किया गया।

विवरण:

- भारत में विनिर्माण में नवाचार के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) के सहयोग से सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।
- इसने 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 8,000 से अधिक फर्मों में अपना सर्वेक्षण किया है, जिसमें विनिर्माण और संबंधित सेवा क्षेत्र और एमएसएमई शामिल हैं।

मुख्य बिंदू:

- यह पाया गया है कि कर्नाटक राज्य न केवल अपने विनिर्माण क्षेत्र में सबसे नवीन है, बल्कि यहां निर्माण क्षेत्र में नवाचार करने वाली कंपनियों की संख्या सबसे अधिक है।
- यह भी पाया गया कि विनिर्माण में नवाचार पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) में सबसे कम है, इसके बाद बिहार का स्थान है।
- डीएसटी ने कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा को उच्च नवप्रवर्तन राज्यों के रूप में स्थान दिया।
- पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का उच्चतम स्कोर है, जबकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर है।
- पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा, कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तेलंगाना के बगल में होने के बावजूद आंध्र प्रदेश सबसे निचली रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हैदराबाद अब तेलंगाना में है।

अभिनव फर्म:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 8,074 फर्मों में से केवल 25.01 प्रतिशत को ही नवोन्मेषी माना गया। संबंधित राज्यों से सर्वेक्षण किए गए कुल निर्माण फर्मों में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्रमशः 46.18 प्रतिशत, 39.10 प्रतिशत और 31.90 प्रतिशत पर अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा था।
- ओडिशा, बिहार और झारखंड ने क्रमशः 12.78 प्रतिशत, 13.47 प्रतिशत और 13.71 प्रतिशत पर अभिनव फर्मों की सबसे कम हिस्सेदारी दर्ज की।

पृष्ठभूमि:

- भारत सरकार ने पहली बार 2011 में राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि फर्मों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने में नवाचारों की भूमिका अविकसित थी।
- 2019 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूसरे राष्ट्रव्यापी नवाचार सर्वेक्षण के साथ पालन करने का फैसला किया और बड़े, मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों में फैले विनिर्माण और संबद्ध सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से नवाचार सर्वेक्षण को संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) को सौंपा।

आगे की राह:

- सर्वेक्षण इसलिए किया गया है ताकि केंद्र और राज्य सरकारें, साथ ही उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र में कमियों की पहचान कर सकें और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें दूर कर सकें।
- विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग भी ऊपर जाएगी। भारत 2022 में सूचकांक पर 132 देशों में से 40 स्थान पर रहा।

व्यक्तियों, उद्योगों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए भारत की पहली ग्रीन क्रेडिट योजना

चर्चा में क्यों?

- वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने भारत के पहले ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (जीसीपी) को शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार की है।
- यह स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ग्रीन क्रेडिट का प्रस्तावित घरेलू बाजार मंच पर व्यापार किया जा सकेगा।

कार्यान्वयन:

- एमओईएफसीसी ने प्रस्ताव दिया है कि पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति जिसमें संबंधित मंत्रालयों या विभागों के अधिकारी, डोमेन विशेषज्ञ और उद्योग संघ शामिल होंगे, जीसीपी के कार्यान्वयन को नियंत्रित करेंगे।

गतिविधियों में शामिल हैं:

- इस मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत आठ चुनिंदा गतिविधियों की पहचान की है जिनके लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है।
- इनमें शामिल है:
  a) वृक्षारोपण;
  b) जल संरक्षण, जल संचयन और जल उपयोग दक्षता/बचत;
  c) प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि पद्धति को बढ़ावा देना;

d) अपशिष्ट प्रबंधन;
e) वायु प्रदूषण में कमी;
f) मैंग्रोव संरक्षण और नवीनीकरण;
g) ईकोमार्क-आधारित ग्रीन क्रेडिट; और
h) स्थायी प्रौद्योगिकी और सामग्री का उपयोग करके भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण।

- व्यक्ति, निजी क्षेत्र, उद्योग, किसान समूह, वन उद्यम, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), जिला और ग्राम पंचायत इन निर्दिष्ट गतिविधियों को करने के लिए हरित ऋण अर्जित कर सकते हैं।
- अधिसूचना में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, इन संस्थाओं को पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान भी करना होगा।

यह किस प्रकार काम करेगा?

- जीसीपी व्यवस्थापक पर्यावरणीय मुआवज़ा एकत्र करेगा और इसे एक अलग समर्पित खाते में जमा करेगा।
- इस कोष का उपयोग संचालन समिति द्वारा अनुमोदित जीसीपी के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य गतिविधियों के साथ-साथ बाजार स्थिरीकरण के उपाय करने के लिए किया जाएगा।
- प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट का एक मौद्रिक मूल्य होगा।
- ग्रीन क्रेडिट को पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनियों या उद्योगों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल हस्तक्षेप करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए खरीदा जा सकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सभी खिलाड़ियों को जोड़ेगा, जो ग्रीन क्रेडिट के आपूर्तिकर्ता हैं।
- ग्रीन क्रेडिट सृजित करने और जारी करने के लिए प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट गतिविधि/प्रक्रिया के लिए थ्रेसहोल्ड और बेंचमार्क विकसित किए जाएंगे।
- प्रत्येक गतिविधि के संबंध में जीसी की एक इकाई का आवंटन प्राप्त करने योग्य पर्यावरणीय परिणाम, संसाधन आवश्यकता की समानता, पैमाने की समानता, कार्यक्षेत्र, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- सरकार जीसीपी के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं का विकास और स्थापना भी करेगी, जिसमें पात्र ग्रीन क्रेडिट गतिविधियों का स्व-मूल्यांकन, परियोजनाओं का पंजीकरण, ग्रीन क्रेडिट जारी करना और प्रदर्शन की निगरानी शामिल है।

संचालन समिति की भूमिका:

- संचालन समिति न केवल जीसीपी को संस्थागत बनाने की प्रक्रियाओं को मंजूरी देगी, बल्कि इसके नियमों और विनियमों को भी मंजूरी देगी और ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी।
- यह जीसीपी के कार्यान्वयन की लागत और व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से शुल्क और शुल्क के प्रकार और राशि का भी निर्धारण करेगा।

प्रशासक:

- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) जीसीपी का प्रशासक होगा और पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन, निगरानी और संचालन करेगा।
- यह ग्रीन क्रेडिट दर्ज करेगा और सभी लेन-देन का रिकॉर्ड बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापार अपेक्षित अनुशासन के साथ हो।
- आईसीएफआरई जीसी परियोजनाओं के पंजीकरण और जीसी के अनुदान के लिए विकासशील पद्धतियों और मानकों और प्रक्रियाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक अलग-अलग गतिविधि के लिए तकनीकी या क्षेत्रीय समितियों का गठन करेगा।
- आईसीएफआरई संचालन समिति के अनुमोदन से ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए दिशानिर्देश भी जारी करेगा।

व्यापार मंच:

- ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीसीपी व्यवस्थापक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेडिंग सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 8 साल पूरे

संदर्भ:

- हाल ही में, तीन सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाएं; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के 8 साल पूरे कर लिए हैं।

विवरण:

- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रहे, दो बीमा योजनाएं शुरू कीं - पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई। इसके साथ ही सरकार ने वृद्धावस्था की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए अटल पेंशन योजना- एपीवाई भी शुरू की।
- प्रधानमंत्री ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारम्भ 9 मई, 2015 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल से किया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

- **योजना:** पीएमजेजेबीवाई एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इसका साल-दर-साल नवीकरण किया जाता है।
- **पात्रता:** 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग

नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं।

- **लाभ:** 436/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जीवन कवर।
- **नामांकन:** योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
- **उपलब्धियां:** 26.04.2023 तक, योजना के तहत कुल नामांकन 16.19 करोड़ से अधिक हो गए हैं और 6,64,520 दावों के लिए 13,290.40 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- **योजना:** पीएमएसबीवाई एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है।
- **पात्रता:** 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं।
- लाभ: दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रूपये (आंशिक विकलांगता के मामले में रु. 1 लाख) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है।
- **नामांकन:** योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।
- **उपलब्धियां:** 26.04.2023 तक, योजना के तहत कुल नामांकन 34.18 करोड़ से अधिक और 1,15,951 दावों के लिए 2,302.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

पृष्ठभूमि:

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई थी।
- यह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है।
- एपीवाई का प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) करता है।
- **पात्रता:** एपीवाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं और चुने गए पेंशन राशि के आधार पर देय योगदान अलग-अलग हैं।
- **लाभ:** इस योजना में शामिल होने के बाद ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के आधार पर उनकी 60 वर्ष की आयु के बाद ग्राहकों को गारंटीशुदा न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये मिलती है।

योजना के लाभों का संवितरण:

- इसके तहत मासिक पेंशन ग्राहक को मिलेगी, और उसके बाद उसके पति या पत्नी को और फिर उन दोनों की मृत्यु के बाद ग्राहक की 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
- ग्राहक की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, ग्राहक का पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल ग्राहक की उम्र 60 वर्ष पूरी न हो जाए।

केंद्र सरकार द्वारा योगदान:

- न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी, अर्थात, यदि योगदान के आधार पर संचित राशि निवेश पर अनुमानित रिटर्न से कम होती है और न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए फंड देगी।
- वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल अधिक है, तो अभिदाताओं को बढ़ा हुआ पेंशन लाभ मिलेगा।
- **भुगतान आवृत्ति:** ग्राहक मासिक / तिमाही / छमाही आधार पर एपीवाई में योगदान कर सकते हैं।
- **योजना से निकासी:** सरकारी सह-योगदान और उस पर वापसी/ब्याज की कटौती पर कुछ शर्तों के अधीन सदस्य स्वैच्छिक रूप से एपीवाई से बाहर निकल सकते हैं।
- **उपलब्धियां:** 27.04.2023 तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने योजना की सदस्यता ली है।

'हरित सागर : हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से हरित पत्तन दिशानिर्देश 2023 'हरित सागर' का शुभारंभ किया गया है।

विवरण:

- हरित सागर दिशानिर्देश- 2023 'प्रकृति के साथ कार्य करने' की अवधारणा के साथ स्वयं को आगे बढ़ाते हुए और पोर्ट इकोसिस्टम के जैविक घटकों पर प्रभाव को कम करने की भावना के साथ बंदरगाह के

विकास, संचालन व रखरखाव में इकोसिस्टम की कार्य क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना करता है।

- यह पहल पत्तन संचालन में स्वच्छ/हरित ऊर्जा के उपयोग, भंडारण के लिए बंदरगाह क्षमता विकसित करने, हरित ईंधनों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल/इथेनॉल इत्यादि के कुशल प्रबंधन और सुरक्षित इस्तेमाल करने पर जोर देता है।
- ये दिशानिर्देश प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लक्ष्य के साथ एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो निर्धारित समयसीमा में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने के संदर्भ में लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से हरित गतिविधियों पर केंद्रित योजना कार्यान्वयन तथा करीबी निगरानी के माध्यम से और अधिक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अवसर लेकर आते हैं।

उद्देश्य:

- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर बंदरगाह संचालन से शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करने और निगरानी को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट को न्यूनतम करना, पुनः चक्रित करना, पुनरावृत्ति करना और दोबारा इस्तेमाल में लाना है।
- इसमें बंदरगाहों से संबंधित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के प्रमुख बिंदु, हरित हाइड्रोजन सुविधा का विकास, एलएनजी का भंडारण, तटीय पवन ऊर्जा का उपयोग आदि शामिल हैं और ग्रीन रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई) मानक अपनाने के लिए अवसर प्रदान करता है।

'सागर श्रेष्ठ सम्मान' पुरस्कार:

- वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार 137.56 एमएमटी के उच्चतम कार्गो का प्रबंधन करने के लिए कांडला के दीनदयाल पोर्ट को दिया गया है।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को टर्न अराउंड टाइम में प्रमुख मील का पत्थर स्थापित करने के लिए पुरस्कार मिला है। पारादीप पोर्ट को शिप बर्थ डे आउटपुट पर बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- कामराजर पोर्ट को प्री-बर्थिंग डिटेंशन टाइम में सफलता मिली है, जबकि कोचीन पोर्ट को टर्न-अराउंड-टाइम (नॉन-कंटेनर पोर्ट) में बेहतर कार्य निष्पादन की ट्रॉफी दी गई है।
- पिछले वर्ष 16.56% की उच्चतम कार्गो वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए पारादीप पोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृद्धिशील प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ोतरी वाली श्रेणी में मोरमुगाओ पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ शिप बर्थ डे आउटपुट के लिए एक और पुरस्कार दिया गया है, जबकि कामराजार पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ प्री-बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए सम्मानित किया गया है।
- कार्गो हैंडलिंग, एवरेज टर्नअराउंड टाइम, शिप बर्थडे आउटपुट और आइडल टाइम एट बर्थ, ऑपरेटिंग रेशियो, प्री बर्थिंग डिटेंशन के आधार पर समग्र वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर पारादीप पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार प्रदान किया गया है।

नए जीएसटी अनुपालन उपाय

चर्चा में क्यों?

- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के अंतर्गत कर चोरी को रोकने और अनुपालन बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण उपायों में, सरकार ने व्यवसायों से व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान उत्पन्न करने के लिए सीमा को 10 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये कम करने का निर्णय लिया है, और केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए बैकएंड एप्लिकेशन में जीएसटी रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल शुरू किया है।

- जीएसटी धोखाधड़ी और नकली चालान के मामलों के बढ़ते मामलों के बीच, इन परिवर्तनों से अधिक व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन जनादेश के व्यापक होने की संभावना है और जीएसटी राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी।

ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल क्या है?

- यह अधिकारियों को डेटा एनालिटिक्स और सिस्टम द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुने गए केंद्र-प्रशासित करदाताओं के जीएसटी रिटर्न की जांच करने में सक्षम बनाएगा।
- कर अधिकारियों को रिटर्न से जुड़े जोखिमों के कारण विसंगतियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- वे जीएसटीएन कॉमन पोर्टल के माध्यम से रिटर्न में देखी गई विसंगतियों के संचार के लिए करदाताओं के साथ बातचीत करेंगे और उत्तर की स्वीकृति के आदेश जारी करने या कारण बताओ नोटिस जारी करने या ऑडिट/जांच शुरू करने के रूप में बाद की कार्रवाई करेंगे।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न की जांच के साथ ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें कर अधिकारियों के पास पहले से ही आवश्यक डेटा है।

ई-चालान के लिए क्या बदलाव हैं?

- सरकार ने व्यवसायों के लिए व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन के लिए ई-चालान उत्पन्न करने की सीमा को जीएसटी के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। बदलाव 1 अगस्त से लागू होंगे।
- वर्तमान में, 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी बी2बी लेनदेन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है।

ई-चालान क्या परिकल्पना करता है?

- जीएसटी परिषद ने सितंबर 2019 में अपनी 37वीं बैठक में ई-चालान के मानक को मंजूरी दी थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य पूरे जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-संचालनीयता को सक्षम करना था।
- इसके अंतर्गत, सभी चालानों के लिए एक सामान्य मानक सुनिश्चित करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यान्वयन प्रस्तावित किया गया था,

अर्थात, एक सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न ई-चालान किसी अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ने में सक्षम होना चाहिए और मशीन पठनीयता के माध्यम से, एक चालान समान रूप से हो सकता है व्याख्या की।

- एक समान चालान प्रणाली के साथ, कर अधिकारी रिटर्न को पहले से भर सकते हैं और समाधान संबंधी मुद्दों को कम कर सकते हैं।
- ई-चालान शुरू में 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था।

आगे की राह:

- जबकि ई-चालान सीमा में कमी को जीएसटी राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, यह छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को भी बढ़ाएगा।

एसडीजी को पूरा करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला भोपाल पहला भारतीय शहर बन गया है

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश में भोपाल संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है।
- अब इसमें स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षाएं (वीएलआर) होंगी जो स्थानीय सरकार की क्षमता और प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करेंगी।

विवरण:

- भोपाल ने 'एजेंडा फॉर एक्शन: सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल' लॉन्च किया है, जिसका अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया।
- एसडीजी स्थानीयकरण एजेंडे का अनुवाद कर रहा है, हमारी दुनिया को बदल रहा है: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा (एजेंडा 2030 के रूप में जाना जाता है), स्थानीय कार्यों और प्रभावों में जो लक्ष्यों की वैश्विक उपलब्धि में योगदान करते हैं।

स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा (वीएलआर)

- वीएलआर शहरों और क्षेत्रों को सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने और उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।
- भोपाल का वीएलआर भोपाल नगर निगम, यूएन-हैबिटेट और 23 से अधिक स्थानीय हितधारकों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है, जो एक स्थायी और समावेशी शहरी परिवर्तन के लिए शहर की आकांक्षाओं को मापने के लिए प्रदर्शित करता है।
- भोपाल के वीएलआर ने एसडीजी की समीक्षा के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण शामिल किया, जिसमें लोग, ग्रह और समृद्धि के तीन स्तंभों में 56 विकासात्मक परियोजनाओं की गुणात्मक मैपिंग और एसडीजी 11 (सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज) की गहन मात्रात्मक समीक्षा शामिल थी।

एजेंडा 2030:

- 2015 में, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने एजेंडा 2030 को अपनाया, जिसमें 17 एसडीजी और 169 लक्ष्य लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए कार्य योजना के रूप में शामिल थे।
- सदस्य राज्य स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) के माध्यम से एसडीजी की उपलब्धि की दिशा में अपनी प्रगति की रिपोर्ट करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने स्वयं के उप-राष्ट्रीय समीक्षाओं, तथाकथित वीएलआर, में तेजी से संलग्न हो रही हैं, जो शहरों और क्षेत्रों के लिए उपयोगी साबित हुई हैं।
- वीएनआर के विपरीत, स्थानीय समीक्षाओं का 2030 एजेंडा या अन्य अंतर-सरकारी समझौतों में प्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक आधार नहीं होता है, भले ही 2030 एजेंडा कई स्थानों पर इसके कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने वाली सरकारों के महत्व को रेखांकित करता है।
- एजेंडा 2030 की उपलब्धि में शहरों और क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 169 लक्ष्यों में से कम से कम 60% को उनकी भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह:

- वीएलआर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं जो स्थानीय कार्रवाई में सबसे आगे हैं।
- न्यूयॉर्क शहर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के एचएलपीएफ को अपनी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रस्तुत करने वाला पहला शहर बना।
- 2021 तक, कुछ 33 देशों ने सार्वजनिक रूप से 114 वीएलआर या इसी तरह के समीक्षा दस्तावेज उपलब्ध कराए थे।

वित्तीय नियामक लिबोर से अवस्थांतर क्यों कर रहे हैं?

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, आरबीआई ने कहा कि कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने अभी तक लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट (एलआईबीओआर) बेंचमार्क से पूर्ण अवस्थांतर की सुविधा नहीं दी है।

- उन्होंने अपने सभी वित्तीय अनुबंधों में फ़ॉलबैक खंड शामिल नहीं किए थे जो यूएस $ लिबोर या संबंधित घरेलू मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (एमआईएफ़ओआर) का संदर्भ देते हों।
- लिबोर और मिफोर दोनों 30 जून, 2023 से एक प्रतिनिधि बेंचमार्क नहीं रहेंगे।

लिबोर क्या है?

- लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है जो अलग-अलग दरों को जोड़ती है जिस पर बैंकों की राय है कि वे लंदन इंटरबैंक बाजार में एक-दूसरे से उधार ले सकते हैं (एक विशेष अवधि के लिए)।
- इसका उपयोग ओवर-द-काउंटर मार्केट्स (बिना किसी एक्सचेंज का उपयोग किए सीधे भाग लेने वाले) और वैश्विक स्तर पर एक्सचेंजों में फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप और अन्य डेरिवेटिव वित्तीय साधनों में ट्रेडों को व्यवस्थित करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया जाता है।
- इसके अलावा, बंधक, क्रेडिट कार्ड और छात्र ऋण सहित अन्य उपभोक्ता ऋण उत्पाद भी इसे बेंचमार्क दर के रूप में उपयोग करते हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

- प्रत्येक कारोबारी दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे (लंदन समयानुसार) से पहले, लिबोर (LIBOR) पैनल के बैंक समाचार और वित्तीय डेटा कंपनी, थॉमसन रॉयटर्स को अपनी प्रस्तुति देते हैं।
- पैनल में जेपी मॉर्गन चेस (लंदन शाखा), लॉयड्स बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका (लंदन शाखा), रॉयल बैंक ऑफ कनाडा और यूबीएस एजी जैसे वाणिज्यिक बैंकर शामिल हैं। सबमिशन के बाद, योगदान दरों को रैंक किया गया है।
- चरम चतुर्थक, ऊपर और नीचे, बाहर रखा गया है और मध्य चतुर्थक का औसत लिबोर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। विचार यह है कि जितना संभव हो सके माध्यिका के निकट हो।

क्या था इसे लेकर विवाद?

- तंत्र में केंद्रीय दोष यह था कि यह अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा करते हुए अपनी रिपोर्टिंग के प्रति ईमानदार होने के लिए बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर था।
- दरों को सार्वजनिक किया गया। इसलिए, संभावित और वर्तमान ग्राहकों को धन प्राप्त करने में विभिन्न नुकसानों के बारे में बताना विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा। घटना विशेष रूप से 2008 के वित्तीय संकट के दौरान प्रदर्शित हुई थी जब प्रस्तुतियाँ कृत्रिम रूप से कम कर दी गई थीं (संकट के बीच)।
- 2012 में, बार्कलेज ने कदाचार को स्वीकार किया और अमेरिकी न्याय विभाग को जुर्माने के रूप में $160 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हो गया।
- वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी मई 2008 में अध्ययन किया था कि कई पैनलिस्ट बाजार के अन्य उपायों की तुलना में "काफी कम उधारी लागत" का भुगतान कर रहे थे।
- एक अन्य देखी गई घटना अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थाओं की व्यापारिक इकाइयों की डेरिवेटिव स्थिति के अनुसार प्रस्तुतिकरण (उच्च या निम्न) को बदलने की प्रवृत्ति थी।

एसओएफआर (SOFR):

- 2017 में, यू.एस. फ़ेडरल रिज़र्व ने एक पसंदीदा विकल्प के रूप में सिक्योर्ड ओवरनाइट फ़ाइनेंसिंग रेट (SOFR) की घोषणा की।
- तदनुसार, भारत में, एमआईऍफ़ओआर के स्थान पर एसओऍफ़आर और संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट (MMIFOR) का उपयोग करके नए लेनदेन किए जाने थे।
- यह देखने योग्य रेपो दरों, या रातोंरात नकद उधार लेने की लागत पर आधारित है, जो यू.एस. ट्रेजरी सिक्योरिटीज द्वारा संपार्श्विक है।
- इस प्रकार, यह एक प्रचलित लेन-देन-आधारित दर बना रहा है और लिबोर के रूप में एक विशेषज्ञता निर्णय की आवश्यकता से दूर जा रहा है। यह इसे संभावित रूप से बाजार में हेरफेर करने के लिए कम प्रवण बना देगा।

व्यवस्था परिवर्तन पर भारत किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रहा है?

- आरबीआई ने अपने नवंबर 2020 के बुलेटिन में कहा था कि, भारत में, लिबोर के लिए एक्सपोजर इससे जुड़े ऋण अनुबंधों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (एफसीएनआर-बी) जमाओं के साथ ब्याज और डेरिवेटिव की फ्लोटिंग दरों के साथ हैं।
- अगस्त 2020 में, इसने बैंकों से कहा था कि वे अपने LIBOR जोखिम का आकलन करें और वैकल्पिक संदर्भ दरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। 31 दिसंबर, 2021 के बाद (या उससे पहले, यदि संभव हो) दर्ज किए गए अनुबंधों को संदर्भ दर के रूप में लिबोर का उपयोग नहीं करना था।
- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तारीख से पहले दर्ज किए गए अनुबंधों में फॉलबैक क्लॉज होते हैं, यानी, जब संदर्भ दर अब प्रकाशित नहीं होती है, तो संशोधित विचारों के लिए एक समझौता, पारदर्शिता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रीन डिपॉजिट पर आरबीआई द्वारा नियामक ढांचा तैयार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया है।
- नए ढाँचे के तहत, ग्रीन डिपॉज़िट स्वीकार करने वाले बैंकों को इस बारे में अधिक जानकारी देनी होगी कि वे इन डिपॉज़िट का निवेश कैसे करते हैं।

ग्रीन डिपॉजिट क्या हैं?

- ग्रीन डिपॉजिट नियमित डिपॉजिट से बहुत अलग नहीं है जो बैंक अपने ग्राहकों से स्वीकार करते हैं। एकमात्र बड़ा अंतर यह है कि बैंक पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए हरित जमा के रूप में प्राप्त होने वाले धन को निर्धारित करने का वादा करते हैं।
- उदाहरण के लिए, बैंक यह वादा कर सकता है कि ग्रीन डिपॉजिट का उपयोग जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। बैंक उन जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट का उपयोग करने से भी बच सकता है जो जलवायु के लिए हानिकारक माने जाते हैं।
- ग्रीन डिपॉजिट अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन शेयर आदि की एक विस्तृत श्रृंखला में सिर्फ एक उत्पाद है, जो निवेशकों को पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी परियोजनाओं में पैसा लगाने में मदद करता है।

क्या कहता है आरबीआई का नियामक ढांचा?

- ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए आरबीआई का ढांचा कुछ शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए बैंकों को पूरा करना होगा।
- सबसे पहले, बैंकों को अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित नियमों या नीतियों के एक सेट के साथ आना होगा, जिनका ग्राहकों से ग्रीन डिपॉजिट निवेश करते समय पालन किया जाना आवश्यक है।
- इन नियमों को बैंकों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक करने की आवश्यकता है और बैंकों को प्राप्त ग्रीन डिपॉजिट की राशि, इन डिपॉजिट को विभिन्न हरित परियोजनाओं के लिए कैसे आवंटित किया गया, और पर्यावरण पर ऐसे निवेश के प्रभाव के बारे में नियमित जानकारी का खुलासा करना होगा।
- एक तीसरे पक्ष को बैंकों द्वारा उन परियोजनाओं के संबंध में किए गए दावों को सत्यापित करना होगा जिनमें बैंक अपनी हरित जमाराशियों का निवेश करते हैं और साथ ही इन व्यावसायिक परियोजनाओं की स्थिरता प्रमाणिकता भी।
- आरबीआई उन क्षेत्रों की एक सूची लेकर आया है जिन्हें टिकाऊ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार ग्रीन डिपॉजिट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण शामिल हैं।
- बैंकों को जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, तंबाकू, जुआ, ताड़ के तेल और जल विद्युत उत्पादन से जुड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं में हरित जमा राशि का निवेश करने से रोक दिया जाएगा।
- नए नियमों का उद्देश्य ग्रीनवाशिंग को रोकना है, जो किसी गतिविधि के सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में भ्रामक दावे करने को संदर्भित करता है।

क्या ग्रीन डिपॉजिट से जमाकर्ताओं/निवेशकों और पर्यावरण को मदद मिलेगी?

- पर्यावरण की परवाह करने वाले जमाकर्ताओं को पर्यावरणीय रूप से स्थायी निवेश उत्पादों में अपना पैसा निवेश करने से कुछ संतुष्टि मिल सकती है। हालांकि, चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जिन परियोजनाओं में बैंक द्वारा ग्रीन फंड का निवेश किया जा सकता है, वे डिज़ाइन द्वारा सीमित हैं।
- जब पर्यावरण की रक्षा करने की बात आती है, तो हरित निवेश के प्रति उत्साही लोगों का मानना है कि हरित परियोजनाओं में पैसा लगाना पर्यावरण की मदद करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक हो सकता है।
- आलोचक, हालांकि, तर्क देते हैं कि हरित निवेश उत्पाद अक्सर निवेशकों को अपने बारे में अच्छा महसूस कराने का एक तरीका होता है और ये निवेश वास्तव में पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं करते हैं।

S&P स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB पर भारत की सॉवरेन रेटिंग

संदर्भ:

- एसऐंडपी ग्लोबल रेटिंग ने भारत की सॉवरिन रेटिंग स्थिर परिदृश्य के साथ दीर्घावधि के लिए 'बीबीबी-' और कम अवधि के लिए 'A-3' रखी है। एजेंसी ने कहा है कि मजबूत आर्थिक बुनियाद के कारण अगले 2 से 3 साल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27
Real GDP (YoY in %)	7.0	6	6.9	6.9	7.1
Debt (as % of GDP)*	84.4	84.9	84.1	83.8	83.1
Retail inflation (YoY in %)	6.8	5.0	4.3	4.4	4.7
Fiscal deficit (as % of GDP)*	10.0	8.9	8.1	7.6	7.3
Investment (as % of GDP)	32.3	31.4	31.5	31.0	30.5
Exports (as % of GDP)	22.6	21.8	21.8	21.3	21
CAD (as % of GDP)	2.9	2.2	1.5	1.6	1.6

Note: S&P forecasts (except FY23); *Figures for Centre+states Source: S&P

मुख्य बिन्दु:

- एसएंडपी को उम्मीद है कि भारत 2023-24 में 6 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर दर्ज करेगा, निवेश और उपभोक्ता गति के साथ अगले कुछ वर्षों में विकास की संभावनाओं में मदद मिलेगी, क्योंकि देश के 2024-25 और 2025 में 6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। -26।
- देश के सार्वजनिक वित्त से सावधान रहने के बावजूद, इसने पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवंटन में भारत की मजबूत वृद्धि पर विश्वास व्यक्त किया, जो सरकार के वित्तीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है।
- इसमें कहा गया है कि मजबूत राजस्व लाभ के बावजूद भारत में राजकोषीय मजबूती समान रेटिंग स्तरों वाले क्षेत्रीय समकक्षों से पीछे रही है। लेकिन इसने उम्मीद की कि केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में 2026-27 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 7.3 प्रतिशत पर अपने बड़े घाटे को धीरे-धीरे कम कर देगी।
- एसएंडपी ने अगले तीन वर्षों में समग्र शुद्ध सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 85 प्रतिशत से नीचे स्थिर करने का अनुमान लगाया है, जो कि जीडीपी के 75 प्रतिशत के पूर्व-महामारी स्तर से अधिक होगा, लेकिन 90 प्रतिशत से अधिक की महामारी के शिखर से नीचे होगा।

UNDESA रिपोर्ट:

- संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (यूएनडीईएसए) ने विश्व की आर्थिक स्थिति और अन्य पहलुओं पर अपने साल के मध्य के अनुमान में 2024 कैलेंडर वर्ष में भारत की वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।
- भारत की अर्थव्यवस्था में 2023 में 5.8 प्रतिशत और 2024 में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जो लचीली घरेलू मांग से समर्थित है। जैसा कि (दक्षिण एशियाई) क्षेत्र अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है; संभावित सूखा और बाढ़ भी आर्थिक दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।

फिच रेटिंग्स:

- इससे पहले, फिच रेटिंग्स ने भी भारत के दीर्घकालिक सॉवरेन ऋण के लिए एक स्थिर दृष्टिकोण के साथ अपनी सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग 'बीबीबी-' को दोहराया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में विकास की संभावनाएं तेज हो गई हैं क्योंकि निजी क्षेत्र मजबूत निवेश वृद्धि के लिए तैयार दिखाई दे रहा है।
- इसने कहा था कि लचीला निवेश संभावनाओं द्वारा समर्थित, 2023-24 के लिए 6 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान के साथ, भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक होगा।

- इसमें कहा गया है कि उच्च मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरों, और वैश्विक मांग में कमी के साथ-साथ महामारी से प्रेरित मांग में कमी के कारण विपरीत परिस्थितियां थीं।

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार "ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने" और "स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स साइटों को विकल्प प्रदान करने" के लिए इस वर्ष औपचारिक रूप से डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) शुरू करने पर विचार कर रही है।
- जबकि इसने कंपनियों से ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में शामिल होने का आग्रह किया है, अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ी बोर्ड में शामिल होने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।

ओएनडीसी क्या है?

- सरकार ई-कॉमर्स बाजार की मूलभूत संरचना को मौजूदा "प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक ओपन-नेटवर्क मॉडल" में बदलना चाहती है। ओएनडीसी को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रोजेक्ट के बाद तैयार किया गया है, जिसे कई लोग सफलता के रूप में देखते हैं।
- यूपीआई परियोजना लोगों को पैसे भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देती है, चाहे वे किसी भी भुगतान प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हों। इसी तरह, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ई-कॉमर्स बाजार में सामान के खरीदार और विक्रेता उन प्लेटफॉर्म पर ध्यान दिए बिना लेनदेन कर सकें, जिन पर वे पंजीकृत हैं।
- अतः, ओएनडीसी के अंतर्गत, उदाहरण के लिए, अमेज़ॅन पर पंजीकृत एक खरीदार सीधे फ्लिपकार्ट पर बेचने वाले विक्रेता से सामान खरीद सकता है। इस तरह के लेन-देन को हकीकत बनाने के लिए सरकार ने कंपनियों को ओएनडीसी में स्वयं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
- ओएनडीसी का पायलट संस्करण 2021 में कुछ प्रमुख शहरों में लॉन्च किया गया था और हजारों विक्रेता पहले ही प्लेटफॉर्म पर शामिल हो चुके हैं। हालाँकि, अमेज़न और फ्लिप्कार्ट ने अभी तक ओएनडीसी नेटवर्क पर अपने मुख्य शॉपिंग प्लेटफॉर्म को ऑन-बोर्ड नहीं किया है।

केंद्र इसके लिए क्यों जोर दे रहा है?

- सरकार का मानना है कि ओएनडीसी कुछ बड़े प्लेटफॉर्मों द्वारा ई-कॉमर्स बाजार के वर्चस्व को समाप्त कर देगा। इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स बाजार वर्तमान में निजी प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित और वर्चस्व वाले "साइलो" में टूट गया है।
- उदाहरण के लिए, अमेज़न और फ्लिप्कार्ट पर कुछ विक्रेता संस्थाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है, जिसमें उनकी अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। स्विगी और ज़ोमैटो जैसे खाद्य वितरण ऐप पर भी विक्रेताओं से उच्च कमीशन वसूलने का आरोप लगाया गया है।
- ओएनडीसी जैसे एक खुले नेटवर्क के साथ, जो खरीदारों और विक्रेताओं को प्लेटफार्मों में जोड़ता है, सरकार खेल के मैदान को समतल करने और निजी प्लेटफार्मों को बेमानी बनाने की उम्मीद करती है।

आगे क्या निहित है?

- सरकार के टेक्नोक्रेट्स की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक कुशल विकल्प के साथ आने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा क्योंकि सरकार ओएनडीसी को रोल आउट कर रही है। यह देखा जाना बाकी है कि सरकार का खुला नेटवर्क विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों को सूचीबद्ध करेगा या नहीं।
- प्रतियोगिता सामान्य तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उन उत्पादों को प्रमुखता से सूचीबद्ध करने के लिए प्रेरित करती है जो खरीदारों को आकर्षित करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। उनकी ऑन-बोर्डिंग और विक्रेताओं की लिस्टिंग भी ग्राहकों के आदेशों को पूरा करने के लिए विक्रेताओं की क्षमता से काफी प्रभावित होती है।
- वास्तव में, प्लेटफॉर्म विशिष्ट ऑन-बोर्डिंग और लिस्टिंग प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। यदि खुले नेटवर्क के नियम प्लेटफॉर्मों को ऐसे निवेशों से लाभ उठाने से रोकते हैं, तो वे उन्हें बनाना बंद कर सकते हैं।
- यह अंततः उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए एक कुशल बाज़ार का निर्माण करना ओएनडीसी के लिए प्रमुख चुनौती बन सकता है।

सुरक्षा

आईईडी से होने वाले खतरे को कम करना

संदर्भ:

- उग्रवादियों के हाथों में तात्कालिक विस्फोटक उपकरण शक्तिशाली उपकरण क्यों हैं? कश्मीर में आतंकवादियों या मध्य भारत में माओवादियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के अलावा और क्या किया जा सकता है?

हाल की घटनाएं:

- 5 मई को, जम्मू संभाग के राजौरी-पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पांच सैनिक शहीद हो गए और एक अन्य घायल हो गया।

- छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा इलाके में 26 अप्रैल को एक आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 सुरक्षाकर्मियों को मार डाला। जब जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया तो वे माओवादी विरोधी मिशन पर निकले थे।

क्या कोई सामरिक गलतियां हुई हैं?

- उग्रवादी, चाहे वे कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा हों या मध्य भारत में माओवादी, सुरक्षा बल एक ऐसे दुश्मन से निपट रहे हैं, जिसका चेहरा नहीं है, जिसे पहचाना नहीं जा सकता और जो लोगों के बीच छिपा हुआ है।
- सुरक्षाकर्मी केवल आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं, आशंका पर नहीं, उग्रवादियों को 'पहला प्रस्तावक लाभ' देते हुए।
- "तत्काल कार्रवाई (IA) या काउंटर एम्बुश ड्रिल" के लिए उपलब्ध प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया समय कुछ सेकंड है।
- सभी मानक ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रक्रियाएं, तकनीकी उपाय, आदि, आईईडी/बारूदी सुरंगों की पहचान और पता लगाने और उनमें पकड़े जाने से बचने के लिए निर्देशित हैं।

त्रुटियों को कैसे कम किया जा सकता है?

- पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है वाहन से यात्रा करने से बचना। यात्रा का सबसे सुरक्षित तरीका उस क्षेत्र में पैदल है जहां वामपंथी उग्रवाद सक्रिय है।
- इन अध्ययनों से पता चलता है कि माओवादी क्षेत्रों में 60% से अधिक हताहत/मौतें बारूदी सुरंगों/आईईडी में घात लगाए वाहनों के कारण होती हैं, जैसा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ की घटना में भी देखा गया है।
- नियमित संचालन जैसे क्षेत्र पर प्रभुत्व, घेराबंदी और तलाशी, लंबी दूरी की गश्त, घात-सह-गश्त आदि केवल पैदल ही की जानी चाहिए। वाहन यात्रा शायद ही कभी की जानी चाहिए और वह भी केवल अत्यावश्यक परिचालन कारणों से, उचित परिश्रम करने के बाद।
- यदि वाहन यात्रा अत्यंत आवश्यक है, तो आगे और वापसी की यात्रा कभी भी एक ही मार्ग से नहीं होनी चाहिए, न ही दिन के समय में की जानी चाहिए।
- माओवादी, नागरिक हताहतों के जोखिम से बचने के लिए, रात के समय न तो आईईडी चलाते हैं, न ही विरोधी कर्मियों/दबाव प्रेरित खानों का उपयोग करते हैं।

क्या छलावरण में घूमने से मदद मिलेगी?

- चुपके, छलावरण और छिपाव आतंकवाद विरोधी अभियानों के अभिन्न अंग हैं।
- सेना के हरे रंग के वाहन और सीआरपीएफ के हल्के हरे रंग के वाहन दूर से ही आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जिससे आतंकवादियों को आईईडी घात लगाने का पर्याप्त समय और अवसर मिल जाता है।
- यदि वाहन यात्रा अत्यंत आवश्यक है, तो सुरक्षा बलों से नागरिक या राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें लेने की अपेक्षा की जाती है। आसान पहचान से बचने के लिए, उन्हें नागरिकों के साथ मुफ्ती में हथियारों के साथ सावधानी से छुपाकर यात्रा करनी चाहिए।

बख्तरबंद वाहनों और अन्य सुरक्षात्मक गियर के बारे में क्या?

- कुछ युद्ध क्षेत्रों में वाहनों की तैनाती अनिवार्य है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले सुरक्षा बलों को विस्फोट प्रतिरोधी कपड़े, हेलमेट और आंखों की सुरक्षा जैसे उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर से लैस किया जाना चाहिए।
- विस्फोट की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए उनके वाहनों को वी-आकार और आर्मर-प्लेटेड हल, विस्फोट प्रतिरोधी तकनीक और उचित सैंडबैगिंग से भी लैस किया जाना चाहिए।
- मशीनगनों और अन्य हथियारों को वाहनों के ऊपर बाहर की ओर घुमाने वाली सीटों के साथ लगाया जाना चाहिए, जहां से पुरुष बाहर 360 डिग्री का अवलोकन कर सकें।
- इसके साथ ही सुरक्षा बलों को हमेशा कम से कम दो से तीन वाहनों के काफिले में यात्रा करनी चाहिए, उनके बीच कम से कम 40 से 50 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए, ताकि अगर एक वाहन बारूदी सुरंग में फंस जाता है, तो अन्य वाहनों में कर्मी स्थिति लेने और खतरे को बेअसर करने में सक्षम हों।

किसी क्षेत्र को यात्रा के लिए सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है?

- बारूदी सुरंगों और आईईडी का पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए मेटल डिटेक्टर, ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार और प्रशिक्षित स्निफर डॉग जैसी विभिन्न पहचान विधियों का कठोर और नियमित कार्यान्वयन आवश्यक है।
- सड़क खोलने वाली पार्टियां हमले का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यूजीवी (मानव रहित जमीनी वाहन) से लैस ड्रोन और सड़क खोलने वाली पार्टियों के माध्यम से हवाई निगरानी की जाती है।
- उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर, बारूदी सुरंगों या आईईडी वाले ज्ञात या संदिग्ध क्षेत्रों की मैपिंग की जा सकती है और उनके लिए आकस्मिक योजना तैयार की जा सकती है। इसमें निवारक और शमन दोनों उपायों के हिस्से के रूप में सुरक्षित मार्ग स्थापित करना, चेकपॉइंट स्थापित करना और निकासी योजना बनाना शामिल है।

विस्फोट से क्या सीखा जा सकता है?

- एक आईईडी घात एक द्वीपीय, स्टैंडअलोन घटना नहीं है। इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें फाइनेंसर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, बिल्डर और ट्रिगरमैन शामिल हैं।
- यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अफगानिस्तान में केवल एक वर्ष (2008-9) में, अमेरिकी फोरेंसिक जांच टीमों ने बम विस्फोटों के दृश्यों से बरामद किए गए आईईडी और विस्फोटकों के अवशेषों से 5,000 फिंगर प्रिंट निकाले।
- इसने IED घात में शामिल सैकड़ों संदिग्धों और साथियों की पहचान और पता लगाने में मदद मिली।
- मेहनती और वैज्ञानिक जांच, सावधानीपूर्वक संग्रह और सबूतों की मार्शलिंग के माध्यम से लिंकेज की स्थापना, चार्जशीट तैयार करना, इसके बाद त्वरित परीक्षण और सजा, आतंकवाद के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करते हैं।

अन्य उपाय क्या हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है?

- केंद्र और राज्यों दोनों में, सरकारी स्तर पर कई उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- इनमें बारूदी सुरंग और आईईडी की रोकथाम, पता लगाने और निकासी के लिए सूचना, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य देशों के साथ

सहयोग शामिल है; बारूदी सुरंगों और आईईडी के उपयोग, उत्पादन और व्यापार को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों और विनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन।

- परिवहन के दौरान आसानी से पता लगाने के लिए उद्योग और खनन आदि में उपयोग किए जाने वाले विस्फोटकों में सुगंधित रसायनों और/या बायोसेंसर को अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए विधायी उपायों की आवश्यकता होती है।
- इसी तरह, विस्फोटकों और डेटोनेटरों के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री पर कड़े नियंत्रण के लिए विधायी उपायों की आवश्यकता है। अन्य देशों ने अरबों खर्च कर कई काउंटर-आईईडी उपाय किए हैं।
- उदाहरण के लिए, अमेरिका ने "आईईडी को रोकने, पहचानने और पराजित करने" के लिए संयुक्त सुधार-खतरा हार संगठन की स्थापना की और 2005 से काउंटर आईईडी उपायों पर करीब 20 अरब डॉलर खर्च किए हैं।
- नाटो का काउंटर-आईईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैड्रिड में स्थित है; राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तहत भारत में एक छोटी इकाई मौजूद है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- लेकिन यह देखते हुए कि आईईडी भारत में आतंकवादियों से लड़ने के लिए बड़े झटके पैदा कर रहे हैं, यह सही समय है कि गृह मंत्रालय के तहत एक व्यापक एजेंसी बनाई जाए जो भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों के प्रयासों का समन्वय करे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विधायी, तकनीकी और प्रक्रियात्मक सहायता प्रदान करे।

ब्रिगेडियर और उच्च रैंक के अधिकारियों की होगी समान वर्दी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारतीय सेना ने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त, 2023 से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी सामान्य पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तथा मज़बूत करने हेतु अपने कैडर एवं नियुक्ति के बावजूद समान वर्दी पहनेंगे।

कैसे बदलेगी सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों की वर्दी?

- ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल के रैंक के सभी अधिकारी अब एक ही रंग की टोपी, रैंक के सामान्य बैज, एक सामान्य बेल्ट बकल और एक सामान्य पैटर्न के जूते पहनेंगे।
- वे अब अपने कंधों पर रेजिमेंटल डोरी (रस्सी) नहीं पहनेंगे। वे 'स्पेशल फोर्सेज', 'अरुणाचल स्काउट्स', 'डोगरा स्काउट्स' आदि जैसी कोई शोल्डर फ्लैश भी नहीं पहनेंगे।
- इस प्रकार वे कोई विशिष्ट वर्दी नहीं पहनेंगे जो उन्हें एक विशिष्ट रेजिमेंट या सैन्य-दल के सदस्य के रूप में नामित करे। इन वरिष्ठ रैंकों के सभी अधिकारियों हेतु एक समान डिज़ाइन होगा।

सेना में ऐसे पहनावे को पहनने की वर्तमान स्थिति क्या है?

- भारतीय सेना की विभिन्न शाखाएँ अपने रेजिमेंटल या कोर संबद्धता के आधार पर अलग-अलग वर्दी पहनती हैं, जैसे बेरेट, डोरी और रैंक के बैज।
- अतिरिक्त पोशाक या उपकरण जो वर्दी या पोशाक को पूरा करने के लिये विशेष रूप से सैन्यकर्मियों द्वारा पहने जाते हैं।
- इन्फैंट्री अधिकारी और सैन्य खुफिया अधिकारी गहरे हरे रंग की टोपी पहनते हैं, बख्तरबंद वाहिनी के अधिकारी काली टोपी पहनते हैं और अन्य वाहिनी अधिकारी गहरे नीले रंग की टोपी पहनते हैं। सैन्य पुलिस कोर के अधिकारी लाल रंग की टोपी पहनते हैं।
- वर्तमान में लेफ्टिनेंट से जनरल रैंक तक के सभी अधिकारी अपने सैन्य-दल (रेजिमेंटल) या कोर संबद्धता के अनुसार वर्दी पहनते हैं।
- प्रत्येक इन्फैंट्री रेजिमेंट और कोर के पास डोरी का अपना पैटर्न होता है जिसे वे कंधे के चारों ओर पहनते हैं और जो परंपरा के अनुसार दाएं या बाएं शर्ट की जेब में टिक जाता है।
- रैंक के बैज भी अलग-अलग होते हैं - राइफल रेजिमेंट रैंक के काले रंग के बैज पहनते हैं, जबकि कुछ रेजिमेंट गिल्ट और सिल्वर रंग के बैज पहनते हैं। अलग-अलग रंगों के बैकिंग हैं, जो व्यक्तिगत परंपराओं और रेजिमेंट या कोर के रीति-रिवाजों के अनुसार रैंक के इन बैज के साथ पहने जाते हैं।
- वर्दी पर बटन भी रेजिमेंटल परंपरा के अनुसार भिन्न होते हैं। राइफल रेजिमेंट काले बटन पहनते हैं जबकि ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के अधिकारी सुनहरे बटन पहनते हैं।
- रेजिमेंटल परंपराओं के अनुसार बेल्ट में अलग-अलग बकल होते हैं, और प्रत्येक का अपना क्रेस्ट होता है।

इस निर्णय का महत्त्व:

- यह निर्णय भारतीय सेना में एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- यह मानक वर्दी भारतीय सेना के सच्चे लोकाचार को दर्शाते हुए वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों हेतु सामान्य पहचान सुनिश्चित करेगी।
- रेजिमेंटल संकीर्णता को समाप्त करके और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सामान्य पहचान एवं उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देकर सेना आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने तथा बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है।
- किसी रेजिमेंट या सैन्य-दल के प्रति वफादारी या समर्पण को रेजिमेंटल संकीर्णता (Regimental Parochialism) कहा जाता है। किसी इकाई के प्रति गर्व और वफादारी अक्सर उसी संगठन के भीतर अन्य इकाइयों के साथ सहयोग या प्रतिस्पर्द्धा की कमी का कारण बन सकती है।
- यह मिश्रित रेजिमेंटल समूह के सैनिकों को आदेश देने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की क्षमता में भी सुधार कर सकता है।

- रेजिमेंटल वर्दी के बजाय एक समान वर्दी के प्रावधान से वरिष्ठ कमांडर एक अधिक समावेशी और सहयोगी नेतृत्त्व शैली का निर्माण कर सकते हैं जो पारंपरिक वफादारी और संबद्धता प्रदर्शित करती हो।

क्या ऐसा पहली बार किया जा रहा है?

- वास्तव में, सेना अब उस प्रथा पर वापस लौट रही है जो लगभग 40 साल पहले अपनाई गई थी, जब सेवा में रेजिमेंटल संबद्धता पहनने की दिशा में बदलाव आया था।
- 1980 के दशक के मध्य तक, रेजिमेंटल सेवा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक थी। कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के समान वर्दी पैटर्न और प्रतीक चिन्ह थे। कर्नलों और ब्रिगेडियरों ने अपने रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह को त्याग दिया और अपनी टोपी के बैज पर अशोक का प्रतीक चिन्ह धारण किया। बेरेट का रंग खाकी था।
- हालांकि, 1980 के दशक के मध्य में एक बटालियन या रेजिमेंट की कमान को कर्नल के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार, कर्नलों ने फिर से रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह पहनना शुरू कर दिया।
- इसके अलावा, ब्रिगेडियरों को जनरल ऑफिसर्स की कैप बैज पहनने की अनुमति थी, जिसमें क्रॉस की हुई तलवार और बलूत के पत्तों की माला के साथ बैटन शामिल होता है।

अन्य सेनाओं में पैटर्न:

- कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी को ब्रिटिश सेना में कर्मी/स्टाफ की वर्दी कहा जाता है, भारतीय सेना की वर्दी पैटर्न और संबंधित प्रतीक इसी से प्रेरित है। यह इसे रेजिमेंटल वर्दी से भिन्न बनाता है।
- रेजिमेंटल वर्दी के किसी भी आइटम, विशेष रूप से हेडड्रेस (सिर पर पहना जाने वाला), को स्टाफ की वर्दी के साथ पहनने की अनुमति नहीं है।
- पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाएँ भी ब्रिटिश सेना के समान ही पैटर्न का पालन करती हैं।
- लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से उपर के किसी भी अधिकारी को रेजिमेंटल वर्दी नहीं पहननी होती है, यानी बिलकुल नए किस्म की वर्दी मिलती है। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी समान पैटर्न वाली वर्दी पहनते हैं।

ब्रिटेन, यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देगा

चर्चा में क्यों?

- यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें प्रदान करेगा, जिसके लिए वह हमलावर रूसी सेना को पीछे धकेलने के लिए अनुरोध कर रहा है।

विवरण:

- यूक्रेन को अब तक विभिन्न प्रकार के हथियार और गोला-बारूद प्राप्त हुए हैं, जिनमें एंटी-टैंक मिसाइल, एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम और आर्टिलरी शामिल हैं, क्योंकि रूस ने फरवरी 2022 में इस पर आक्रमण किया था।
- स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, प्रत्येक की लागत £ 2 मिलियन है, यूक्रेनी बलों को अग्रिम पंक्ति के पीछे स्थित रूसी सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता प्रदान करेगी; विशेष रूप से क्रीमिया में, जिस पर मास्को ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा कर लिया था।

लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल की क्षमता क्या है?

- स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसमें स्टील्थ क्षमताएं भी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है।
- इसे पहली बार "ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा 1997 में स्टॉर्म शैडो लॉन्ग-रेंज मिसाइल के विकास और उत्पादन के लिए MBDA सिस्टम्स के साथ €1.13bn अनुबंध के बाद निर्मित किया गया था।
- फ्रांस ने 1997 में अपने बलों के लिए स्टॉर्म शैडो के विकास और निर्माण के लिए MBDA को भी नियुक्त किया।
- इस मिसाइल के पास 250 किमी की फायरिंग रेंज है। इस मिसाइल का वजन 1300 किग्रा है। मिसाइल 5.10 मीटर लंबी है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- यह सभी मौसमों में दिन और रात संचालित करने में सक्षम है और एयरबेस, राडार प्रतिष्ठानों, संचार केंद्रों और बंदरगाह सुविधाओं जैसे उच्च-मूल्यवान स्थिर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस स्टॉर्म शैडो भी उच्च परिशुद्धता वाली गहरी मार करने की क्षमता प्रदान करता है क्योंकि इसमें एक परिष्कृत नेविगेशन प्रणाली है जिसमें जड़त्वीय नेविगेशन (आईएनएस), वैश्विक शामिल है
- इस मिसाइल में BROACH (बम रॉयल ऑर्डनेंस ऑगमेंटेड चार्ज) वारहेड, एक उच्च-प्रौद्योगिकी वारहेड है, जो पहले लक्ष्य की सतह को काटता है, उसमें प्रवेश करता है और फिर विस्फोट करता है।

इसका उपयोग कहाँ किया गया है?

- स्टॉर्म शैडो को यूरोफाइटर टाइफून, राफेल, मिराज 2000 और टोरनेडो से संचालित किया जाता है।
- यह रॉयल एयर फोर्स, फ्रांसीसी वायु सेना, इतालवी वायु सेना और कई निर्यात देशों के साथ सेवा में है और इसने इराक, लीबिया और सीरिया में परिचालन सेवा देखी है।

सामाजिक मुद्दे

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

संदर्भ:

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) लागू होने के दस साल

बाद, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है कि इसके कार्यान्वयन के संबंध में "गंभीर खामियां" और "अनिश्चितता" हैं।

POSH अधिनियम का गठन कैसे किया गया था?

- वर्ष 1992 में, राजस्थान सरकार की महिला विकास परियोजना के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था क्योंकि उसने एक साल की लड़की की शादी को रोकने की कोशिश की थी।
- अपराध के खिलाफ कार्यकर्ता समूहों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के खिलाफ गारंटी "लिंग समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अधिनियमित" कानून की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया।
- वर्ष 1997 में विशाखा दिशानिर्देशों का एक संहिता निर्धारित किया गया था, जिसे विशाखा दिशानिर्देश कहा जाता है, ताकि कानून लागू होने तक वैधानिक शून्य को भरा जा सके। इन्हें "सभी कार्यस्थलों में सख्ती से देखा जाना था" और कानून में बाध्यकारी और लागू करने योग्य थे।
- इसके बाद, 2007 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री, कृष्णा तीरथ द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण विधेयक पेश किया गया। बाद में इसे संसद में पेश किया गया और संशोधनों के माध्यम से पारित किया गया।
- संशोधित विधेयक 9 दिसंबर, 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) या पॉश (POSH) अधिनियम के रूप में लागू हुआ।

नियोक्ताओं पर क्या आवश्यकताएं लगाई गई हैं?

- कानून के अनुसार 10 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करनी होगी, जिससे कोई भी महिला कर्मचारी औपचारिक यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क कर सकती है।
- इसकी अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जानी चाहिए, कम से कम दो महिला कर्मचारी, एक अन्य कर्मचारी, और एक तीसरा पक्ष जैसे कि पांच साल का अनुभव रखने वाला एक एनजीओ कार्यकर्ता, यौन उत्पीड़न की चुनौतियों से परिचित होना चाहिए।
- इसके अलावा, अधिनियम देश के प्रत्येक जिले को 10 से कम कर्मचारियों वाली फर्मों में काम करने वाली महिलाओं और घरेलू श्रमिकों, घर-आधारित श्रमिकों, स्वैच्छिक सरकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि सहित अनौपचारिक क्षेत्र से शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय समिति बनाने का आदेश देता है।
- नियोक्ता को जिला अधिकारी के साथ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत में की गई कार्रवाई के बारे में एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

अधिनियम के कार्यान्वयन में क्या बाधाएं हैं?

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईसीसी के गठन में खामियों को बताया कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 ने आज तक आईसीसी का गठन नहीं किया है।
- फैसले ने उन मामलों में अनुचित संविधान को भी चिह्नित किया जहां आईसीसी स्थापित किए गए थे, यह इंगित करते हुए कि उनके पास या तो सदस्यों की अपर्याप्त संख्या थी या अनिवार्य बाहरी सदस्य की कमी थी। हालांकि, जब पीओएसएच अधिनियम की बात आती है तो यह एकमात्र कार्यान्वयन से संबंधित चिंता नहीं है।
- चिंताओं में से एक यह है कि अधिनियम संतोषजनक रूप से जवाबदेही को संबोधित नहीं करता है, यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कार्यस्थल अधिनियम का पालन करने के लिए कौन प्रभारी है, और यदि इसके प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- हितधारक यह भी बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए कानून किस प्रकार काफी हद तक दुर्गम है। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने ध्यान दिया है कि कार्यस्थलों पर कई कारणों से यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट बहुत कम दर्ज की जाती है।
- इस तरह की पूछताछ करने के तरीके के बारे में कानून में अक्षम कामकाज और स्पष्टता की कमी ने न्याय प्रणाली से जुड़े पहुंच अवरोधों को दोहरा कर समाप्त कर दिया है।
- संगठनों की शक्ति गतिशीलता और पेशेवर नतीजों का डर भी महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज करने के रास्ते में खड़ा है।

SC के हालिया दिशा-निर्देश क्या हैं?

- अदालत ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया कि क्या मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थानों, निकायों आदि ने अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी), स्थानीय समितियों (एलसी) और आंतरिक समितियों (आईसी) का गठन किया है।
- इन निकायों को अपनी संबंधित समितियों का विवरण अपनी वेबसाइटों में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है।

स्वास्थ्य

वैज्ञानिकों ने भारत में डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सिनेशन आवश्यक बताया

चर्चा में क्यों?

- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में डेंगू वायरस का नाटकीय रूप से उभार हुआ है और देश में पाए जाने

वाले इसके स्वरूपों के प्रसार को रोकने के लिए टीका विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

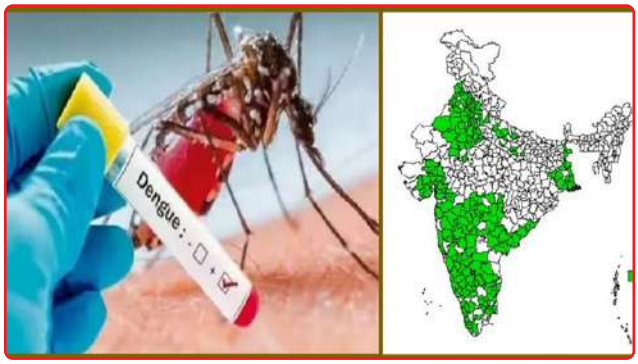

विवरण:

- पिछले 50 वर्षों में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में।
- टीम ने जांच की कि इनमें से प्रत्येक 'सीरोटाइप' अपने पैतृक अनुक्रम से, एक-दूसरे से और अन्य वैश्विक अनुक्रमों से कितना अलग हुआ।
- डेंगू फैलता है और कई कारकों द्वारा लगाए गए चयन दबावों के अनुकूल हो जाता है जिससे नए रूपों का उदय हो सकता है।

डेंगू क्या होता है?

- डेंगू वायरस Flaviviridae परिवार से संबंधित है और इसके चार व्यापक श्रेणियां 'सीरोटाइप- (डेंगू 1, 2, 3 और 4)' हैं।
- एडीज मच्छर द्वारा मनुष्यों में यह वायरस फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति को काटने से संक्रमित हो जाता है।
- एक बार जब वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है, तो यह मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं में प्रतिकृति बनाता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हैं।
- इसके बाद वायरस यकृत, प्लीहा, और लिम्फ नोड्स सहित अन्य अंगों में फैल जाता है, जिससे कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं।

भारत में डेंगू कैसे विकसित हुआ है?

- आईआईएससी के शोधकर्ताओं ने वर्ष 1956 और 2018 के बीच संक्रमित रोगियों से एकत्र किए गए डेंगू वायरस के भारतीय स्वरूपों के सभी उपलब्ध (408) आनुवंशिक अनुक्रमों की पड़ताल की गई।
- अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, 2012 तक भारत में 'डेंगू 1 और 3' प्रमुख स्वरूप थे। हालांकि, हाल के वर्षों में ' डेंगू 2' पूरे देश में अधिक प्रभावी हो गया है, जबकि कभी सबसे कम संक्रामक माना जाने वाला 'डेंगू 4' अब दक्षिण भारत में अपनी जगह बना रहा है।
- कभी-कभी लोग पहले एक सीरोटाइप से संक्रमित हो सकते हैं और फिर एक भिन्न सीरोटाइप के साथ द्वितीयक संक्रमण विकसित कर सकते हैं, जिससे अधिक गंभीर लक्षण हो सकते हैं।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि दूसरा सीरोटाइप पहले के समान है, तो पहले संक्रमण के बाद उत्पन्न हुए मेजबान के रक्त में एंटीबॉडी नए सीरोटाइप से बंध जाते हैं और मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं।
- प्राथमिक संक्रमण के बाद मानव शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडी लगभग 2-3 वर्षों तक सभी सेरोटाइप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। समय के साथ, एंटीबॉडी का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, और क्रॉस-सीरोटाइप सुरक्षा खो जाती है।

आगे की राह:

- नए निष्कर्ष आगे बताते हैं कि बीमारी के लिए टीका विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है।
- भले ही भारत में डेंगू एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है, फिर भी इस बीमारी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक वैक्सीन कैंडिडेट के तीसरे चरण के परीक्षण के बीच में है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट और पैनासिया बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

दुर्लभ विकार के इलाज के लिए डॉक्टरों ने अजन्मे बच्चे के मस्तिष्क की अपनी तरह की पहली सर्जरी की

चर्चा में क्यों?

- चिकित्सा विज्ञान में गेम चेंजर क्या हो सकता है, अमेरिकी डॉक्टरों की टीम ने गर्भ में पलने वाले बच्चे की मस्तिष्क के अंदर एक दुर्लभ रक्त वाहिका की असामान्य स्थिति का इलाज करने के लिए उसकी ब्रेन सर्जरी की है।

विनस ऑफ गेलन इंफोर्मेशन:

- वेन ऑफ गैलेन मालफॉरमेशन (VOGM) नामक स्थिति के इलाज के लिए भ्रूण की सर्जरी की गई।
- गेलन मालफॉर्मेशन की स्थिति तब विकसित होती है जब ब्रेन से हार्ट तक खून पहुंचाने वाली नलिकाओं का विकास नहीं हो पाता।
- ब्रेन की धमनियां खून को नसों (capillaries) के बजाय सीधे शिराओं (veins) में प्रवाहित करती हैं। इससे दिल खून से भर जाता है।
- 'वेन ऑफ गैलेन मालफॉर्मेशन हाई फ्लो एबनॉर्मल कनेक्शन है, जिससे नसों में अतिरिक्त दबाव होता है, जिसके कारण हृदय और फेफड़ों की ओर रक्त का बहाव बढ़ता है।
- शरीर के बाकी हिस्सों में खून पहुंचाने के लिए हृदय को अतिरिक्त काम करना पड़ता है। इस असामान्यता वाले शिशुओं में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है।

गर्भाशय में सर्जरी:

- अल्ट्रासाउंड प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित बच्चे के जन्म से पहले गर्भाशय सर्जरी की गई थी। प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अपेक्षित आक्रामक प्रसवोत्तर प्राकृतिक इतिहास का पूर्ण उन्मूलन हुआ।

- एक अल्ट्रासाउंड में स्थिति का पता तब चला जब भ्रूण 30 सप्ताह का था और डॉक्टरों ने माता-पिता को बताया कि बच्चे का दिल बड़ा हो गया है, जिसके बाद VOGM का पता चला।
- सर्जरी तब की गई थी जब भ्रूण की गर्भकालीन आयु 34 सप्ताह से थोड़ी अधिक थी।

आगे की राह:

- यह दृष्टिकोण इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के प्रबंधन में एक प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, शुरुआत के बाद गंभीर मल्टीऑर्गन पैथोफिज़ियोलॉजी को उलटने पर केंद्रित रणनीति से रोकथाम पर केंद्रित है।

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने वृद्ध वयस्कों के लिए पहले आरएसवी वैक्सीन को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में रेस्पिरेटरी सीनसीटियल वायरस (RSV: respiratory syncytial virus) के कारण होने वाले लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज (LRTD: lower respiratory tract disease) की रोकथाम के लिए GSK फार्मा की Arexvy (ह्यूमन रेस्पिरेटरी सीनसीटियल वायरस वैक्सीन, एडजुवेंटेड) को मंजूरी दी है।
- यह विश्व में कहीं भी ओल्ड एडल्ट्स के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला RSV टीका है।

रेस्पिरेटरी सीनसीटियल वायरस (RSV)

- RSV एक कॉमन संक्रामक वायरस है जो संभावित रूप से गंभीर श्वसन बीमारी का कारण बन सकता है।
- RSV एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में फेफड़ों और सांस लेने के मार्ग में संक्रमण का कारण बनता है।
- वृद्ध वयस्कों यानी ओल्ड एडल्ट्स को आंशिक रूप से उम्र बढ़ने की साथ प्रतिरक्षा में में कमी के कारण इसकी वजह से गंभीर बीमारी का खतरा बना रहता है।
- RSV का इन्फेक्शन मौसमी है, आमतौर पर शरद ऋतु के दौरान शुरू होता है और सर्दियों में सर्वोच्च स्तर पर कर लेता है।

सहरुग्णताएं:

- यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, इस से लगभग 60,000 से 120,000 लोग अस्पताल में भर्ती होते है और 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों में 6,000 से 10,000 मौतें होती हैं।
- आरएसवी संक्रमण बच्चों में अधिक आम है, लेकिन कई बार यह बुजुर्ग आबादी पर भी हमला करता है। आरएसवी आमतौर पर हल्के, ठंडे जैसे लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए यह गंभीर हो सकता है। यह वायरस निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है, जो वायुमार्ग को फुला देता है और उन्हें बलगम से भर देता है।

अन्य टीके:

- फाइजर और मॉडर्ना द्वारा आरएसवी के लिए दो और टीकों ने पहले ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों पर नैदानिक परीक्षण पूरा कर लिया है और जल्द ही एफडीए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- जबकि फाइजर द्वारा विकसित टीका प्रोटीन-आधारित है, मॉडर्ना ने आरएसवी वैक्सीन विकसित करने के लिए सार्स-सीओवी-2 वैक्सीन की तरह एमआरएनए तकनीक का उपयोग किया है।
- जीएसके 50-59 वर्ष की आयु के वयस्कों में भी वैक्सीन का परीक्षण कर रहा है, जिसमें अंतर्निहित कोमोर्बिडिटी वाले प्रतिभागी भी शामिल हैं। परिणाम 2023 के अंत तक आने की उम्मीद है।

आगे की राह:

- टीका 2023-2024 RSV सीज़न से पहले यू.एस. में वृद्ध वयस्कों के लिए उपलब्ध होगा, जो आमतौर पर सर्दियों के महीनों से पहले शुरू होता है।

ड्रग रिकॉल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अनजाने में दवाओं के गलत लेबल वाले बैच को बाज़ार में उतार दिया, जो कि अस्वीकृत दवाओं की बिक्री की समस्या एवं भारत में ड्रग रिकॉल कानून की आवश्यकता को उजागर करता है।
- जबकि इस तरह के रिकॉल अमेरिका में नियमित रूप से होते हैं, जिसमें भारतीय कंपनियाँ भी शामिल हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं देखा जाता है।

ड्रग रिकॉल:

- ड्रग रिकॉल तब होता है जब प्रेस्क्रिप्शन या ओवर-द-काउंटर दवा को उसके हानिकारक या साइड इफेक्ट के कारण बाज़ार से हटा दिया जाता है।
- ड्रग रिकॉल एक विपणन किये गए दवा उत्पाद को हटाने या सही करने की प्रक्रिया है जो किसी दवा की सुरक्षा, प्रभावकारिता या गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले कानूनों और नियमों का उल्लंघन करती है।

- ड्रग रिकॉल सामान्यतः तब जारी किया जाता है जब कोई उत्पाद दोषपूर्ण, दूषित, गलत लेबल वाला पाया जाता है या रोगियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु जोखिम उत्पन्न करता है।
- ड्रग रिकॉल का लक्ष्य प्रभावित उत्पाद को बाज़ार से हटाकर जनता को नुकसान से बचाना है और उन उपभोक्ताओं हेतु उपाय या धन वापसी की सुविधा प्रदान करना है जिन्होंने पहले ही उत्पाद खरीद लिया है।

भारत में ड्रग रिकॉल कानून की आवश्यकता:

- वर्तमान में, बाज़ार से घटिया दवाओं के पूरे बैच को वापस लेने के लिये भारत में कोई कानून नहीं है।
- राज्य दवा नियामक ऐसी स्थिति में अधिक-से-अधिक अपने राज्य से दवाओं के किसी विशेष बैच को वापस लेने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन यह देखते हुए कि भारत एक साझा बाज़ार है, यह संभव है कि दवाओं का एक ही बैच कई राज्यों में वितरित हो।
- ऐसे मामले में एक केंद्रीय दवा नियामक का होना काफी आवश्यक है जो राष्ट्रीय रिकॉल को क्रियान्वित और समन्वित कर सके।
- वर्ष 1976 में इसे एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चिह्नित करने के बावजूद भारत में अभी भी दवाओं को वापस लेने के संबंध में एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है।
- नतीजतन, सरकारी विश्लेषकों द्वारा दवाओं को NSQ घोषित करने के बाद भी पूरे भारत से इस प्रकार की दवाओं को वापस लेने की कोई वास्तविक व्यवस्था नहीं है।

भारत में घटिया दवाओं के लिये नियामक ढाँचे की कमी का कारण:

- जटिल औषधि नियमन मुद्दों से निपटने के मामले में सरकार का औषधि नियामक निकाय वैसा नहीं है जैसी उसे होना चाहिये। स्थिति के प्रति उदासीनता, क्षेत्र में विशेषज्ञता की कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा की तुलना में दवा उद्योग के विकास को सक्षम करने में अधिक रुचि आदि इसके विभिन्न प्रमुख कारकों में से हैं।
- भारत में नियामक संरचना अत्यधिक खंडित है, प्रत्येक राज्य का अपना दवा नियामक है। लेकिन विखंडन के बावजूद एक राज्य में निर्मित दवाएँ देश भर के सभी राज्यों में बेची जा सकती हैं।
- एक प्रभावी रिकॉल तंत्र बनाने के लिए, दवाओं को वापस लेने की जिम्मेदारी को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें एक प्राधिकरण देश भर से दवाओं को वापस लेने में विफलताओं के लिए कंपनियों को उत्तरदायी ठहराने के लिए कानूनी शक्ति का प्रयोग करे। हालांकि, दवा उद्योग और राज्य दवा नियामकों दोनों ने नियामक शक्तियों के अधिक केंद्रीकरण का विरोध किया है।
- भारत के दवा नियामक इस तथ्य से अवगत हैं कि एक अनिवार्य ड्रग रिकॉल प्रणाली, जो आवश्यक रूप से व्यापक प्रचार की प्रणाली पर केंद्रित होनी चाहिए, भारत के दवा उद्योग में मामलों की स्थिति को जनता के सामने लाएगी।

क्या होता है जब घटिया दवाओं को वापस नहीं लिया जाता है?

- लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, लगभग निश्चित रूप से प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाओं से मर रहे हैं या पीड़ित हैं क्योंकि बाजार से घटिया दवाओं को तेजी से नहीं हटाया जा रहा है।
- सरकारी प्रयोगशालाओं में हर महीने दर्जनों दवाएं रैंडम-परीक्षण में विफल हो जाती हैं। आदर्श रूप से, इन दवाओं को आवश्यक रूप से पारदर्शी तरीके से वापस लिया जाएगा, साथ ही लोगों को विफलताओं के बारे में सूचित किया जाएगा।
- यदि भारत में वास्तव में ऐसा होता है, तो लोगों को लगभग दैनिक आधार पर अलर्ट की बाढ़ आ जाएगी, जिससे दवा नियामकों पर व्यापक सुधारों को स्थापित करने का दबाव बढ़ जाएगा।

जहरीली शराब से मृत्यु की बढ़ती घटनाएँ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू और विल्लुपुरम जिलों में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मृत्यु हो गई।
- ये घटनाएं मुश्किल से एक महीने बाद हुईं जब राज्य सरकार ने कहा कि उसने ऐसी मौतों को नियंत्रण में कर लिया है।

शराब में अल्कोहल क्या होता है?

- शराब में अल्कोहल की मात्रा के आधार पर पृथक किया जाता है; 5% या लगभग बियर में, 12% या लगभग वाइन में तथा 40% या लगभग आसुत स्पिरिट्स (सभी आयतन के अनुसार) पाया जाता है।
- यह प्रचलित धारणा के विपरीत, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया है कि "इसके उपभोग का कोई भी स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है"। लंबे समय तक उपयोग इस पर निर्भरता की ओर जाता है, कुछ कैंसर और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, और अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है।
- इथेनॉल (C2H5OH) एक कार्बन परमाणु है जो तीन हाइड्रोजन परमाणुओं और एक और कार्बन परमाणु से बंधा होता है; दूसरा कार्बन परमाणु भी दो हाइड्रोजन परमाणुओं और हाइड्रॉक्सिल समूह से बंधा होता है, जिसे OH- आयन के रूप में भी जाना जाता है।
- इसके शरीर के अंदर, यह यकृत और पेट में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज (ADH) एंजाइम द्वारा एसिटाल्डीहाइड में उपापचयित होता है। फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज (ALDH) एंजाइम एसीटैल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देते हैं।
- शराब के सेवन के प्रतिकूल प्रभाव, हैंगओवर से लेकर कैंसर तक, एसीटैल्डिहाइड के कारण होते हैं।

नकली शराब क्या होता है?

- इस नकली शराब में मेथनॉल युक्त तरल मिश्रण भी होता है।
- कई मामलों में, ऐसी शराब सामान्य तौर पर घर में बनी शराब होती है, जैसे अरक, जिसमें नशीला प्रभाव (बोलचाल की भाषा में, इसकी किक)

को मजबूत करने और/या इसकी थोक मात्रा को बढ़ाने के लिए मेथनॉल मिलाया गया था। अरक ताड़ के पेड़ के किण्वित रस से आसवित होता है।

- खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय पदार्थ) विनियम 2018 विभिन्न शराबों में मेथनॉल की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा निर्धारित करता है।
- ये मान एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए हैं, जिनमें नारियल फेनी में "अनुपस्थित", देशी शराब में 50 ग्राम प्रति 100 लीटर और पॉट-डिस्टिल्ड स्पिरिट में 300 ग्राम प्रति 100 लीटर शामिल हैं।

मेथनॉल क्या है?

- प्रत्येक मेथनॉल अणु (CH_3OH) में एक कार्बन परमाणु तीन हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ा होता है।
- खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची I में मेथनॉल शामिल है। भारतीय मानक IS 517 इस बात पर लागू होता है कि मेथनॉल की गुणवत्ता का पता किस प्रकार लगाया जाए, और साथ में तमिलनाडु विकृत स्प्रिट, मिथाइल अल्कोहल, और वार्निश (फ्रेंच पोलिश) नियम 1959, मेथनॉल पैकेजिंग पर क्या संकेत होना चाहिए।
- मेथनॉल का उत्पादन करने का सबसे सामान्य तरीका 50-100 वायुमंडलीय दबाव और 250°C पर उत्प्रेरक के रूप में कॉपर और जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाना है। पूर्व-औद्योगिक युग में, प्राचीन मिस्र में वापस जाने पर, लोगों ने लकड़ी को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके मेथनॉल (कई अन्य उपोत्पादों के साथ) भी बनाया।
- मेथनॉल के कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, जिनमें एसिटिक एसिड, फॉर्मलडिहाइड और सुगंधित हाइड्रोकार्बन के अग्रदूत के रूप में शामिल है। इसका उपयोग विलायक के रूप में और एंटीफ्रीज़ के रूप में भी किया जाता है। तमिलनाडु में, मेथनॉल के निर्माण, निर्यात, आयात, भंडारण और बिक्री के लिए 1959 के नियमों के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

नकली शराब किस प्रकार मारती है?

- 1945 से भारत और विश्व के इतिहास में प्रत्येक जहरीली त्रासदी में जहर मेथनॉल रहा है। कुछ फल खाने के परिणामस्वरूप मानव शरीर में मेथनॉल की असीम मात्रा (2006 के एक अध्ययन के अनुसार स्वस्थ व्यक्तियों की सांस में 4.5 पीपीएम) होती है। लेकिन एक वयस्क के लिए भी, शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम शुद्ध मेथनॉल के 0.1 मिलीलीटर से अधिक विनाशकारी हो सकता है।
- यह एक बार निगले जाने के बाद, मेथनॉल को लीवर में ADH एंजाइम द्वारा मेटाबोलाइज़ किया जाता है, जिससे फॉर्मेल्डिहाइड (H-CHO) बनता है। फिर एएलडीएच (ALDH) एंजाइम फॉर्मलडिहाइड को फॉर्मिक एसिड (HCOOH) में बदल देते हैं।
- इसमें समय के साथ फॉर्मिक एसिड का संचय एक हानिकारक स्थिति की ओर ले जाता है जिसे मेटाबोलिक एसिडोसिस कहा जाता है।
- इसके द्वारा एसिडोसिस से एसिडिमिया भी हो सकता है, यह एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त का पीएच अपने सामान्य मान 7.35 से कम हो जाता है, तेजी से अम्लीय हो जाता है। रक्त का पीएच सामान्य रूप से एक एसिड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और एक आधार, जैसे बाइकार्बोनेट आयन (HCO3–) के बीच संतुलन द्वारा बनाए रखा जाता है।
- जैसे ही मेथनॉल का चयापचय होता है, बाइकार्बोनेट आयन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे एसिड का प्रभाव बढ़ जाता है।
- फॉर्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम के साथ भी हस्तक्षेप करता है, जो बदले में कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करता है और लैक्टिक एसिड के निर्माण की ओर जाता है, जो एसिडोसिस में योगदान देता है।
- मेथनॉल-विषाक्तता मस्तिष्क शोफ, रक्तस्राव और मृत्यु का कारण भी बन सकती है।

ऐसे जहर का इलाज किस प्रकार किया जा सकता है?

- एक बार मेथनॉल के अंतर्ग्रहण के बाद, शरीर को इसे पूरी तरह से समाप्त करने में कुछ समय लगता है। एक अनुमान से पता चलता है कि 48 घंटों के बाद भी 33% जितना पीछे रह गया है। यह पूरी तरह से जठरांत्र संबंधी मार्ग के माध्यम से अवशोषित होता है और रक्त-मेथनॉल स्तर 90 मिनट के भीतर अपने अधिकतम मूल्य तक पहुंच सकता है।
- मेथनॉल विषाक्तता का इलाज करने के दो तत्काल तरीके हैं। एक है इथेनॉल का प्रशासन करना। यह उल्टा लग सकता है लेकिन एडीएच एंजाइम के लिए इथेनॉल मेथनॉल के साथ बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करता है। नतीजतन, मेथनॉल को मेटाबोलाइज होने से फॉर्मल्डेहाइड में रखा जाता है।
- दूसरा विकल्प फोमेपिज़ोल नामक एक एंटीडोट का प्रशासन करना है, जिसमें एक समान तंत्र है - यह एडीएच एंजाइम की क्रिया को धीमा कर देता है, जिससे शरीर फॉर्मल्डेहाइड का उत्पादन उस दर पर करता है जिससे शरीर जल्दी से निकल सकता है, घातक प्रभावों को अंदर आने से रोकता है।
- कार्रवाई के दोनों उपाय उनके विशिष्ट यौगिकों की उपलब्धता से सीमित हैं। फोमेपिज़ोल (Fomepizole) महंगा है जबकि फार्मास्युटिकल-ग्रेड इथेनॉल को पर्यवेक्षण के तहत प्रशासित करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता रक्त से मेथनॉल और फॉर्मिक एसिड लवण को हटाने के लिए व्यक्ति से डायलिसिस करवा सकते हैं, और गुर्दे और रेटिना को होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं।
- वे फोलिनिक एसिड भी दे सकते हैं, जो फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटने के लिए प्रोत्साहित करता है। फोमेपिज़ोल और फोलिनिक एसिड दोनों ही डब्लूएचओ की आवश्यक दवाओं की सूची में हैं।

भारत डेंगू के खिलाफ अपना पहला स्वदेशी टीका विकसित करने के करीब

संदर्भ:

- आईसीएमआर के आमंत्रण पर दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनेसिया बायोटेक ने डेंगू के खिलाफ वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आवेदन किया है।
- भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन कैंडीडेट की सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्षमता के साथ ही उसके असर के मूल्यांकन के लिए तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- डेंगू वायरस रोग दुनिया भर में महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर का कारण बनता है। भारत में हर साल 2.5 लाख लोग डेंगू की वजह से या तो बीमार पड़ते हैं या मृत्यु हो जाती है।
- डेंगू की वैश्विक घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है, दुनिया की लगभग आधी आबादी इस बीमारी की वजह से जोखिम में है।
- हालांकि अनुमानित 100-400 मिलियन संक्रमण प्रत्येक वर्ष होते हैं, 80% से अधिक आम तौर पर हल्के और स्पर्शोन्मुख होते हैं।
- इसलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में शीर्ष दस वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के तौर पर डेंगू की पहचान की थी।

संभावित वैक्सीन:

- सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन का बच्चों पर अध्ययन शुरू किया गया है।
- इसके साथ ही पैनेसिया की वैक्सीन का आईसीएमआर की वित्तपोषित 20 साइट्स पर 18 से 80 साल की आयु वाले 10,335 लोगों पर तीसरे चरण में डबल ब्लाइंड, प्लेसीबो कंट्रोल्ड ट्रायल करने की योजना है।
- फेज 3 प्रोटोकॉल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (जनवरी 2023) द्वारा अनुमोदित किया गया है और कंपनी अगस्त-सितंबर में शुरू होने वाले परीक्षणों के साथ वैक्सीन उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

डेंगू वैक्सीन की विशेषताओं में

- यह स्वीकार्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा प्रोफ़ाइल (कोई एंटीबॉडी-निर्भर वृद्धि नहीं),
- डेंगू के सभी चार सीरोटाइप के खिलाफ सुरक्षा को प्रेरित करना,
- इसके द्वारा गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम को कम करना,
- व्यक्ति की पहले सीरो-स्थिति और उम्र के बावजूद निरंतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और प्रभावशीलता को प्रेरित करना शामिल है।

आगे की राह:

- वयस्कों के लिए डेंगू वैक्सीन का ट्रायल इसी साल अगस्त से शुरू हो सकते हैं।

बीमारियों की जानकारी के लिए डब्लूएचओ का नवीनतम वैश्विक नेटवर्क

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से खतरे का तेजी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करने में सहायता करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है।

मुख्य विचार:

- इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क (IPSN) देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, नमूनों को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सिस्टम में सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचाना और ट्रैक किया जाता है, जबकि जानकारी साझा की जाती है और कोरोनावायरस महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई की जाती है।
- नेटवर्क वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए रोगज़नक़ जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा।

अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए, आईपीएसएन में कार्य के पाँच क्षेत्र शामिल हैं:

आम चुनौतियों को हल करने के लिए अभ्यास के समुदाय:

- आईपीएसएन के काम के केंद्र में अभ्यास के समुदायों का एक समूह है जो रोगज़नक़ जीनोमिक्स पर काम कर रहे भागीदारों के बीच आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है। इनमें से पहला जीनोमिक्स डेटा पर आईपीएसएन कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है।
- इसकी परियोजनाओं और डिलिवरेबल्स का उद्देश्य डेटा मानकों और प्रोटोकॉल को सुसंगत बनाना है, यह सुनिश्चित करना है कि जीनोमिक्स डेटा उपकरण उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं, और यह कि डेटा और लाभ साझाकरण बढ़ाया जाता है।

प्रयासों को संरेखित करने और दक्षिण-दक्षिण आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए कंट्री स्केल-अप एक्सीलरेटर:

- आईपीएसएन ने रोगजनक जीनोमिक निगरानी के लिए देश की क्षमता में तेजी से वृद्धि करने के लिए आईपीएसएन सदस्यों के प्रयासों को तेज करने और बढ़ाने के लिए कंट्री स्केल-अप एक्सेलरेटर (सीएसयूए) की स्थापना की है।
- सीएसयूए की परियोजनाओं और डिलिवरेबल्स का उद्देश्य वैश्विक वस्तुओं के रूप में क्षमता निर्माण उपकरणों का एक सेट बनाना है, और क्षमता विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण द्विपक्षीय और उप-क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ाना है।

इक्विटी में सुधार और आईपीएसएन परियोजनाओं को शक्ति प्रदान करने हेतु वित्तीयन:

- दाता प्रयासों के बेहतर समन्वय और सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए, आईपीएसएन ने एक फंडर्स फोरम की स्थापना की है, जो आईपीएसएन गतिविधियों और छोटे अनुदान कोष सहित सदस्यों का समर्थन करने के लिए सचिवालय के साथ काम करता है।

एजेंडा पर जीनोमिक निगरानी रखने के लिए उच्च-स्तरीय वकालत और संचार:

- देशों, भागीदारों, क्षेत्रीय संगठनों और डब्ल्यूएचओ के सक्रिय जुड़ाव के साथ, आईपीएसएन वैश्विक एजेंडे पर रोगज़नक़ जीनोमिक निगरानी रखता है और रणनीतिक खरीद-इन सुनिश्चित करता है।

भागीदारों को एक साथ लाने के लिए रोगज़नक़ जीनोमिक्स के लिए वैश्विक भागीदार मंच:

- वार्षिक फोरम पैथोजेन जीनोमिक सर्विलांस में शामिल सभी आईपीएसएन संस्थाओं के प्रमुख खिलाड़ियों को एक साथ लाता है, साझेदारी बनाने, नवाचारों को प्रस्तुत करने, विचारों को सामाजिक बनाने और राजनीतिक और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की वकालत करने के लिए एक हाई-प्रोफाइल मंच प्रदान करता है।

महत्त्व:

- डब्ल्यूएचओ ने नए नेटवर्क के "महत्वाकांक्षी" लक्ष्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह "स्वास्थ्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है"।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ईयू का नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम

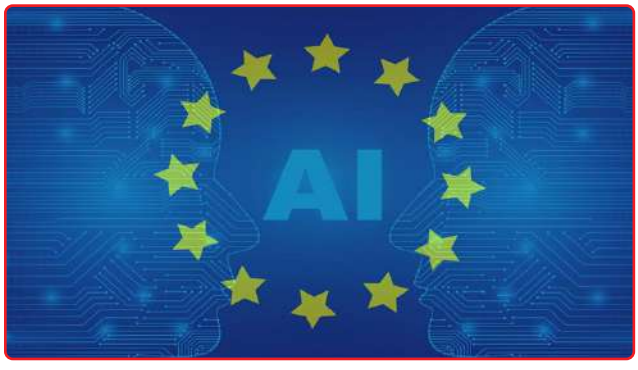

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के महत्वाकांक्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिमियम के एक नए मसौदे पर प्रारंभिक समझौते पर पहुंची, जिसे पहली बार दो वर्ष पहले तैयार किया गया था।

कृत्रिम बुद्धि को क्यों विनियमित करें?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियां सर्वव्यापी हो गई हैं और उनके एल्गोरिदम अधिक उन्नत हो गए हैं; उनसे जुड़े जोखिम और अनिश्चितताएं भी बढ़ी हैं।
- कई एआई उपकरण अनिवार्य रूप से ब्लैक बॉक्स हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें डिजाइन करने वाले भी यह नहीं समझा सकते हैं कि एक विशेष आउटपुट उत्पन्न करने के लिए उनके अंदर क्या चल रहा है।
- एआई-सक्षम चेहरे की पहचान के कारण गलत व्यक्ति की गिरफ्तारी में जटिल और अस्पष्ट एआई उपकरण पहले ही प्रकट हो चुके हैं; एआई आउटपुट में भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह; और हाल ही में, बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) पर आधारित चैटबॉट जैसे जनरेटिव प्रीट्रेन्ड ट्रासफॉर्मर-3 (जीपीटी-3) और 4 बहुमुखी, मानव-प्रतिस्पर्धी और वास्तविक दिखने वाली सामग्री उत्पन्न कर सकते हैं, जो गलत या कॉपीराइट वाली सामग्री हो सकती है।
- हाल ही में, ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क और एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव वोज़्नियाक सहित उद्योग के हितधारकों ने एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एआई लैब को छह महीने के लिए जीपीटी-4 से अधिक शक्तिशाली एआई मॉडल के प्रशिक्षण को रोकने के लिए कहा गया, जिसमें समाज और मानवता के लिए संभावित जोखिम का हवाला दिया गया था।

एआई अधिनियम को किस प्रकार बनाया गया?

- एआई में पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही लाने और यूरोपीय संघ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के जोखिमों को कम करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से 2021 में कानून का मसौदा तैयार किया गया था।
- इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से लेकर वित्त और ऊर्जा तक विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक प्रश्नों और कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना है। कानून "प्रौद्योगिकी के कुछ उपयोगों से जुड़े नुकसान को कम करने या रोकने के दौरान एआई के तेज को बढ़ावा देने" के बीच संतुलन बनाना चाहता है।
- यूरोपीय संघ के 2018 जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) ने जिस तरह से इसे वैश्विक डेटा संरक्षण व्यवस्था में एक उद्योग का नेता बना दिया है, उसी तरह एआई कानून का उद्देश्य "प्रयोगशाला से बाजार तक एआई में उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में यूरोप की स्थिति को मजबूत करना" है। और सुनिश्चित करें कि यूरोप में एआई 27 देशों के ब्लॉक के मूल्यों और नियमों का सम्मान करता है।

मसौदा दस्तावेज में क्या शामिल है?

- यह मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ज्ञान के साथ-साथ तर्क-आधारित और सांख्यिकीय दृष्टिकोण पर आधारित एआई टूल्स की पहचान करता है।
- अधिनियम का केंद्रीय दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के "स्वास्थ्य और सुरक्षा या मौलिक अधिकारों" के जोखिम के स्तर के आधार पर एआई तकनीक का वर्गीकरण है।
- अधिनियम में चार जोखिम श्रेणियां हैं - अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और न्यूनतम।

निषेध:

- अधिनियम कुछ अपवादों के साथ अस्वीकार्य जोखिम श्रेणी में प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर रोक लगाता है।
- इनमें सार्वजनिक स्थानों पर रीयल-टाइम फेशियल और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का उपयोग शामिल है; सरकारों द्वारा नागरिकों के सामाजिक स्कोरिंग की प्रणाली "अनुचित और असंगत हानिकारक उपचार" के लिए अग्रणी; किसी व्यक्ति के व्यवहार को विकृत करने की अचेतन तकनीकें; और प्रौद्योगिकियां जो युवा या बुजुर्गों, या विकलांग व्यक्तियों की कमजोरियों का फायदा उठा सकती हैं।

उच्च जोखिम वाली श्रेणी:

- यह अधिनियम उच्च जोखिम वाली श्रेणी में एआई पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें डेवलपर्स और ऐसी प्रणालियों के उपयोगकर्ताओं के लिए बाजार से पहले और बाद की कई आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।
- इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कुछ प्रणालियों में बायोमेट्रिक पहचान और प्राकृतिक व्यक्तियों का वर्गीकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार (भर्ती), कानून प्रवर्तन, न्याय वितरण प्रणाली और आवश्यक निजी और सार्वजनिक सेवाओं (वित्तीय सेवाओं तक पहुंच जैसे ऋण अनुमोदन प्रणाली सहित) तक पहुंच प्रदान करने वाले उपकरण शामिल हैं।
- सीमित और न्यूनतम जोखिम श्रेणी में एआई सिस्टम जैसे स्पैम फिल्टर या वीडियो गेम को पारदर्शिता दायित्वों जैसी कुछ आवश्यकताओं के साथ उपयोग करने की अनुमति है।

अनुरूपता का निर्धारण:

- इससे पहले कि उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम बाजार में आ सकें, वे अधिनियम में 'अनुरूपता आकलन' के रूप में ज्ञात सख्त समीक्षाओं के अधीन होंगे जैसे एल्गोरिथम प्रभाव आकलन एआई उपकरण, पक्षपात, उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं, और सिस्टम आउटपुट के समग्र डिजाइन और निगरानी को खिलाए गए डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए।
- इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियाँ पारदर्शी, व्याख्यात्मक हों, मानवीय निरीक्षण की अनुमति दें और उपयोगकर्ता को स्पष्ट और पर्याप्त जानकारी दें।
- इसके अलावा, चूंकि एआई एल्गोरिदम को विशेष रूप से समय के साथ विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उच्च जोखिम वाले सिस्टम को अनिवार्य पोस्ट-मार्केट मॉनिटरिंग दायित्वों का भी पालन करना चाहिए जैसे प्रदर्शन डेटा लॉग करना और निरंतर अनुपालन बनाए रखना, इस बात पर विशेष ध्यान देना कि ये कार्यक्रम अपने जीवनकाल में किस प्रकार बदलते हैं।

चैटजीपीटी जैसे सामान्य प्रयोजन एआई पर हालिया प्रस्ताव क्या है?

- हाल ही में फरवरी 2023 तक, सामान्य उद्देश्य एआई जैसे कि भाषा मॉडल आधारित चैटजीपीटी, इंटरनेट पर अवधारणाओं को सारांशित करने से लेकर कविताओं, समाचार रिपोर्टों और यहां तक कि कोलंबियाई अदालत के फैसले की सेवा के लिए ढेर सारे कार्यों के लिए उपयोग एआई प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के लिए यूरोपीय संघ के सांसदों की योजनाओं में शामिल नहीं था।
- दो वर्ष पहले प्रकाशित एआई अधिनियम के लिए ब्लॉक के 108-पृष्ठ के प्रस्ताव में "चैटबॉट" शब्द का केवल एक उल्लेख शामिल था।
- जबकि वर्तमान मसौदे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ओपनएआई के चैटजीपीटी निर्माताओं जैसे सामान्य-उद्देश्य वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (जीपीएआईएस) किन दायित्वों के अधीन होंगे, कानून निर्माता इस बात पर भी बहस कर रहे हैं कि क्या जीपीएआईएस के सभी रूपों को उच्च जोखिम के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
- मसौदे के वास्तव में लागू होने से पहले इसमें कई बार संशोधन किया जा सकता है।

वैश्विक एआई अभिशासन वर्तमान में कहां खड़ा है?

एआई बिल ऑफ राइट्स (एआईबीओआर):

- यू.एस. में वर्तमान में व्यापक एआई विनियमन नहीं है और उसने काफी हद तक निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। बाइडेन प्रशासन ने एआई बिल ऑफ राइट्स (AIBoR) के लिए एक खाका जारी किया।
- व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी (OSTP) द्वारा विकसित, एआई बिल ऑफ राइट्स आर्थिक और नागरिक अधिकारों के लिए आईआई के नुकसान की रूपरेखा तैयार करता है और इन नुकसानों को कम करने के लिए पाँच सिद्धांत निर्धारित करता है।
- खाका, यूरोपीय संघ की तरह एक क्षैतिज दृष्टिकोण के बजाय, स्वास्थ्य, श्रम और शिक्षा जैसे व्यक्तिगत क्षेत्रों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के साथ एआई शासन के लिए एक क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण का समर्थन करता है, इसे क्षेत्रीय संघीय एजेंसियों को अपनी योजनाओं के साथ बाहर करने के लिए छोड़ देता है।.
- एआईबीओआर को प्रशासन द्वारा एक बाध्यकारी विधान के बजाय एक मार्गदर्शन या एक पुस्तिका के रूप में वर्णित किया गया है।

चीन द्वारा विनियम:

- चीन 2022 में विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले विश्व के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियमों के साथ सामने आया।
- इसने अनुशंसा एल्गोरिदम को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाया, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि वे सूचना का प्रसार किस प्रकार करते हैं। चीन के साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना (CAC), जिसने नियमों का मसौदा तैयार किया, ने कंपनियों को "सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने", "राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक सार्वजनिक हित को खतरे में डालने" और उपयोगकर्ताओं के वैध हितों को नुकसान पहुंचाने पर "स्पष्टीकरण देने" के लिए कहा।
- कानून का एक अन्य भाग डीप फेक उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली डीप सिंथेसिस तकनीक को लक्षित करता है।
- पारदर्शिता रखने और एल्गोरिद्म के काम करने के तरीके को समझने के लिए, चीन के एआई रेगुलेशन अथॉरिटी ने एल्गोरिद्म की एक रजिस्ट्री या डेटाबेस भी बनाया है, जहां डेवलपर्स को अपने एल्गोरिद्म, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले डेटा सेट की जानकारी और संभावित सुरक्षा जोखिमों को रजिस्टर करना होता है।

चीन ने पहली जीन-संपादित फसल सुरक्षा की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

➲ चीन ने जीन-संपादित सोयाबीन की सुरक्षा को मंजूरी दे दी है, यह एक फसल में प्रौद्योगिकी की अपनी पहली मंजूरी है, क्योंकि देश खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

विवरण:

➲ निजी स्वामित्व वाली शेडोंग शुनफेंग बायोटेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड द्वारा विकसित सोयाबीन में दो संशोधित जीन हैं, जो पौधे में स्वस्थ वसा ओलिक एसिड के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।

➲ आनुवंशिक संशोधन के विपरीत, जो एक पौधे में विदेशी जीन का परिचय देता है, जीन संपादन मौजूदा जीन को बदल देता है।

➲ तकनीक को जीएमओ की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है और चीन सहित कुछ देशों में इसे अधिक हल्के ढंग से विनियमित किया जाता है, जहां 2022 में जीन-संपादन पर नियम प्रकाशित किए गए थे।

आगामी फसलें:

➲ शुनफेंग जीन-संपादित फसलों के व्यावसायीकरण की मांग करने वाली चीन की पहली कंपनी होने का दावा करती है।

➲ कंपनी के एक प्रतिनिधि ने कहा, यह वर्तमान में लगभग 20 अन्य जीन-संपादित फसलों पर शोध कर रहा है, जिनमें उच्च उपज वाले चावल, गेहूं और मक्का, शाकनाशी प्रतिरोधी चावल और सोयाबीन और विटामिन सी युक्त सलाद शामिल हैं।

अन्य देशों में संभावना:

➲ संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित कंपनी कैलीक्स्ट (CLXT.O) ने एक उच्च ओलिक सोयाबीन भी विकसित किया है, जो एक स्वस्थ तेल का उत्पादन करता है जो 2019 में अमेरिका में स्वीकृत होने वाला पहला जीन-संपादित भोजन था।

➲ संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, जापान ने भी स्वस्थ टमाटर और तेजी से बढ़ने वाली मछलियों सहित जीन-संपादित खाद्य पदार्थों को मंजूरी दी है।

इसे क्यों पेश किया गया है?

➲ यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब प्रमुख अनाज निर्यातक यूक्रेन में व्यापार तनाव, अनियमित मौसम और युद्ध ने देश के 1.4 बिलियन लोगों को खिलाने पर चीन में चिंताओं को बढ़ा दिया है।

➲ बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग भी आहार संबंधी बीमारियों में उछाल का सामना कर रहा है।

आगे की राह:

➲ चीन जीएमओ फसलों को भी बढ़ावा दे रहा है और 2023 में बड़े पैमाने पर जीएम मकई का परीक्षण शुरू कर रहा है।

➲ हालांकि, नियामक प्रक्रिया में धीमे सुधार को देखते हुए, जीन-संपादित फसलों को बाजार में लाने की उम्मीद तेज है।

वैज्ञानिकों ने नई तरह की आणविक मोटर खोजा

चर्चा में क्यों?

➲ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (NCBS), बेंगलुरु सहित शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक नई तरह की आणविक मोटर की सूचना दी है।

➲ खोज जीव विज्ञान और चिकित्सा में पहले से अप्रत्याशित सेलुलर प्रक्रियाओं और संभावित अनुप्रयोगों के द्वार खोलती है।

आणविक मोटर्स की भूमिका:

➲ शरीर कीt प्रत्येक कोशिका विद्युत-रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक जटिल सूप है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं।

➲ कोशिकाओं को चीजों को स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे दो अंगों को एक साथ खींचना, सामान को केंद्रक की ओर और दूर ले जाना, तथा उपकोशिकीय अणुओं की गति को शक्ति देना। इनमें से कई क्रियाएं आणविक मोटर्स द्वारा संचालित होती हैं, जो यांत्रिक कार्य करने के लिए जैव रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं।

किस प्रकार EEA1 अपने कठोर आकार को फिर से प्राप्त करता है?

➲ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बताया था कि जब Rab5 नामक एक एंजाइम EEA1 नामक एक लंबे प्रोटीन से बंधता है, तो प्रोटीन अपना तना हुआ और कठोर आकार खो देता है और फ्लॉपी बन जाता है। यह 'पतन' एक कोशिका के अंदर दो झिल्लियों को एक दूसरे के करीब खींचता है।

➲ नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने बताया है कि EEA1 एक अन्य तंत्र में अपने कठोर आकार को पुनः प्राप्त करता है ताकि यह झिल्लियों को करीब लाने के लिए फिर से फ्लॉपी बन सके, एक नई तरह की दो-भाग आणविक मोटर का निर्माण कर सके।

➲ इससे पहले, यह स्पष्ट नहीं था कि EEA1 अपने कठोर आकार को फिर से शुरू कर सकता है या नहीं, ताकि पूरी प्रक्रिया अन्य प्रोटीनों की सहायता के बिना स्वयं को दोहरा सके।

➲ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि इसे अपने कठोर आकार को फिर से शुरू करना पड़ा क्योंकि EEA1 हजारों झिल्लियों पर काम करता है, और प्रत्येक झिल्ली जोड़ी के लिए प्रोटीन जितना बड़ा अणु बनाना व्यर्थ होगा। 200 एनएम से अधिक पर, ईईए सामान्य प्रोटीन से 100 गुना अधिक लंबा है।

जीटीपी हाइड्रोलिसिस:

➲ शोधकर्ताओं ने बताया कि EEA1 फिर से कठोर होने के लिए GTP हाइड्रोलिसिस नामक प्रतिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त करता है। GTP हाइड्रोलिसिस की मध्यस्थता GTPases नामक एंजाइम द्वारा की जाती है। Rab5 ऐसा ही एक है।

➲ मोटर लीवर जैसी आगे-पीछे की क्रिया उत्पन्न नहीं करती, जैसा कि अधिकांश मोटरें करती हैं, लेकिन एक अणु को दो अवस्थाओं के बीच अपने लचीलेपन को बदलने की अनुमति देती है। साथ ही, अधिकांश

आणविक मोटर्स एटीपी नामक एक अन्य अणु से अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जबकि रब5-ईईए1 मोटर जीटीपी का उपयोग करती है।

- EEA1 फ्लॉपी होने पर कई ट्रिलियन आकारों में से एक हो सकता है, लेकिन जब यह कठोर होता है तो इसका केवल एक (रॉड जैसा) आकार हो सकता है। फ्लॉपी अवस्था में अधिक एन्ट्रापी होती है और "एन्ट्रोपीली फेवरेट" होती है। इसलिए जब यह कठोर से फ्लॉपी की ओर जाता है, तो यह झिल्लियों पर एक एंट्रोपिक बल लगाता है जिसे यह खींचता है।

आगे की राह:

- EEA1 द्वारा मेम्ब्रेन फ्यूज़न पर प्रकाश डालने के अलावा, अध्ययन ऐसे कई मैकेनो-केमिकल प्रोटीन या असेंबली के लिए लागू एक सामान्य तंत्र भी प्रदान करता है जो सेल में यांत्रिक कार्य के लिए न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलिसिस की रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है।

ब्लूस्की नवीनतम माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म

सन्दर्भ:

- एलोन मस्क के अधिग्रहण के बाद से, ट्विटर लगातार खबरों में रहा है।
- हालांकि विकेन्द्रीकृत मास्टोडन एक शुरुआती दावेदार के रूप में उभरा, ब्लूस्की ट्विटर के सिंहासन के संभावित दावेदार के रूप में सामने आया है।

ब्लूस्की क्या है?

- ब्लूस्की एक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और एटी प्रोटोकॉल (ऑथेंटिकेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल) पर बनी सोशल वेबसाइट है।
- ब्लूस्की को इसकी संस्थापक टीम के कारण ट्विटर के प्रतियोगी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसकी संरचना के संदर्भ में यह अलग है, क्योंकि यह एक विकेन्द्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र का भाग बनने के लिए है।
- एटी प्रोटोकॉल पर बने ऐप्स के उपयोगकर्ता अपने फॉलोअर्स, मीडिया, काम और डेटा खोए बिना प्लेटफॉर्म के बीच आ-जा सकेंगे। यह खाता सुवाह्यता, जैसा कि सुविधा कहा जाता है, एटी प्रोटोकॉल की संरचना का एक प्रमुख भाग है।

ब्लूस्की के पीछे कौन है?

- ब्लूस्की के सीईओ जय गर्बर हैं, जो क्रिप्टोकरंसी की पृष्ठभूमि वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ब्लूस्की को 2019 में ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोरसी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए सुश्री ग्रेबर को चुना था।
- ट्विटर और ब्लूस्की अंततः एक दूसरे के साथ जुड़ने और काम करने के लिए बने थे, लेकिन कंपनियों ने 2022 में अपना सेवा समझौता समाप्त कर दिया।

क्या ब्लूस्की ट्विटर का स्थान ले सकता है?

- फिलहाल अभी नहीं क्योंकि ब्लूस्की वर्तमान में निजी बीटा में है, जिसका अर्थ है कि केवल एक चुनिंदा समूह को आमंत्रण कोड के माध्यम से शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसे आज़माने में रुचि रखने वाले अन्य लोग स्वयं को प्रतीक्षा सूची में जोड़ सकते हैं।
- नियमित ब्लूस्काई सदस्यों को समय-समय पर एक नया आमंत्रण कोड भी दिया जाता है जिसे वे नए आवेदकों के साथ साझा कर सकते हैं जिन्हें वे विश्वसनीय समझते हैं।

यह ब्लूस्की पर कैसा है?

- इसके सीईओ द्वारा रीट्वीट किए गए ब्लूस्की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट ट्विटर के समान एक यूजर इंटरफेस दिखाते हैं, जिसमें टिप्पणी, शेयर या "हार्ट" पोस्ट के विकल्प होते हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लूस्की पर प्रतिभागियों की संख्या कम होने के कारण सेलेब्रिटी उपयोगकर्ताओं को उनके ट्विटर प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में कम "लाइक" और "शेयर" दिखाई दे रहे हैं।
- प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं के पास अपने डोमेन को अपने हैंडल के रूप में सेट करने की क्षमता भी होती है, जिससे उनके खातों को पारिस्थितिक तंत्र में लिंक करना और उनकी पहचान को प्रमाणित करना आसान हो जाता है।
- जबकि ब्लूस्की का लक्ष्य एक अधिक विकेन्द्रीकृत संरचना प्राप्त करना है, वर्तमान में इसे एक आधिकारिक टीम द्वारा विनियमित किया जा रहा है और इसे एक ही सर्वर पर होस्ट किया जाता है।

यूके द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सफलता

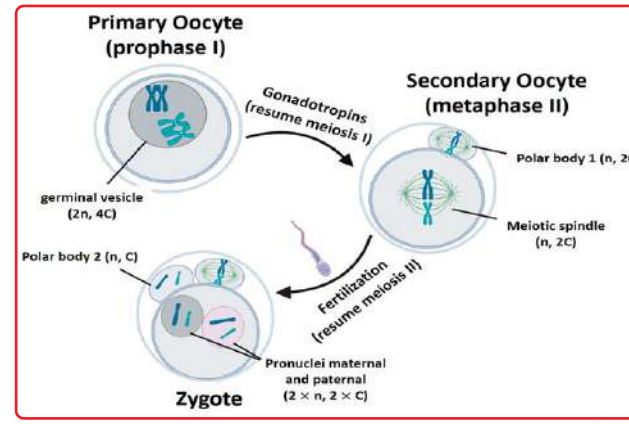

चर्चा में क्यों?

- माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) के रूप में जानी जाने वाली प्रजनन तकनीक को मंजूरी देने वाला यूके विश्व का पहला देश बनने के आठ वर्ष बाद, अप्रैल 2023 तक "पांच से कम" बच्चे इस प्रक्रिया का उपयोग करके पैदा हुए हैं।
- यूके फर्टिलिटी रेगुलेटर ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी (एचएफईए) ने हाल ही में इसकी पुष्टि की है।

- वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया इस थेरेपी को मंज़ूरी देने वाला दूसरा देश बन गया।

तीन माता-पिता आईवीएफ:

- माइटोकॉन्ड्रिया प्रतिस्थापन में मां के अंडे से परमाणु आनुवंशिक सामग्री को एक दाता अंडे में स्थानांतरित करना शामिल है जिसका परमाणु डीएनए हटा दिया गया है ताकि भ्रूण को माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी विरासत में न मिले।
- इससे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों से ग्रस्त महिला को स्वस्थ बच्चे जन्म देने में मदद मिलेगी। परिणामी आईवीएफ भ्रूण जैविक माता-पिता से शुक्राणु और अंडे को जोड़ता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया दाता के अंडे से होता है।
- इसके परिणामस्वरूप, बच्चे के पास अपने माता-पिता में से प्रत्येक के डीएनए के साथ-साथ दाता के 37 जीन होते हैं। यही वजह है कि इस तकनीक को थ्री-पैरेंट आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) भी कहा जाता है।

महत्त्व:

- माइटोकॉन्ड्रिया किसी कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी म्यूटेशन ऊर्जा की कमी वाले अंगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
- यू.के. में लगभग 6,500 शिशुओं में से एक माइटोकॉन्ड्रियल विकार के साथ जन्म लेते हैं, जिससे हृदय और यकृत रोग, और श्वसन संबंधी समस्याएं जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिससे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है।
- 2013 में, यह प्रक्रिया यू.के. में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लोगों की जान बचा सकती है।

माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट द्वारा एक बच्चे के तीन माता-पिता

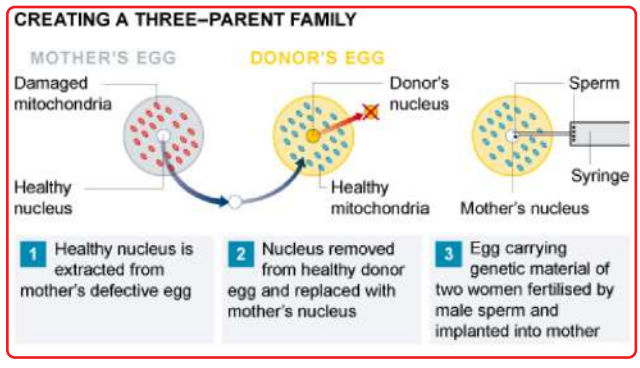

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, यू.के. में तीन व्यक्तियों के डीएनए का उपयोग करके एक बच्चे का जन्म हुआ।
- तकनीकी रूप से, इस बच्चे के तीन माता-पिता होते हैं, जैविक माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री (डीएनए) के अलावा एक दाता से माइटोकॉन्ड्रिया प्राप्त करते हैं। बच्चे को मां के माइटोकॉन्ड्रियल रोग को विरासत में लेने से रोकने के लिए, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए अग्रणी तकनीक का उपयोग किया गया था।

बच्चे को 'तीन माता-पिता' की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- बच्चे ने अपना अधिकांश डीएनए अपने माता-पिता से प्राप्त किया, और एक मामूली प्रतिशत दाता से, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया अंडे को निषेचित करते समय उपयोग किया गया है।
- माइटोकॉन्ड्रिया मूल रूप से कोशिकाओं के पावरहाउस हैं। वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार मानव शरीर में कोशिका कार्य के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।
- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके को प्रभावित करने वाले कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं (विशेष रूप से मस्तिष्क, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, गुर्दे, हृदय, यकृत के 'ऊर्जा-भूखे' ऊतकों में), और इस तरह सेल के कार्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाले रोगों को माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहा जाता है।
- जब माइटोकॉन्ड्रिया बिगड़ा हुआ होता है और पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, तो यह अंगों के कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है, जिससे पूरे शरीर में लक्षणों का एक व्यापक वर्गीकरण होता है, जिसमें मस्तिष्क क्षति, अंग विफलता और मांसपेशियों की क्षय शामिल है।
- बच्चे के बढ़ने के साथ-साथ लक्षण अधिक से अधिक कमजोर होते जाते हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। कुछ अनुमान माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों की घटनाओं को 5,000 लोगों में से एक के रूप में रखते हैं।
- इस मामले में, मां को माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी थी, वह अपने बच्चे को नहीं देना चाहती थी। वह डोनर एग भी नहीं चाहती थी, क्योंकि बच्चे में डोनर का जेनेटिक मैटेरियल होगा।

वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है?

- माइटोकॉन्ड्रियल रोग केवल मां द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, और अनुसंधान शिशु को विरासत में मिली बीमारी से बचाने का एक तरीका खोजने का प्रयास कर रहा है।
- यहां, न्यूकैसल फर्टिलिटी क्लिनिक द्वारा विकसित और परिष्कृत इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से, बच्चे के जैविक पिता के शुक्राणु का उपयोग जैविक मां के अंडों को निषेचित करने के लिए किया गया था, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी है, और तीसरी, अलग से स्पष्ट माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिला दाता।
- फिर, दाता के अंडे से केन्द्रक अनुवांशिक सामग्री को हटा दिया जाता है और जैविक माता-पिता की अनुवांशिक सामग्री के साथ बदल दिया जाता है।
- अंतिम उत्पाद जिसमें माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री (डीएनए) और महिला दाता से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, और एक बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी अवधि तक ले जाया जाता है जो मां के माइटोकॉन्ड्रियल रोग से मुक्त होगा। इस प्रक्रिया को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट (एमडीटी) कहा जाता है।

क्या एमडीटी को सुसाध्य बनाने के लिए कोई कानून है?

- एमडीटी पर शोध, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (एमआरटी) के रूप में भी जाना जाता है, यूके में न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टरों द्वारा उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रिया वाली महिलाओं को आनुवंशिक विकारों के जोखिम के बिना बच्चे को जन्म देने में सहायता करने के लिए किया गया था।

- शोध में हुई प्रगति ने यूके सरकार को 2015 में प्रक्रिया की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया। दो वर्ष बाद न्यूकैसल क्लिनिक इसे करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला केंद्र बन गया, और पहले कुछ मामलों को 2018 में मंजूरी दी गई।
- यू.के. के मानव निषेचन और भ्रूणविज्ञान प्राधिकरण (एचएफईए) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर स्वीकृति दी जाती है, जिसने कम से कम 30 मामलों को हरी झंडी दी है।
- 2016 में न्यू यॉर्क में न्यू होप फर्टिलिटी सेंटर में जॉन झांग के नेतृत्व वाली टीम द्वारा नियोजित एक तकनीक के साथ 'तीन माता-पिता' से जॉर्डन के एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन यह मेक्सिको में काम कर रहा था।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेनदेन मॉडल

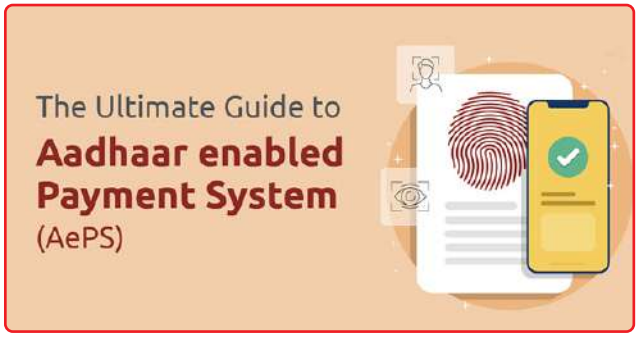

चर्चा में क्यों?

- साइबर अपराधी अब उपयोगकर्ताओं के बैंक खातों को निकालने के लिए बायोमेट्रिक पीओएस डिवाइस और बायोमेट्रिक एटीएम संचालित करने के लिए सिलिकॉन थम्स का उपयोग कर रहे हैं।

एईपीएस क्या है?

- आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) एक बैंक-आधारित मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) उपकरणों और माइक्रो एटीएम पर ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके द्वारा मॉडल ओटीपी, बैंक खाते और अन्य वित्तीय विवरणों की आवश्यकता को हटा देता है।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अनुसार, यह केवल बैंक नाम, आधार संख्या, और आधार नामांकन के दौरान कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट का उपयोग करके धन हस्तांतरण की अनुमति प्रदान करता है।

क्या एईपीएस डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है?

- इस संदर्भ में न तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और न ही एनपीसीआई स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि एईपीएस डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है या नहीं।
- सेवा के लिए किसी सक्रियता की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता यह है कि उपयोगकर्ता का बैंक खाता उनके आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए।
- जो उपयोगकर्ता आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से बैंकिंग सेवा प्रदाता को अपना आधार नंबर जमा करना होगा।

बायोमेट्रिक जानकारी कैसे लीक होती है?

- जबकि 2018, 2019 और 2022 में आधार डेटा उल्लंघनों की सूचना मिली है, यूआईडीएआई ने डेटा के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया है। हालाँकि, UIDAI का डेटाबेस एकमात्र स्रोत नहीं है जहाँ से डेटा लीक किया जा सकता है।
- आधार संख्या फोटोकॉपी, और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आसानी से उपलब्ध हैं, और अपराधी उपयोगकर्ता जानकारी का उल्लंघन करने के लिए आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
- स्कैमर्स ने अतीत में, लेन-देन शुरू करने के लिए उपकरणों को धोखा देने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया है।

आप अपनी आधार बायोमेट्रिक जानकारी को किस प्रकार सुरक्षित करते हैं?

- यूआईडीएआई आधार (सूचना का साझाकरण) विनियम, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव कर रहा है, जिसके लिए आधार संख्या रखने वाली संस्थाओं को विवरण साझा नहीं करने की आवश्यकता होगी, जब तक कि आधार संख्या को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में उचित माध्यम से संशोधित या ब्लैक आउट नहीं किया गया हो। यूआईडीएआई ने एक नया टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी लागू किया है जो मशीन-लर्निंग-आधारित सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है, फिंगरप्रिंट की 'जीवंतता' की जांच करने के लिए फिंगर मिन्यूटी और फिंगर इमेज कैप्चर का संयोजन करता है।
- इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर या मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपनी आधार जानकारी को लॉक करना सुनिश्चित करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी बायोमेट्रिक जानकारी, भले ही छेड़छाड़ की गई हो, का उपयोग वित्तीय लेनदेन शुरू करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने पर इसे अनलॉक किया जा सकता है, जैसे संपत्ति पंजीकरण और पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए, जिसके बाद इसे फिर से लॉक किया जा सकता है।

आधार का उपयोग कर वित्तीय घोटाले के मामले में क्या किया जा सकता है?

- यदि उपयोगकर्ताओं ने अपने आधार बायोमेट्रिक जानकारी को पहले से लॉक नहीं किया है, तो उन्हें अपने बैंक खातों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के मामले में तुरंत ऐसा करना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने बैंकों और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। समय पर रिपोर्ट करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि धोखाधड़ी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया कोई भी धन पीड़ित को वापस कर दिया जाए।
- आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि अनधिकृत लेन-देन होने पर ग्राहक शून्य देयता का हकदार होता है, और ग्राहक ऐसे अनधिकृत लेनदेन के संबंध में बैंक से एक संचार प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है।

मशीन लर्निंग मॉडल

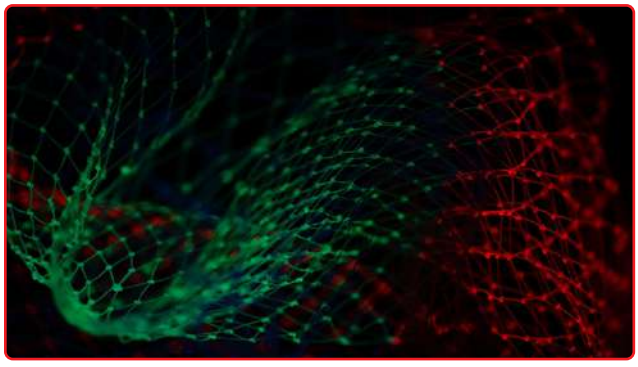

चर्चा में क्यों?

- मशीन लर्निंग (एमएल), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपक्षेत्र है, जो कंप्यूटर को इनपुट और वांछित आउटपुट के उदाहरण प्रदान करके संरचित डेटा, भाषा, ऑडियो या छवियों के आधार पर कार्यों को हल करना सिखाता है।
- यह पारंपरिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से अलग है, जहां प्रोग्रामर विशिष्ट निर्देशों का क्रम लिखते हैं। यहां, एमएल मॉडल अपने कई नॉब्स को पैरामीटर नामक समायोजन करके वांछनीय आउटपुट उत्पन्न करना सीखता है।

गहरे तंत्रिका नेटवर्क:

- 2010 के पहले भाग में, डीप न्यूरल नेटवर्क्स (DNNs) ने हाथ से तैयार की गई सुविधाओं और सरल क्लासिफायर की क्लासिक पाइपलाइन की जगह, एमएल पर तेजी से कब्जा कर लिया। डीएनएन एक संपूर्ण दस्तावेज़ या छवि को ग्रहण करते हैं और सुविधाओं को निकालने का एक विशेष तरीका निर्दिष्ट करने की आवश्यकता के बिना, एक अंतिम आउटपुट उत्पन्न करते हैं।
- जबकि ये गहरे और बड़े मॉडल अतीत में मौजूद थे, उनके बड़े आकार ने उनके उपयोग में बाधा डाली। 2010 के दशक में डीएनएन के पुनरुत्थान को बड़े पैमाने पर डेटा की उपलब्धता और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट नामक तेज़ समानांतर कंप्यूटिंग चिप्स के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।
- इसके अलावा, पाठ या छवियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल अभी भी अलग थे - आवर्तक तंत्रिका नेटवर्क भाषा की समझ में लोकप्रिय थे जबकि दृढ़ तंत्रिका नेटवर्क (सीएनएन) कंप्यूटर दृष्टि में लोकप्रिय थे, अर्थात् दृश्य विश्व की एक मशीन समझ।

ट्रांसफार्मर की उत्पत्ति:

- 2017 में प्रकाशित 'अटेंशन इज़ ऑल यू नीड' नामक एक अग्रणी पेपर में, गूगल की एक टीम ने ट्रांसफॉर्मर, एक डीएनएन आर्किटेक्चर प्रस्तावित किया, जिसने आज सभी तौर-तरीकों (छवि, ऑडियो और भाषा) में लोकप्रियता हासिल की है।
- मूल पेपर में एक वाक्य को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के कार्य के लिए ट्रांसफॉर्मर प्रस्तावित किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे गूगल अनुवाद एक वाक्य को अंग्रेजी से हिंदी में परिवर्तित करते समय करता है।

ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है?

- ट्रांसफॉर्मर दो भागों वाला न्यूरल नेटवर्क है। पहला भाग एक 'एनकोडर' है जो स्रोत भाषा (अंग्रेजी) में इनपुट वाक्य को समाहित करता है और दूसरा भाग एक 'डिकोडर' है जो लक्ष्य भाषा (हिंदी) में अनुवादित वाक्य उत्पन्न करता है।
- एन्कोडर प्रत्येक शब्द को स्रोत वाक्य में एक अमूर्त संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करता है जो शब्द के अर्थ को वाक्य के संदर्भ में कैप्चर करता है, और इसे मेमोरी बैंक में संग्रहीत करता है।
- ये दोनों प्रक्रियाएं 'ध्यान' नामक एक तंत्र का उपयोग करती हैं, इसलिए कागज का नाम। पिछले तरीकों में एक महत्वपूर्ण सुधार लंबे वाक्यों या पैराग्राफों का सही ढंग से अनुवाद करने के लिए ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है। ट्रांसफॉर्मर को अपनाने के बाद विस्फोट हो गया।
- उदाहरण के लिए, चैटजीपीटी में कैपिटल 'टी' का मतलब 'ट्रांसफॉर्मर' है।
- कंप्यूटर दृष्टि में ट्रांसफॉर्मर भी लोकप्रिय हो गए हैं क्योंकि वे एक छवि को छोटे चौकोर पैच में काटते हैं और उन्हें एक वाक्य में शब्दों की तरह पंक्तिबद्ध करते हैं। ऐसा करके, और बड़ी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षण के बाद, एक ट्रांसफॉर्मर सीएनएन से बेहतर परिणाम प्रदान कर सकता है।
- आज, ट्रांसफॉर्मर मॉडल इमेज वर्गीकरण, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन, एक्शन रिकॉग्निशन और कई अन्य कार्यों के लिए सबसे अच्छा तरीका है।

'अटेंशन' क्या है?

- एमएल में अटेंशन एक मॉडल को यह सीखने की अनुमति देता है कि विभिन्न इनपुट्स को कितना महत्व दिया जाना चाहिए।
- अनुवाद उदाहरण में, ध्यान मॉडल को स्मृति बैंक से शब्दों का चयन करने या तौलने की अनुमति देता है, जब यह तय करना होता है कि कौन सा शब्द अगला उत्पन्न करना है। एक छवि का वर्णन करते समय, अगला शब्द उत्पन्न करते समय ध्यान मॉडल को छवि के प्रासंगिक भागों को देखने की अनुमति देता है।
- ध्यान-आधारित मॉडलों का एक आकर्षक पहलू बहुत सारे डेटा को पार्स करके स्वयं को खोजने की उनकी क्षमता है।
- ट्रांसफॉर्मर स्टेरॉयड पर ध्यान देने वाले मॉडल हैं। वे एनकोडर के भीतर, इनपुट वाक्य या छवि में सार्थक संदर्भ प्रदान करने के लिए, और डिकोडर से एनकोडर तक अनुवादित वाक्य उत्पन्न करते समय या किसी छवि का वर्णन करते हुए, दोनों में कई ध्यान परतें रखते हैं।

ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग:

- 2022 से, ट्रांसफ़ॉर्मर मॉडल बड़े हो गए हैं और पहले की तुलना में अधिक डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं। जब ये कॉलोज़स लिखित पाठ पर प्रशिक्षित होते हैं, तो उन्हें बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) कहा जाता है। ChatGPT सैकड़ों अरबों मापदंडों का उपयोग करता है जबकि GPT-4 सैकड़ों खरबों का उपयोग करता है।
- जबकि इन मॉडलों को सरल कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि रिक्त स्थानों को भरना या अगले शब्द की भविष्यवाणी करना, वे सवालों के जवाब देने, कहानियां बनाने, दस्तावेज़ों को सारांशित करने, कोड लिखने और यहां तक कि गणितीय शब्द समस्याओं को चरणों में हल करने में बहुत अच्छे हैं।

प्रयोजन:

- वैज्ञानिक समुदाय को अभी यह पता लगाना है कि इन मॉडलों का कठोरता से मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। "मतिभ्रम" के उदाहरण भी हैं, जिससे मॉडल आत्मविश्वासी लेकिन गलत दावे करते हैं।
- डेटा की निजता और रचनात्मक कार्यों को श्रेय देने जैसी सामाजिक चिंताओं को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है, जो उनके उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

रेडियोमेट्रिक डेटिंग में कैल्शियम 41 की स्वीकार्यता

सन्दर्भ:

- यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ़ चाइना (USTC) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में, हेफ़ेई ने कैल्शियम-41 का उसी तरह उपयोग करने का तरीका दर्शाया है जिस तरह कार्बन-डेटिंग में कार्बन-14 का उपयोग किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- 1947 में अपने आविष्कार के बाद से, कार्बन डेटिंग ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे वैज्ञानिकों को कार्बन-14 की मात्रा के आधार पर जैविक सामग्री की आयु का अनुमान लगाने की अनुमति प्रदान की है।
- हालांकि, कार्बन-14 का आधा जीवन 5,700 वर्ष है, इसलिए तकनीक लगभग 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु निर्धारित नहीं कर सकती है।

कैल्शियम-41:

- 1979 में, वैज्ञानिकों ने 99,400 वर्षों के अर्ध-जीवन के साथ कैल्शियम-41 का उपयोग करने का सुझाव दिया। यह तब उत्पन्न होता है जब अंतरिक्ष से ब्रह्मांडीय किरणें मृदा में कैल्शियम परमाणुओं में टकराती हैं, और पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाती हैं, जो जीवाश्म हड्डियों और चट्टान के डेटिंग का द्वार खोलती हैं। लेकिन इससे पहले कि वस्तुओं को मज़बूती से दिनांकित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, कई समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है।
- जब कोई जैविक इकाई जीवित होती है, तो उसका शरीर कार्बन-14 परमाणुओं को अवशोषित और खोता रहता है। जब यह मर जाता है, तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है और मौजूदा कार्बन-14 का क्षय होने लगता है।
- शरीर में इन परमाणुओं की आपेक्षिक प्रचुरता और संख्या जो वहां होनी चाहिए थी, के बीच के अंतर का उपयोग करके, शोधकर्ता अनुमान लगा सकते हैं कि इकाई की मृत्यु कब हुई थी।
- कार्बन डेटिंग के साथ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक मुद्दा कार्बन-14 परमाणुओं का पता लगाना था, जो लगभग 1,012 कार्बन परमाणुओं में एक बार होता है। कैल्शियम -41 दुर्लभ है, लगभग 1,015 कैल्शियम परमाणुओं में एक बार होता है।

एटीटीए:

- नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने एक समाधान के रूप में एटम-ट्रैप ट्रेस विश्लेषण (एटीटीए) नामक एक तकनीक प्रस्तुत की।
- एटीटीए इन परमाणुओं का पता लगाने के लिए काफी संवेदनशील है; इतना विशिष्ट कि वे अन्य समान परमाणुओं के लिए भ्रमित न हों और एक टेबलटॉप पर फिट हो जाएं।
- एक नमूने को ओवन में वाष्पीकृत किया जाता है। वाष्प में परमाणु लेजर-ठंडा होते हैं और प्रकाश और चुंबकीय क्षेत्र से बने पिंजरे में लोड होते हैं। एक परमाणु में, एक कक्षीय में एक इलेक्ट्रॉन अगले में संक्रमण कर सकता है यदि उसे एक विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा दी जाती है; फिर वह उस ऊर्जा को मुक्त करके वापस छलांग लगाता है।

इलेक्ट्रॉन संक्रमण:

- एटीटीए में, एक लेज़र की आवृत्ति को इस तरह ट्यून किया जाता है कि यह कैल्शियम-41 में एक इलेक्ट्रॉन संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है।
- इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित और छोड़ते हैं, जिससे उनके परमाणुओं की उपस्थिति का पता चलता है। शोधकर्ताओं ने समुद्री जल में 12% सटीकता के साथ प्रत्येक 1,016 कैल्शियम परमाणुओं में एक कैल्शियम -41 परमाणु को खोजने में सक्षम होने की सूचना दी।
- एटीटीए पोटेशियम-41 परमाणुओं से भी बचा जाता है, जो कैल्शियम-41 परमाणुओं के समान होते हैं लेकिन समान इलेक्ट्रॉन संक्रमण की कमी होती है।

आगे की राह:

- शोधकर्ता वर्तमान में एक पृथ्वी-विज्ञान अनुप्रयोग की खोज कर रहे हैं। गर्म जलवायु में, ग्लेशियर पीछे हट जाते हैं और नीचे की चट्टान को कैल्शियम -41 जमा करने देते हैं। ठंडी जलवायु में, हिमनद आगे बढ़ते हैं और कैल्शियम-41 को चट्टान तक पहुँचने से रोकते हैं।
- इस तरह, वैज्ञानिक एटीटीए का उपयोग करके यह अध्ययन करने की उम्मीद करते हैं कि कोई चट्टान कितनी देर तक बर्फ से ढकी रही।

स्पेसएक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा निजी मिशन लॉन्च

चर्चा में क्यों?

- स्पेसएक्स ने हाल ही में एक्सिऑम स्पेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए दूसरा निजी मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

विवरण:

- चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से उड़ान भरी।
- अंतरिक्ष यान दो सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में ले गया, जिसमें दो अन्य लोगों के साथ देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री शामिल थीं।

- सऊदी अरब साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कमांडर पैगी व्हिटसन, पायलट जॉन शॉफनर, और मिशन विशेषज्ञ अली अलकर्नी और रेयानाह बरनावी को अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ये चारों एक निजी एयरोस्पेस कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा परिकल्पित वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।
- वे विज्ञान, आउटरीच और व्यावसायिक गतिविधियों के पूर्ण प्रकटन को लागू करने के लिए परिक्रमा प्रयोगशाला में काम करेंगे और रहेंगे।
- शून्य-गुरुत्वाकर्षण प्रयोगशाला में रहने के दौरान, वे यह अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग करेंगे कि माइक्रोग्रैविटी स्टेम सेल और मोटे ऊतक के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती है।
- उनके काम का उद्देश्य बीमारियों का पता लगाना और पृथ्वी पर लोगों के लिए उपचार विकसित करना है। चार सदस्यीय टीम आईएसएस पर करीब 20 प्रयोग करने के लिए तैयार है।

पृष्ठभूमि:

- चार अंतरिक्ष यात्री तीन रूसी, तीन अमेरिकी और अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल-नेयादी के साथ शामिल होंगे, जो अप्रैल 2023 में स्पेसवॉक पर जाने वाले पहले अरब नागरिक हैं।
- अक्सिओम स्पेस ने अप्रैल 2022 में आईएसएस के लिए अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन पूरा किया, जिसमें तीन व्यवसायियों और पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइकल लोपेज़-एलेग्रिया को Ax-1 के भाग के रूप में कक्षा में 17 दिन बिताने के लिए भेजा गया।

निजी अंतरिक्ष स्टेशन:

- एक्सिओम स्पेस के लिए, ये मिशन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर पहला कदम है: अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, जिसके पहले मॉड्यूल के 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
- अलग होने और स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करने से पहले स्टेशन को सबसे पहले आईएसएस से जोड़ा जाएगा।
- नासा ने 2030 के आसपास आईएसएस को सेवानिवृत्त करने और इसके बजाय अंतरिक्ष यात्रियों को निजी स्टेशनों पर भेजने की योजना बनाई है, जो अपने स्वयं के ग्राहकों की मेजबानी भी करेगा, जिससे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कई कंपनियों द्वारा कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
- रूस ने हाल ही में 2028 तक आईएसएस के अपने उपयोग का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने पिछले वर्ष यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण को लेकर क्रेमलिन और पश्चिम के बीच संबंधों के टूटने की धमकी दी थी।
- अन्य अंतरराष्ट्रीय भागीदार; जापान, कनाडा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्वयं को 2030 तक संचालन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

पर्यावरण

भारत एवं चीन ने कार्बन ट्रांजिशन का रोडमैप पेश किया

चर्चा में क्यों?

- भारत, चीन द्वारा समर्थित, जी20 समूह के भीतर एक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि देशों को जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करने के बजाय कार्बन उत्सर्जन में कटौती का रोडमैप चुनने दिया जा सके।

विभिन्न मार्ग:

- भारत सितंबर में एक समूह शिखर सम्मेलन में जारी होने वाली विज्ञप्ति में 'मल्टीपल एनर्जी पाथवे' वाक्यांश को शामिल करने का इच्छुक है और चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया है।
- शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर योजनाओं की दिशा में काम करते हुए, ऊर्जा परिवर्तन के लिए कई रास्ते देशों को संसाधनों, यहां तक कि कोयले का चयन करने में सक्षम बनाएंगे।
- यह मुहावरा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2015 के पेरिस समझौते के अनुरूप है जो "विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों में आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों" का समर्थन करता है।

चरणबद्ध कोयले का उपयोग:

- गुजरात में जी20 एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप (ETWG) की बैठक में, भारत ने अमीर देशों द्वारा कोयले के उपयोग को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित एक समय सीमा का विरोध किया।
- भारत के वार्षिक बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग तीन-चौथाई है और भारत ने अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन का हवाला देते हुए लंबे समय से ईंधन के अपने उपयोग का बचाव किया है।
- चीन ने बैठक के दौरान भारत का समर्थन करते हुए कहा कि वह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है और अपने 'सभी' संसाधनों को इष्टतम उपयोग के लिए रखना चाहता है। दोनों देश दुनिया में कोयले के शीर्ष दो उपभोक्ता हैं।

- सात अमीर देशों के समूह (G7) के जलवायु मंत्रियों ने हाल ही में बेरोकटोक जीवाश्म ईंधन के चरण-समाप्ति में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की ताकि नवीनतम स्तर पर 2050 तक ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य प्राप्त किया जा सके।

पृष्ठभूमि:

- नवंबर 2022 में मिस्र में हुए पिछले जलवायु परिवर्तन विचार-विमर्श में कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के आह्वान का सामना करते हुए, भारत ने कहा कि प्राकृतिक गैस सहित सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। हाल ही में हुई जी20 बैठक में, भारत ने कोयले को अलग करने के बजाय जीवाश्म ईंधन पर ध्यान केंद्रित रखा।
- भारत और चीन, विश्व के दो सबसे अधिक जनसँख्या वाले देश, लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों के बावजूद, अक्सर अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में आम स्थिति लेते हैं।
- मार्च में, यूरोपीय संघ नवंबर में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन से पहले एक वैश्विक जीवाश्म ईंधन चरण को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ।

आगे क्या होगा?

- भारत सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- जी20 में अन्य देशों के साथ-साथ जी7 देशों के साथ-साथ रूस, चीन, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब शामिल हैं।

पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के कुछ प्रमुख बिन्दु

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2-3 मई, 2023 को बर्लिन में आयोजित किया गया।

विवरण:

- इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन (COP28) की मेजबानी कर रहे हैं।
- सीओपी28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र संदेश:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने "अर्थव्यवस्थाओं की सफाई; 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पाथवे प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधन की आदत को छोड़ने और हर क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
- उन्होंने ऐक्सेलरैशन एजेंडा के लिए अपने पहले के आह्वान को भी दोहराया, जहां "सभी देश अपनी नेट जीरो डेडलाइन पर तेजी से आगे बढ़ते हैं"।
- एजेंडा में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सदस्य देशों में 2030 तक और 2040 तक अन्य सभी में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, साथ ही शुद्ध शून्य बिजली उत्पादन प्राप्त करने और प्रमुख क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने का आह्वान करता है।

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

वैश्विक नवीकरणीय लक्ष्य

- जर्मन विदेश मंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए विश्व को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज कटौती करने की आवश्यकता है। उन्होंने अगले जलवायु सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित वैश्विक लक्ष्य के बारे में भी चर्चा शुरू की।
- जी7 ने पवन और सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जी7 में जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

जीवाश्म ईंधन: चरणबद्ध उत्पादन या उत्सर्जन कम करना?

- सीओपी28 के मनोनीत अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रतिभागियों से मुलाकात करने का आह्वान किया।
- उन्होंने 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और उसके बाद 2040 में दोगुना करने का आह्वान किया, लेकिन उनका संबोधन जीवाश्म ईंधन 'उत्सर्जन' को कम करने पर केंद्रित था।

$100 बिलियन जलवायु वित्त के मार्ग पर

- विकसित देश 2009 में सीओपी15 के दौरान 2020 तक 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष देने के लिए "सही मार्ग" पर हैं।
- एक हालिया अनुमान के अनुसार केवल उभरते बाजारों के लिए 2030 तक जलवायु वित्त की आवश्यकता $1 ट्रिलियन प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि जलवायु वित्त की जरूरत उस राशि से 10 गुना से अधिक है, जो विकसित देश 100 अरब डॉलर के आंकड़े के लिए प्रतिबद्ध होने के 14 वर्ष बाद जुटा पाए हैं।
- हालांकि 2023 में $100 बिलियन के संकल्प को पूरा किया जा सकता था, लेकिन अब जरूरतें बढ़ गई हैं। यह वित्तीय क्षतिपूर्ति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

ग्लोबल स्टॉकटेक:

- वर्ष 2023 ग्लोबल स्टॉकटेक का वर्ष है, जो अनिवार्य रूप से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की एक आवधिक समीक्षा है जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या मौजूदा प्रयास पेरिस समझौते में निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
- 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से यह पहला वैश्विक स्टॉकटेक वर्ष है और पिछले दो वर्षों से रिपोर्ट पर काम चल रहा है। यह 2023 के सितंबर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

- पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के परिणाम को टिकाऊ जीवन शैली के साथ-साथ टिकाऊ खपत पर एक संदेश देना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अगले दौर को सूचित किया जा सके।

क्या भूमि पुनर्स्थापन पृथ्वी की सुरक्षा कर सकता है?

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में बताया गया है कि मनुष्यों ने नौ ग्रहों की सीमाओं में से चार का उल्लंघन किया है।
- यह संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) और उसके सहयोगियों द्वारा तैयार किया गया था और परिमित भूमि संसाधनों की कमी और दुनिया की भूमि को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है।

ग्रहों की सीमाएं क्या हैं?

- ग्रहों की सीमाएं पर्यावरणीय सीमाओं की सीमाएं हैं जो "मानवता के लिए सुरक्षित परिचालन स्थान" को परिभाषित करती हैं। नौ ग्रहों की सीमाएं हैं:
  1. जैव विविधता की हानि
  2. भूमि-उपयोग परिवर्तन
  3. जलवायु परिवर्तन
  4. नाइट्रोजन और फास्फोरस (भू-रासायनिक) चक्र
  5. मीठे पानी का उपयोग
  6. महासागर अम्लीकरण
  7. रासायनिक प्रदूषण
  8. वायुमंडलीय लोडिंग
  9. ओजोन रिक्तीकरण
- इनमें से, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, भूमि-उपयोग परिवर्तन और भू-रासायनिक चक्र पहले ही पार हो चुके हैं।
- ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, ये उल्लंघन सीधे मानव-प्रेरित मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से जुड़े हुए हैं।

क्या भूमि बहाली पृथ्वी की मदद कर सकती है?

- रिपोर्ट भूमि बहाली को "ऐसी गतिविधियों की निरंतरता के रूप में परिभाषित करती है जो मानवीय जरूरतों को पूरा करने और जीवमंडल प्रबंधन में सुधार के स्पष्ट उद्देश्य के साथ भूमि क्षरण को टालती है, कम करती है और उलट देती है"।
- इन गिरावट से बचने का मतलब उन प्रथाओं को खत्म करना है जो पर्यावरण को खराब करते हैं, भूमि और पारिस्थितिक तंत्र रूपांतरण से लेकर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं तक।
- इसके द्वारा स्थायी भूमि और जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है, जबकि भूमि क्षरण को उलटने के लिए मिट्टी, वाटरशेड और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अन्य तत्वों को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ आजीविका में सुधार करना और ग्रह पर सभी जीवन रूपों को बनाए रखने के अंतिम लक्ष्य के साथ, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करना।
- यह भूमि जैव विविधता के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के बीच की क्रियात्मक कड़ी है, जिसका अर्थ है कि परस्पर जुड़े संकटों को हल करने के लिए भूमि को पुनर्स्थापित करना महत्वपूर्ण है।

भू-निम्नीकरण तटस्थता:

- विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी भूमि बहाली, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के साथ मिलकर, वर्तमान संकटों से उबरने और एक न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है।
- इसके सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए भूमि बहाली की वैश्विक वार्षिक लागत 2030 तक कम से कम $300 बिलियन होने की उम्मीद है। बहाली गतिविधियों में निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर के आर्थिक लाभ में $7 और $30 के बीच वापसी का अनुमान लगाया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा का मानना है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए 'भूमि क्षरण तटस्थता' प्राप्त करना एक प्रभावी तरीका है।
- यूएनसीसीडी 'भूमि निम्नीकरण तटस्थता' को "एक राज्य के रूप में परिभाषित करता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों और सेवाओं का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक भूमि संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता स्थिर रहती है या निर्दिष्ट अस्थायी और स्थानिक पैमाने और पारिस्थितिक तंत्र में वृद्धि होती है"।

खाद्य प्रणाली और भूमि क्षरण:

- कृषि ने पृथ्वी को किसी भी अन्य मानव गतिविधि से अधिक प्रभावित किया है।
- यह न केवल खाद्य फसलों को उगाने का अभ्यास है, बल्कि पशु चारा के उत्पादन, मिट्टी और पानी की गिरावट, वन भूमि की हानि, और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखने जैसी संबंधित गतिविधियां भी हैं जो उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ती हैं।
- दुनिया भर में, खाद्य प्रणालियां 80% वनों की कटाई और 70% मीठे पानी के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं, और स्थलीय जैव विविधता के नुकसान का एकमात्र सबसे बड़ा कारण हैं। खतरे यहीं खत्म नहीं होते।
- भू-क्षरण, मरुस्थलीकरण, और सूखा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। हमारी कृषि पद्धतियों के भीतर दीर्घकालिक स्वस्थ प्रथाओं और उत्पादकता को बहाल करना वैश्विक खाद्य प्रणालियों में स्थिरता पर स्विच करने की कुंजी होगी।

भूमि बहाली हासिल करना:

- ज्यादातर मामलों में, भूमि बहाली गतिविधियां वही होती हैं जो भविष्य की भूमि चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे सूखे से निपटना, मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करना आदि।

- बाढ़, सूखा और जंगल की आग कुछ सामान्य पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं जो भूमि को खराब करती हैं।
- एकीकृत भूमि उपयोग योजना; भूमि उपयोग के सर्वोत्तम संयोजन की पहचान करना, जबकि दोनों हितधारकों की जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करना और साथ ही भूमि संसाधनों को संरक्षित करना भूमि क्षरण को दूर करने का एक कुशल तरीका है।
- लाभ को अधिकतम करते हुए भू-दृश्यों की पहचान करना लागत-प्रभावी दृष्टिकोण है, जैसे कि वैश्विक पुनर्स्थापन हॉटस्पॉट में।
- पुनर्योजी कृषि पद्धतियां, जैसे छत पर खेती और वर्षा जल संचयन, भूमि को बहाल करने में मदद करती हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए और वायुमंडलीय कार्बन को अलग करते हुए संभावित रूप से फसल की पैदावार बढ़ा सकती हैं। वे सार्थक आजीविका भी सृजित करते हैं, आय बढ़ाते हैं और स्वस्थ जलवायु में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।

आगे की राह:

- भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने और सूखा, बाढ़ आदि जैसी आपदाओं के पैमाने और आवृत्ति को कम करने में मदद मिलेगी।
- रिपोर्ट के अनुसार स्थायी भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं में बदलाव की सुविधा के लिए समावेशी और जिम्मेदार प्रशासन भी महत्वपूर्ण है।
- यह भूमि बहाली को एक साझा जिम्मेदारी के रूप में चित्रित करता है, और यह कि सरकारों, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है जो भूमि उपयोग प्रणालियों को बदल दें।

पश्चिमी घाट उत्तर-दक्षिण प्रजातियों में जैव-भौगोलिक विभाजन

सन्दर्भ:

- पालघाट दर्रा जो लगभग 40 किमी चौड़ा है, जिसे प्रायः पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण विच्छिन्नता के रूप में जाना जाता है, जिसमें खड़ी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, और दोनों के दोनों समुद्र तल से 2,000 मी ऊपर ऊठी हुई हैं।

पालघाट दर्रा का महत्व:

- पालघाट गैप ऐतिहासिक रूप से केरल राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में है।
- यह सड़क और रेलवे दोनों के लिए एक गलियारा है जो कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। भरथप्पुझा नदी इसके माध्यम से होकर बहती है।
- पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के विपरीत, पालघाट दर्रा में वनस्पति को शुष्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों में विभाजन को भी चिह्नित करता है। उदाहरण के लिए पालघाट दर्रा के केवल एक तरफ मेंढकों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

उत्पति:

- यह दर्रा एक भूगर्भीय अपरूपण क्षेत्र है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। शियर जोन पृथ्वी की पपड़ी में कमजोर क्षेत्र हैं, यही कारण है कि कोयम्बटूर में कभी-कभी झटके महसूस किए जाते हैं।
- इस पालघाट दर्रा की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के गोंडवाना भूभाग से अलग होने के बाद महाद्वीपीय तल के बहाव/विस्थापन से भी हुई है।
- भारत और मेडागास्कर तब तक एक भूभाग के रूप में बने रहे जब तक कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखीय गतिविधि ने दोनों को विभाजित नहीं किया, विभाजन जहां पालघाट दर्रा स्थित है, यह मेडागास्कर के पूर्वी किनारे पर रानोत्सरा दर्रा में दिखाई देता है।
- भूभाग लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले विभाजित हो गया था, और इससे पहले दर्रा बन गया था; हालांकि कितनी समय पहले यह इस पर विवाद है।

बायोग्राफिकल विभाजन:

- यह अनुमान लगाया जाता है कि दर्रा के उत्तर और दक्षिण में प्रजातियों में जैव-भौगोलिक विभेद का एक कारण एक प्राचीन नदी या सुदूर अतीत में समुद्र का आक्रमण हो सकता है।
- नीलगिरी की तरफ हाथियों की आबादी उनके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अन्नामलाई और पेरियार अभयारण्यों में हाथियों से भिन्न होती है।
- आईआईएससी बैंगलोर के एक अध्ययन ने व्हाइट-बेल्ड शॉर्टविंग, एक स्थानिक और संकटग्रस्त पक्षी की आबादी में डीएनए अनुक्रम विचलन डेटा का विश्लेषण किया है।
- ऊटी और बाबा बुदान के आसपास पाए जाने वाले पक्षियों को नीलगिरी ब्लू रॉबिन कहा जाता है; अन्नामलाई समूह दिखने में थोड़ा अलग है, और इसे व्हाइट-बेल्ड ब्लू रॉबिन कहा जाता है।

दर्रा के दक्षिण:

- किसी क्षेत्र की जैव विविधता को दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है: प्रजातियों की समृद्धि, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या से संबंधित है, और जातिवृत्तीय विविधता, जहां पाई जाने वाली सभी प्रजातियों की विकासवादी आयु को जोड़ा जाता है।
- ये दोनों लक्षण पालघाट दर्रा के दक्षिण में पश्चिमी घाट में प्रचुर मात्रा में हैं, जैसा कि हैदराबाद और अन्य संस्थानों में सीसीएमबी के समूहों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है।
- यहाँ पेड़ों की 450 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जिनमें मैगनोलिया चम्पाका (चंपा; तमिल: सम्बागान) जैसी कुछ प्रजातियाँ शामिल हैं, जो लगभग 130 मिलियन वर्षों से अधिक समय से हैं।

मौसम:

- भूमध्य रेखा से निकटता के कारण गर्म मौसम, और नम हवा दक्षिणी पश्चिमी घाटों में भरपूर बारिश लाती है। इसलिए, यह क्षेत्र जीवन के सभी रूपों के लिए एक द्वीप आश्रय रहा है, भले ही हिमयुग के चक्र और सूखे ने आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता को कम कर दिया हो।
- पालघाट दर्रा के उत्तर में पश्चिमी घाटों में सालाना अधिक बारिश होती है, लेकिन दक्षिण में वर्ष भर समान रूप से बारिश होती है।

तितलियों के प्रवास अध्ययन से उनका संरक्षण : रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- शोधकर्ताओं के एक दल द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन ने दक्षिण भारत में मिल्कवीड तितलियों के प्रवास पैटर्न पर प्रकाश डाला है।
- इसमें इन तितलियों के संरक्षण और भूमि उपयोग में चल रहे परिवर्तनों, निवास स्थान के क्षरण और जलवायु के गर्म होने की स्थिति में उनके प्रवासन में योगदान करने की क्षमता है।

मिल्कवीड तितलियों द्वारा प्रवास:

- दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाद, मिल्कवीड तितलियाँ पूर्वी घाटों और मैदानी इलाकों से पश्चिमी घाटों की ओर प्रवास करती हैं, उनके आगमन पर दो महीने से अधिक समय तक सक्रिय रहती हैं।
- अक्टूबर और अप्रैल के बीच, पश्चिमी घाटों में अधिकांश मिल्कवीड तितलियाँ सर्दियों और शुष्क मौसम के दौरान विशिष्ट स्थलों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। जब गर्मियों की बारिश दक्षिणी भारत को ठंडा कर देती है, तो तितलियाँ पूर्व की ओर पूर्वी घाटों और मैदानों में चली जाती हैं।

महत्वपूर्ण अवलोकन:

- अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश तितलियों के पंख पूर्व की ओर यात्रा के दौरान पश्चिम की ओर प्रवास की तुलना में टूट जाते हैं।
- इसके अलावा, उन्होंने पाया कि प्रवासन में शामिल प्रमुख प्रजातियाँ, डार्क ब्लू टाइगर और डबल-ब्रांडेड कौवा, पश्चिमी घाट के मध्य और उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार और अर्ध-सदाबहार जंगलों में प्रजनन करते नहीं पाए जाते हैं।
- पश्चिमी घाट में आने वाले गहरे नीले रंग के बाघ और डबल-ब्रांडेड कौवे के वयस्क विपरीत दिशा में पलायन कर सकते हैं और पूर्वी घाट और दक्षिणी भारत के मैदानी इलाकों में प्रजनन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण भूमिका:

- प्रवास के दौरान मिल्कवीड तितलियों का प्रवास भी एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक भूमिका निभाता है। परागणकर्ताओं के रूप में, उनके आवागमन पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। आवास विनाश और जलवायु परिवर्तन से उनके प्रवास को खतरा है।
- उनके प्रवासन पैटर्न और भोजन की आदतों का अध्ययन करने से पौधे और पशु जीवन के परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला जा सकता है।

आगे की राह:

- उनके प्रवासन के रहस्यों को उजागर करने से इन सुंदर प्राणियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में सहायता मिल सकती है।

समुद्री तितलियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील

संदर्भ:

- समुद्री तितलियां एक अद्भुत जीव हैं, जो समुद्री घोंघे के एक उपसमूह से सम्बन्ध रखती हैं। हालांकि यह जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
- इन पर किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि दक्षिणी महासागर में पाए जाने वाले इस समूह की सबसे छोटी प्रजातियां जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं और बढ़ते तापमान के साथ इनकी आबादी तेजी से कम हो रही है।

विशेषताएँ:

- शेल्ड टेरोपोड्स, पानी में मुक्त रूप से तैरने वाले समुद्री घोंघों का एक समूह है, जो समुद्र की सतह या उसके बहुत करीब रहते हैं।
- घोंघे की तरह ही उनके पास मांसपेशियों से बने पैर होते हैं, जिनका उपयोग वो ठोस सतह पर सरकने के बजाय पानी में तैरने के लिए 'फ्लैपर' के रूप में करते हैं।

खतरा:

- देखा जाए तो जैसे-जैसे समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की बढ़ती मात्रा को सोख रहा है वो पानी को अधिक अम्लीय बना रहा है। इसकी वजह से बाहरी आवरण, या यह कहें कि इस अम्लीय जल में इन छोटी समुद्री तितलियों के 'घर' घुल जाते हैं। नतीजन बिना आवरण के इन नाजुक प्रजातियों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है।
- उनकी घटी हुई आबादी बड़े टेरोपोड्स और अन्य समुद्री जीवों को भी प्रभावित करती है क्योंकि उनका यह भोजन है। ऐसे में अंटार्कटिका के आसपास के समुद्रों में पानी के नीचे की पूरी खाद्य श्रृंखला इससे प्रभावित हो सकती है।

- बढ़ते अम्लीकरण से सभी खोल वाले समुद्री घोंघे समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जीवन चक्र अलग-अलग होता है।

लिमसीना रेट्रोवर्सा अधिक जोखिम में क्यों है?

- वैज्ञानिकों ने टेरोपोड्स की प्रमुख प्रजातियों लिमसीना रंगी और लिमसीना रेट्रोवर्सा का अध्ययन किया है।
- यदि इन दोनों प्रजातियों के जीवन चक्र को देखें तो लिमसीना रंगी जोकि एक ध्रुवीय प्रजाति है उसके किशोर और वयस्क सर्दियों के दौरान पाए गए। लेकिन उसके विपरीत लिमसीना रेट्रोवर्सा जोकि एक उपध्रुवीय प्रजाति है उसके सर्दियों के दौरान केवल वयस्क दिखाई दिए।
- समुद्र सर्दियों में सबसे अधिक अम्लीय होता है क्योंकि ठंडा पानी अधिक CO_2 अवशोषित करता है। इसका मतलब है कि समुद्री तितलियों के लिए सर्दियों के महीने सबसे खतरनाक होते हैं।
- रिसर्च के अनुसार यह खतरा लिमसीना रेट्रोवर्सा के लिए कहीं ज्यादा था। वैज्ञानिकों ने इसके कारण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लिमसीना रंगी के वयस्क और किशोर दोनों ही सर्दियों के दौरान सह-अस्तित्व में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवित रहने की सम्भावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है चूंकि यदि एक समूह सुरक्षित रहता है तो पूरी आबादी पर जोखिम घट जाता है।
- वहीं इसके विपरीत लिमसीना रेट्रोवर्सा के केवल वयस्क सर्दियों के इस दौर में रहते हैं ऐसे में यदि एक समूह पर इसका असर पड़ता है तो उससे पूरी आबादी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
- यदि यह परिस्थितियां लम्बे समय तक बनी रहती हैं तो इस बढ़ते तापमान से दोनों में से कोई भी प्रजाति सुरक्षित नहीं है।
- जैसे-जैसे उत्सर्जन बढ़ता है, महासागरों का अम्लीकरण तेज होता है और वसंत तक फैलता है जब प्रजातियां पैदा होती हैं और वे लार्वा चरण में होती हैं जोखिम में डाल सकता है। नतीजन यह भविष्य में इन प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।

आगे की राह:

- वैज्ञानिक यह समझने के लिए स्कोटिया सागर में आवासों का अध्ययन करेंगे कि समुद्री तितलियां कैसे प्रभावित होती हैं। निष्कर्ष सामान्य रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर महासागर अम्लीकरण के प्रभावों पर अध्ययन को भी सूचित कर सकते हैं।

वर्ष 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण 80 प्रतिशत तक कम : संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यदि दुनिया भर के देश और कंपनियां मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके नीति और बाजार में बदलाव करती हैं, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण 80 फीसदी तक कम हो सकता है।
- इस प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने के लिए एक वैश्विक समझौते पर पेरिस में दूसरे दौर की वार्ता से पहले इस रिपोर्ट को जारी किया गया है।

सर्कुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान करने के लिए ठोस प्रथाओं, बाजार में बदलाव और नीतियों के समाधान-केंद्रित विश्लेषण पर ध्यान दिया है।
- दुनिया भर में 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को 80 प्रतिशत तक कम करने के लिए, रिपोर्ट समस्या के बढ़ते आकार को कम करने के लिए सबसे पहले अनावश्यक प्लास्टिक को समाप्त करने का सुझाव देती है।
- इसके बाद, बाजार में तीन तरह के बदलाव करने के सुझाव दिए गए हैं, पुन: उपयोग और उत्पादों में विविधता लाना इसमें शामिल है।

रीसाइक्लिंग:

- पुन: उपयोग: भरने योग्य बोतलें, बल्क डिस्पेंसर, डिपॉजिट-रिटर्न-स्कीम, पैकेजिंग टेक-बैक स्कीम आदि सहित पुन: उपयोग के विकल्पों को बढ़ावा देकर 2040 तक 30 प्रतिशत प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
- पुनर्चक्रण या रीसाइक्लिंग- यदि पुनर्चक्रण एक अधिक स्थिर और लाभदायक उद्यम बन जाता है, तो 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को अतिरिक्त 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
- जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी हटाने, पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए तय दिशानिर्देशों को लागू करने और अन्य उपायों से आर्थिक रूप से पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक की हिस्सेदारी 21 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
- पुनर्विन्यास और विविधता- वैकल्पिक सामग्री जैसे कागज या कूड़े की खाद या कंपोस्टेबल सामग्री से बने उत्पादों के साथ प्लास्टिक रैपर, पाउच और टेकअवे आइटम जैसे उत्पादों के बदले अन्य सामग्रियों को अपनाने से प्लास्टिक प्रदूषण में अतिरिक्त 17 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है।
- पुनर्चक्रण पर लगने वाली राशि को ध्यान में रखते हुए, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव के बाद 1.27 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी।

अनुशंसाएँ:

- इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एक वैश्विक राजकोषीय ढांचा अंतरराष्ट्रीय नीतियों का हिस्सा हो सकता है ताकि रीसायकल सामग्री को नए सामग्रियों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।
- इसके समाधान के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके और निगरानी प्रणाली और वित्तपोषण तंत्र स्थापित किया जा सके।
- यूएनईपी ने कहा कि अब और 2040 के बीच की छोटी समयरेखा को देखते हुए, उस कचरे से निपटने के लिए "उप-इष्टतम समाधान" का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, हालांकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन

या वायु विषाक्त पदार्थों में वृद्धि के प्रभावों को आगे के अध्ययन की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- इस संधि वार्ता को INC2 के रूप में जाना जाता है, 29 मई से 2 जून तक होगी और इसके परिणामस्वरूप पहले संधि मसौदे के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होने की उम्मीद है, जिसे नवंबर में केन्या में तीसरे दौर की वार्ता से पहले करने की आवश्यकता है।

यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

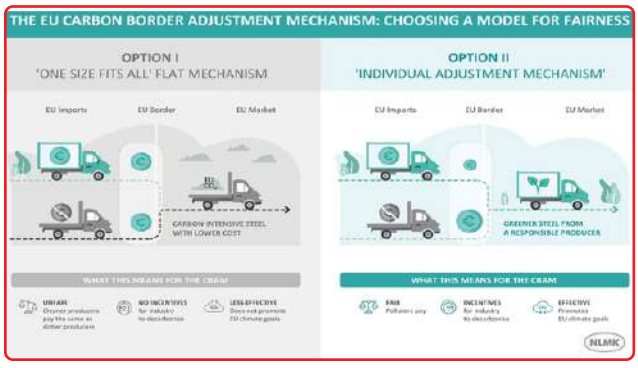

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, यूरोपीय आयोग के सह-कार्यकारियों ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) पर हस्ताक्षर किए।
- इसे यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन सघन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाले कार्बन पर उचित मूल्य लगाने और गैर-यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक "ऐतिहासिक उपकरण" के रूप में वर्णित किया गया है।

सीबीएएम क्या है?

- इसका प्राथमिक उद्देश्य 'कार्बन रिसाव' को रोकना है। यह एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जहां यूरोपीय संघ के निर्माता कार्बन-गहन उत्पादन को कम कठोर जलवायु नीतियों वाले क्षेत्र के बाहर के देशों में ले जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यूरोपीय संघ निर्मित उत्पादों को अधिक कार्बन-गहन आयातों से बदलना है।
- वर्ष 2026 से, एक बार जब सीबीएएम पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो यूरोपीय संघ में आयातकों को आयात के देय कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना होगा, यदि उत्पाद महाद्वीप में कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के अंतर्गत उत्पादित किया गया था।
- इसके विपरीत, यदि कोई गैर-यूरोपीय संघ उत्पादक आयातित वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए गए कार्बन के लिए घर वापस या किसी अन्य देश में कीमत (या कर) का भुगतान कर रहा है, तो यूरोपीय संघ के आयातक के लिए संबंधित लागत में कटौती की जाएगी।
- आयोग, सदस्य राज्यों के प्रासंगिक अधिकारियों के साथ समन्वय में, घोषणाओं की समीक्षा और सत्यापन के साथ-साथ सीबीएएम प्रमाणपत्रों की बिक्री के लिए केंद्रीय मंच का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होगा। आयातकों को मई के अंत तक पिछले वर्ष में क्षेत्र में आयात किए गए सामानों की मात्रा और सन्निहित उत्सर्जन की वार्षिक घोषणा करनी होगी।
- यहाँ विचार कार्बन रिसाव की संभावना को रोकने के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ के देशों में उत्पादकों को उनकी निर्माण प्रक्रियाओं में सी.बी.ए.एम. उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, यह आयात और यूरोपीय संघ के उत्पादों के बीच एक स्तरीय बाजार उपलब्ध होगा।
- यह महाद्वीप के व्यापक यूरोपीय ग्रीन डील का भी हिस्सा होगा जो 2030 तक 1990 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी हासिल करने और 2050 तक एक जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनने का प्रयास करता है।

क्यों चिंतित हैं देश?

- सीबीएएम शुरू में कुछ सामानों और चुनिंदा प्रीकर्सर के आयात पर लागू होगा, जिनका उत्पादन कार्बन-गहन है और सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन क्षेत्रों जैसे 'रिसाव' का खतरा है।
- वर्ष 2021 में, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने निष्कर्ष निकाला था कि रूस, चीन और तुर्की तंत्र से सबसे अधिक प्रभावित थे।
- इन क्षेत्रों में संघ को निर्यात के स्तर पर विचार करते हुए, यह कहा गया है कि विकासशील देशों में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक प्रभावित होंगे। मोज़ाम्बिक सबसे कम-विकासशील देश होगा।
- यूरोपीय संघ के देश संयुक्त रूप से स्टील और एल्युमीनियम सहित सभी उत्पादों के लिए भारत के निर्यात मिश्रण का लगभग 14% प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत पर प्रभाव:

- पांच खंडों में भारत का निर्यात 2019 और 2021 के बीच यूरोपीय संघ को कुल निर्यात का 2% से कम का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, विनियमन का प्रभाव सीमित दिखाई दे सकता है, इसके दीर्घकालिक प्रभाव कई कारकों के लिए गंभीर हो सकते हैं।
- यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और बाद के अनुमानित विकास को देखते हुए, निर्यात का आकार (सीबीएएम क्षेत्रों सहित) निश्चित रूप से बढ़ेगा।
- सीबीएएम का दायरा अपने वर्तमान दायरे से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करेगा। "यह देखते हुए कि भारत के उत्पादों में अपने यूरोपीय समकक्षों की तुलना में अधिक कार्बन तीव्रता है, लगाए गए कार्बन टैरिफ आनुपातिक रूप से अधिक होंगे, जिससे भारतीय निर्यात काफी हद तक अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियां (CBAM सहित) अन्य देशों को समान विनियमन लागू करने के लिए मजबूर करेंगी, जो अंततः भारत के व्यापारिक संबंधों और भुगतान संतुलन पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" के रूप में होंगी।

संस्कृति

शिलाभट्टारिका (ताम्रपत्र) का पुर्नअध्ययन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीओआरआई) के शोधकर्ताओं ने बादामी (आधुनिक कर्नाटक में) के प्रसिद्ध चालुक्य

सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री के रूप में शिलाभट्टारिका को स्थापित करके प्राचीन भारत की प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री पर नवीन प्रकाश डालने का दावा किया है।

विवरण:

- पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (बीओआरआई) में दक्षिण एशिया की पांडुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है।
- तांबे की प्लेटों पर शिलालेखों के डिकोडिंग के बाद उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि शिलाभट्टारिका एक चालुक्य राजकुमारी थी, संभवतः पुलकेशिन द्वितीय की बेटी थी, जिसने 610-642 ईस्वी तक शासन किया था और 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट के पास एक युद्ध में कन्नौज के हर्षवर्धन को पराजित किया था।

इतिहासलेखन में बदलाव:

- इस व्याख्या के महत्व ने शीलभट्टारिका पर नवीन प्रकाश डाला है, जो प्राचीन भारत में शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के पुरुष-प्रधान क्षेत्र में एक कवयित्री के रूप में उभरी।
- संस्कृत कवि-आलोचक राजशेखर, जो 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी के थे और गुर्जर-प्रतिहारों के दरबारी कवि थे, ने शिलाभट्टारिका की उनकी सुरुचिपूर्ण और सुंदर रचनाओं के लिए प्रशंसा की थी।
- प्रसिद्ध मराठी कवयित्री शांता शेल्के ने भी शिलाभट्टारिका के छंदों से प्रेरणा लेकर अपने सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक - तोच चंद्रमा नाभत (यह आकाश में वही चंद्रमा है) की रचना की है।
- तांबे की प्लेटों का डिकोडिंग भी शिलाभट्टारिका को वर्तमान सिद्धांत के विपरीत 7 वीं शताब्दी सीई में रहने के रूप में बादामी चालुक्यों के इतिहासलेखन में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जिसमें वह 8 वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट शासक ध्रुव की पत्नी के रूप में है।

ताम्रपत्र प्रशस्ति:

- बादामी चालुक्य शासक विजयादित्य (696-733 सीई) के शासनकाल से डेटिंग करने वाली पांच तांबे की प्लेटों के साथ एक ताम्रपत्र प्रशस्ति को पढ़ा गया है।
- इस प्रशस्ति में 23.4 सेमी x 9.4 सेमी माप वाली पांच प्लेटें थीं, जो एक सुंदर वराह (सूअर) मुहर वाली तांबे की अंगूठी द्वारा एक साथ जुड़ी हुई थीं। वराह मुहर बादामी चालुक्यों का ट्रेडमार्क है।
- चार्टर में 65 पंक्तियों के साथ एक संस्कृत पाठ था, जो लेट-ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ था।

अन्य निष्कर्ष:

- इन प्लेटों के एक प्राथमिक अध्ययन से पता चलता है कि विजयादित्य ने जनवरी-फरवरी 717 ई.पू. माघ, शाका वर्ष 638 के महीने में कोगली विषय में एक वैदिक विद्वान विष्णुशर्मा को सिक्कतरु गांव दान में दिया था।
- इस सिक्काटेरू की पहचान कर्नाटक के विजयनगर जिले में कोगली के पास स्थित चिगातेरी के रूप में की गई थी। लेकिन यह सब पूरा नहीं था। प्लेटों से पता चला कि विजयादित्य ने शिलाभट्टारिका के पुत्र महेंद्रवर्मा के अनुरोध पर गांव दान किया था।
- (डिकोडेड) पाठ आगे कहता है कि "महेंद्रवर्मा की सिफारिश पर, राजा विजयादित्य चालुक्य ने एक विद्वान विष्णुशर्मा को चिगतेरी गांव दान में दिया था।"

महत्त्व:

- यह वंशावलियों से अधिक, गूढ़वचन शिलाभट्टारिका और उनकी कविता के महत्व को ध्यान में लाता है।

विविध

सबाल्टर्न स्कूल और दक्षिण एशियाई अध्ययन में गुहा का योगदान

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हो गया।
- इन्होंने दक्षिण एशिया का अध्ययन करने के लिए एक नए तरीके की शुरुआत की, जो पहले विद्वता पर हावी अभिजात वर्ग की चिंताओं की प्रधानता से हटकर था।

सबाल्टर्न स्कूल:

- उन्होंने अपने सहयोगियों (जिनमें से कई उनके छात्र थे) के साथ सबाल्टर्न स्कूल शुरू किया, जो इतिहास में सबसे प्रभावशाली उत्तर-औपनिवेशिक, उत्तर-मार्क्सवादी स्कूलों में से एक है।
- इस स्कूल के प्रभाव ने विश्व भर से और जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर छात्रवृत्ति को आकार देने के लिए दक्षिण एशियाई इतिहास को पार कर लिया है।

विवरण:

- 23 मई, 1923 को सिद्धकाटी, बैकरगंज (वर्तमान बांग्लादेश) में जन्मे, वे 1959 में यूके चले गए। वहां वे ससेक्स विश्वविद्यालय में इतिहास के पाठक थे।

- भारतीय इतिहास का अध्ययन और अध्यापन करते समय, उन्होंने माना कि भारत में और उसके बारे में मुख्यधारा के ऐतिहासिक आख्यान भारत के अतीत की जटिलता का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे। महत्वपूर्ण रूप से, जो पारंपरिक आख्यान छूट गए, वह निम्नवर्गों - सबाल्टर्न की आवाज़ थी।

शब्द 'सबाल्टर्न':

- "सबाल्टर्न" शब्द सबसे पहले इतालवी मार्क्सवादी दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्स्की द्वारा किसी अन्य, अधिक शक्तिशाली वर्ग के आधिपत्य के अधीन लोगों के किसी भी वर्ग (ग्राम्स्की, किसानों और श्रमिकों के लिए) को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था।
- इस शब्द को रणजीत गुहा और समान विचारधारा वाले सहयोगियों ने 1980 के दशक की शुरुआत में दक्षिण एशियाई अध्ययन के क्षेत्र में "ज्यादातर शोध और अकादमिक कार्यों की अभिजात्य पूर्वाग्रह विशेषता को सुधारने" में उठाया था।

सबाल्टर्न स्कूल का संदर्भ:

- दक्षिण एशिया पर मुख्यधारा की विद्वता, सबाल्टर्न स्कूल से पहले, या तो औपनिवेशिक यूरोसेंट्रिज्म का उत्पाद थी या देशी अभिजात वर्ग की विचारों से प्रभावित थी, जो अक्सर औपनिवेशिक ढांचे और आख्यानों से बहुत प्रभावित होती थी।
- उदाहरण के लिए, जेम्स मिल्स का प्राचीन (हिंदू), मध्यकालीन (मुस्लिम) और आधुनिक (औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक) में भारतीय इतिहास का तीन-भाग वर्गीकरण आज तक प्रभावशाली बना हुआ है, जिससे राष्ट्रवादी इतिहासकारों की पीढ़ियों को आकार मिला है।
- यह न केवल यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रचलित ढांचे का एक विचारहीन आरोपण है, बल्कि यह उन संदर्भों की विविधता को भी स्मरण करता है जिन्हें ऐतिहासिक अध्ययन में शामिल होना चाहिए।

कृषक चेतना:

- ये औपनिवेशिक भारत में किसानों के उग्रवाद के अपने स्थायी पहलुओं (1983) में, वह औपनिवेशिक भारत में किसानों की चेतना और असंतोष की अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों के बारे में लिखते हैं।
- जबकि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत से ही किसान प्रतिरोध दर्ज किया गया था। उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से भिन्न था। उनका काम किसान के दृष्टिकोण से किसान विद्रोह का अध्ययन करने पर केंद्रित था। यह विद्रोही किसानों को देशी संभ्रांतों द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक एजेंसी के बजाय उनकी अपनी राजनीतिक एजेंसी प्रदान करता है।
- यहां तक कि अब तक आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक स्रोतों जैसे औपनिवेशिक दस्तावेजों को देखता है, तो उनका दृष्टिकोण उन्हें समस्यात्मक बनाता है, रचनाकारों की स्थिति के बारे में जागरूक और परिणामस्वरूप, स्वयं स्रोतों में संभावित पूर्वाग्रहों से अवगत होता है।

सबाल्टर्न स्कूल की कुछ आलोचनाएँ:

- जहाँ सबाल्टर्न स्कूल 1980 के दशक के बाद से दक्षिण एशिया और उत्तर औपनिवेशिक समाजों पर विद्वानों के काम की पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में बेहद प्रभावशाली रहा है, यह अपने आलोचकों के बिना नहीं रहा है।
- सबाल्टर्न स्कूल की मुख्य आलोचनाओं में से एक संरचना की कीमत पर एजेंसी पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। आलोचकों का तर्क है कि सबाल्टर्न स्कूल उन तरीकों की अनदेखी करता है जिनमें सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं सबाल्टर्न समूहों की एजेंसी को बाधित करती हैं। नतीजतन, सबाल्टर्न स्कूल पर सबाल्टर्न एजेंसी और प्रतिरोध के अत्यधिक रोमांटिक दृश्य पेश करने का आरोप लगाया गया है।
- इसके अलावा, सबाल्टर्न स्कूल का राजनीतिक दृष्टिकोण पहचान-आधारित आंदोलनों और प्रतिरोध पर केंद्रित है।
- यह दृष्टिकोण वर्ग-आधारित राजनीति के महत्व और सबाल्टर्न समूहों के परिवर्तनकारी संघर्षों में शामिल होने को नज़रअंदाज़ करता है जो मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को चुनौती देता है।

एशिया-प्रशांत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं: एस्केप (ESCAP)

चर्चा में क्यों?

- एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्केप) के एक नए अध्ययन के अनुसार, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश देश चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं।
- इस क्षेत्र के देशों में आवश्यक डेटा के साथ-साथ अनुकूलन और शमन प्रयासों का समर्थन करने के साधनों की कमी है।
- आपदा प्रबंधन निर्णायक रणनीति के अभाव में, जलवायु परिवर्तन पूरे क्षेत्र में गरीबी और असमानता का एक प्रमुख कारण बना रहेगा।

संभावित खतरे:

- पिछले 60 वर्षों में, इस क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ा है। अत्यधिक, अप्रत्याशित मौसम की घटनाएं और प्राकृतिक खतरे अधिक लगातार और तीव्र हो गए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गर्मी की लहरें, बाढ़ और सूखे ने जीवन और विस्थापन का भारी नुकसान किया है, लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाया है और लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है।
- इन आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में से छह इस क्षेत्र में हैं। यहां खाद्य व्यवस्था बाधित हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं और समाज कमजोर हो रहे हैं।
- यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो जलवायु परिवर्तन चल रहे अतिव्यापी संकटों और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को खतरे में डाल देगा।

- जलवायु परिवर्तन और जलवायु-प्रेरित आपदाएं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए खतरा बन रही हैं, जो अक्सर कठिन परिश्रम से प्राप्त विकास लाभ को कम कर रही हैं।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर अवलोकन:

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र विश्व के आधे से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। यह वैश्विक जनसँख्या के महत्वपूर्ण अनुपात के साथ विश्व के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र विश्व के अधिकांश निचले शहरों और कमजोर छोटे द्वीप राज्यों का भी घर है।
- जलवायु परिवर्तन की लागत पहले ही बहुत अधिक है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खतरों से होने वाली वार्षिक औसत हानि लगभग 780 बिलियन डॉलर है।
- एक मध्यम जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के अंतर्गत, इन नुकसानों के $1.1 ट्रिलियन तक और सबसे खराब स्थिति में $1.4 ट्रिलियन तक बढ़ने की संभावना है।
- इस मोर्चे पर मौजूदा वित्त पोषण जलवायु कार्रवाई में निवेश या 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
- वर्ष 2030 तक केवल सात साल बचे हैं, एसडीजी के लिए लक्ष्य वर्ष, उपलब्ध वित्त को बढ़ाना और जलवायु कार्रवाई महत्वाकांक्षा को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

आवश्यक कदम:

ऊर्जा:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, 2020 में क्षेत्र की लगभग 85 प्रतिशत प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति जीवाश्म ईंधन से हुई। यहां स्टील और सीमेंट का उत्पादन जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
- अक्षय ऊर्जा के तेजी से उपयोग के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों के पुनर्गठन, नई तकनीकी क्षमताओं और आपूर्ति और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। रिपोर्ट में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सीमा पार बिजली ग्रिड पर जोर दिया गया है।
- इसने जलवायु-रोधी ऊर्जा प्रणालियों पर बल दिया। पनबिजली, जो क्षेत्र की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का सबसे बड़ा हिस्सा रखती है, तेजी से अविश्वसनीय हो गई है।

परिवहन क्षेत्र:

- मुख्य रूप से तेल द्वारा संचालित परिवहन क्षेत्र को निम्न-कार्बन मार्ग पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- यह एकीकृत भूमि उपयोग, योजना, कम कार्बन या शुद्ध-शून्य-कार्बन उत्सर्जन के साथ स्थायी परिवहन मोड में स्थानांतरित करने के साथ-साथ वाहन और ईंधन दक्षता में सुधार के माध्यम से परिवहन दूरी को कम करके प्राप्त किया जा सकता है।
- वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी देश (विकसित या विकासशील) परिवहन क्षेत्र में स्थिरता हासिल करने के रास्ते पर नहीं है। अधिकांश विकसित और विकासशील देशों को सार्वभौमिक शहरी पहुंच, लिंग और दक्षता के नीतिगत लक्ष्यों पर कम स्थान दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश:

- क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करना है। व्यापार को जलवायु-स्मार्ट होना चाहिए, 2005 के बाद से हस्ताक्षरित 85 प्रतिशत क्षेत्रीय व्यापार समझौते जिसमें कम से कम एक एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्था पार्टी है, में जलवायु संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
- निजी क्षेत्र को कम कार्बन मार्ग की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जलवायु स्थिरता को व्यवसाय संचालन में शामिल किया जाना चाहिए।
- स्थिरता रिपोर्ट जारी करने वाली कंपनियों की संख्या और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए लेखांकन में हाल ही में वृद्धि हुई है। कुछ कंपनियों ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण को एक उपकरण के रूप में पेश किया है।

शासन एवं राजव्यवस्था

आवारा कुत्ते और अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या

चर्चा में क्यों?

- लोगों पर कुत्तों के हमले की बार-बार आने वाली खबरों ने भारत में आवारा कुत्तों के प्रबंधन को एक प्रशासनिक और कानूनी समस्या बना दिया है।

अपशिष्ट प्रबंधन से कुत्ते के काटने का क्या संबंध है?

- "वहन क्षमता" भोजन और आश्रय की उपलब्धता से निर्धारित होती है।
- खुले में रहने वाले कुत्ते, इन सुविधाओं के अभाव में, सड़क पर कूड़ा हटाने वाले हैं जो भोजन के लिए इधर-उधर घूमते हैं, अंततः अनावृत कचरा डंपिंग स्थलों की ओर आकर्षित होते हैं। कुत्ते इस प्रकार भोजन के अवसरों के कारण शहरी डंप जैसे लैंडफिल के आसपास इकट्ठा होते हैं।
- भारतीय शहरों में बढ़ती जनसंख्या ने ठोस कचरे में आश्चर्यजनक वृद्धि में योगदान दिया है। भारतीय शहर प्रतिदिन 1,50,000 मीट्रिक टन से अधिक शहरी ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन 2019 में घरों, रेस्तरां, विक्रेताओं और अन्य खाद्य सेवा खुदरा विक्रेताओं के डिब्बे में समाप्त हो गया।
- भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति औसतन 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह कचरा अक्सर भूखे-पीड़ित, मुक्त-घूमने वाले कुत्तों के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है जो शहरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि शहरी मलिन बस्तियाँ जो सामान्य तौर पर कचरा डंपिंग साइटों और लैंडफिल के बगल में स्थित होते हैं।

शहरीकरण की क्या भूमिका है?

- शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो आधिकारिक 2019 की पशुधन गणना के अनुसार 1.5 करोड़ थी। हालांकि, स्वतंत्र अनुमान के अनुसार यह संख्या करीब 6.2 करोड़ है।
- 2012 और 2020 के बीच कुत्ते के काटने की संख्या एक साथ दोगुनी हो गई है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा रेबीज के बोझ का सामना करता है, जो इस बीमारी के कारण होने वाली वैश्विक मौतों का एक तिहाई हिस्सा है।
- 2015 में, 10 भारतीय मेट्रो शहरों में किए गए एक अध्ययन में मानव जनसँख्या, नगरपालिका और खाद्य अपशिष्ट की मात्रा और शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया।

शहरीकरण और ठोस अपशिष्ट उत्पादन के बीच संबंध:

- जबकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि बढ़ती आबादी और नगर निगम के कचरे के कारण सीधे कुत्ते के काटने में वृद्धि हुई है, विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरीकरण और ठोस अपशिष्ट उत्पादन के बीच एक संबंध हो सकता है, जो अपशिष्ट निपटान के कुप्रबंधन के कारण दिखाई देता है।
- पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की समस्या और अपर्याप्त बचाव केंद्र, खराब अपशिष्ट प्रबंधन के साथ मिलकर, भारत में आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, अधिकांश लैंडफिल और डंपिंग स्थल शहरों की परिधि में, मलिन बस्तियों और बस्ती कॉलोनियों के बगल में स्थित हैं। इस प्रकार, कुत्ते के काटने का अनुपातहीन बोझ शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है।
- वर्ष 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि ग्रामीण मलिन बस्तियों की तुलना में सामान्य तौर पर डंपिंग साइटों के करीब स्थित शहरी मलिन बस्तियों में कुत्तों के काटने का प्रचलन अधिक था।

भारत द्वारा इसका निदान

- "आवारा कुत्तों के खतरे" के प्रति भारत की प्रतिक्रिया पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम पर निर्भर करती है, जिसके माध्यम से नगरपालिका निकाय कुत्तों की आबादी को धीमा करने के लिए कुत्तों को फंसाते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं।
- दूसरा टीकाकरण अभियान सहित रेबीज नियंत्रण के उपाय थे।
- कुत्ते के काटने के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में कम जागरूकता, टीकों की अनियमित आपूर्ति, उपचार की मांग में देरी, और राष्ट्रीय नीति की कमी जैसे समस्या से ग्रस्त है।

सरकार द्वारा फांसी के विकल्प पर समिति पर विचार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया कि वह फांसी से मृत्यु के दर्द रहित और अधिक गरिमापूर्ण विकल्प की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रही है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के समक्ष प्रस्तुत होकर, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में वापस रिपोर्ट करने के लिए जुलाई तक का समय मांगा।

पृष्ठभूमि:

- मार्च में, न्यायालय ने सरकार से डेटा प्रदान करने के लिए कहा था जो फांसी से मौत के अलावा कैदियों को फांसी देने की अधिक स्वीकार्य विधि का संकेत दे सके।
- मुख्य न्यायाधीश ने उस सुनवाई में सरकार को राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, कानून के प्रोफेसरों, डॉक्टरों और वैज्ञानिक व्यक्तियों के साथ एक समिति के गठन का सुझाव दिया था।
- अदालत ने केंद्र को संकेत दिया था कि अगर यह साबित हो जाता है कि मौत की सजा देने का एक और "मानवीय" तरीका है जो असंवैधानिक रूप से फांसी देकर मौत को अंजाम दे सकता है तो वह मृत्युदंड देने का एक वैकल्पिक तरीका भी निर्देशित कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्या था मामला?

- न्यायालय वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाँसी से मौत की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी।
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (5) में कहा गया है कि मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति को "उसकी मृत्यु होने तक गले से लटकाया जाएगा"।
- दरअसल, 2018 में केंद्र ने फांसी से मौत के समर्थन में एक हलफनामा दाखिल किया था. इसने घातक इंजेक्शन की तुलना में फांसी से लटकाने की विधि को "अमानवीय और क्रूर" नहीं पाया था।

समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना कुछ अधिकार देने पर विचार करेगी: केंद्र सरकार

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह समान-लिंग विवाह की कानूनी मान्यता के लिए उनकी याचिकाओं पर विचार किए बिना, बैंकिंग और बीमा जैसे क्षेत्रों में समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा उनके दैनिक जीवन में सामना की जाने वाली "वास्तविक, मानवीय चिंताओं" को दूर करने के लिए प्रशासनिक उपायों पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के लिए तैयार है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सरकार के रुख को समान लिंग वाले जोड़ों के सहवास के अधिकार की व्यापक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में एक "कदम आगे" और यहां तक कि "बड़ा सकारात्मक" करार दिया।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिक्रिया:

- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब यह जांच की जा सकती है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को "किसी भी प्रकार के भेदभाव, सामाजिक या अन्यथा का सामना किए बिना हमारे देश में एक सामान्य, शांतिपूर्ण वातावरण में एक साथ सहवास करने का अधिकार है"।
- इसमें कहा गया है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का सरकार का सुझाव समलैंगिक जोड़ों के बीच सहवास संबंधों की घटनाओं को पर ध्यान दिया है।

SC पीठ के विचार:

- न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे सरकार के प्रस्ताव को भविष्य में बदलाव के लिए एक "निर्माण खंड" के रूप में मानें।
- न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ताओं को कानूनी रूप से समान-लिंग विवाह को मान्यता देने के लिए अदालत से न्यायिक घोषणा प्राप्त करनी हो, लेकिन "प्रशासनिक और विधायी पहलुओं में कई, कई बदलाव आवश्यक होंगे"। अदालत समलैंगिक विवाह को मान्यता देती है या नहीं, इन मानवीय चिंताओं पर ध्यान देना होगा।
- जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि सरकार भले ही समलैंगिक संबंधों को शादी का दर्जा देने में अनिच्छुक हो, लेकिन इससे पैदा होने वाली मानवीय चिंताओं को दूर करने में अनिच्छुक नहीं।
- न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को "ऑल-ऑर-नो अप्रोच" के लिए नहीं जाना चाहिए और अंत में एक गतिरोध पर पहुंचना चाहिए।

देश की 62 सैन्य छावनियां समाप्त

संदर्भ:

- भारत में बासठ छावनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और सभी फौजी क्षेत्रों को एक सैन्य स्टेशन के रूप में बदल दिया जाएगा। जबकि नागरिक क्षेत्र स्थानीय नगर पालिकाओं के तहत आ जाएंगे।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का योल छावनी का टैग हटाने वाला पहला राज्य है।

विवरण:

- छावनी के भीतर सैन्य क्षेत्र को एक सैन्य स्टेशन में बदल दिया जाएगा जबकि नागरिक क्षेत्र को नगरपालिका में मिला दिया जाएगा। छावनी बोर्ड के कर्मचारियों और संपत्ति को पड़ोसी नगर पालिकाओं द्वारा ले लिया जाएगा।
- यह 'छावनियां बनाने की पुरातन औपनिवेशिक प्रथा' में एक बड़ा बदलाव होगा।

महत्व:

- नागरिक जो अब तक, नगरपालिका के माध्यम से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच नहीं बना रहे थे, अब उनका लाभ उठाने की स्थिति में होंगे।
- जहां तक सेना का संबंध है, वह भी अब सैन्य स्टेशन के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

पृष्ठभूमि:

- आजादी के समय देश में 56 छावनियां थीं और 1947 के बाद 6 और अधिसूचित की गईं। 1962 में आखिरी छावनी अजमेर में बनाई गई थी।
- रक्षा सम्पदा कार्यालयों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, रक्षा मंत्रालय देश में सबसे बड़ा भूस्वामी है, जिसके पास लगभग 17.99 लाख एकड़ जमीन है।
- इसमें से लगभग 1.61 लाख एकड़ 62 अधिसूचित छावनियों के भीतर है। शेष भूमि, लगभग 16.38 लाख एकड़, देश भर में और छावनियों के बाहर फैली हुई है।
- छावनियों से संबंधित मामले, जिनमें नए भवनों का निर्माण, भवन की ऊंचाई, वाणिज्यिक रूपांतरण, सीवेज और बाकी सभी शामिल हैं, छावनी बोर्ड द्वारा नियंत्रित किए जाते थे।
- अंबाला और आगरा में पहले ही छावनियां हो चुकी हैं, जबकि धर्मशाला, सीतापुर जैसी छावनियों को 1947 से पहले डी-नोटिफाई कर दिया गया था।

राज्य का विषय:

- छावनियों को नगर पालिका माना जाता है और नगर पालिकाओं को चलाना राज्य का विषय है।
- छावनियों में रहने वाले निवासियों को राज्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभ नहीं मिलता है क्योंकि छावनियों को रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा विभाग के माध्यम से छावनी बोर्डों द्वारा शासित किया जाता है।
- रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाता है।

'आदर्श कारागार अधिनियम'

चर्चा में क्यों?

- केंद्र ने मौजूदा कानून की कमियों को दूर करने और सुधार तथा कैदियों के पुनर्वास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नया 'आदर्श कारागार अधिनियम 2023' तैयार किया है जो आजादी से पहले के 130 साल पुराने कानून की जगह लेगा।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

- इस कानून में जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले बंदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए दण्ड का प्रावधान है।
- इसमें उच्च सुरक्षा जेल, ओपन जेल (ओपन और सेमी ओपन), आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान
- इस कानून में खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान
- इसमें कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि के लिए प्रावधान
- कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास और उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने पर बल देना

औपनिवेशिक काल के कानून:

- देश में जेल और उनमें हिरासत में रखे गए व्यक्ति राज्य का विषय हैं तथा इस संदर्भ में मौजूदा कानून, 1894 का जेल अधिनियम आजादी से पहले का कानून है और लगभग 130 साल पुराना है।
- दो अन्य संबंधित कानून; प्रिजनर्स एक्ट, 1900 और द ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1950 भी दशकों पुराने हैं।

आदर्श जेल अधिनियम का महत्व:

- यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा, इस अधिनियम से जेल प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और कैदियों के सुधार और पुनर्वास का प्रावधान किया जाएगा
- यह कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और समाज में उनके पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

आगे की राह:

- यह (मौजूदा) अधिनियम मुख्य रूप से अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था को लागू करने पर केंद्रित है।

मौजूदा अधिनियम में कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं है।'

- यह व्यापक 'आदर्श कारागार अधिनियम, 2023' को समग्र रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने और मौजूदा जेल कानून की खामियों को दूर करने तथा जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल आदि के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत रूसी तेल के शोधन और इसे यूरोप को बेचने में सबसे आगे, रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) द्वारा 'लॉन्ड्रोमैट: हाउ द प्राइस कैप एलायंस वाइटवॉश रशियन ऑयल इन थर्ड कंट्रीज' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई।

विवरण:

- वर्ष 2023 की पहली तिमाही के नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 'द लॉन्ड्रोमैट' देशों के रूप में नामित पांच देशों का नेतृत्व करता है, जो रूसी तेल खरीदते हैं और यूरोपीय देशों को प्रसंस्कृत उत्पाद बेचते हैं, इस प्रकार रूस के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हैं।
- रिपोर्ट, एनालिटिक्स फर्म केप्लर के नवीनतम डेटा और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के साथ मेल खाती है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार यूरोपीय संघ (ईयू) के देश, जो "मूल्य कैप गठबंधन" का हिस्सा हैं, जो किसी भी खरीदे गए तेल के लिए व्यापार और बीमा को रोकता है।
- रिपोर्ट में भारतीय विक्रेताओं और यूरोपीय खरीदारों पर रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सह-स्वामित्व वाली गुजरात की एक रिफाइनरी से कच्चे उत्पादों को बेचकर संभावित रूप से "प्रतिबंधों को दरकिनार" करने का आरोप लगाया गया है।
- यूरोपीय देश केवल उन तेल उत्पादों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो उन्होंने पहले रूस से सीधे खरीदे थे, और वही उत्पाद तीसरे देशों में "व्हाइटवॉश" किए गए हैं और उनसे प्रीमियम पर खरीदे गए हैं।

भारत द्वारा निर्यात:

- तथाकथित "लॉन्ड्रोमैट" देशों में, भारत, जो अप्रैल में पांचवें महीने के लिए समुद्री रूसी कच्चे तेल का उच्चतम वैश्विक उपभोक्ता बना रहा, गठबंधन देशों को कच्चे उत्पादों के निर्यात में अन्य सभी से आगे है, प्राइस कैप गठबंधन देशों को लगभग 3.8 मिलियन टन तेल उत्पादों का निर्यात करना, जिसमें यूरोपीय संघ, जी-7 देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं।
- उदाहरण के लिए, यूक्रेन में रूसी युद्ध से पहले की अवधि की तुलना में, मार्च 2023 में भारत से डीजल का निर्यात तीन गुना बढ़कर लगभग 1,60,000 बैरल प्रति दिन हो गया, जिससे डीजल वर्तमान में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार के सबसे बड़े घटकों में से एक बन गया है।
- गुजरात में दो बंदरगाहों से सबसे अधिक तेल उत्पादों का निर्यात किया जा रहा था: सिक्का बंदरगाह जो रिलायंस के स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की सेवा करता है, और वाडीनार बंदरगाह जो नायरा एनर्जी से तेल उत्पादों को शिप करता है, जिसका आंशिक स्वामित्व (49.13%) रोसनेफ्ट के पास है, आरोप है कि यह अमेरिका और यूरोप द्वारा एकतरफा रूप से लगाए गए "प्रतिबंधों को दरकिनार" कर सकता है।

जासूसी विरोधी कानून में संशोधन : चीन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, चीन की विधायिका ने चीन के जासूसी विरोधी कानून में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का दायरा व्यापक हो गया।
- ये संशोधन पत्रकारों, विदेशी अधिकारियों, साथ ही चीन में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों के बीच आए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अधिकारियों के निशाने पर आ गए हैं।
- यह केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय "विकास और सुरक्षा" के दोहरे महत्व पर जोर देता है।

चीन का जासूसी विरोधी कानून क्या है?

- हालिया संशोधन चीन के 2014 के जासूसी विरोधी कानून में किए गए हैं। कानून का अनुच्छेद 1 कहता है कि कानून के पीछे का विचार "जासूसी आचरण को प्रतिबंधित करना, रोकना और दंडित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है।"
- यह चीनी उद्यमों और संगठनों सहित प्रति-जासूसी के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा" के साथ-साथ "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण को शामिल करने पर कानून का ध्यान केंद्रित करने के व्यापक दायरे ने चीन में अधिकार समूहों और विदेशी उद्यमों दोनों के बीच चिंता उत्पन्न की।
- विदेशी सरकारें विशेष रूप से चिंतित हैं कि क्या चीनी कंपनियां, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में, अधिकारियों को अपने विशाल डेटा की पेशकश करने के लिए बाध्य होंगी।

- एक अन्य लेख आम नागरिकों को राष्ट्रीय जासूसी विरोधी प्रयासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और किसी भी गतिविधि को संदेहास्पद और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को सूचित करता है।
- उन्होंने कानून के दायरे को और व्यापक कर दिया है, जिसमें से एक परिवर्तन यह घोषणा करता है कि "राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों से संबंधित सभी दस्तावेज़, डेटा, सामग्री और आइटम" को राज्य के रहस्यों के समान ही संरक्षित किया जाएगा।
- साइबर हमलों को शामिल करने के लिए जासूसी की परिभाषा का भी विस्तार किया गया है।

संशोधित कानून का क्या असर होगा?

- संशोधित कानून का चीन के भीतर और बाहर दोनों जगह भयावह प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- चीनी पत्रकार, शिक्षाविद और अधिकारी जो अक्सर विदेशी समकक्षों के साथ जुड़ते हैं, ऐसा करने से पहले दो बार सोचने की संभावना है, कम से कम स्पष्ट सरकारी मंजूरी के बिना, विशेष रूप से डोंग यूयू की गिरफ्तारी के मद्देनजर।
- चीनी और विदेशी विद्वानों के बीच अप्रतिबंधित जुड़ाव, जो शी जिनपिंग युग में पहले से ही सीमित हो गया था, और भी दुर्लभ होने की संभावना है।
- अमेरिकी सलाहकार फर्म बैन एंड कंपनी पर चीनी अधिकारियों द्वारा हाल ही में रिपोर्ट की गई जांच और अमेरिकी ड्यू डिलिजेंस कंपनी मिंट्ज ग्रुप पर छापे के बाद विदेशी उद्यमों के भी चिंतित होने की संभावना है।
- चीन में उपस्थिति वाली भारतीय कंपनियां, विशेष रूप से फार्मा और आईटी जैसे संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में, विस्तारित कानून और "राष्ट्रीय सुरक्षा" की व्यापक परिभाषाओं के तहत जोखिमों के प्रति अपने जोखिम की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से पड़ोसियों के बीच बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर।

भारत ने मालदीव को दो युद्धपोत सौंपें

चर्चा में क्यों?

- मालदीव की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) को भारत में निर्मित दो युद्धपोत सौंपे।

मुख्य बिन्दु:

- इनमें शामिल एक तेज गश्ती पोत (एफपीवी), जो उच्च गति पर तटीय और अपतटीय निगरानी में सक्षम है, को एमएनडीएफ तट रक्षक जहाज हुरवी के रूप में कमीशन किया गया था।
- और एक अन्य जहाज प्रस्तुत किया वह एक लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (LCA) था, जो कर्मियों और उपकरणों को ले जाने और विरोध के बावजूद उन्हें समुद्र तट पर उतारने में सक्षम था।
- वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, भारत ने मालदीव को ऐसी भारतीय रक्षा सहायता की आपूर्ति के लिए क्रेडिट लाइन के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए।

पृष्ठभूमि:

- यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शांति और सुरक्षा के प्रति भारत और मालदीव की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- संबंध 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) की जुड़वां नीतियों से उत्पन्न हुए हैं।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2019 में मालदीव का दौरा किया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति में, "मालदीव सर्वोच्च प्राथमिकता है"।

भारत-इजराइल के बीच औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में समझौता

चर्चा में क्यों?

- भारत और इजराइल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा इजराइल के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय (डीडीआर एंड डी) के बीच औद्योगिक अनुसंधान और विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य विचार:

- यह समझौता ज्ञापन विशिष्ट परियोजनाओं को लागू करने के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत औद्योगिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सहयोग को सक्षम बनाएगा।
- सहयोग में हेल्थ केयर सहित एयरो स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, अवसंरचना तथा इंजीनियरिंग, रसायन तथा पेट्रो केमिकल्स, ऊर्जा उपकरणों सहित सतत ऊर्जा, इकोलॉजी, पर्यावरण, पृथ्वी और समुद्र विज्ञान तथा जल, खनन, खनिज, धातु और पदार्थ, कृषि, पोषण तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल है।

- इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग को आगे बढाया जाएगा तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढाने के लिए सीएसआईआर – डीडीआरएंडडी के प्रमुखों के नेतृत्व में एक संयुक्त संचालन समिति द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।
- उन्होंने इस क्षेत्र में भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर सहयोग का स्वागत किया, जिसमें क्रमश: हाई अल्टीच्यूड प्लेटफॉर्म, सीएसआईआर का हाइड्रोजन वैली प्रोग्राम शामिल हैं।

आगे की राह:

- वर्तमान सीएसआईआर – डीडीआरएंडडी सहयोग एक और पंख जोड़ेगा और यह भारत-इजराइल संबंधों के लिए मील का पत्थर होगा।
- भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहा है और साथ ही भारत और इजराइल में सफल राजनयिक संबंधों के तीस वर्ष पूरे हुए हैं।

सैन्य अभ्यास के दौरान भारतीय और आसियान जहाजों को पार करती चीनी नौकाएं

चर्चा में क्यों?

- चीन ने एक बार फिर समुद्री सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सोमवार को हथियारबंद नौकाओं ने घुसपैठ की। यह घुसपैठ दक्षिण चीन सागर में किया, जहां भारत और आसियान देशों की नौसेनाएं सैन्य अभ्यास में भाग ले रही थीं।
- ऐसा लगता है कि चीन नौसैनिक सैन्य अभ्यास को बाधित करने और भय का माहौल बनाने के लिए हथियारबंद समूहों का इस्तेमाल कर रहा है।

विवरण:

- भारत, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के नौसैनिक जहाजों और विमानों ने आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME 2023) के दो दिवसीय समुद्री चरण में भाग लिया।
- चीनी नौकाएं जब जहाजों की तरफ बढ़ीं तब अभ्यास में शामिल जहाज वियतनामी विशेष आर्थिक क्षेत्र में थे। हालांकि, हथियार बंद नौकाएं और नौसैनिक जहाज बिना किसी संघर्ष के एक-दूसरे को पार कर गए। साथ ही, एक चीनी अनुसंधान पोत भी इन नावों के पीछे उसी क्षेत्र की तरफ आ रहा था।
- ऐसे मिलिशिया में व्यावसायिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं शामिल हैं, जो दक्षिण चीन सागर में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चीनी अधिकारियों के साथ समन्वय में काम करती हैं।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास:

- AIME 2023 में कुल नौ जहाज और छह विमान शामिल थे, इसके अलावा, ब्लॉक के सदस्य राज्यों से 1,800 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया।
- AIME -2023 का हार्बर चरण 2 मई से 4 मई, 2023 तक चांगी नौसेना बेस में आयोजित किया गया, और समुद्री चरण 7 मई से 8 मई, 2023 तक दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया गया।
- AIME -2023 का प्राथमिक लक्ष्य भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र में निर्बाध संचालन करने का अवसर प्रदान करना था।
- आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा ने AIME 2023 के बंदरगाह चरण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में सफलतापूर्वक भाग लिया।

कैलिफोर्निया में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित।

मुख्य बिन्दु:

- यह 'एसबी 403' विधेयक एक मौजूदा कानून में जाति को संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ता है। यह कानून कैलिफोर्निया प्रांत के सभी लोगों को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने, लाभ, सुविधाओं, विशेषाधिकारों या सेवाओं में एक समान अधिकार देता है।
- यह एसबी 403 विधेयक उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन्हें जातिगत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के कारण व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुँचाया गया है।
- यह उन लोगों के लिए दृढ़ कानूनी परिणाम भी प्रदान करता है जो जातिगत भेदभाव और जाति-आधारित हिंसा में भाग लेने या अनुमति देने के लिए जिम्मेदारी या प्रभाव से बचने की मांग करते हैं।

चिंताएं:

- हालांकि, कई भारतीय-अमेरिकियों को डर है कि लोक नीति में जाति को विधिबद्ध करने से अमेरिका में हिंदूफोबिया (हिंदुओं से घृणा की भावना) की घटनाएं बढ़ेंगी।

पृष्ठभूमि:

- सिएटल पहला अमेरिकी शहर था जिसने 2023 की शुरुआत में अपने भेदभाव-विरोधी क़ानूनों में जाति संरक्षण को शामिल किया था, और कई

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने इसी तरह के कदम उठाए हैं।

- जाति-उत्पीड़ित व्यक्तियों के अधिवक्ताओं ने कहा है कि संस्थान और कार्यस्थल जातिगत पूर्वाग्रह से निपटने के लिए कम सुसज्जित हैं, जिसे हाल के वर्षों में अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के बीच प्रलेखित किया गया है।

आगे की राह:

- विभिन्न धार्मिक और जाति पृष्ठभूमि के संगठनों के गठबंधन ने भी बिल का समर्थन किया। कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा अब विधेयक पर विचार करेगी।

एसजी 9 सम्मलेन : दूर संचार क्षेत्र को गति

चर्चा में क्यों?

- पहली बार भारत SG9 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।
- यह बैठक 9 मई से 18 मई, 2023 तक आयोजित की जा रही है, और यह SG9 की पहली भौतिक बैठक है, जो कोविड-19 महामारी के बाद आयोजित की जा रही है।

कार्यक्रम का स्थान:

- भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग (डीओटी) आईआईएससी परिसर में "ब्रॉडबैंड केबल और टेलीविजन / ऑडियोविज़ुअल कंटेंट ट्रांसमिशन और एकीकृत ब्रॉडबैंड केबल नेटवर्क" पर आईटीयू-टी अध्ययन समूह 9 (एसजी -9) की बैठक का आयोजन कर रहे हैं।
- SG9 केबल और ब्रॉडबैंड टीवी के प्रसारण, वितरण और प्रतिपादन के विभिन्न पहलुओं को देखता है।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू):

- वर्ष 1865 में स्थापित, आईटीयू संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है।
- यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं को आवंटित करता है, जबकि तकनीकी मानकों को भी विकसित करता है जो नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को निर्बाध रूप से परस्पर जोड़ना सुनिश्चित करते हैं।
- यह दुनिया भर में वंचित समुदायों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) तक पहुंच में सुधार करने की कोशिश करता है।
- आईटीयू में एसजी 9 दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्राथमिक और द्वितीयक वितरण के लिए दूरसंचार प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें पहुंच सेवाएं और उभरते इंटरैक्टिव मीडिया शामिल हैं।

यूएस, पापुआ न्यू गिनी के बीच रक्षा सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अमेरिका ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि यह प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।

पापुआ न्यू गिनी क्यों?

- यह ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में पापुआ न्यू गिनी की स्थिति इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।
- यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भीषण लड़ाई का स्थल था, और लगभग 10 मिलियन लोगों की आबादी के साथ, यह सबसे अधिक आबादी वाला प्रशांत द्वीप राष्ट्र है।

मुख्य विचार:

- नया समझौता सुरक्षा सहयोग में सुधार करने, पापुआ न्यू गिनी के रक्षा बल की क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और पीएनजी ने अवैध मछली पकड़ने से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए अमेरिकी तट रक्षक गश्ती दल के माध्यम से पीएनजी के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की समुद्री निगरानी बढ़ाने पर एक अलग समझौता किया।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका पीएनजी रक्षा बल के लिए सुरक्षात्मक उपकरण, जलवायु परिवर्तन शमन और अंतरराष्ट्रीय अपराध और एचआईवी/एड्स से निपटने सहित आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए पीएनजी के साथ काम करते हुए नए फंड में $45 मिलियन प्रदान करेगा।
- यह मानवतावादी सहायता और आपदा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए पीएनजी रक्षा क्षमता का विस्तार करेगा, और अमेरिकी और पीएनजी बलों को एक साथ प्रशिक्षित करना आसान बनाएगा।

चीनी प्रभाव:

- अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी और भारतीय प्रधान मंत्री ने PNG की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में 14 प्रशांत द्वीप नेताओं के साथ अलग-अलग शिखर सम्मेलन आयोजित किए, जिसमें क्षेत्र की स्वास्थ्य, विकास और जलवायु परिवर्तन की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन का संकल्प लिया।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी प्रशांत द्वीप राष्ट्रों को चीन के साथ सुरक्षा संबंध बनाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यह

तनाव चीन द्वारा सोलोमन द्वीप के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उत्पन्न हुआ जो ताइवान के चिंता का विषय है।

- यह प्रशांत द्वीपों के नेता, जिनके क्षेत्र 40 मिलियन वर्ग किमी (15 मिलियन वर्ग मील) समुद्र में फैले हुए हैं, ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर उनकी सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राथमिकता हैं।
- यह ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत के क्वाड नेताओं ने जापान के हिरोशिमा में प्रशांत के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी।

पलाऊ के साथ समझौता:

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने पलाऊ के साथ एक कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन पर भी हस्ताक्षर किए, जो संयुक्त $ 7.1 बिलियन के तीन समझौतों में से एक है जो मूल रूप से 1980 के दशक में पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स और फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के साथ किए गए समझौतों को नवीनीकृत करेगा जो अमेरिकी रक्षा जिम्मेदारी और प्रशांत के विशाल रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं।

शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्यकारी दल का वर्चुअली शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्चुअल मोड में शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्यकारी दल की शुरुआत की।
- अमेरिकी शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिकी कार्यकारी दलों की स्थापना की घोषणा 11.04.2022 को वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान की गई थी।

मुख्य बिन्दु:

- यह उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष शैक्षिक संस्थानों, उद्योग हितधारकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। इस सहयोग का उद्देश्य कौशल अंतराल को दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना और दोनों देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- यह प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार कौशल की गुणवत्ता और सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और मान्यता तंत्र के महत्व पर जोर दिया।
- भारतीय पक्ष ने शैक्षणिक योग्यता और कौशल प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता के महत्व को समझाया जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की सुगम गतिशीलता के लिए आवश्यक है।
- यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावना को स्वीकार करते हुए, प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मैचमेकिंग के महत्व पर चर्चा की।
- यह प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और नवाचार और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साझेदारी को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुए।
- यह दोनों पक्ष शैक्षिक संस्थानों के बीच अधिक अंतर-संबंधों को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। भारतीय पक्ष ने प्रस्ताव दिया कि आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त/दोहरे और ट्विनिंग पाठ्यक्रमों के विकास का पता लगाया जा सकता है।
- यह दोनों पक्षों ने नौकरी बाजार की जरूरतों के साथ शिक्षा क्षेत्र को संरेखित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के महत्व को स्वीकार किया।

आगे की राह:

- दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- संयुक्त कार्यकारी दल नियमित बैठकों को जारी रखने और भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और कौशल विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस रास्ते तलाशने पर सहमत हुआ।

भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

- भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में ने नई दिल्ली के रेल भवन में आयोजित एक समारोह में वर्चुअल रूप से 20 ब्रॉड गेज (बीजी) इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत इन डीजल इंजनों को सौंपने से सितंबर 2022 में बांग्लादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान की गई एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पूरी होती है।
- बांग्लादेश रेलवे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय पक्ष ने इंजनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया है। ये इंजन बांग्लादेश में यात्री की बड़ी संख्या और मालगाड़ी संचालन को संभालने में मदद करेंगे।

ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी:

- भारतीय रेलवे सीमा पार रेल संपर्क को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने और दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- अब तक, गेडा-दरसाना, बेनापोल-पेट्रापोल, सिंघाबाद-रोहनपुर, राधिकापुर-बिरोल और हल्दीबाड़ी-चिलहाटी पर पांच ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी जारी हैं।
- दो और सीमा पार रेल संपर्कों, अखौरा-अगरतला और महिहासन-शाहबाजपुर पर कार्य प्रगति पर है और शीघ्र पूरा होने तथा शुरू होने की संभावना है।

यात्री ट्रेनें:

- लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच तीन जोड़ी यात्री रेलगाड़ियां कोलकाता-ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका मिताली एक्सप्रेस चल रही हैं।

द्विपक्षीय व्यापार:

- रेल के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार में प्रति माह वृद्धि हो रही है। दोनों देशों के बीच लगभग 100 मालगाड़ियां चल रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 2.66 मीट्रिक टन माल बांग्लादेश भेजा गया था।
- भारत से बांग्लादेश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में स्टोन, डीओसी, खाद्यान्न, चाइना क्ले, जिप्सम, मक्का, प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।
- वर्ष 2020 से पार्सल कंटेनर और न्यू मॉडिफाइड गुड्स (एनएमजी) रेक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके माध्यम से आम तौर पर कृषि उत्पादों, कपड़ों, तैयार माल, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और ट्रैक्टरों को भेजा जाता है। जियो-सिंथेटिक बैग भेजे जाने की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है और गुजरात से 3 पार्सल रेलगाड़ियां बांग्लादेश भेजी गई हैं।

पृष्ठभूमि:

- बांग्लादेश में रेल सेवा में सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, जुलाई 2020 में अनुदान के आधार पर 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन बांग्लादेश को सौंपे गए थे।

अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्र में रिफाइनरी परियोजना के खिलाफ विरोध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, महाराष्ट्र सरकार ने तटीय रत्नागिरी जिले में राजापुर तहसील के बारसू गांव में मृदा परीक्षण करना शुरू किया, यह जानने के लिए कि क्या साइट प्रस्तावित बहु-अरब डॉलर की रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परियोजना के लिए उपयुक्त है, जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान रिफाइनरी परिसर के रूप में जाना जाता है।
- अप्रैल 2022 तक, भारत की तेल शोधन क्षमता 251.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जिससे यह एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर बन गया।

बारसु रिफाइनरी परियोजना क्या है?

- परियोजना, जिसकी क्षमता 60 मिलियन टन प्रति वर्ष होने की उम्मीद है, सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- इस परियोजना की शुरुआत 2014 में की गई थी और इसकी लागत लगभग तीन लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी।
- यह परियोजना भारत की तेजी से बढ़ती पेट्रोकेमिकल मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स विकसित करने का भी प्रस्ताव करती है।
- शुरुआत में यह परियोजना बारसू से करीब 20 किलोमीटर दूर नानार में बनने वाली थी। हालांकि, स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और शिवसेना के कड़े विरोध के कारण, परियोजना को 2019 में डिनोटिफाई कर दिया गया था।

ग्रामीणों का विरोध

- बारसू-सोलगाँव और पड़ोसी गाँवों के सैकड़ों निवासी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित हैं।
- यह परियोजना एक ऐसे क्षेत्र में है जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, जिसमें क्षेत्र के लिए स्थानिक वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियाँ हैं। कोंकण क्षेत्र में बड़े आम ऑर्किड के साथ-साथ कटहल और काजू के बागान हैं।
- ग्रामीणों ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाई द्वारा उत्पन्न संभावित स्वास्थ्य खतरों के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जिससे बड़ी मात्रा में प्रदूषकों का उत्सर्जन होने की उम्मीद है।
- स्थानीय लोगों के अनुसार, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की उपस्थिति के कारण कोंकण पहले से ही वायु प्रदूषण से पीड़ित है। कई किसानों ने चिंता व्यक्त की कि यदि परियोजना के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया तो वे अपनी आजीविका का स्रोत खो देंगे।

- स्थानीय लोगों का कहना है कि परियोजना को मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे राज्य के अधिक शुष्क क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

क्या है राज्य सरकार का स्टैंड?

- नवंबर 2021 में, शिंदे-फडणवीस सरकार ने शुरुआती 2,220 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए छह गांवों के निवासियों को भूमि अधिग्रहण नोटिस जारी करना शुरू किया।
- यह परियोजना का एक मजबूत समर्थक रहा है और तर्क दिया कि यह कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से एक लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के अलावा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

राजस्थान में लिथियम भंडार मिला

संदर्भ:

- जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की रिपोर्ट्स के मुताबिक नागौर जिले की डेगाना नगरपालिका में लिथियम के पर्याप्त भंडार की पहचान की गई है।
- राजस्थान में मिले इस भंडार में जम्मू-कश्मीर में पाए गए 5.9 मिलियन टन की तुलना से भी काफी अधिक लिथियम है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- राजस्थान में मिले भंडार का लीथियम देश की लगभग 80 फीसदी मांग और जरूरत को पूरा कर सकती है।
- यह लिथियम दुनिया भर में सबसे हल्की और साथ ही सबसे नरम धातु है। यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है और EV बैटरियों में प्रमुख कंपोनेंट्स में से एक है।
- अभी तक भारत लिथियम जैसे कई खनिजों जैसे निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। भारत में लिथियम के भंडार मिलने से अब इसके लिए विदेशों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

वैश्विक उत्पादन:

- इस समय, दुनिया का 47 प्रतिशत लिथियम उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, 30 प्रतिशत चिली में और 15 प्रतिशत चीन में होता है।
- लेकिन, खनिज का 58 प्रतिशत प्रसंस्करण चीन में, 29 प्रतिशत चिली में और 10 प्रतिशत अर्जेंटीना में होता है।

भारत के ईवी उद्योग के लिए महत्व:

- जैसा कि भारत ने राजस्थान में महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज की है, जम्मू और कश्मीर में पहले खोजे गए भंडार के अलावा, देश अगले 4 वर्षों में ईवी के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की स्थिति में है।
- बैटरी, चीन के प्रभुत्व वाली एकल सबसे बड़ी लागत और आपूर्ति होने के नाते, भारत के ईवी उद्योग के लिए एक प्रमुख बाधा रही है।
- हालांकि, 'मेक इन इंडिया' पहल और लिथियम भंडार की खोज के साथ, भारत अब विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करने और लिथियम की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सक्षम है।
- यह विकास न केवल भारत को अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है बल्कि देश के ईवी उद्योग के लिए एक आशाजनक भविष्य बनाते हुए अन्य देशों को लिथियम की आपूर्ति करने की भी अनुमति देता है।

भारतीय डाक करोड़ों कारोबारियों का लॉजिस्टिक्स साझेदार

चर्चा में क्यों?

- भारतीय डाक ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विवरण:

- यह समझौता ज्ञापन 'भारत ई-मार्ट' नामक एक पोर्टल के संचालन की सुविधा प्रदान करता है, जो व्यापारियों के परिसर से प्रेषित वस्तुओं के पिक-अप की सुविधा प्रदान करेगा यह पूरे देश में वस्तुओं को दरवाजे पर वितरण सुनिश्चित करेगा।
- यह माना जा रहा है कि इससे सीएआईटी से जुड़े आठ करोड़ व्यापारियों को लाभ होगा।

समान समझौते:

- हाल के दिनों में भारतीय डाक ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राईफेड) के क्षेत्रीय केंद्रों के साथ इसी तरह के समझौते किए हैं, जिससे वस्तु भेजने वाले व पाने वाले के दरवाजे पर पार्सल की पिक-अप और डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा सके।
- इसके अलावा जल्द ही भारतीय डाक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) मंच में खुद को शामिल कर लेगा। ओएनडीसी मंच को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से एक लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के रूप में विकसित किया जा रहा है।

डाक विभाग का रूपांतरण:

- इससे प्रौद्योगिकी के उपयोग व नई सेवाओं को शामिल करने से भारतीय डाक एक आधुनिक और विविध सेवा प्रदाता बन गया है।
- आज यह 1.59 लाख डाकघरों के अपने नेटवर्क के माध्यम से हर गांव में बैंकिंग व बीमा की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ सरकार की संचालित कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को सुदूर स्थान तक पहुंचाता है।

आगे की राह:

- सीएआईटी और भारत ई-मार्ट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) देश के छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करेगा, जो उनके व्यवसायों व रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा।

अमेरिकी ऋण सीमा पर गतिरोध

चर्चा में क्यों?

- अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने हाल ही में कांग्रेस को सूचित किया कि देश 1 जून की शुरुआत में अपने ऋण चूक सकता है, यदि रिपब्लिकन-वर्चस्व वाले हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव और राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस के बीच ऋण सीमा को बढ़ाने या निलंबित करने के लिए आम सहमति नहीं बन पाई।

अमेरिकी ऋण सीमा क्या है?

- जब संघीय सरकार जितना प्राप्त करती है उससे अधिक खर्च करती है, तो इससे बजट घाटा बढ़ता है। इसके बाद ऋण अर्जित करते हुए अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है।
- सरकार अमेरिकी निवेशकों और कंपनियों, बैंकों, पेंशन फंड, विदेशी निवेशकों और देशों को बॉन्ड जैसी ऋण प्रतिभूतियां बनाकर और बेचकर उधार लेती है। इनमें से सबसे बड़ा भाग स्वयं अमेरिकी संघीय सरकार के पास है, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, चिकित्सा देखभाल, संघीय पेंशन आदि के लिए पैसा रखती है।
- जबकि प्रशासन और कांग्रेस कराधान और खर्च पर निर्णय लेते हैं, करों का संग्रह और धन का उधार यूएस ट्रेजरी विभाग द्वारा किया जाता है।

दूसरा लिबर्टी बॉण्ड अधिनियम:

- वर्ष 1917 में, तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को अनुपस्थित कांग्रेस सांसदों की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना प्रथम विश्व युद्ध के लिए धन निकासी की अनुमति देने के लिए, कांग्रेस ने दूसरा लिबर्टी बांड अधिनियम पारित किया।
- हालांकि, कांग्रेस ने उधार लेने की सीमा तय की (उस समय 11.5 बिलियन डॉलर), इस प्रकार एक ऋण सीमा बनाई गई जिसे केवल कांग्रेस (सदन और सीनेट) के अनुमोदन से ही बढ़ाया जा सकता था।
- यूएस सरकार कई बार कर्ज की सीमा तक पहुंच चुकी है या उसके करीब पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने 1960 के बाद से 78 अलग-अलग बार या तो ऋण सीमा की परिभाषा को स्थायी रूप से बढ़ाने, अस्थायी रूप से बढ़ाने या संशोधित करने के लिए कार्य किया है।
- जबकि सरकार को ऋण सीमा तक पहुँचने के बाद कराधान राजस्व प्राप्त करना जारी है, वह अपने मौजूदा बिलों का भुगतान करने के लिए और अधिक उधार नहीं ले सकती है। अमेरिका तब अपने ऋण-धारकों का भुगतान करने में असमर्थ होगा, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट होगा।

ऋण सीमा गतिरोध आवर्ती मुद्दा क्यों बन गया है?

- कांग्रेस उन कार्यक्रमों को मंजूरी देती है जिनके लिए उसके पास पूरी फंडिंग नहीं होती है। और एक सीमा के भीतर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उधार ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कांग्रेस $100 खर्च को मंजूरी देती है, तो $70 करों से आता है, लेकिन बाकी के भुगतान के लिए सरकार जो उधार ले सकती है, उसकी सीमा मात्र $15 तय की गई है।
- ऋण सीमा पर असहमति राजनीतिक सौदेबाजी का मुख्य कारण बन गया है क्योंकि किसी भी वृद्धि या निलंबन को कांग्रेस द्वारा अनुमोदित किया जाना है। जैसे-जैसे अमेरिकी राजनीति तेजी से ध्रुवीकृत होती जा रही है, विपक्ष ने अक्सर बजटीय और अन्य विधायी रियायतें प्राप्त करने के तरीके के रूप में ऋण सीमा का उपयोग किया है।
- यूएस 2011 में खतरनाक रूप से अपने ऋण पर चूक करने के करीब आ गया जब रिपब्लिकन और ओबामा प्रशासन अंतिम समय तक सीमा बढ़ाने के लिए एक समझौते पर नहीं पहुंच सके। पर्यवेक्षकों ने 2011 की तुलना में हाउस रिपब्लिकन और बिडेन प्रशासन के बीच मौजूदा गतिरोध को और भी गड़बड़ बताया है।
- रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैककार्थी के नेतृत्व वाले सदन ने एक विधेयक पारित किया जिसमें मौजूदा $31.4 ट्रिलियन ऋण सीमा में वृद्धि के साथ खर्च में $4.8 ट्रिलियन की कटौती शामिल है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति स्वच्छ ऋण-सीमा में वृद्धि चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कटौती के लिए बातचीत नहीं करेंगे, जिसके कारण वर्तमान गतिरोध बना हुआ है।

यदि यूएस डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा?

- विश्लेषकों का कहना है कि डिफॉल्ट के बाद का कोई परिदृश्य निर्धारित नहीं है क्योंकि यू.एस. ने वास्तव में इससे पहले कभी भी अपने ऋण पर चूक नहीं की है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी और वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए "विनाशकारी" स्थिति की चेतावनी दी है।
- अगर सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को ब्याज का भुगतान नहीं कर सकती है, जो इसकी ऋण प्रतिभूतियों के मालिक हैं, तो यह विश्व को वित्तीय संकट में डाल सकता है।
- यूएस डिफॉल्ट की "अकल्पनीय" घटना से एजेंसियों द्वारा अमेरिकी साख का एक और डाउनग्रेड हो सकता है, बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हो सकता है, डॉलर का कमजोर होना, स्टॉक की बिकवाली और अमेरिकी सरकार के लिए उधार लेने की लागत में वृद्धि हो सकती है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को नवरत्न का दर्जा

चर्चा में क्यों?

➲ रेल मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला।

आरवीएनएल:

➲ आरवीएनएल को 24 जनवरी, 2003 को पीएसयू के रूप में निगमित किया गया था, जिसका उद्देश्य फास्ट ट्रैक आधार पर रेलवे के बुनियादी ढांचे की क्षमताओं के निर्माण और वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन और एसपीवी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाना था।

➲ यह निदेशक मंडल की नियुक्ति के साथ 2005 में कंपनी का परिचालन शुरू हुआ था।

➲ इस कंपनी को सितंबर, 2013 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 3000 करोड़ रुपये है, जिसकी चुकता शेयर पूंजी 2085 करोड़ रुपये है।

आरवीएनएल को निम्नलिखित काम सौंपे गए हैं :

I. पूर्ण परियोजना जीवन चक्र को कवर करने वाली परियोजना के विकास और कार्यों का निष्पादन करना।

II. यदि आवश्यक हो, तो व्यक्तिगत कार्यों के लिए परियोजना केंद्रित एसपीवी बनाना।

III. आरवीएनएल द्वारा एक रेलवे परियोजना पूरी किए जाने पर, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे इसका संचालन और रखरखाव करेगा।

आगे की राह:

➲ आरवीएनएल को "नवरत्न" का दर्जा मिलने से उसके अधिकार, परिचालन स्वतंत्रता और वित्तीय स्वायत्तता में वृद्धि होगी जिससे आरवीएनएल की प्रगति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। यह विशेष रूप से इसलिए भी अहम है, क्योंकि आरवीएनएल रेलवे से परे और यहां तक कि विदेश स्थित परियोजनाओं में भी अपना विस्तार कर रही है।

बैंक बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने और उसका निपटान करने के लिए 100 दिन का अभियान : आरबीआई

संदर्भ:

➲ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि देश के हरेक जिले में बैंक बिना दावे वाली जमा (अनक्लेम्ड डिपॉजिट) के शीर्ष 100 खातों का निपटान करने के लिए 100 दिनों तक एक विशेष अभियान चलाएगा।

➲ बैंकों का यह अभियान एक जून, 2023 से शुरू होगा।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होते हैं?

➲ RBI के नियमों के मुताबिक, सेविंग्स या करेंट अकाउंट के बैलेंस अमाउंट जिसे 10 साल में कभी ऑपरेट नहीं किया गया हो, या फिर ऐसे टर्म डिपॉजिट जिनका मैच्योर होने की तारीख से 10 साल बाद तक किसी दावा नहीं किया हो, उन्हें 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' (Unclaimed Deposit) कहा जाता है।

➲ लंबे समय तक दावा नहीं किए जाने पर बैंक इन खातों को रिजर्व बैंक के 'जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता' कोष में स्थानांतरित कर देते हैं।

वेब पोर्टल:

➲ हाल ही में, आरबीआई ने जनता के लिए एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल स्थापित करने की भी घोषणा की है, ताकि वे कई बैंकों में दावा न की गई जमा राशि की खोज कर सकें।

➲ आरबीआई समय-समय पर अपनी जन जागरूकता पहलों के माध्यम से जनता के सदस्यों को ऐसी जमाराशियों का दावा करने के लिए संबंधित बैंक की पहचान करने और उससे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है।

आगे की राह:

➲ यह उपाय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में दावा न की गई जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमाराशियों को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों का पूरक होगा।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 'मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

➲ आवासन और शहरी कार्यों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के मेगा अभियान 'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शहर' का शुभारंभ किया।

ट्रिपल आर :

➲ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने अपशिष्ट प्रबंधन-कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण यानी आरआरआर के लिए अभियान शुरू किया गया है जिस का शीर्षक है- 'मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर'।

- शहरी भारत कचरे से 'धन' बनाने के सिद्धांतों को तेजी से अपना रहा है, नागरिक सक्रिय रूप से पुन: उपयोग के लिए पुरानी वस्तुओं को नवीनीकृत कर रहे हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत समग्र शून्य-अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को गति दे रहा है।
- ट्रिपल आर 'वेस्ट टू वेल्थ' यानी कचरे से धन अभियान की रीढ़ है और इसने कई शिल्पकारों, रिसाइकल करने वालों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि को कचरे को कई उत्पादों में बदलने के लिए सशक्त बनाया है।

मुख्य विचार:

- इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य शहरों में कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण(आरआरआर) के लिए एकल संग्रह केंद्र स्थापित करना है, ताकि नागरिकों के कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौने और इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक का पुन: उपयोग या पुनर्नवीनीकरण किया जा सके।
- तीन सप्ताह का यह अभियान एसबीएम-यू 2.0 के तहत कचरे को कम करने, पुन उपयोग करने तथा उसके नवीनीकरण के नागरिकों के संकल्प को मजबूत करेगा और स्थायी दैनिक आदतों को अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सामूहिक कार्रवाई करने के मिशन लाईफ के उद्देश्य को भी बढ़ावा देगा।
- आरआरआर केंद्रों को 20 मई, 2023 को देश भर में लॉन्च किया जाना है और यह नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों आदि के लिए अप्रयुक्त या उपयोग की गई प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़े, जूते, किताबें और खिलौने जमा करने के लिए एकल समाधान के रूप में काम करेगा।
- संग्रह के बाद, इन वस्तुओं को विभिन्न हितधारकों को पुन: उपयोग के लिए नवीनीकृत करने या नए उत्पादों में बनाने के लिए दिया जाएगा, इस प्रकार सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण को सही मायने में आगे बढ़ाया जाएगा।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने आरआरआर थीम गीत प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया।

आगे की राह:

- मेरी लाईफ, मेरा स्वच्छ शहर अभियान का समापन विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून, 2023 को सभी के द्वारा लाईफ के संकल्प के साथ होगा, इसके साथ सभी शहरों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है।

संदर्भ:

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने पिछले 8 वर्षों में 17 प्रतिशत सीएजीआर के साथ लगातार वृद्धि की है। इस साल इसने उत्पादन में एक प्रमुख मानदंड को पार किया है। यहां 105 बिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 9 लाख करोड़ रुपये) का उत्पादन हुआ।

- इससे भारत, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। इस वर्ष 11 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 90 हजार करोड़ रुपये) का मोबाइल फोन का निर्यात किया गया।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की भूमिका बढ़ रही है, और भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है।
- मोबाइल फोन के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) की सफलता को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के पीएलआई योजना 2.0 को स्वीकृति दे दी।

मुख्य विशेषताएं:

- सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की पीएलआई योजना 2.0 के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस आते है।
- इस योजना का बजटीय परिव्यय 17,000 करोड़ रुपये है।
- इस योजना की अवधि 6 वर्ष है
- अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन 3.35 लाख करोड़ रुपये है
- अनुमानित वृद्धिशील निवेश 2,430 करोड़ रुपये है
- अपेक्षित वृद्धिशील प्रत्यक्ष रोजगार 75,000 है

महत्व:

- भारत सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला भागीदार के रूप में उभर रहा है।
- बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर कंपनियों ने भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है। यह देश के भीतर बड़ी मांग रखने वाले मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग द्वारा समर्थित है।
- अधिकांश प्रमुख कंपनियां भारत में स्थित सुविधा से भारत के भीतर घरेलू बाजारों की आपूर्ति करना चाहती हैं और भारत को एक निर्यात केंद्र बनाना चाहती हैं।

आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट का संचालन बंद किया

संदर्भ:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि आरबीआई की घोषणा के मुताबिक, नोट वैध करेंसी बना रहेगा ।
- केंद्रीय बैंक ने जनता को 2000 रुपये के नोट जो छह साल पहले नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद पेश किए गए थे, जमा करने या या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल लेने की सलाह दी है।

RBI ने 2000 रुपए के नोट क्यों बंद कर दिए हैं?

- 2000 रुपये के नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत लाया गया था। 2000 रुपये का नोट लाने का मुख्य उद्देश्य, 500-1000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद कम हुए कैश फ्लो की पूर्ति करना था।
- इस उद्देश्य की पूर्ति के साथ, और अन्य मूल्यवर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बाद, 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
- आरबीआई ने 2000 रुपये के अधिकतर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए थे। आरबीआई ने बताया है कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का निर्णय 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत लिया गया है।

क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

- क्लीन नोट पॉलिसी के तहत RBI जनता को बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है और पुराने नोटों को वापस लेती है।
- आरबीआई ने इससे पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया था क्योंकि उनमें 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सिक्योरिटी फीचर्स हैं।
- हालांकि, 2005 से पहले जारी किए गए नोट लीगल करेंसी बने हुए हैं। उन्हें केवल इसलिए वापस ले लिया गया क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनरूप नहीं थे।

छत्तीसगढ़ के गेवरा में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनाने की योजना : केंद्र

चर्चा में क्यों?

- केंद्र की दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स (एसईसीएल) के छत्तीसगढ़ में गेवरा मेगा परियोजना की क्षमता को एक वर्ष में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन करने की योजना है, जिससे यह एशिया में एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बन जाएगी।
- गेवरा मेगा परियोजना वर्तमान में देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान है और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है।

मुख्य विचार:

- केंद्र गेवरा मेगा परियोजना को एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान बनाने की योजना बना रहा है।
- गेवरा मेगा परियोजना का स्वामित्व एसईसीएल के पास है।
- एसईसीएल एक राज्य के स्वामित्व वाली मिनीरत्न कंपनी है और कोल इंडिया इसकी मूल कंपनी है।

पृष्ठभूमि:

- पूर्वी कालीमंतन में इंडोनेशिया की संगट्टा खदान, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी सतह कोयला उत्पादक खदान थी, जो 2021 में लगभग 49.2 मिलियन टन कोयले और अनुमानित 51.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) रन-ऑफ-माइन का उत्पादन करती थी।

सुरक्षा

सेना की कई ऑटोमेशन पहलों का रियल टाइम, ऑपरेशनल तस्वीर जारी

चर्चा में क्यों?

- संजय प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक नया युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली (बीएसएस) मैदानों, रेगिस्तानों और पहाड़ों में व्यापक सत्यापन के बाद तैनात किए जाने की प्रक्रिया में है।

बीएसएस क्या है?

- बीएसएस के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक सभी फील्ड फॉर्मेशन के लिए निगरानी केंद्र बनाने का लक्ष्य है।
- यह हजारों सेंसरों को एकीकृत करेगा जो आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (एसीसीसीएस) के साथ एकीकृत करके सेंसर-शूटर ग्रिड को पूरा करने के अलावा सभी स्तरों पर कमांडरों और कर्मचारियों को एक एकीकृत निगरानी तस्वीर के प्रावधान को सक्षम बनाएगा।
- यह प्रणाली सेंसर, उपग्रह, यूएवी या मानव रहित हवाई वाहन, और गश्त सहित सीमाओं के पार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भारत के विरोधियों की गतिविधियों पर डेटा को भी एकीकृत करती है।

कार्यान्वयन:

- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), गाजियाबाद, परियोजना का सिस्टम इंटीग्रेटर है, और इलाके में सैकड़ों परीक्षणों के बाद, इसने सेना की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 95% से अधिक की सफलता दर दर्शायी है।
- परीक्षणों के भाग के रूप में, सेना की दो कोर के अंतर्गत कुछ निगरानी केंद्र स्थापित किए गए थे, और अब बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी के साथ, पूरी परियोजना 2025 के अंत तक लागू की जाएगी।

निर्णय समर्थन प्रणाली:

- इन परियोजनाओं को सक्षम बनाने के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए सुरक्षित नेटवर्क का आसन्न संचालन सेवाओं के लिए बैंडविड्थ की प्रचुरता प्रदान करेगा।
- इसके अलावा, सेना देश भर में कैप्टिव डेटा सेंटर स्थापित कर रही है और ये इस वर्ष पूरी तरह से चालू हो जाएंगे।
- बीएसएस का पूरक सेना सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली है, जो पूर्ववर्ती लड़ाकू सूचना निर्णय समर्थन प्रणाली का एक उन्नत और पुन: डिज़ाइन किया गया संस्करण है, जो सभी परिचालन और प्रबंधकीय सूचना प्रणालियों से इनपुट को एकीकृत करेगा।
- सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर द आर्मी (एसएएमए) नामक एक निर्णय समर्थन प्रणाली ने एसीसीसीएस, बीएसएस, ई-सिट्रेप और प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन से इनपुट को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।

आगे की राह:

- यह स्वचालन परियोजनाओं की एक श्रृंखला में से एक है, जिससे परिचालन दक्षता में संचयी रूप से सुधार करने, जमीन पर कमांडरों के लिए युद्धक्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और मानव संसाधन प्रबंधन, रसद, सूची प्रबंधन, चिकित्सा सेवाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यात्मक दक्षता प्रदान करने की उम्मीद है।

रोल ऑफ ऑनर

चर्चा में क्यों?

- अप्रैल 2023 में, पांच महिला कैडेट, जिन्होंने चेन्नई में प्रतिष्ठित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में अपना प्रशिक्षण पूरा किया, ने सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल होकर इतिहास रच दिया।
- हालांकि महिलाओं को 1992 से सेना की सहायक शाखाओं में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, यह पहली बार है जब वे आर्टिलरी, एक लड़ाकू शाखा में प्रवेश कर रही हैं।

विवरण:

- जनवरी 2023 में, सेना प्रमुख जनरल ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि सेना ने महिला अधिकारियों को तोपखाने की शाखा में कमीशन देने का फैसला किया है और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।
- आर्टिलरी में अधिकारियों के रूप में नियुक्त होने के बाद, इन युवतियों से उनकी संबंधित इकाइयों में शामिल होने की उम्मीद है जो बोफ़ोर, धनुष और एम-777 हॉवित्जर, के-9 वजरा स्व-चालित बंदूकें और अन्य को संभालती हैं।

पृष्ठभूमि:

- चेन्नई में ओटीए 1990 के दशक की शुरुआत से सैन्य ज्ञान और नेतृत्व कौशल प्रदान करके महिला कैडेटों को सज्जन कैडेटों के साथ प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दे रहा है।
- इस बार, 121 सज्जन कैडेटों और 36 महिला कैडेटों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उन्हें सेना की विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया।

आईएनएस मगर सेवामुक्त

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग जहाज आईएनएस मगर को 36 वर्षों तक देश की प्रतिष्ठित सेवा के बाद हाल ही में सेवामुक्त कर दिया गया।

आईएनएस मगर के बारे में:

- INS मगर को 16 नवंबर, 1984 को मीरा तहिलियानी द्वारा लॉन्च किया गया था और 18 जुलाई, 1987 को दिवंगत एडमिरल आर एच तहिलियानी द्वारा गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता में कमीशन किया गया था।

सेवाओं के मुख्य अंश:

- अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने समुद्र सेतु सहित कई अभियानों, उभयचर अभ्यासों और मानवीय मिशनों और संचालनों में भाग लिया, जिसमें 4,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को COVID-19 महामारी के दौरान दुनिया के विभिन्न कोनों से वापस लाया गया था।

- जहाज़ ने 2004 में सुनामी के बाद बचे 1,300 से अधिक लोगों को निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भारतीय सेना के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यासों का हिस्सा रहा था।
- वर्ष 2018 में, जहाज को एक प्रशिक्षण जहाज में बदल दिया गया और कोच्चि में पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में शामिल हो गया।

भारत-थाईलैंड कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल (इंडो-थाई कॉर्पेट) का 35वां संस्करण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड कॉर्डिनेटेड पैट्रॉल (इंडो-थाई कॉर्पेट) का 35वां संस्करण 03 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया था।

विवरण:

- भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) केसरी, एक स्वदेश निर्मित एलएसटी (एल) और थाई मैजेस्टी के जहाज़ (एचटीएमएस) सैबुरी, एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट, और दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमानों ने अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पर कॉर्पेट में भाग लिया।

कॉर्पेट के बारे में:

- यह दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना 2005 से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर द्वि-वार्षिक कॉर्पेट अभ्यास का आयोजन कर रही है।
- यह कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर-क्षमता का निर्माण करता है और गैर-कानूनी गैर-नियमित एवं अनियमित (आईयूयू) तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी और सशस्त्र डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और दबाने के लिए उपाय प्रदान करता है।
- यह आगे चलकर तस्करी और अवैध आप्रवासन की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव (एसएआर) अभियानों के संचालन के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करके परिचालन तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है।

सागर:

- भारत सरकार के सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के तहत, भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
- यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, समन्वित गश्ती, संयुक्त ईईजेड निगरानी, और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन के माध्यम से हासिल किया गया है।
- भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसमें गतिविधियों और बातचीत का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुआ है।

आगे की राह:

- 35वां इंडो-थाई कॉर्पेट अंतर-संचालनीयता को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ती के प्रगाढ़ बंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों को आगे ले जाने की दिशा में एक और कदम है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच नौ-सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को विस्तारित करने के अपने समग्र प्रयास के अनुरूप छह दिवसीय समुद्रीय अभ्यास शुरू किया।

विवरण:

- भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस-कवरत्ती, एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और एक चेतक हेलीकॉप्टर को 'समुद्र शक्ति' अभ्यास के तहत तैनात किया है।
- इंडोनेशियाई नौसेना ने युद्धक पोत केआरआई सुल्तान इस्कंदर मुडा, सीएन 235 समुद्री गश्ती विमान और एएस पैंथर हेलीकॉप्टर तैनात किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- अभ्यास के बंदरगाह चरण में नौसैनिकों की एक-दूसरे के पोत पर आवाजाही, पेशेवर सहभागिता और विषय वस्तु के विशेषज्ञों का आदान-प्रदान शामिल है।
- समुद्री चरण के दौरान, हथियारों से फायरिंग, हेलीकाप्टर संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध और वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन की योजना बनाई गई है।
- समुद्र शक्ति दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतरसंक्रियता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी।

आगे की राह:

- अभ्यास 'समुद्र शक्ति' का मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता, जुड़ाव और आपसी सहयोग को बढ़ाना है।

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना के पहले मोर्चे के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत 'आईएनएस मोरमुगाओ' से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।

आईएनएस मोरमुगाओ:

- पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर नामित, मोरमुगाओ ने संयोग से 19 दिसंबर, 2021 को अपनी पहली समुद्री उड़ान भरी, जब गोवा ने पुर्तगाली शासन से 60 साल की मुक्ति का जश्न मनाया।
- 7400 टन के विस्थापन के साथ इस राजसी जहाज की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है।
- जहाज को चार शक्तिशाली गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है, एक संयुक्त गैस और गैस (COGAG) विन्यास में, जो 30 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। जहाज में स्टील्थ विशेषताओं को बढ़ाया गया है जिसके परिणामस्वरूप रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) कम हो गया है।

क्षमताएं:

- आईएनएस मोरमुगाओ परिष्कृत अत्याधुनिक हथियारों और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे सेंसर से सुसज्जित है।
- जहाज में एक आधुनिक निगरानी रडार लगा है जो तोपखाना हथियार प्रणालियों को लक्षित डेटा प्रदान करता है। इसकी एंटी-सबमरीन युद्ध क्षमताएं स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर्स, टॉरपीडो लॉन्चर्स और एएसडब्ल्यू हेलिकॉप्टरों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) युद्ध स्थितियों के तहत लड़ने के लिए सुसज्जित है।

आगे की राह:

- यह विध्वंसक के लिए फायरिंग करने वाली पहली ब्रह्मोस थी और यह 'बुल्स आई' को हिट करने में सफल रही।
- यह समुद्र में 'आत्मनिर्भर' और भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का एक और प्रतीक है।

रोहिंग्या शरणार्थियों को जेल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं

चर्चा में क्यों?

- भारत उन रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दे रहा है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के साथ शरणार्थी स्थिति का निर्धारण पूरा कर लिया है और "पुनर्वास के लिए तीसरे देशों से अनुमोदन प्राप्त किया है", "शरण की छाया: भारत में रोहिंग्या शरणार्थी" शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट में कहा गया है "।
- रिपोर्ट, आज़ादी प्रोजेक्ट, महिलाओं के अधिकारों के लिए गैर-लाभकारी संस्था, और शरणार्थी इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, जो राज्य विहीन लोगों के अधिकारों की वकालत करती है, द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी, जिसे हाल ही में जारी किया गया था।

रिपोर्ट में किया गया दावा:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर सहयोगी देशों और अन्य यूरोपीय देशों में पुनर्वास की वकालत करके "बाहर निकलने के वीजा से इनकार करने के बजाय, भारत अधिक पुनर्वास के अवसरों को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है"।
- एक ओर, जब उन्हें दूसरे देश में बसने का मौका मिलता है तो उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाती है; दूसरी ओर, भारत में रोहिंग्या को "अवैध प्रवासियों" के रूप में बदनाम किया जाता है, जो "मुस्लिम-विरोधी और शरणार्थी-विरोधी ज़ेनोफ़ोबिया" का सामना कर रहे हैं, और म्यांमार वापस भेजे जाने के लगातार डर में रहते हैं।
- भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिनकी संख्या कम से कम 20,000 है, मनमाना हिरासत है। एक बार उठा लेने के बाद, उन्हें "होल्डिंग सेंटर्स" में रखा जाता है, जहाँ स्थितियाँ "दयनीय" होती हैं।

मानवाधिकारों का उल्लंघन:

- वास्तविक और धमकी भरे निर्वासन ने भी रोहिंग्या समुदाय के भीतर भय की भावना को बढ़ावा दिया है, जिससे कुछ लोग बांग्लादेश में शिविरों में लौटने के लिए प्रेरित हुए हैं।
- हालांकि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, बाल अधिकारों पर सम्मेलन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार सम्मेलन भारत को रोहिंग्या को म्यांमार वापस नहीं करने के लिए बाध्य करता है, "सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के तर्कों को स्वीकार किया कि रोहिंग्या एक थे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और निर्वासन को रोकने से इनकार "।

- रिपोर्ट में झुग्गी जैसी बस्तियों में रोहिंग्याओं की कठोर जीवन स्थितियों का विवरण दिया गया है, जहां सुरक्षित बहता पानी या शौचालय नहीं है, और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की शिक्षा, या रोजगार के अवसरों तक कोई पहुंच नहीं है।
- जबकि पहले यूएनएचसीआर कार्ड शिक्षा और आजीविका के कुछ स्तर तक पहुंच प्रदान करते थे, और निरोध और निर्वासन से सुरक्षा प्रदान करते थे, अब सरकार ने यह रुख अपनाया है कि "वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना यूएनएचसीआर शरणार्थी की स्थिति का भारत में कोई महत्व नहीं है"।

आगे की राह:

- यह भारत से औपचारिक रूप से भारत में रोहिंग्या को "अवैध प्रवासियों के बजाय शरण के अधिकार के साथ शरणार्थियों" के रूप में मान्यता देने का आग्रह करता है।
- इसमें से कम, यूएनएचसीआर कार्ड को "मूल शिक्षा, कार्य, और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के लिए पर्याप्त या निवास के प्रमाण के रूप में शरणार्थियों के लिए आधार कार्ड के प्रावधान" के रूप में मान्यता देकर भारत कम से कम "निवास की एक सरल स्वीकृति" कर सकता है।

सामाजिक मुद्दे

इसरो द्वारा पीजी एवं यूजी के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक नया प्रारंभिक स्तर का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 'अंतरिक्ष विज्ञान और प्रोद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) शुरू किया।

मुख्य बिंदू:

- इस कार्यक्रम के तहत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य-पृथ्वी संपर्क, इंस्ट्रुमेंटेशन और एरोनॉमी सहित अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन शामिल किए जाएंगे।
- भारतीय शिक्षा जगत के वैज्ञानिक और इसरो केंद्रों इस कार्यक्रम को संभालेंगे।
- प्रशिक्षण में अंतरिक्ष विज्ञान की क्रॉस-डिसिप्लिनरी प्रकृति पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को इस बात की जानकारी मिलेगी कि क्षेत्र में व्यक्तिगत योग्यताओं को कैसे लागू किया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम से मानव क्षमता के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है जो भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान का नेतृत्व करेगा।
- व्याख्यान में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान अन्वेषण कार्यक्रम और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर विषय भी शामिल होंगे।

रिमोट सेंसिंग कोर्स:

- इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने भी दो लघु पाठ्यक्रमों की घोषणा की है - सुदूर संवेदन आंकड़ा अधिग्रहण और सुदूर संवेदन आंकड़ा संसाधन।
- पाठ्यक्रम एशिया और प्रशांत (सीएसएसटीईएपी) में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और क्रमशः 21 अगस्त से 1 सितंबर और 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हैदराबाद के निकट शादनगर में एनआरएससी के पृथ्वी स्टेशन पर निर्धारित किए जाते हैं।
- CSSTEAP संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक शैक्षणिक संस्थान है।स्टार्ट (START) कार्यक्रम इसरो के उन छात्रों की मदद करने के प्रयासों का हिस्सा है जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाना चाहते हैं।

आगे की राह:

- छात्र इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन, विभिन्न भारतीय संस्थानों में चल रहे शोध का अनुभव, उनकी व्यक्तिगत योग्यता अंतरिक्ष के कुछ पहलुओं के अनुरूप कैसे होगी, इसकी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विषय की क्रॉस-डिसिप्लिनरी प्रकृति की सराहना करते हैं, और तदनुसार अपना कैरियर मार्ग चुनते हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक वर्ष गर्भावस्था, प्रसव या जन्म के पहले सप्ताह के दौरान मरने वाली महिलाओं और शिशुओं की संख्या में आ रही कमी में समस्याएं आ रही है।

विवरण:

- मातृ और नवजात स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में सुधार और मृत जन्म को कम करने की रिपोर्ट ने भारत को शीर्ष पर रखा है, जो वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात जन्म (788,000 कुल मृत्यु) का 17 प्रतिशत है।

- गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की दुनिया भर में अस्वीकार्य रूप से उच्च दर से मृत्यु हो रही है, और COVID-19 महामारी ने उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए और अधिक झटके पैदा किए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच हुए सुधार वर्ष 2010 के बाद के वर्षों की तुलना में तेज़ थे।
- MMR में वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.8% की दर से वार्षिक कमी देखी गई, जो वर्ष 2010 एवं 2020 के बीच घटकर 1.3% हो गई है।
- प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 70 मौतों के MMR के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अगले दशक में इस सूचक को 11.9% तक कम करने हेतु सुधार की आवश्यकता है।
- स्टिलबर्थ रेट (SBR) वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.3% एवं वर्ष 2010 और 2021 के बीच 1.8% कम हो गया था।
- वर्ष 2022 और 2030 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 12 से कम मृत जन्मों के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये 5.2% की दर से इस प्रकार की मौतों में कमी लाने की आवश्यकता है।
- नवजात मृत्यु दर (Neonatal Mortality Rate- NMR) में समान पैटर्न दर्ज किया गया है; वर्ष 2000 और 2009 के बीच 3.2% की कमी, वर्ष 2010 और 2021 के बीच 2.2% की कमी।
- नवजात मृत्यु दर को पूरी तरह नियंत्रित करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये वर्ष 2022 और 2030 के बीच NMR को और 7.2% कम करने की आवश्यकता है।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- भारत के बाद वर्ष 2020 में सबसे अधिक निरपेक्ष मातृ और नवजात मृत्यु तथा मृत जन्म वाले देश नाइजीरिया (540,000 मौतें), पाकिस्तान (474,000), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (241,000), इथियोपिया (196,000), बांग्लादेश (121,000), चीन (108,000), इंडोनेशिया (103,000), अफगानिस्तान (95,000) एवं तंज़ानिया (94,000) हैं।
- मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करने के तीन तरीके हैं: प्रसव-पूर्व देखभाल हेतु कम-से-कम चार बार चिकित्सीय सलाह लेना, जन्म के समय कुशल परिचारक की उपलब्धता और जन्म के बाद पहले दो दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल।
- प्रसव-पूर्व देखभाल कवरेज वर्ष 2010 के 61% से बढ़कर वर्ष 2022 में 68% हो गया है, जिसमें वर्ष 2025 तक 69% की वृद्धि अनुमानित है।
- वर्ष 2010 और 2022 के बीच जन्म के समय कुशल परिचर (attendant) की सुविधा कवरेज 75% से बढ़कर 86% हो गया है तथा वर्ष 2025 तक 88% तक पहुँचने की उम्मीद है।
- प्रसवोत्तर देखभाल कवरेज में उच्चतम सुधार देखा गया है, वर्ष 2010 और 2022 के बीच 54% से 66% तक की वृद्धि के साथ वर्ष 2025 तक यह कवरेज 69% तक पहुँचने का अनुमान है।

आपातकालीन प्रसूति देखभाल:

- मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
- लेकिन उप-सहारा अफ्रीका में ईएमओसी प्रदान करने वाली लगभग 36 प्रतिशत सुविधाओं को उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में 62 प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक ईएमओसी सुविधाओं की तुलना में कार्यशील माना जाता है।
- इस मोर्चे पर सुधार से मातृ मृत्यु को कम करने में काफी मदद मिल सकती है, जिसका एक प्रमुख कारण प्रसवोत्तर रक्तस्राव है, जिसे जन्म के 24 घंटे के भीतर 500 मिलीलीटर से अधिक रक्त के नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रसवोत्तर रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेपों का एक सेट भारी रक्तस्राव को 60 प्रतिशत तक कम कर सकता है, एक नए अध्ययन से पता चला है।

लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण:

- एक लिंग परिवर्तनकारी दृष्टिकोण मातृ और नवजात मृत्यु दर को संबोधित कर सकता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, भेदभाव, गरीबी और अन्याय जैसे खराब मातृ स्वास्थ्य परिणामों को जन्म देने वाले अंतर्निहित कारकों को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य

COVID महामारी अब एक आपात स्थिति नहीं है : WHO

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि COVID-19 अब वैश्विक आपातकाल के रूप में योग्य नहीं है।

अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य खतरा:

- इसमें कहा गया है कि भले ही आपातकालीन चरण खत्म हो गया था, लेकिन महामारी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने अपने मामले का समर्थन करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में मामलों में हालिया उछाल की ओर इशारा किया।
- डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हजारों लोग अभी भी हर हफ्ते वायरस से मर रहे हैं, और लाखों अन्य दुर्बल, दीर्घकालिक प्रभावों से पीड़ित हैं।
- महामारी एक साल से अधिक समय से नीचे की ओर बढ़ रही थी, यह स्वीकार करते हुए कि अधिकांश देश कोविड-19 से पहले ही जीवन में लौट आए हैं।

पृष्ठभूमि:

- जब संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने पहली बार 30 जनवरी, 2020 को कोरोनवायरस को एक अंतरराष्ट्रीय संकट घोषित किया था, तब

तक इसे कोविड-19 नाम नहीं दिया गया था और चीन के बाहर कोई बड़ा प्रकोप नहीं था।

- तीन साल से अधिक समय के बाद, वायरस के कारण विश्व स्तर पर संक्रमण के अनुमानत: 76.4 करोड़ मामले सामने आए और लगभग पांच अरब लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक मिली है।
- डब्ल्यूएचओ ने अपने उच्चतम स्तर की सतर्कता बढ़ा दी और संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल करार दिया, जो तीन साल से अधिक समय तक बना रहा।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम(एलएमआईएस),सक्षम (स्टिम्युलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट) का शुभारंभ किया।
- यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।

सक्षम क्या है?

- देश के सभी स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरो के लिए सक्षम ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने का एक समर्पित और एकीकृत मंच है।
- यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के तृतीयक देखभाल से लेकर महानगरों के कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी रूप से दक्षता-उन्नयन सुनिश्चित करेगा।
- वर्तमान में सक्षम: एलएमआईएस 200 से अधिक नागरिक स्वास्थ्य और 100 से अधिक नैदानिक चिकित्सा को वर्चुअल माध्यम से चला रहा है। मानदंडो को पूरा करने के बाद प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।

नॉन शुगर स्वीटनर्स पर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन

ख़बरों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चीनी के "स्वस्थ" विकल्प के रूप में गैर-चीनी मिठास (NSS) जैसे कि एस्पार्टेम, सैकरीन, स्टीविया और अन्य डेरिवेटिव के उपयोग के खिलाफ सलाह देते हुए नए दिशानिर्देश जारी।

विवरण:

- अपने 'सशर्त' दिशानिर्देश में, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वजन नियंत्रण प्राप्त करने या आहार से संबंधित गैर-संचारी रोगों के जोखिम को कम करने के साधन के रूप में नॉन-शुगर स्वीटनर्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- एनएसएस पर स्पॉटलाइट 2015 के बाद तेज हो गई, जब डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि चीनी का अधिक सेवन वजन बढ़ने और मोटापे से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उपभोक्ता विकल्प के रूप में एनएसएस की ओर रुख कर रहे हैं।

गैर-चीनी मिठास क्या हैं?

- गैर-चीनी मिठास (NSS) को मुक्त शर्करा के कम या बिना-कैलोरी विकल्प के रूप में विपणन किया जाता है जो वजन घटाने में सहायता करता है, और मधुमेह वाले व्यक्तियों में रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।
- WHO द्वारा अध्ययन की गई NSS श्रेणियों में acesulfame K, aspartame, advantame, cyclamates, neotame, saccharin, sucralose, और stevia डेरिवेटिव शामिल हैं।
- Aspartame लोकप्रिय रूप से डायट कोला को मीठा करने के लिए उपयोग किया जाता है जो 'कोई चीनी नहीं, कोई कैलोरी नहीं' होने का दावा करते हैं। Saccharin का उपयोग चाय या कॉफी को मीठा बनाने के लिए किया जाता है।

डब्ल्यूएचओ का आकलन

- डब्ल्यूएचओ ने वयस्कों और बच्चों में एनएसएस के सेवन पर कुल 283 अध्ययनों का विश्लेषण किया। परीक्षणों का परिणाम यह था कि उन्होंने नोट किया कि एनएसएस का 'उच्च सेवन' मोटापे के जोखिम में 76% वृद्धि और बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) में 0.14 किग्रा/एम2 वृद्धि से जुड़ा था।
- डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि एनएसएस के लंबे समय तक इस्तेमाल से टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

चिंताएं क्या हैं?

- नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को लोगों को गैर-चीनी मिठास पर मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए क्योंकि नौ में से एक महिला और 25 में से एक पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।
- मोटे लोगों को मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में अनुमानित 2.5 करोड़ लोग प्री-डायबिटीज के साथ जी रहे हैं।

WHO की पोषण संबंधी सलाह क्या है?

- डब्लूएचओ का कहना है कि जब वजन घटाने के अध्ययन की बात आती है तो एनएसएस की भूमिका को अलगाव में देखना मुश्किल होता है, इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस मैट्रिक्स में गुणवत्ता (पोषण प्रोफ़ाइल) और आहार की मात्रा भी महत्वपूर्ण है।
- यह वैकल्पिक खाद्य पदार्थ रखने की सिफारिश करता है जो कम से कम संसाधित, बिना चीनी वाले खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हैं।
- अध्ययनों का विश्लेषण करते हुए, डब्ल्यूएचओ ने पाया है कि कुछ विषयों में वजन घटाने को पूरी तरह से चीनी से एनएसएस पर स्विच करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह भोजन के कम हिस्से के आकार या ऊर्जा सेवन पर भी निर्भर करता है।

आगे क्या?

- स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रीय नीति के रूप में इस 'सशर्त' सिफारिश को अपनाने का फैसला करने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा शुरू करनी होगी।
- डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि इस दिशानिर्देश की मदद से, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वाद वरीयताओं और खाने के व्यवहार को बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ऑफ-द-शेल्फ घटकों से विकसित नए कम लागत वाले स्टार सेंसर का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च

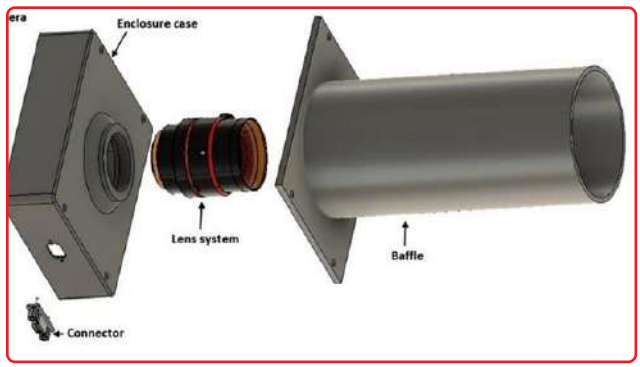

चर्चा में क्यों?

- ऑफ-द-शेल्फ घटकों से खगोलविदों द्वारा विकसित एक नया निम्न-लागत स्टार सेंसर हाल ही में इसरो द्वारा पीएसएलवी सी-55 पर लॉन्च किया गया था।
- अपने पहले अंतरिक्ष परीक्षण में पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) पर स्थापित सेंसर अच्छा निष्पादन कर रहा है और आरंभिक डेटा ने अब इसकी रूपरेखा तथा इसके कार्य को भी सत्यापित कर दिया है।

स्टारबेरीसेंस पेलोड

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) द्वारा विकसित स्टारबेरीसेंस पेलोड 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया था।
- इस अभिनव निम्न-लागत सेंसर, जिसका डिजाइन शीघ्रता से यह गणना करने के लिए किया गया है कि उपग्रह कहां इंगित कर रहा है, इसका पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण किया जा रहा है।
- स्टार बेरी सेन्स ने न केवल अंतरिक्ष में कठिन स्थितियों को सहन किया है बल्कि अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर रहा है, प्रारंभिक डेटा यह भी दर्शाता है कि यह (प्वाइंटिंग डायरेक्शन) इंगित दिशा की गणना करने में सक्षम है।
- स्टार्ट सेंसर अंतरिक्ष में अपने दृश्य के क्षेत्र में सितारों की पहचान करने के द्वारा अंतरिक्ष में अपने प्वाइंटिंग डायरेक्शन को प्राप्त करने में सक्षम है।
- इस पेलोड का निर्माण विख्यात मिनी कंप्यूटर स्पचबेरी पी के ईर्द-गिर्द किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर को इन-हाउस डिजाइन किया गया था।

आगे की राह:

- किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी समय उपग्रह को कहां इंगित किया जा रहा है। जहां ऐसा करने के कई तरीके हैं, एक स्टार सेंसर किसी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान के ओरिएन्टेशन के बारे में सबसे सटीक जानकारी प्रदान करता है।

ऑप्टिकल ट्वीजर्स का उपयोग करके मृदु कोलाइड्स (सॉफ्ट कोलाइड्स) में कणों को ट्रैक करने की नई विधि जो लक्षित औषधि वितरण करेगा

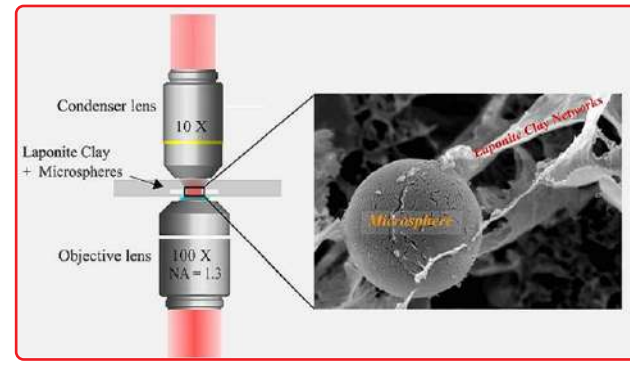

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों ने प्रकाशिक चिमटी (ऑप्टिकल ट्वीजर्स) का उपयोग करके मृदु मिट्टी के कोलाइड्स के अंदर मिट्टी के कणों की गति को जांचने (ट्रैक करने) की ऐसी विधि का पता लगाया है - जिसके जैविक प्रणालियों में उपयोग ने 2018 में उसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलवाया।
- कणों को ट्रैक करके एक वांछित लक्ष्य के रूप में उनमे हेरफेर करने के बाद इस नई विधि का लक्षित दवा वितरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

लैपोनाइट:

- ऐसी ही प्रकाशिक चिमटी (ऑप्टिकल ट्वीजर्स) का उपयोग करते हुए रमन अनुसंधान संस्थान (रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट-आरआरआई) के शोधकर्ताओं ने एक संश्लेषित (सिंथेटिक) मिट्टी - लैपोनाइट की गतिशीलता और उसमे छिपे हुए संरचनात्मक विवरणों का अध्ययन करने का प्रयास किया।

- चूंकि ये मिट्टी के कण समान आकार (मोनोडिस्पर्स) वाले और पारदर्शी होते हैं, इसलिए वे प्रकाश के अंतर्गत उन्नत अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं।
- लैपोनाइट औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली अपरिष्कृत सामग्री है। इस मिट्टी में डिस्क के आकार के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 25 से 30 नैनोमीटर (एनएम) और मोटाई एक एनएम होती है।
- प्रायोगिक सेटअप के लिए लैपोनाइट के क्ले सस्पेंशन में बिखरे हुए पॉलीस्टीरीन बीड्स का उपयोग किया गया था। समय बीतने के साथ ही मिट्टी के कणों के बीच स्थिरवैद्युतिकीय संक्रिया (इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन) के कारण सूक्ष्मसंरचनाओं (माइक्रोस्ट्रक्चर्स) विकसित होने का उल्लेख किया गया था।
- ये माइक्रोस्ट्रक्चर समय बीतने के साथ मजबूत होते गए जबकि उनके नेटवर्क का आकार लैपोनाइट कणों की सांद्रता पर निर्भर करता था।

प्रयोग और परिणाम:

- टीम ने इस कार्य के लिए ऑप्टिकल चिमटी (ट्वीजर) का प्रयोग किया क्योंकि वे नैनोमीटर पैमाने (स्केल) में जांच की गति को मापना चाहते थे, क्योंकि ऐसे में समय बीतने के साथ माध्यम के गुण विकसित होते हैं।
- ऑप्टिकल ट्वीजर एक प्रकाशिकी प्रयोगशाला में उपलब्ध एक लोकप्रिय उपकरण है, जिसका उपयोग सूक्ष्म बलों को मापने और कुछ नैनोमीटर तक लंबाई के पैमाने पर एक गहन लेजर बीम के तंग फोकस पर फंसे हुए द्विविद्युतीय (डाईइलेक्ट्रिक) दानों (बीड्स) में हेरफेर करने के लिए किया जाता है।
- यह जाच के लिए फंसे हुए कण में गति को उत्प्रेरित करने की अनुमति देता है, और इसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण अंतर्निहित माध्यम के पहले से अप्राप्य स्थानीय विस्कोएलास्टिक गुणों को जान्ने के लिए किया जाता है।
- इसके अलावा, इस टीम ने लैपोनाइट माइक्रोस्ट्रक्चर द्वारा निर्मित औसत छिद्र क्षेत्रों की जांच करने के लिए क्रायोजेनिक फील्ड उत्सर्जन (इमीशन) स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (क्रायो-एफईएसईएम) का उपयोग किया।

निष्कर्ष:

- इस प्रकार रमन अनुसंधान संस्थान (आरआरआई) की टीम ने मिट्टी की निलंबन (सस्पेंशन) संरचनाओं की आकारिकी (मोर्फोलोजी) और माइक्रोमीटर लंबाई के पैमाने पर जांच कण गतिकी के बीच प्रत्यक्ष संबंध के प्रसार पर अपना निष्कर्ष निकाला।

नई तकनीक जो सरल यांत्रिक कंपन को बिजली में परिवर्तित करती है

चर्चा में क्यों?

- स्वच्छ ऊर्जा की भूखी दुनिया में, इंजीनियरों ने एक नई तकनीकी बनाई है जो पेसमेकर से लेकर अंतरिक्ष यान तक हर चीज में सामान्य यांत्रिक कंपन को बिजली में पावर सेंसर में बदल देती है।
- वाटरलू विश्वविद्यालय और टोरंटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा अपनी तरह का पहला, उपन्यास उत्पादन प्रणाली कॉम्पैक्ट, भरोसेमंद, कम लागत वाली और बहुत, बहुत हरी है।

पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव:

- प्रणाली पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित है, जो एक उपयुक्त पदार्थ पर दबाव डालकर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है।
- प्रभाव 1880 में खोजा गया था, और तब से, सीमित संख्या में पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री, जैसे कि क्वार्ट्ज और रोशेल साल्ट, का उपयोग सोनार और अल्ट्रासोनिक इमेजिंग से लेकर माइक्रोवेव उपकरणों तक की तकनीकों में किया गया है।
- समस्या यह है कि अब तक, वाणिज्यिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री की बिजली पैदा करने की सीमित क्षमता थी।

एडाब्को कॉपर:

- उन्होंने जाह्न-टेलर प्रभाव का उपयोग करते हुए एडैबको कॉपर क्लोराइड नामक एक आणविक धातु-हैलाइड यौगिक के एक बड़े एकल क्रिस्टल को विकसित करके शुरू किया, जो एक क्रिस्टल क्षेत्र के सहज ज्यामितीय विरूपण से संबंधित एक प्रसिद्ध रसायन विज्ञान अवधारणा है।
- अत्यधिक पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री का उपयोग रिकॉर्ड शक्ति घनत्व के साथ नैनोजेनरेटर बनाने के लिए किया गया था जो किसी भी गतिशील परिस्थितियों में मानव गति से ऑटोमोटिव वाहनों तक एक ऐसी प्रक्रिया में छोटे यांत्रिक कंपन का उत्पादन कर सकता है जिसमें न तो सीसे की आवश्यकता होती है और न ही गैर-नवीकरणीय ऊर्जा की।
- नैनोजेनरेटर छोटा, 2.5 सेंटीमीटर वर्गाकार और एक बिजनेस कार्ड की मोटाई के बारे में है और इसे अनगिनत स्थितियों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।

आगे की राह:

- इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आवश्यक अरबों सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विशाल श्रृंखला में सेंसर को शक्ति देने की क्षमता है।
- भविष्य में, एक विमान का कंपन इसकी संवेदी निगरानी प्रणालियों को शक्ति प्रदान कर सकता है, या किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन उनके बैटरी-मुक्त पेसमेकर को चालू रख सकती है।

वैज्ञानिकों चंद्रमा के भीतर का अवलोकन करेंगे

चर्चा में क्यों?

- नासा ने घोषणा की है कि 2025 तक चार अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर एक लंबी स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे।

➲ लेकिन, मनुष्यों के लौटने से पहले, चंद्र सतह के प्रमुख विवरणों को जानना अत्यावश्यक है जो सुचारू संचालन सुनिश्चित कर सके।

चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र का विकास:

➲ अपोलो मिशन के आधी सदी से भी अधिक समय बाद, जिसने चंद्र के सतह का अध्ययन के द्वार खोल दिए, खगोलविदों ने हुड के नीचे का अध्ययन किया और इसकी आंतरिक संरचना के भाग प्रकट किए।

➲ एक अध्ययन में, वैज्ञानिक आंतरिक कोर के अस्तित्व के प्रदर्शन के कारण चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र के विकास पर सवाल उठाते हैं और एक वैश्विक मेंटल ओवरटर्न परिदृश्य का समर्थन करते हैं जो सौर मंडल के एक अरब वर्षों में चंद्र बमबारी के समय पर पर्याप्त अंतर्दृष्टि लाता है।

ठोस क्रोड़:

➲ वैज्ञानिकों की एक टीम ने खुलासा किया कि चंद्रमा का पृथ्वी की तरह एक ठोस कोर है और चंद्र परत में लौह युक्त सामग्री है।

➲ चंद्रमा का ठोस कोर लगभग 500 किलोमीटर व्यास का है, या इसके आकार का लगभग 15 प्रतिशत है, और यह एक ऐसी धातु से बना है जिसका घनत्व लोहे के घनत्व के करीब है।

➲ उन्होंने मेंटल में भौतिक विस्थापन के प्रमाण भी पाए, जो चंद्रमा के विकास के दौरान कोर और क्रस्ट के बीच की मध्यवर्ती परत है।

➲ इसे लूनर मेंटल का उत्क्रमण कहा जाता है और यह चंद्रमा की सतह पर आयरन युक्त तत्वों की उपस्थिति की व्याख्या करने में मदद करता है।

➲ वे अनुमान लगाते हैं कि सामग्री सतह पर आ गई होगी और चंद्रमा की पपड़ी में ज्वालामुखीय चट्टानें जमा हो गई होंगी। फिर, क्रस्ट में आसपास की सामग्री की तुलना में बहुत घने तत्व वापस गिर गए और मेंटल और कोर के बीच इंटरफेस में वापस आ गए।

आगे की राह:

➲ यह कार्य आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है, विशेष रूप से सौर मंडल के इतिहास को सूचित करने और कुछ घटनाओं को समझने के लिए, जैसे कि चंद्र चुंबकीय क्षेत्र का गायब होना: मूल रूप से वर्तमान पृथ्वी की तुलना में सौ गुना अधिक शक्तिशाली, यह आज लगभग न के बराबर है।

बिट्स-पिलानी (हैदराबाद) ने सेंसर के साथ बीमारी का पता लगाने वाला मास्क विकसित किया

सन्दर्भ:

➲ यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक फेस मास्क COVID-19 और अन्य श्वसन रोगों से रक्षा कर सकता है।

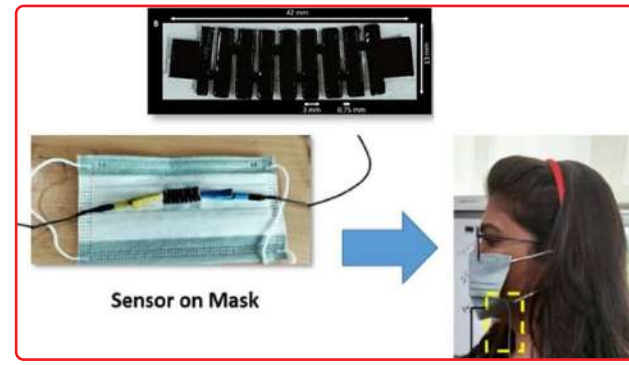

➲ जैसा कि बिट्स-पिलानी हैदराबाद परिसर में माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम्स, माइक्रोफ्लुइड्स और नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स लैब के शोधकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है, अब इसका उपयोग किसी के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एक गैर-आक्रामक उपकरण के रूप में भी किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

➲ उन्होंने सर्जिकल मास्क के साथ रीयल-टाइम अटैचमेंट के लिए एक 3-डी कार्बन नैनोमटेरियल किरिगामी-आधारित स्ट्रेचेबल, लचीला लेजर प्रेरित ग्राफीन (एलआईजी) डिजाइन और विकसित किया।

➲ एलआईजी सांस की दर (बीआर) या श्वसन दर (आरआर), शरीर के तापमान, नाड़ी की दर, और रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक संकेतों की निगरानी के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री है।

➲ शोधकर्ताओं ने साँस लेने और छोड़ने के दौरान प्रतिरोध में परिवर्तन को मान्य करके कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के सांस पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए गैस मास्क से जुड़े सेंसर का उपयोग किया।

अनुप्रयोग:

➲ सांस लेने की दर सामान्य तौर पर उम्र के आधार पर भिन्न होती है जब तक कि व्यक्ति बीमार न हो। आरआर और बीआर को मापकर, किसी व्यक्ति की फिटनेस को ब्रीथ इंडेक्स द्वारा या बस निर्धारित किया जा सकता है।

➲ संवेदक को बिना किसी जलन के मुंह और नाक के ऊपर रखा जा सकता है और स्थिर कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

➲ स्वास्थ्य देखभाल, रोग निदान, ई-त्वचा, और इसी तरह की पहचान क्षमता एक सेकंड से भी कम होने के साथ विभिन्न परिदृश्यों में आवेदन किए गए हैं।

इसरो ने तमिलनाडु महेंद्रगिरि में नई केंद्र में रॉकेट इंजन का परीक्षण शुरू किया

चर्चा में क्यों?

➲ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में हाल ही में कमीशन किए गए सेमी-क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण शुरू कर दिया है।

➲ इसरो प्रणोदन परिसर (आईपीआरसी) में परीक्षण सुविधा विकसित की गई है।

विवरण:

- इस सुविधा में प्रणोद कक्ष को छोड़कर सभी इंजन प्रणालियां शामिल हैं।
- परीक्षण कम दबाव और उच्च दबाव टर्बो-पंप, गैस जनरेटर, और नियंत्रण घटकों सहित प्रणोदक फ़ीड प्रणाली के डिजाइन को मान्य करने के लिए नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला में से पहला है।
- 2000 kN प्रणोद की शक्ति वाला सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, जो भविष्य के लॉन्च वाहनों के पहले चरण के बूस्टर को शक्ति प्रदान करेगा, इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (LPSC) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- यह लिक्विड ऑक्सीजन (LOX)-मिट्टी के तेल प्रणोदक संयोजन पर काम करता है।

परिणाम:

- इस परीक्षण ने पहले प्रयास में ही परीक्षण सुविधा और पावर हेड टेस्ट लेख के सफल प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है।

नई अंतरिक्ष नीति:

- केंद्र द्वारा हाल ही में मंजूर की गई नई अंतरिक्ष नीति में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से हटेगा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा।
- इसमें कहा गया है कि इसरो, मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास पर और बाह्य अंतरिक्ष की मानवीय समझ का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आगे की राह:

- इसरो आने वाले महीनों में दो बड़े मिशन लॉन्च करने की तैयारी के अंतिम चरण में है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य एल-1 मिशन और चंद्रयान-3 मिशन, जिसे चंद्रमा पर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में प्रो. जयंत वी. नार्लीकर, उत्कृष्ट खगोलशास्त्री, आईयूसीएए, पुणे के संस्थापक निदेशक ने पहला एएसआई गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया।

आईयूसीएए:

- इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में न्यूक्लिएशन और सक्रिय समूहों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।

प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के बारे में:

- प्रो. स्वरूप को व्यापक रूप से भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है।
- उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप (ओआरटी) और जायंट मेट्रूवेव रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरटी) के निर्माण की कल्पना की और भारतीय पर्यावरण के लिए अनुकूलित नवीन, लागत प्रभावी विचारों का उपयोग करते हुए इसका नेतृत्व किया।
- वह एक दूरदर्शी और स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (एसकेए) के सबसे मजबूत शुरुआती समर्थकों में से एक थे।
- वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (एनसीआरए), पुणे के संस्थापक निदेशक थे।

गगनयान के लिए री एंट्री कैप्सूल पैराशूट बेंगलुरु में इसरो सुविधा के लिए भेजे गए

चर्चा में क्यों?

- प्रस्तावित गगनयान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले कैप्सूल की सुरक्षित वापसी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पैराशूट जुलाई में बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की सुविधा में फिटमेंट परीक्षणों से गुजरने के लिए तैयार हैं।

- गगनयान में पृथ्वी की निचली कक्षा में तीन अंतरिक्ष यात्रियों के चालक दल को भेजने की परिकल्पना की गई है।

विकासकर्ता:

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत आगरा स्थित प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ADRDE) ने भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान के लिए पैराशूट विकसित किया है।

विन्यास:

- पैराशूट विन्यास में 10 पैराशूट होते हैं। उड़ान के दौरान अनुक्रम "एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट" के दो पैराशूटों की तैनाती के साथ शुरू होता है, जो क्रू मॉड्यूल पैराशूट कम्पार्टमेंट के लिए सुरक्षा कवर है, इसके बाद गति को स्थिर करने और नीचे लाने के लिए दो और "ड्रग पैराशूट परिनियोजन" होते हैं।
- ड्रग पैराशूट रिलीज होने पर, "पायलट पैराशूट" प्रणाली के तीन पैराशूटों का उपयोग "मुख्य पैराशूट" के तीन पैराशूटों को अलग-अलग निकालने के लिए किया जाएगा, ताकि लैंडिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल की गति को सुरक्षित स्तर तक कम किया जा सके।

आगे की राह:

- परीक्षण वाहन प्रदर्शन (TVD-1) उड़ान देश के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने तेलंगाना में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया।

मुख्य विचार:

- नवीन एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला (बीसी लैब) एनआईपीएचएम में स्थापित की गई एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है, जिसमें जैव कीटनाशकों और जैव नियंत्रण एजेंटों के लिए उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की सुविधा है। इनमें प्रेडटर्स और पैरासाइटोइड्स, एंटोमोपैथोजेनिक कवक, जैव उर्वरक, एनपीवी, फेरोमोन और वनस्पतियां शामिल हैं।
- जैव-नियंत्रण एजेंटों, जैव-कीटनाशकों एवं जैव-उर्वरकों का उपयोग रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने में मदद करेगा, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकेगा और इससे मिट्टी एवं पौधों के स्वास्थ्य में सुधार की गतिविधियां संचालित करने में सहायता मिलेगी।
- नवीन एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला में एक कीट संग्रहालय, खरपतवार संग्रहालय, प्रदर्शनी हॉल, प्राकृतिक कृषि प्रकोष्ठ आदि भी होंगे, जहां पर कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीटों एवं खरपतवारों के नमूनों को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित या जीवित रूपों में प्रदर्शित किया जाएगा।

एनआईपीएचएम:

- एनआईपीएचएम विभिन्न जैविक एजेंटों, जैव-कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के साथ कीट प्रबंधन के लिए कृषि पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (एईएसए) तथा पारिस्थितिक इंजीनियरिंग (ईई) जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- एनआईपीएचएम विभिन्न फसलों में कीट और रोग प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

आगे की राह:

- एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला जैसी सुविधा की शुरुआत होना भारत में रसायन मुक्त टिकाऊ कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- यह सुविधा देश में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में कृषि अधिकारियों, एक्सटेंशन अधिकारियों तथा किसानों के ज्ञान व कौशल को बढ़ाने में भी मदद करेगी।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे धूमकेतु को देखा है, जिसके आसपास पानी है।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी), दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशाला ने मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में एक धूमकेतु पर पानी का पता लगाया है।
- मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट सूर्य के चारों ओर केंद्रित मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है।

मुख्य विचार:

- वेब पर लगे नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण ने धूमकेतु 238P/रीड पर जल वाष्प का पता लगाया, हालांकि, अन्य धूमकेतुओं के विपरीत, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है।
- धूमकेतु 238P/रीड समय-समय पर एक प्रभामंडल या कोमा प्रदर्शित करता है और यह स्थापित करने वाले पहले लोगों में से एक था कि क्षुद्रग्रह बेल्ट में धूमकेतु हैं।
- इससे पहले, यह काफी हद तक माना जाता था कि धूमकेतु नेपच्यून की कक्षा से परे, सौर मंडल के किनारे कुइपर बेल्ट में रहते हैं।
- वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अनुमान लगाया है कि पानी की बर्फ को बृहस्पति की कक्षा के अंदर गर्म क्षुद्रग्रह बेल्ट में संरक्षित किया जा सकता है और नई पुष्टि ने उनकी अटकलों को मान्य किया है।

अवलोकन:

- अध्ययन में कहा गया है कि हालांकि मेन-बेल्ट धूमकेतु के अस्तित्व का मतलब क्षुद्रग्रह बेल्ट में पानी की बर्फ की मौजूदगी से है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीनों के साथ गहन जांच के बावजूद इन वस्तुओं के आसपास कोई गैस नहीं मिली है।
- अवलोकन का आश्चर्यजनक कारक गायब कार्बन डाइऑक्साइड रहा, जो एक धूमकेतु में वाष्पशील सामग्री का लगभग 10 प्रतिशत बनाता है जिसे सूर्य की गर्मी से आसानी से वाष्पित किया जा सकता है।
- उनका मानना है कि धूमकेतु के बनने के समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था लेकिन गर्म तापमान के कारण वह कार्बन डाइऑक्साइड खो चुका है।

महत्व:

- यह पहली बार है कि वैज्ञानिक इस क्षेत्र में पानी के संकेतों का पता लगाने में सक्षम हुए हैं जो उन्हें पृथ्वी के करीब एक और रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं - पृथ्वी को पानी कैसे मिला?

भारत के हिमालयन टेलीस्कोप अध्ययन में ब्रह्माण्ड की सबसे ऊर्जावान पिंडों में से एक का अवलोकन किया

चर्चा में क्यों?

- भारत के लद्दाख में स्थित हेनल वेधशाला और दुनिया के अन्य 10 टेलीस्कोप की मदद हुए अध्ययन में ब्रह्माण्ड की सबसे ऊर्जावान पिंडों में से एक का अवलोकिन किया गया है।
- इस शोध में वैज्ञानिकों ने बीएल लैसर्टे (बीएल लैक) नाम के ब्लेजार की चमक को विशेष तौर पर अवलोकित किया गया जो पृथ्वी से 95 करोड़ प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है।

ब्लेज़र क्या है?

- ब्लेज़र एक प्रकार की आकाशगंगा है जो एक विशाल ब्लैक होल द्वारा संचालित होती है और ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है।
- ब्लेजार को अति उच्च ऊर्जावान कणों को उत्सर्जित करने वाले पिंडों में गिना जाता है जिसें गामा विकिरण, एक्स विकिरण और रेडियो तरंगें शामिल हैं।

मुख्य बिन्दु:

- भारत के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने इस बीएल लैक ब्लेजर का अध्ययन किया है जिसकी असामान्य चमक वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रही है।
- बीएल लैक ब्लेजार की असामान्य चमक वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रही है। इस पिंड को करीब एक सदी पहले ही सबसे पहले देखा गया था और तभी से यह धीरे धीरे अपनी शीर्ष चमक की स्थिति की ओर बढ़ रहा है।
- ये बहुत ही संकुचित तरह के संचरनाएं होती हैं जिनमें समय समय पर विसंगति पूर्ण चमक देखने को मिलती हैं।
- उन्होंने कहा कि उनकी चमक के स्तर में विचलन अलग-अलग हो सकता है और कुछ घंटों, दिनों, हफ्तों या महीनों तक भी रह सकता है।

विभिन्न तरंगों का अध्ययन

- बहुत से टेलीस्कोप की मदद लेने का मकसद पिंड से आने वाली अलग अलग प्रकार की तरंगों के जरिए उसका अध्ययन करना था. ये टेलीस्कोप रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, प्रकाशीय, पराबैगनी, एक्स रे, और गामा वेवलेंथ की तरंगे पकड़ सकते हैं।

पहले के अवलोकन:

- जुलाई 2020 में खगोलविदों ने संदेह जताया था कि बीएल लैक की चमक को बढ़ते हुए देखा गया था।
- इसके बाद हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप सहित 11 टेलीस्कोप की 84 दिनों तक इस ब्लेजार पर केंद्रित किया गया जिससे उसके आंकड़े हासिल कर उसका अध्ययन किया जा सके।
- समय के साथ बीएल लैक की चमक बढ़ती जा रही थी और अगस्त 2020 में पाया गया कि इसकी चमक शीर्ष पर पहुंच गई है। यह पोलैंड में स्थित संशोधित डल-किरखम टेलीस्कोप द्वारा अच्छी तरह से कैप्चर किया गया था।
- अवलोकनों से पता चला कि बीएल लैक की चमक 11.8 से 14 तक पहुंच गई है वहीं अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम को इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्वाला के दौरान 7.5 से 76.3 गॉस के बीच में मिली।

आगे की राह:

- ये नए पैरामीटर भविष्य में बीएल लैक के मल्टीस्पेक्ट्रल अध्ययन का आधार बनेंगे।

वैज्ञानिकों को भारत में भेड़िया कुत्तों के संकरण का पहला प्रमाण मिला

चर्चा में क्यों?

- वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने देश में भेड़िया-कुत्ते के संकरण का पहला प्रमाण पाया है।
- निष्कर्षों ने दावा किया गया है कि भेड़िया (कैनिस ल्यूपस)-डॉग (कैनिस ल्यूपस फेमिलेरिस) संकरण से भेड़ियों में कुछ अनुकूलन में भारी कमी हो सकती है, जिससे अंततः भेड़ियों की आबादी में गिरावट आ सकती है।

शोध किस प्रकार किया गया?

- उन्होंने नोट किया कि महाराष्ट्र में पुणे के पास प्रकृति प्रेमियों के एक समूह द्वारा एक असामान्य रूप से पीले रंग के कोट के साथ एक संदिग्ध भेड़िया-कुत्ते संकर जंतु को एक तस्वीर में कैद किया गया था। उन्होंने उस जंतु का पीछा किया और उसके द्वारा छोड़े गए बालों को इकट्ठा किया।
- इसके बाद नमूनों का उपयोग डीएनए निकालने के लिए किया गया और अन्य वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को अलग करने, पहचानने, दबाने और पालन करने के लिए संसाधित किया गया।
- शोधकर्ताओं ने तब 11 भेड़ियों के संपूर्ण जीनोम का उपयोग किया जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के तीन शामिल थे। अन्य तीन पश्चिम और मध्य एशिया से थे और शेष पांच भारतीय भेड़िये थे।
- उन्होंने केन्या, नेपाल, भारत, चीन और पूर्वी एशिया के कुत्तों सहित नमूनों के विश्लेषण के लिए 16 कुत्तों के जीनोम का भी इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने तीन जीनोम का उपयोग करके सुनहरे गीदड़ और ढोल के मिश्रण के लिए प्रजातियों की भी जांच की।
- परिणामों ने प्रायद्वीपीय भारत में भेड़िया-कुत्ते के संकरण की घटना का खुलासा किया जिसमें भेड़ियों की आबादी में कुत्ते के जीनोम अंतर्मुखीकरण के साक्ष्य दिखाए गए चित्र हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- हालांकि भारत में भेड़िया-कुत्ते संकरण की अवधारणा पर लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था, कोई प्रकाशित रिपोर्ट या साक्ष्य मौजूद नहीं था।
- कैनिड प्रजातियों में ऐसा संकरण जटिल है। अन्य स्तनधारी प्रजातियों के विपरीत कैनिड संकर के दोनों लिंग उपजाऊ होते हैं, जहां बहुत कम अपवादों के साथ नर बंध्य होते हैं। यह भेड़ियों में कुत्ते के जीनोम के अंतर्मुखीकरण को संभव बनाता है और इसके विपरीत संभव है।
- ऊपर बताई गई जटिलता के अलावा उच्च जनसंख्या टर्नओवर और प्रजनन सदस्यों की हानि के कारण भेड़ियों के झुण्ड टूट सकते हैं और सामाजिक संरचना में व्यवधान आ सकता है। ऐसे कारक संकरण दरों को और भी बढ़ा सकते हैं।
- हालांकि, ये परिदृश्य इन जंगली आबादी को एक संकरण भंवर में धकेल सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप अंततः संकरण के माध्यम से विलुप्ति हो सकती है।

आगे की राह:

- शोधकर्ताओं ने ट्रैकिंग, निगरानी, शिकार के आधार का आकलन करने, मानव और वन्य जीवन के बीच संबंधों को समझने के माध्यम से संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, यह देखते हुए कि भारत में मानव-वन्यजीव संपर्क व्यापक है।

सीमित आर्सेनिक एक्सपोजर भी संज्ञानात्मक क्षमता को खराब कर सकता है: अध्ययन

चर्चा में क्यों?

- हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि आर्सेनिक के कम सेवन से भी बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में संज्ञानात्मक कार्य प्रभावित हो सकता है।

विवरण:

- शोध अध्ययन इस बात की एक बड़ी जांच का भाग है कि पर्यावरण और जैविक कारकों की एक श्रृंखला युवा लोगों में न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है।
- यह भी पाया गया है कि आर्सेनिक के संपर्क में आने वालों ने ग्रे मैटर (मस्तिष्क के ऊतक जो संज्ञानात्मक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं) और मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्रों के भीतर कमजोर कनेक्शन को कम कर दिया था जो एकाग्रता, कार्यों के बीच स्विच करने और सूचना के अस्थायी भंडारण को सक्षम बनाता है।

अनुसंधान की मूल बातें:

- आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क से वैश्विक आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली 'मौन महामारी' उत्पन्न हो सकती है।
- अपने शोध के लिए, वैज्ञानिकों ने भारत भर के पांच क्षेत्रों के 1,014 प्रतिभागियों के कम्प्यूटरीकृत परीक्षणों (जो संज्ञानात्मक कार्य का मूल्यांकन करते हैं) और मस्तिष्क-छवियों (जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को चित्रित करते हैं) की एक बैटरी में मूत्र के नमूने (आर्सेनिक जोखिम का अनुमान लगाने के लिए) प्रदर्शन को जोड़ा। .
- आर्सेनिक का संपर्क विशेष रूप से गरीबों के लिए हानिकारक है।

सरोकार:

- 1990 के दशक से, बिहार और पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने आर्सेनिक संदूषण को संबोधित करने की मांग की है।
- नियोजित एक सामान्य रणनीति भूजल निकासी के बजाय पाइप्ड पानी की पहुंच को प्रोत्साहित करना और आर्सेनिक हटाने वाले संयंत्र स्थापित करना है।

इसरो न्यू जेनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 29 मई को अंतरिक्ष में NVS-01 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करेगा, जो नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) श्रृंखला का हिस्सा है।

विवरण:

- 2,232 किलोग्राम का उपग्रह श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से भारत के वर्कहॉर्स, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) को अंतरिक्ष में ले जाएगा।
- इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा।
- NVS-01 नाविक समूह के लिए परिकल्पित दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है जिसे उन्नत सुविधाओं के साथ नाविक को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NavIC क्या है?

- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) एक मुफ्त सेवा है जो अमेरिकी सरकार द्वारा अनुरक्षित कक्षा में उपग्रहों की एक श्रृंखला द्वारा प्रदान की जाती है। NavIC, GPS के लिए भारत का जवाब है।
- भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन (NavIC) इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है जो कक्षा में सात उपग्रहों का एक समूह है जो ग्राउंड स्टेशनों के साथ मिलकर काम करता है।
- नेटवर्क सामान्य उपयोगकर्ताओं और रणनीतिक उपयोगकर्ताओं, अर्थात् सशस्त्र बलों, दोनों को नौवहन सेवाएं प्रदान करता है।
- नौसैनिक समूह के सात उपग्रहों में IRNSS-1A, IRNSS-1B, IRNSS-1C, IRNSS-1D, IRNSS-1E, IRNSS-1F और IRNSS-1G उपग्रह शामिल हैं।

अनुप्रयोग:

- बेहतर स्थिति, नेविगेशन और समय के लिए देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए प्रणाली विकसित की गई थी।
- नेटवर्क में भारत सहित एक क्षेत्र और भारतीय सीमा से 1500 किमी तक का क्षेत्र शामिल है। सिग्नल 20 मीटर से बेहतर उपयोगकर्ता स्थिति सटीकता और 50 नैनोसेकंड से बेहतर समय सटीकता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- प्रणाली का उपयोग स्थलीय, हवाई और समुद्री परिवहन, स्थान-आधारित सेवाओं, व्यक्तिगत गतिशीलता, संसाधन निगरानी, सर्वेक्षण और भूगणित, वैज्ञानिक अनुसंधान, समय प्रसार और तुल्यकालन, और जीवन सुरक्षा चेतावनी प्रसार में किया जाता है।
- एनएवीआईसी प्रणाली एल5 बैंड में काम करती है, जो विशेष रूप से भारतीय प्रणाली को सौंपी गई एक संरक्षित आवृत्ति है। यह समर्पित आवृत्ति प्रणाली की मजबूती को बढ़ाती है और अन्य संकेतों से न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करती है।

आगे की राह:

- NVS-1 को 29 मई को लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सेवाओं का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त रूप से L1 बैंड सिग्नल शामिल हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

कूनो में पांच और चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा

चर्चा में क्यों?

- मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रह रहे पांच और चीतों को मानसून से पहले कूनो के खुले जंगल में छोड़ा जाएगा. इसमें तीन मादा और दो नर चीते हैं ।

चीता परियोजना:

- यह बयान एक विशेषज्ञ समिति द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को सौंपी गई रिपोर्ट पर आधारित था, जो चीता परियोजना के लिए नोडल निकाय है।
- समिति के सदस्यों ने 30 अप्रैल को केएनपी का दौरा किया और चीता परियोजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।
- जंगली बिल्ली को भारतीय आवास में फिर से पेश करने के लिए एक स्थानांतरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सितंबर 2022 से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से बीस चीतों को लाया गया है।
- उनके अनुकूलन के हिस्से के रूप में, जानवरों को विशेष बाड़ों में रखा गया था। हालांकि, उनमें से दो की मौत हो गई, एक गुर्दे के संक्रमण से और दूसरा एक ज़ोरदार शिकार के बाद दिल की विफलता के कारण।

दीर्घकालिक योजना:

- जानवरों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की दीर्घकालिक योजना यह है कि उन्हें धीरे-धीरे जंगल में छोड़ दिया जाए और अफ्रीका से अधिक जानवरों को तब तक जोड़ा जाए जब तक कि एक दशक में एक बड़ी आत्मनिर्भर आबादी स्थापित नहीं हो जाती है, जबकि प्राकृतिक मृत्यु दर और अनुकूलन से संबंधित चुनौतियों का हिसाब लगाया जाता है।
- अब तक, चार चीतों को पहले ही जंगल में छोड़ दिया गया है।
- शेष चीते, मानसून के मौसम (जून-सितंबर) की अवधि के लिए अनुकूलन शिविरों में रहेंगे।
- सितंबर के बाद, जब मानसून समाप्त होता है, तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में "योजनाबद्ध तरीके" से केएनपी या आसपास के क्षेत्रों में अधिक जानवरों को छोड़ दिया जाएगा।
- चीतों को केएनपी से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और जब तक वे "महत्वपूर्ण खतरे" में नहीं हैं, तब तक उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा।

चिंता:

- स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि चीतों के पास राष्ट्रीय उद्यान में शिकार करने के लिए औसतन बहुत कम जगह और सीमित पहुंच थी, और यह भारत में उनके अंतिम उत्कर्ष के लिए काफी समस्याएं पैदा करेगा।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, केएनपी में उपलब्ध स्थान, पार्क में लगभग 1,00,000 वर्ग किमी और पार्क के आसपास के परिदृश्य में 6,00,000, 21 चीतों के लिए पर्याप्त था। वर्तमान में, 18 हैं।

विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलकर डीकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेंगे

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) विकसित करने की योजना बना रही है जहां कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित किया जाएगा।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय साथ मिलकर इस उद्देश्य के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित कर रहे हैं।

क्षेत्र:

- जैसा कि भारत में वर्तमान में एक ऊर्जा बचत-आधारित बाजार तंत्र है, नई अवतार कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना एक बढ़े हुए दायरे के साथ एनर्जी ट्रांसमिशन से जुड़े प्रयासों को बढ़ाएगी जो भारत में संभावित ऊर्जा क्षेत्रों को कवर करेगी।
- इन क्षेत्रों के लिए, जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता बेंचमार्क और लक्ष्य विकसित किए जाएंगे, जो जलवायु लक्ष्यों के अनुसार भारत के उत्सर्जन के ग्राफ के साथ एकरूप होंगे। कार्बन क्रेडिट का व्यापार इस क्षेत्रीय ग्राफ के प्रदर्शन के आधार पर होगा।
- इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई है कि गैर-बाध्यकारी क्षेत्रों से जीएचजी कटौती को प्रोत्साहित करने के लिए समवर्ती रूप से एक स्वैच्छिक तंत्र का विकास होगा।

प्रमुख बिंदु:

- आईसीएम विभिन्न पंजीकृत परियोजनाओं से कार्बन उत्सर्जन में कमी और निष्कासन के आकलन के लिए कार्यप्रणाली विकसित करेगा, और योजना के संचालन के लिए आवश्यक सत्यापन, पंजीकरण, सत्यापन और जारी करने की प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। परामर्श के बाद उत्सर्जन योजना के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग, सत्यापन (एमआरवी) दिशानिर्देश भी विकसित किए जाएंगे।
- आईसीएम को लागू करने में शामिल प्रत्येक पार्टी की विशिष्ट भूमिकाओं के साथ एक व्यापक संस्थागत और शासन संरचना की स्थापना की जाएगी। विषयवस्तु में अप-स्किलिंग के लिए सभी संस्थाओं की क्षमता निर्माण किया जाएगा।
- आईसीएम निजी और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उत्सर्जन क्रेडिट की मांग के माध्यम से न्यूनीकरण के नए अवसर जुटाएगा।
- यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया, प्रतिस्पर्धी कार्बन बाजार तंत्र कम से कम लागत पर जीएचजी उत्सर्जन को कम करने में सक्षम होगा, दोनों इकाई के स्तर पर, साथ ही साथ समग्र क्षेत्र और भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने को प्रेरित करेगा।

आगे की राह:

- भारत अपने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु कार्रवाई में सबसे आगे रहा है।
- भारत के संवर्धित जलवायु लक्ष्यों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार आईसीएम का विकास कर रही है।
- इनके द्वारा कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को गति देकर, आईसीएम 2005 के स्तर के मुकाबले 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

भूजल दोहन से जमीन के धँसने की प्रवृति देखी गई

चर्चा में क्यों?

- उत्तराखंड के एक पहाड़ी शहर जोशीमठ में इमारतों में दरारें और धंसती जमीन, 2023 की शुरुआत में राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थीं।

- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फरीदाबाद के मैदानी इलाकों में भी इसी तरह की घटना वर्षों से चल रही है। इसके लिए संभावित रूप से अत्यधिक भूजल निकासी है।

उत्तर-पश्चिम भारत में स्थिति:

- उत्तर-पश्चिम भारत में कृषि पद्धतियां भूजल निकासी पर बहुत अधिक निर्भर हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्षों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सीमित मानसूनी बारिश के साथ, भूजल तालिका खतरनाक रूप से नीचे है।
- उदाहरण के लिए, पंजाब में 76% भूजल ब्लॉक 'अतिदोहित' हैं। चंडीगढ़ में यह 64% और दिल्ली में करीब 50% है। इसका मतलब यह है कि जितना भूजल रिचार्ज किया जा सकता है उससे अधिक निकाला जाता है।
- समय के साथ, जब अंतर्निहित जलभृत (गहरे पानी के चैनल जो रिसकर पानी के भंडार होते हैं) को रिचार्ज नहीं किया जाता है, तो वे सूख जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी और चट्टान की परतें धंसने लगती हैं।

'अत्यधिक शोषण' के परिणाम:

- वर्षों से कोयला, तेल और गैस के लिए जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे किए गए खुदाई कार्यों ने 'मिट्टी की बस्ती' या खनन से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए मिट्टी के डूबने के उदाहरण दिखाए थे।
- यहां से यह अनुमान लगाया गया कि यदि तेल और गैस निष्कर्षण सबडक्शन (डूबने) का कारण बनता है, तो निश्चित रूप से भूजल को भी कुछ भूमिका निभानी चाहिए।
- जल शक्ति मंत्रालय की एक सहायक संस्था सीजीडब्ल्यूबी को भारत के भूजल संसाधनों की स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा गया है
- इसमें भूजल अवलोकन की एक प्रणाली है, साल में चार बार कुएं और पानी के स्तर की निगरानी करता है। हालांकि, यह 'अति शोषण' के परिणामों का विश्लेषण नहीं करता है।

एनसीआर के आंकड़े:

- एक शोध दल ने सेंटिनल-1 उपग्रह (ग्रेस से अलग) के डेटा का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि 2011-2017 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र औसतन 15 मिमी प्रति वर्ष धंस गया।
- शहरीकरण और अनियोजित विकास प्रमुख कारक थे और इसने भूजल निकासी को बढ़ा दिया।
- दिल्ली-एनसीआर के जिन हिस्सों में धंसाव देखा गया, वे टेक्टोनिक (भूकंप से जुड़ी) फॉल्ट लाइनों से बहुत दूर थे।

विश्व जैव विविधता दिवस 2023

संदर्भ:

- अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है।
- 2023 की थीम 'समझौते से कार्रवाई तक' जैव विविधता का निर्माण' है।

इतिहास:

- जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की उत्पत्ति का पता पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से लगाया जा सकता है, जिसे आमतौर पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जो 1992 में रियो डी जनेरियो, ब्राजील में हुआ था।
- इस महत्वपूर्ण सभा के दौरान वैश्विक नेताओं ने जैव विविधता की विश्वव्यापी गिरावट का सामना करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया।
- नतीजतन, 22 मई, 1992 को, बड़ी संख्या में देशों ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD) को अपनाया।

जैव विविधता क्या है?

- जैव विविधता, जिसे जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, में जीवन रूपों की विस्तृत श्रृंखला और प्राकृतिक दुनिया के भीतर उनके द्वारा बनाए गए जटिल पैटर्न शामिल हैं।
- आज हम जिस मौजूदा जैव विविधता का निरीक्षण करते हैं, वह अरबों वर्षों की विकासवादी प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो प्राकृतिक तंत्र और मानव गतिविधियों दोनों से प्रभावित है। यह जीवन के परस्पर जुड़े टेपेस्ट्री का गठन करता है, जिसमें हम एक अविभाज्य घटक हैं, और जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा करते हैं।
- जैव विविधता में प्रत्येक प्रजाति के भीतर मौजूद आनुवंशिक विविधताएं भी शामिल हैं, जिसका उदाहरण विभिन्न फसल किस्मों और पशुधन नस्लों द्वारा दिया जाता है। गुणसूत्र, जीन और डीएनए, जो जीवन के मौलिक निर्माण खंडों के रूप में काम करते हैं, व्यक्तियों और प्रजातियों की विशिष्टता में समान रूप से योगदान करते हैं।

क्या हम वैश्विक ढांचे के तहत लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर हैं?

- कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) पर सहमति बने सिर्फ पांच महीने हुए हैं और स्वाभाविक रूप से, बहुत कुछ नहीं किया गया है। फ्रेमवर्क में 23 लक्ष्यों के साथ कुल चार लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है।

- हालांकि, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ढांचा 2011 में स्थापित आइची जैव विविधता लक्ष्यों की तरह समाप्त न हो। ये लक्ष्य, जो जीबीएफ के तहत निर्धारित लक्ष्यों के समान थे, 2020 तक पूरे किए जाने थे, लेकिन विश्व सामूहिक रूप से इनमें से किसी को भी पूरा करने में असफल रहा।
- लगभग दस लाख पशु और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है। जीबीएफ के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ सात वर्ष उपलब्ध हैं।

कार्यान्वयन के मुद्दे:

- 2022 में पार्टियों के 15वें सम्मेलन (COP15) में यह निर्णय लिया गया कि GBF के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। यह निर्णय लिया गया कि विकसित देश 2025 तक विकासशील देशों को 20 बिलियन डॉलर और 2030 तक 30 बिलियन डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदान करेंगे। यह अभी होना बाकी है।
- सदस्य राज्य भी अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को GBF के अनुरूप बनाने पर सहमत हुए। हालांकि, केवल स्पेन ने ही 2023 में पुनर्गठित एनबीएसएपी जमा किया है।
- नई योजनाओं को 2024 में Türkiye में सीओपी 16 से पहले सीबीडी सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में, सचिवालय नई योजनाओं को विकसित करने के लिए देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। भारत इस योजना को तैयार करने की प्रक्रिया में है।
- 30 प्रतिशत भूमि और जल की रक्षा का लक्ष्य सबसे विवादास्पद लक्ष्यों में से एक था। कई लोगों के अनुसार, यह कदम स्वदेशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा।
- मई 2021 में प्रकाशित संरक्षित ग्रह रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 16.64 प्रतिशत भूमि और अंतर्देशीय जल पारिस्थितिकी तंत्र और 7.74 प्रतिशत तटीय जल और महासागर संरक्षित थे। इसमें से 40 प्रतिशत से अधिक 2010 के बाद से हुआ है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत के पास पहले से ही अपने भूमि क्षेत्र का 27 प्रतिशत संरक्षण के तहत है और आसानी से लक्ष्य को पूरा कर लेगा।

आगे की राह:

- तुर्किये में 2024 में पार्टियों के सम्मेलन की अगली बैठक में, विश्व उन लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं का जायजा लेगा जो निर्धारित किए गए हैं।

जन जैव विविधता रजिस्टर का राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) को अद्यतन बनाने और सत्यापन के लिए राष्ट्रीय अभियान आज गोवा में प्रारम्भ किया गया। यह भारत की समृद्ध जैविक विविधता के प्रलेखन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- समारोह का आयोजन गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और गोवा सरकार के सहयोग से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था।

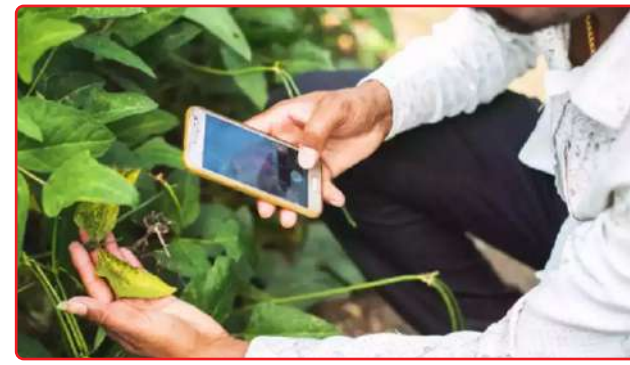

मुख्य बिन्दु:

- यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करने में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
- अब तक देश में 2,67,608 जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों तथा उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है।
- 01 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में सीओपी-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत "लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट (लाइफ)" की अवधारणा के महत्व पर प्रकाश डाला।
- यह अवधारणा पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर व्यक्तियों और संस्थानों को सचेत और सोचे-समझे रूप में संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने का आह्वान करती है।

जन जैव विविधता रजिस्टर के बारे में

- पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (जन जैव विविधता रजिस्टर) जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इसमें आवासों का संरक्षण, भूमि की प्रजातियों का संरक्षण, लोक प्रकारों और खेती, पालतू स्टॉक और जानवरों की नस्लें, सूक्ष्म जीव और क्षेत्र की जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का संचय शामिल है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार देशभर में स्थानीय निकायों द्वारा जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और प्रलेखन को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) बनाई गई हैं।
- बीएमसी का गठन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय निकायों द्वारा किया गया है और उन्हें स्थानीय समुदायों के परामर्श से पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (पीबीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है।

संस्कृति

संसदीय समिति द्वारा विरासत की चोरी पुरावशेषों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

चर्चा में क्यों?

- वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने 'विरासत की चोरी -

भारतीय पुरावशेषों में अवैध व्यापार और हमारी मूर्त सांस्कृतिक विरासत को दोबारा प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की चुनौतियां' नाम से अपनी रिपोर्ट दी थी।

विवरण:

- संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटेन के कोहिनूर हीरा वापस भारत लाने बात कही है। इसमें कहा गया है कि भारत को कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग करनी चाहिए जो 1850 के दशक की शुरुआत में भारत से बाहर चला गया था और अभी ब्रिटिश सम्राट के ताज में जड़ा हुआ है।
- संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि चोरी की कलाकृतियों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोहिनूर का मामला विवादास्पद है क्योंकि इसे महाराजा दलीप सिंह ने 1849 की शांति संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया था।
- भारत के पास हीरे की वापसी की मांग करने की कानूनी क्षमता नहीं है।
- पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल ऐसी पुरावशेषों की वापसी के मुद्दे को उठाता है जिन्हें अवैध रूप से देश से बाहर निर्यात किया गया हो।

यूनेस्को कन्वेंशन:

- संस्कृति मंत्रालय का रुख 2016 में सुप्रीम कोर्ट में दायर उसके हलफनामे के अनुरूप है, जहां उसने कहा था कि हीरे को वापस नहीं लाया जा सकता क्योंकि यह उपहार के रूप में दिया गया था।
- विचार-विमर्श को सीमित करने के लिए, पैनल ने कानून सचिव नितिन चंद्रा से भी मुलाकात की ताकि यह समझा जा सके कि मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।
- उन्होंने पैनल को सूचित किया था कि "1970 के यूनेस्को सम्मेलन के अनुच्छेद 7 और 15 का एक संयुक्त पठन इंगित करता है कि सम्मेलन राज्य दलों को हटाए गए सांस्कृतिक गुणों की बहाली के लिए विशेष समझौते करने से नहीं रोकता है"।

आगे का रास्ता:

- पैनल ने संस्कृति मंत्रालय से "वैश्विक अभ्यास का पालन करने और बहुमूल्य ऐतिहासिक कलाकृतियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने" का आग्रह किया है।

'नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट' के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

- असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), सागरमाला विकास निगम लिमिटेड (एसडीसीएल), असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग (डीआईडब्ल्यूटी), असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य बिन्दु:

- यह समझौता ज्ञापन गुवाहाटी के आसपास सात ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच 'हॉप ऑन हॉप ऑफ' पर आधुनिक नौका सेवा की सुविधा प्रदान करेगा।
- प्रसिद्ध सात धार्मिक स्थलों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वकलांता, डौल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और औनियाती सतरा को कवर किया जाएगा।
- फेरी टर्मिनल पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय में आरामदायक माहौल के आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

कार्यान्वयन:

- यह स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से क्रियान्वित की गई परियोजना के 45 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा होने की संभावना है और यह 12 महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी।
- यह सागरमाला विकास निगम लिमिटेड (एसडीसीएल) और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) संयुक्त रूप से परियोजना लागत के 55 प्रतिशत का योगदान देंगे जबकि शेष असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग (डीआईडब्ल्यूटी) ने परियोजना के लिए मंदिरों के पास घाटों का नि:शुल्क उपयोग करने की सहमति दी है।

प्रारम्भिक परीक्षा

1. बारसु रिफाइनरी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. यह अरामको, एडीएनओसी, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
   2. यह परियोजना नानार में बनने वाली थी लेकिन स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के कारण परियोजना को बारसू में स्थानांतरित कर दिया गया
   3. परियोजना केवल विभिन्न डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स के विकास का प्रस्ताव करती है।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3
2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. राजशेखर चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे।
   2. शिलाभट्टारिका एक प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री और बादामी के पुलकेशिन द्वितीय की बेटी थीं।
   3. पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के हर्षवर्धन को 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट के पास एक युद्ध में हराया था।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3
3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. "फायरसाइड चैट्स" रेडियो प्रसारण के उपयोग का सबसे पहला उदाहरण था।
   2. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने उपरोक्त प्रसारण दिया।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) केवल 1 b) केवल 2
   c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं
4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. यह गरीबों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करता है।
   2. कोई भी प्रवासी श्रमिक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है।
   3. इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3
5. पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (सीएससी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. इसका उद्देश्य परमाणु घटना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मुआवजा राशि स्थापित करना है।
   2. कन्वेंशन केवल उन राज्यों के लिए खुला है जो या तो वियना कन्वेंशन या पेरिस कन्वेंशन के पक्षकार हैं।
   3. भारत इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

   ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
   a) केवल 1 b) 1 और 2 केवल
   c) 2 और 3 केवल d) 1, 2 और 3
6. 'लॉन्ड्रोमैट देश' इसमें शामिल नहीं हैं
   a) जापान b) भारत
   c) टर्की d) सिंगापुर
7. डेंगू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. मानव शरीर में प्रवेश करते समय वायरस सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
   2. यह वायरस एडीज मच्छर द्वारा मनुष्यों में फैलता है।
   3. वायरस लीवर, प्लीहा और लिम्फ नोड्स सहित अन्य अंगों में फैलता है।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3
8. शिताके मशरूम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
   1. यह मशरूम मूल रूप से जापान का है।
   2. इसमें लेंटिनन नामक रसायन होता है।
   3. इसमें एंटी-कार्सिनोजेनिक गुण होते हैं, जिनका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है।

   नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3
9. निम्नलिखित पर विचार कीजिएः
   1. अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल
   2. शिल्पा सैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन
   3. श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता मामला

   निम्नलिखित में से कौन सा/से मामला/(ओं) तलाक से संबंधित है?
   a) 1 और 2 b) 2 और 3
   c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

10. बटन, डिंगरी और मिल्की किसकी किस्में हैं
    a) मशरूम b) अफीम के बीज
    c) चावल d) केला

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वर्तमान में भारत में 62 छावनियाँ हैं।
    2. अजमेर अधिसूचित होने वाली अंतिम छावनी थी।
    3. बैरकपुर अपनी छावनी का टैग हटाने वाली पहली छावनी है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

12. जी7 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. कनाडा इस समूह का संस्थापक सदस्य था।
    2. यूरोपीय संघ ने "गैर-गणना" सदस्य के रूप में जी-7 में पूरी तरह से भाग लिया है।
    3. यूरोपीय संघ, आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

13. गिग वर्कर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वे श्रमिकों को पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर संदर्भित करते हैं।
    2. निर्माण श्रमिक और गैर-प्रौद्योगिकी-आधारित अस्थायी कर्मचारी गैर-प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

14. डी-डॉलराइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. यह वैश्विक बाजारों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने को संदर्भित करता है।
    2. इसका उपयोग फॉरेक्स रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए किया जाता है।
    3. डी-डॉलरकरण देशों के केंद्रीय बैंकों को भू-राजनीतिक जोखिम से बचाने की इच्छा से प्रेरित है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

15. हाल में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रत्येक राज्य की अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. भारत का संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषाओं को निर्दिष्ट करता है।
    2. किसी राज्य की विधायिका राज्य में उपयोग की जाने वाली एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) नवरत्न का दर्जा पाने वाला 13वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) बन गया।
    2. इससे पहले, आरवीएनएल मिनिरत्न श्रेणी - I में था।
    3. भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (बीएचईएल) को 2014 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

17. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. भारत ने इस वर्ष इस सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार किया था।
    2. इसे ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा जारी किया गया है।
    3. भारत की तुलना में श्रीलंका ने सूचकांक में महत्वपूर्ण सुधार किया।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं।
    2. वह छह वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

19. उत्तर-पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह उत्तर-पूर्वी राज्यों में छठी अनुसूची के क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्थापित सांविधिक निकाय है।
    2. परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

20. विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. यह रिपोर्ट हर साल जारी की जाती है।
    2. इसका उद्देश्य 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारों और मीडिया द्वारा प्राप्त प्रेस स्वतंत्रता के स्तर की तुलना करना है।
    3. इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

21. वाशिंगटन घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. संयुक्त प्रतिक्रिया रणनीति के सिद्धांतों को तैयार करने के लिए एक परमाणु सलाहकार समूह का गठन किया जाएगा।
2. दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी तैनात की जाएगी।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

22. जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:
1. यह रूस द्वारा आयोजित किया गया था।
2. सदस्य राज्य एक त्वरण एजेंडा का आह्वान करते हैं, जहां "सभी देश अपनी नेट जीरो समय सीमा पर तेजी से आगे बढ़ते हैं"।
3. एजेंडा में आर्थिक सहयोग और विकास देशों के संगठन में 2030 तक कोयला चरणबद्ध करने का आह्वान किया गया है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. मैतेई समुदाय मणिपुर में एक गैर-आदिवासी समुदाय है।
2. मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की जा रही थी।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

24. लैपोनाइट एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल है
a) फार्मास्युटिकल b) सौंदर्य प्रसाधन उद्योग
c) अंतरिक्ष उद्योग d) A और B दोनों

25. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एक बहुपक्षीय समूह है जिसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं।
2. ईरान और बेलारूस को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जाना तय है।
3. अफगानिस्तान और मंगोलिया दो संवाद भागीदार हैं।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

26. एटीएजीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एक स्वदेशी कैलिबर हॉवित्जर तोप है।
2. विशेष बंदूक प्रणाली C4I के साथ संगत है।
3. ATAGS को मैन्युअल ड्राइव के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

27. वेन ऑफ गैलेन मालफॉर्मेशन (वीओजीएम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक प्रकार का फेफड़ों का विकार है।
2. यह तब होता है जब मस्तिष्क की धमनियां सीधे शिरा से जुड़ती हैं।
3. इस स्थिति के कारण रक्त हृदय और फेफड़ों की ओर तेजी से बढ़ने लगता है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

28. इन-यूटरो सर्जरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है।
2. सर्जरी तब की गई थी जब भ्रूण की गर्भकालीन आयु 34 सप्ताह से थोड़ी अधिक थी।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

29. निम्नलिखित पर विचार कीजिएः
1. वृक्षारोपण
2. कचरे का प्रबंधन
3. इको मार्क आधारित ग्रीन क्रेडिट
उपरोक्त में से किसकी पहचान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत की गई थी जिसके लिए ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है?
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

30. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसकी स्थापना पेरिस में 1989 के G7 शिखर सम्मेलन में हुई थी।
2. वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं और भारत सदस्य देश नहीं है।
3. प्रत्येक पूर्ण बैठक के अंत में, यह केवल एक प्रकार की सूची अर्थात देशों की ब्लैकलिस्ट के साथ सामने आता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 2 और 3 केवल d) केवल 1 और 3

31. ऑपरेशन समुद्र सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसे कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
2. इसे वंदे भारत मिशन (VBM) के साथ लॉन्च किया गया था।
3. इस ऑपरेशन में केवल भारतीय नौसेना के जहाज मगर ने भाग लिया।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

32. ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. रिपोर्ट UNFCCC द्वारा प्रकाशित की जाती है।
    2. इस रिपोर्ट के अनुसार, उल्लंघन सीधे मानव-प्रेरित मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से जुड़े हैं।
    3. भूमि जैव विविधता हानि और जलवायु परिवर्तन के बीच क्रियात्मक कड़ी है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

33. सह-उधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां ऋण की उत्पत्ति एक संस्था द्वारा की जाती है लेकिन जोखिम दो संस्थाओं द्वारा साझा किया जाता है
    2. यह एनबीएफसी पर जवाबदेही लागू करता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

34. कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच संयुक्त पहल है।
    2. यह परियोजना बांग्लादेश में दावकी भूमि बंदरगाह के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ेगी।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

35. जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) और जीन एडिटिंग (जीई) तकनीकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. जीन संपादन विधियों में अन्य जीवों से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री को मूल जीव में पेश किया जाता है।
    2. CRISPR जीन संपादन का एक सामान्य तरीका या उपकरण है

    नीचे दिए गए कूट से गलत विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

36. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: जल निकाय जनगणना:
    1. भारत के अधिकांश जल निकाय एक हेक्टेयर (हेक्टेयर) से कम बड़े हैं।
    2. यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा आयोजित किया गया था।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

37. संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. संविधान की केवल दसवीं अनुसूची दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करती है।
    2. दसवीं अनुसूची के अनुसार, एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
    3. सदस्य को अयोग्य भी ठहराया जा सकता है यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में वोट देता है या मतदान से दूर रहता है जिससे वह संबंधित है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

38. प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन और अन्य उच्च एल्केन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि हैं।
    2. वर्तमान में, प्राकृतिक गैस देश के समग्र ऊर्जा मिश्रण का लगभग 6% ही बनाती है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

39. स्टार्ट कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनने में सक्षम बनाने के इसरो के प्रयासों का हिस्सा है।
    2. कार्यक्रम खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी सहित अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन को कवर करेगा।
    3. इसका उद्देश्य भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

40. Bluesky के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह एक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म और सोशल वेबसाइट है।
    2. यह फेसबुक का प्रतिस्पर्धी है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

41. कुनो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह खथियार-गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों का हिस्सा है।
    2. कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए भारत का दूसरा घर बनने जा रहा है।
    3. इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा नहीं दिया गया है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME 2023) जापान के सागर में हुआ।
    2. सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी (IMDEX-23) की मेजबानी कर रहा है।

3. आईएमडीईएक्स का पहला संस्करण 1997 में आयोजित किया गया था।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

43. लिथियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह दुनिया भर में सबसे हल्की और साथ ही सबसे नरम धातु है।
2. यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

44. अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. अफ्रीकी चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त है।
2. अफ्रीकी चीता की तुलना में एशियाई चीता आकार में बड़ा होता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

45. भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित होता है।
2. वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति का आनंद लेते हैं।
3. राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

46. एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा है।
2. इसका उद्देश्य परिणामोन्मुख परियोजनाओं को प्रदान करके क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर करना है।
3. भारत इस संघ का सदस्य नहीं है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

47. ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह अष्टकोणीय जाली में व्यवस्थित है।
2. यह दुनिया में सबसे पतला, सबसे अधिक विद्युत और तापीय प्रवाहकीय पदार्थ है।
3. ग्राफीन इंडियम की जगह ले सकता है और इस तरह स्मार्टफोन में ओएलईडी स्क्रीन की कीमत कम कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

48. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एक साल की जीवन बीमा योजना है।
2. 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति व्यक्तिगत बैंक या एक डाकघर खाता रखने वाले योजना के तहत नामांकन के हकदार हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

49. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच सौंपी गई है।
2. यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
3. केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

50. गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. द्वीपों का नाम उनके विशाल कछुओं के नाम पर रखा गया है।
2. प्राकृतिक चयन के माध्यम से डार्विन का विकास का सिद्धांत द्वीपों पर स्थानिक प्रजातियों पर उनके अध्ययन से प्रेरित था।
3. ये द्वीप सूरीनाम में स्थित हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

51. क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. वे प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं।
2. तरल ऑक्सीजन बहुत प्रतिक्रियाशील है।
3. ऑक्सीजन को ठोस अवस्था में रखा जाता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

52. इंडो-थाई कॉर्पेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह भारत और थाईलैंड के बीच एक वार्षिक अभ्यास है।
2. इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना है।
3. इसका उद्देश्य हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:

a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

53. निम्नलिखित पुंकेसर सक्षम पर विचार करें:
    1. इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान (NIHFW) द्वारा विकसित किया गया है।
    2. यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य पेशेवरों की समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

54. निम्नलिखित पर विचार कीजिएः
    1. तेलंगाना
    2. कर्नाटक
    3. पश्चिम बंगाल

    ओडीएफ प्लस गांवों के प्रतिशत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य नहीं है?
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) केवल 1 d) केवल 3

55. 'हरित सागर' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. इसका उद्देश्य शून्य उत्सर्जन हासिल करना है।
    2. इसे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
    3. वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण प्रदर्शन का पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्रदान किया गया।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

56. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. दसवीं अनुसूची में सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है।
    2. अयोग्यता के लिए किसी भी याचिका के लंबित होने की परवाह किए बिना विधायक को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
    3. विधायक दल व्हिप की नियुक्ति करता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

57. बहुविवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 394 भारत में द्विविवाह या बहुविवाह को दंडित करती है।
    2. बहुपत्नी विवाहों का सबसे अधिक प्रसार आदिवासी आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में था।
    3. मुसलमानों और हिंदुओं की तुलना में ईसाइयों में बहुविवाह का प्रचलन अधिक था।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. दिल्ली अनुच्छेद 239AA के तहत एक विशेष संवैधानिक स्थिति प्रस्तुत करता है।
    2. अनुच्छेद 239AA विशेष रूप से दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के दायरे से भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर करता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

59. मंकी पॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह एक ज़ूनोसिस बीमारी है जो संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलती है।
    2. यह एक ऑर्थोपॉक्सवायरस है, वायरस का एक जीनस जिसमें वेरियोला वायरस शामिल है जो चेचक का कारण बनता है।
    3. WHO ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चिंता के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) के रूप में मंकीपॉक्स को समाप्त कर दिया है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

60. दिल्ली सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं पर इसका विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
    2. सेवाओं पर दिल्ली सरकार के निर्णयों से उपराज्यपाल बाध्य होंगे।
    3. केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की कार्यकारी शक्ति इसकी विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक नहीं है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

61. आर्कटिक परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. ओटावा घोषणा के कारण इस परिषद का गठन हुआ।
    2. संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस परिषद का सदस्य है।
    3. इस परिषद के पर्यवेक्षक देश को भी मतदान का अधिकार प्राप्त है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

62. प्रो. गोविंद स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. उन्हें व्यापक रूप से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है।
    2. ऊटी रेडियो टेलीस्कोप (ORT) और जायंट मेट्रूवेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण भी उन्होंने ही किया था।
    3. वह स्क्वायर किलोमीटर ऐरे (SKA) के शुरुआती प्रस्तावक थे।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

63. शी-बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है।
    2. यह केवल कामकाजी महिलाओं के लिए सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करने का एक प्रयास है।
    3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

64. निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला शहर बन गया है?
    a) अहमदाबाद b) मुंबई
    c) इंदौर d) भोपाल

65. हाल में कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने राज्य में जाति आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। निम्नलिखित कथन पर विचार करें:
    1. विधेयक उन लोगों को स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें जातिगत पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के कारण व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचाया गया है।
    2. यह जातिगत भेदभाव और जाति-आधारित हिंसा में भाग लेने वालों के लिए दृढ़ कानूनी परिणाम भी प्रदान करता है।
    3. विधेयक मौजूदा कानून में जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में जोड़ने में विफल रहा।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

66. स्टॉर्म शैडो मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह एक एंग्लो-फ्रेंच लो-ऑब्जर्वेबल, लॉन्ग-रेंज क्रूज मिसाइल है।
    2. यह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीपीएस और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है।
    3. इस मिसाइल का उपयोग वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम द्वारा ही किया जाता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

67. केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
    2. इसे देश में भूजल विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

68. डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. इस योजना में संस्थानों के पंजीकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
    2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए आरबीआई को इस फंड को स्थापित करने का अधिकार देती है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

69. चक्रवात मोचा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह इस साल अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात है।
    2. चक्रवाती तूफान का नाम लाल सागर में स्थित एक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया था।
    3. यह स्थान कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

70. गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. ADRDE ने भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पैराशूट विकसित किए हैं।
    2. कैप्सूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पैराशूट का उपयोग किया जाएगा।
    3. मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में ले जाएगा।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

71. आईएनएस मोरमुगाओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. इसका नाम पश्चिमी तट पर ऐतिहासिक बंदरगाह शहर गोवा के नाम पर रखा गया है।
    2. यह 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित किया गया है।
    3. जहाज परमाणु स्थिति में लड़ने के लिए सुसज्जित नहीं है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

72. स्टॉर्म शैडो मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह पारंपरिक और परमाणु लॉन्च की गई गहरी स्ट्राइक मिसाइल दोनों है।
    2. यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से लैस है।
    3. इस मिसाइल में BROACH (बम रॉयल ऑर्डनेंस ऑगमेंटेड चार्ज) वारहेड है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

73. समुद्र शक्ति अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है।
    2. इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंक्रियता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

74. कार्बन डेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है।
    2. चट्टानों के कालनिर्धारण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो विधियाँ पोटेशियम-आर्गन कालनिर्धारण और यूरेनियम-थोरियम-लेड कालनिर्धारण हैं।
    3. ध्रुवीय क्षेत्रों में आइस कोर की आयु का अध्ययन करने के लिए कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड डेटिंग या सीआरएन नियमित रूप से लागू किया जाता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

75. हाल में ब्रिटेन में तीन व्यक्तियों के डीएनए से एक बच्चे का जन्म हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. माइटोकॉन्ड्रिया मूल रूप से कोशिकाओं के पावरहाउस हैं।
    2. वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और मानव शरीर में कोशिका कार्य के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।
    3. बच्चे ने जैविक माता-पिता से माइटोकॉन्ड्रिया और आनुवंशिक सामग्री (डीएनए) प्राप्त की।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

76. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. विशाखा जजमेंट एक ऐतिहासिक मामला है जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अपराध से संबंधित है।
    2. इसकी अध्यक्षता एक महिला को करनी होगी, कम से कम दो महिला कर्मचारी होनी चाहिए।
    3. अधिनियम केवल औपचारिक क्षेत्रों से समितियों के गठन का आदेश देते हैं।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

77. आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. इस मॉडल में ओटीपी, बैंक खाता और अन्य वित्तीय विवरण की भी जरूरत होती है।
    2. यह एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की अनुमति देता है।
    3. यह केवल बैंक का नाम, आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का उपयोग करके फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

78. मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक आंदोलन है।
    2. इसका उद्देश्य प्रो-प्लैनेट पीपल (P3) का एक वैश्विक नेटवर्क बनाना है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

79. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह नासा का सबसे शक्तिशाली इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है।
    2. यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग का परिणाम है।
    3. इस टेलीस्कोप ने मानवता को ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने में मदद की थी।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

80. चैटजीपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह भाषा सीखने के मॉडल पर आधारित है।
    2. GPT का मतलब जनरेटिव प्री-प्रशिक्षित ट्रांसफॉर्मर है।
    3. चैटबॉट को रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक (RLHF) का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

81. अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है।
    2. यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है।
    3. आईटीयू में अध्ययन समूह 9 (एसजी-9) केवल ऑडियो-विजुअल सामग्री के प्राथमिक वितरण के लिए दूरसंचार प्रणालियों के लिए जिम्मेदार है।

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

82. कृत्रिम स्वीटनर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. सैकरीन उच्च खाद्य ऊर्जा वाला एक कृत्रिम मधुरक है।
2. सोडियम साइक्लामेट एक कृत्रिम स्वीटनर है।
3. नियोटेम एक गैर-कैलोरी कृत्रिम स्वीटनर है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. उत्प्रेरक के रूप में कॉपर और जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन से मेथनॉल का उत्पादन होता है।
2. मेथनॉल का उपयोग विलायक के रूप में और एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. शराब के सेवन का प्रतिकूल प्रभाव एसीटैल्डिहाइड के कारण होता है।
2. नकली शराब की विशेषता मेथनॉल युक्त तरल मिश्रण से भी होती है।
3. अरक ताड़ के पेड़ के किण्वित रस से आसवित होता है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

85. समुद्री तितलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह समुद्री घोंघे का उपवर्ग है।
2. यह दक्षिणी महासागर में पाई जाने वाली सबसे छोटी प्रजाति है।
3. उनमें मांसल पैरों की कमी होती है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

86. "ब्लेजर" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एक प्रकार की आकाशगंगा है।
2. यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है।
3. रेडियो तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

87. LIBOR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर के रूप में काम नहीं करता है।
2. यह एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को उधार देते हैं।
3. जलप्रपात पद्धति का उपयोग करके दर की गणना की जाती है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

88. लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक वैश्विक ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पावधि ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को उधार देते हैं।
2. ब्याज दर की गणना केवल यूरो, यूएस डॉलर, स्विस फ्रैंक, जापानी येन और यूके पाउंड स्टर्लिंग जैसी मुद्राओं के लिए की जाती है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

89. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसे घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था।
2. इस योजना का उद्देश्य कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री के लिए प्रोत्साहन देना है।
3. यह योजना नई नौकरियां पैदा करने की उम्मीद में श्रम-गहन क्षेत्रों को लक्षित कर रही है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

90. सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह डॉलर-मूल्यवर्ग डेरिवेटिव और ऋण के लिए एक बेंचमार्क ब्याज दर है।
2. यह ट्रेजरी पुनर्खरीद बाजार में लेनदेन पर आधारित है।
3. यह एक सुरक्षित उधार दर नहीं है।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

91. राजनीतिक दलों के लिए फ्री एयरटाइम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 2003 के संशोधन के माध्यम से इसे वैधानिक आधार दिया गया था।
2. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड एएनआर, 1995 इससे संबंधित है।
3. इस फैसले से, एयरवेव्स को सार्वजनिक संपत्ति घोषित नहीं किया गया था।
नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

92. हाल में खबरों में रहा डॉटेड लैंड शब्द किससे संबंधित है?
    a) वह भूमि जो जमींदारों द्वारा भूमिहीनों को स्वैच्छिक उपहार के रूप में दी गई थी।
    b) यह एक विवादित जमीन है, जिसके मालिकाना हक के कोई स्पष्ट दस्तावेज नहीं हैं।
    c) यह राजाओं या अमीर संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि है।
    d) यह हर्षवर्धन काल के दौरान मंदिरों को दी गई भूमि है।

93. हाल में खबरों में रहा नेह पेमा शेल्पू द्रुपखांग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
    a) जम्मू और कश्मीर b) मणिपुर
    c) अरुणाचल प्रदेश d) सिक्किम

94. ग्रीन डिपॉजिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह नियमित जमा से बहुत अलग नहीं है।
    2. एक बैंक जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए हरित जमा का उपयोग करने से भी बच सकता है।
    3. एक ग्रीन डिपॉजिट अन्य वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में सिर्फ एक उत्पाद है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

95. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. G7 का कोई कानूनी अस्तित्व या आधिकारिक सदस्य नहीं है।
    2. G7 वैश्विक GDP के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करता है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) केवल 1 b) केवल 2
    c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

96. डॉटेड लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. ये विवादित जमीन हैं।
    2. केंद्र सरकार ने उन किसानों को मालिकाना हक दिया था जो 12 साल से अधिक समय से डॉटेड भूमि पर खेती कर रहे हैं।
    3. इस भूमि के लिए एक उचित स्वामित्व दस्तावेज हैं।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

97. क्लीन नोट पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. 2005 से पहले जारी किए गए नोट कानूनी निविदा नहीं रहे।
    2. यह जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के देना चाहता है।
    3. आरबीआई ने पहले 2005 से पहले जारी किए गए सभी बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया था।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

98. हाल में खबरों में रहा ऑपरेशन करुणा किससे संबंधित है?
    a) यह पूरे भारत में साइबर-सक्षम अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने के लिए है।
    b) मणिपुर में कुकी और मैतेई जनजातियों को हिंसा से दबाने के लिए।
    c) चक्रवात मोचा से तबाह म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय मिशन।
    d) जीवित कछुओं और कछुओं के बढ़ते अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए।

99. आर्सेनिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. यह पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद एक अत्यधिक विषैला तत्व है।
    2. भूजल आर्सेनिक जोखिम का एक प्रमुख स्रोत है।
    3. लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से हृदय रोग हो सकता है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

100. निम्नलिखित सूखती हुई झीलों को उनके संबंधित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूखती झीलें	क्षेत्रों
1. अरल सागर	मध्य एशिया
2. Xinkai झील	पूर्वी एशिया
3. डेड सी	दक्षिण पश्चिम एशिया
4. Toshka झीलों	पूर्वोत्तर अफ्रीका

    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 केवल b) केवल 2, 3 और 4
    c) केवल 1 और 4 d) 1, 2, 3 और 4

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. गैर-चीनी मिठास (एनएसएस) को कम या कैलोरी रहित के रूप में विपणन किया जाता है।
    2. आहार कोला को मीठा करने के लिए एस्पार्टेम का लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है।
    3. सुक्रालोज का उपयोग चाय या कॉफी को मीठा करने के लिए किया जाता है।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

102. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
    1. 42वां संशोधन दिल्ली के लिए विधान सभा का परिचय देता है।
    2. संविधान का अनुच्छेद 309 स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सेवाओं के बीच अंतर करता है।
    3. केंद्र शासित प्रदेश में सिविल सेवाएं स्पष्ट रूप से केंद्र की होती हैं।
    नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
    a) 1 और 2 b) 2 और 3
    c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

103. इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क (IPSN) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. नेटवर्क का लक्ष्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचाना और ट्रैक किया जाए।
2. वायरस के आनुवंशिक कोड का विश्लेषण करने के लिए नेटवर्क रोगजनक जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

104. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. कार्बन-14 की अर्द्ध-आयु 5,700 वर्ष है।
2. कैल्शियम-41 की अर्द्ध-आयु 99,400 वर्ष है।
3. कैल्शियम-41 का उत्पादन तब होता है जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक किरणें मिट्टी में मौजूद कैल्शियम परमाणुओं से टकराती हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

105. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर निर्देशन और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
2. यह एक अंतर-सरकारी संगठन है और अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है।
3. इसका मुख्यालय पेरिस में है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

106. गेवरा मेगा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है।
2. परियोजना का स्वामित्व एसईसीएल के पास है।
3. SECL एक राज्य के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

107. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (GBF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसे जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 13वें सम्मेलन (COP13) द्वारा अपनाया गया था।
2. देश 2030 तक 30 प्रतिशत ग्रह की रक्षा करने पर सहमत हुए।
3. देश सालाना 500 बिलियन डॉलर की हानिकारक सरकारी सब्सिडी को कम करने पर भी सहमत हुए।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

108. हाल में जापान में आयोजित जी7 बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यूरोपीय संघ को "गैर-प्रगणित सदस्य" के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया गया था।
2. इस पोस्ट में कोमोरोस और कुक आइलैंड्स का भी प्रतिनिधित्व किया गया था।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

109. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. ONDC को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रोजेक्ट के बाद तैयार किया गया है।
2. ओएनडीसी कुछ बड़े प्लेटफॉर्मों द्वारा ई-कॉमर्स बाजार के वर्चस्व को समाप्त कर देगा।
3. अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट पर कुछ विक्रेता संस्थाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है जिसमें वे अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखते हैं।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

110. स्पेसएक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह एलोन मस्क के स्वामित्व वाली और स्थापित एक निजी कंपनी है।
2. स्पेसएक्स का उद्देश्य अंतरिक्ष और विशेष रूप से मंगल ग्रह का पता लगाना है।
3. SpaceX का सफर इसकी ड्रैगन सीरीज से शुरू होता है

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

111. पापुआ न्यू गिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह ओशिनिया का एक देश है जिसमें न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग शामिल है।
2. इसकी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है।
3. देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

112. निम्नलिखित में से कौन भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम (FIPIC) के सदस्य हैं?
1. फ़िजी 2. फिलिपींस
3. न्यूज़ीलैंड 4. मार्शल द्वीपसमूह
5. पापुआ न्यू गिनी

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 और 5 b) केवल 1, 4 और 5
c) केवल 1, 3, 4 और 5 d) 1, 2, 3, 4 और 5

113. इंडस-एक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) पर पहल के तहत लॉन्च किया गया था।
2. यह रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

114. नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
2. यह जीपीएस के लिए भारत का जवाब है।
3. नेटवर्क सामान्य उपयोगकर्ताओं, रणनीतिक उपयोगकर्ताओं, अर्थात् सशस्त्र बलों को नौवहन सेवाएं प्रदान करता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

115. पापुआ न्यू गिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. यह दक्षिण-पश्चिम प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
2. यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है।
3. होनियारा, चीन की सहायता से निर्मित एक प्रमुख बंदरगाह, पापुआ न्यू गिनी में स्थित है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

116. "फोरम शॉपिंग" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक ऐसी स्थिति है जब एक वादी एक अदालत में जाता है लेकिन उसे वांछित राहत नहीं मिलती है और फिर वह दूसरी अदालत में जाता है।
2. एक वादी शीर्ष अदालत में सीधे नहीं जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 d) इनमे से कोई भी नहीं

117. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएः

1. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण	आंध्र प्रदेश और ओडिशा
2. महानदी जल विवाद: न्यायाधिकरण	ओडिशा और छत्तीसगढ़
3. रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
4. महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण	गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) केवल एक जोड़ा सही है b) केवल तीन जोड़े सही हैं।
c) केवल दो जोड़े सही हैं d) चारों जोड़े सही हैं

118. कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इसका प्राथमिक उद्देश्य 'कार्बन रिसाव' को रोकना है।
2. यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने इस तंत्र पर हस्ताक्षर किए।
3. यह अधिक कार्बन-गहन आयात के साथ यूरोपीय संघ निर्मित उत्पादों को प्रतिस्थापित करेगा।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

119. राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यदि राष्ट्रपति इसे वापस ले लेते हैं, या यदि दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो अध्यादेश पहले ही समाप्त हो सकता है।
2. यदि कोई अध्यादेश ऐसा कानून बनाता है कि संसद संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसे शून्य माना जाएगा।
3. अध्यादेश अगला सत्र शुरू होने की तारीख से छह सप्ताह या 42 दिनों के लिए वैध होता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

120. लेदरबैक कछुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. वे आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़कर हर महासागर में पाए जाते हैं।
2. ये समुद्री कछुओं की एकमात्र प्रजाति हैं जिनमें शल्कों और सख्त खोल की कमी होती है।
3. यह IUCN की लाल डेटा सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है और परिशिष्ट I का हवाला देता है।

नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें:
a) 1 और 2 b) 2 और 3
c) 1 और 3 d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा

1. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की सफलता के लिए कोविड-19 के लिए भारत के हालिया संचालन से किस प्रकार सबक लिया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
2. भारत में, समय के साथ, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने में एक अकथनीय देरी से जुड़े मामलों को संवैधानिक अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है। समय आ गया है कि एक नई संवैधानिक संरचना विकसित की जाए जो समयबद्ध संवैधानिक वितरण तंत्र की मांगों को पूरा करे। टिप्पणी कीजिए।
3. गिग श्रमिक' कौन है और 'प्लेटफॉर्म श्रम' क्या है? क्या नए श्रम संहिता गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं? गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए विदेशी न्यायालयों ने कौन से कानून बनाए हैं?
4. इंटरजेनरेशनल इक्विटी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने में जी20 देशों के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (SAI's) के लिए एंगेजमेंट ग्रुप की भूमिका पर प्रकाश डालिए।
5. भारत ने 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की आवर्ती अध्यक्षता ग्रहण की। जैसा कि रूस, चीन वर्चस्व के लिए होड़ करते हैं, भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के क्या मायने है?
6. जैसा कि भारत स्मार्ट मीटरिंग मध्यवार्तनों के माध्यम से वित्तीय रूप से मजबूत और डिजिटलीकृत ऊर्जा क्षेत्र की अपनी दृष्टि की ओर अग्रसर है, इसे उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन और तैनाती रणनीति का पालन करना चाहिए। टिप्पणी कीजिए।
7. जी-20 की वर्ष भर की अध्यक्षता और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेतृत्व के लिए भारत के समक्ष विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
8. जल निकाय गणना का क्या महत्व है? एकत्र किए गए आंकड़ों से सम्बंधित कमियां क्या हैं? क्या डेटा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और जल निकाय उन्हें किस बनाए रखते हैं?
9. बौद्ध धर्म के साथ अपने मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ, भारत वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म से सम्बंधित चर्चाओं को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में है। टिप्पणी कीजिए।
10. खाड़ी क्षेत्र में नए रणनीतिक अवसरों को हासिल करने के लिए भारत के सामरिक संवाद के लंबे समय से अपेक्षित आधुनिकीकरण अर्थात् पुराने अनुश्रुतियों को बदलने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होगी। टिप्पणी कीजिए।
11. हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा शुरू की गई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। भारत को द्वितीय अंतरिक्ष युग में सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए किन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है?
12. अभी भी विशेष विवाह अधिनियम का उपयोग करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन अधिनियम में वर्तमान लोगों कल्पना की तुलना में अधिक क्षमता होनी चाहिए और अधिकारहीन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। विवाह समानता के लिए चल रहे मामले के संदर्भ में उपरोक्त कथन की पुष्टि कीजिए।
13. भारत परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के प्रति प्रतिरक्षित नहीं रह सकता है। भारत के लिए, दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार नियंत्रण शुरू करने की दिशा में कोई भी कदम जटिल परमाणु राजनीति और प्रतियोगिताओं के बीच एक कठिन कार्य है। विस्तार कीजिए।
14. पुनर्योजी कृषि में लघु कृषकों को वित्तीय लाभ प्रदान करते हुए बिगड़े हुए परिदृश्य में मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता को बहाल करने की अपार क्षमता होती है। पुनर्योजी कृषि किस प्रकार कृषक आय को बढ़ाते हुए भारत के कृषि कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकती है? चर्चा कीजिए?
15. मौटे आनाज पोषण का लोकप्रिय स्रोत क्यों है? मौटे आनाज की गिरी के विभिन्न भाग कौन से हैं? प्रसंस्करण और पॉलिशिंग से मौटे आनाज के पोषक तत्व किस प्रकार प्रभावित होते हैं? क्या मौटे आनाज कठोर, संसाधन-हीन परिस्थितियों में फल-फूल सकते हैं?
16. सदस्य देशों की अपनी वित्तीय जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में जी20 के नए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (डीआरआरडब्लूजी) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
17. राजस्थान सरकार द्वारा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की शुरुआत प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक जीत है, लेकिन आगे कई चुनौतियां हैं जैसे श्रम अधिकारों की कमियों को पाटना। टिप्पणी कीजिए।
18. संसदीय लोकतंत्र की संवैधानिक रूपरेखा उत्तरदायित्व की एक श्रृंखला की परिकल्पना करती है। किस प्रकार दलबदल विरोधी कानून अपने मतदाताओं के प्रति विधायकों की जवाबदेही के लोकतांत्रिक सिद्धांत का खंडन करता है, उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, चर्चा कीजिए?
19. जैसा कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, देश में एक मजबूत नेटवर्क भौतिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होगा। दिए गए परिदृश्य में, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की संभावनाएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?
20. भारत ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को अपनाने, स्थानीयकरण और उपलब्धि की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर बढ़ते वैश्विक आंदोलन में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर के रूप में, भोपाल के अभियान को अन्य भारतीय शहरों को पथ का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टिप्पणी कीजिए।
21. सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के रुख को किस प्रकार विधिमान्य किया? क्या यह अन्य राज्यों में समान दौड़ प्रतियोगिताओं पर लागू होगा? न्यायालय ने पशुओं के अधिकारों को किस प्रकार हल किया?

22. जीनोम अनुक्रमण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? संदर्भ जीनोम मानचित्र को सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलताओं में से एक क्यों माना जाता है? संदर्भ मानचित्र और पैन्जेनोम मानचित्र में क्या अंतर है? नवीनतम जीनोम मानचित्र से भारत किस प्रकार लाभ की उम्मीद कर रहा है?

23. नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के लिए पूंजी जुटाने से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक मजबूत आपूर्ति-श्रृंखला स्थापित करने तक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए सहयोग करने के कई सुसंयोग हैं। टिप्पणी कीजिए।

24. पश्चिमी मुख्यधारा के बाहर किस प्रकार ब्रिक्स एक राजनयिक मंच और विकास वित्तपोषण प्रदान करता है? चर्चा कीजिए।

Answer Key

1.	(a)	2.	(b)	3.	(c)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(a)	7.	(b)	8.	(d)	9.	(d)	10.	(a)
11.	(a)	12.	(b)	13.	(c)	14.	(d)	15.	(b)	16.	(a)	17.	(b)	18.	(c)	19.	(d)	20.	(a)
21.	(a)	22.	(b)	23.	(c)	24.	(d)	25.	(a)	26.	(a)	27.	(b)	28.	(c)	29.	(d)	30.	(a)
31.	(a)	32.	(b)	33.	(c)	34.	(d)	35.	(a)	36.	(a)	37.	(b)	38.	(c)	39.	(d)	40.	(a)
41.	(a)	42.	(b)	43.	(c)	44.	(d)	45.	(a)	46.	(a)	47.	(b)	48.	(c)	49.	(d)	50.	(a)
51.	(a)	52.	(b)	53.	(c)	54.	(d)	55.	(a)	56.	(a)	57.	(b)	58.	(c)	59.	(d)	60.	(a)
61.	(a)	62.	(b)	63.	(c)	64.	(d)	65.	(a)	66.	(a)	67.	(b)	68.	(c)	69.	(d)	70.	(a)
71.	(a)	72.	(b)	73.	(c)	74.	(d)	75.	(a)	76.	(a)	77.	(b)	78.	(c)	79.	(d)	80.	(d)
81.	(a)	82.	(b)	83.	(c)	84.	(d)	85.	(a)	86.	(a)	87.	(b)	88.	(c)	89.	(d)	90.	(a)
91.	(a)	92.	(b)	93.	(c)	94.	(d)	95.	(a)	96.	(a)	97.	(b)	98.	(c)	99.	(d)	100.	(d)
101.	(a)	102.	(b)	103.	(c)	104.	(d)	105.	(a)	106.	(a)	107.	(b)	108.	(c)	109.	(d)	110.	(a)
111.	(a)	112.	(b)	113.	(c)	114.	(d)	115.	(a)	116.	(a)	117.	(b)	118.	(c)	119.	(d)	120.	(a)

दीक्षांत
Education Centre

69th BPSC

PRE+MAINS

सामान्य अध्ययन

ऑनलाइन/ऑफलाइन

- दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की टीम द्वारा
- 600 घंटे का कक्षा कार्यक्रम
- अद्यतन पाठ्यक्रम सामग्री (40 बुकलेट)
- डेली टेस्ट (150 टेस्ट) + यूनिट टेस्ट - 16 टेस्ट
- वर्क बुक - 8
- करेंट अफेयर्स एवं बिहार स्पेशल की विशेष कक्षाएँ
- डाउट क्लियरेंस हेतु विशेष मेन्टर की व्यवस्था

नामांकन प्रारंभ / सीमित सीटें

Fee
~~₹75,000~~
₹30,000
only

*Inaugural fee for first 200 students

13 JUNE

@ 12:30 PM

TO REGISTER INSTALL DIKSHANT APP/ ADD.: 289, DHAKA JOHAR, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09, CALL : 7428092240

DIKSHANT | दीक्षांत

OUR CSE RESULT-2021

SHRUTI SHARMA

GAMINI SINGLA

AISHWARYA VERMA

YAKSH CHAUDHARY

PREETAM KUMAR

FREE COACHING & SCHOLARSHIP PROGRAMME

GENERAL STUDIES

FOUNDATION COURSE FOR IAS

ENGLISH MEDIUM

ONLINE *NEW BATCH* **OFFLINE**

Class Starts 6 JUNE @ 6 PM

FEATURES

CLASSROOM PROGRAMME
24 Months/14 Months
1200-1500 Hrs. Classes
300 Hrs. NCERT Video
& 150 Hrs. PT Booster
Classes on App

STUDY MATERIALS
Latest, Updated &
Exam Oriented
Study Materials
10,000 Pages
(50 Booklets)

CURRENT AFFAIRS
200 Hrs.+ Classes on
Important Issues
for 2 Yrs.
& 3 Years Monthly
Magazine Subscription

WORKBOOK (MAINS)
16 workbooks provides
opportunity to review
and extend your
classroom learnings

UNIT TEST (PRE+MAINS)
32 unit test improves
knowledge, skills,
& aptitude for
prelims & mains exam

DAILY CLASS TEST
250 Prelims and 200 Mains
Test is used to check the
quality of knowledge gained
& started executing

CURRENT AFFAIRS PRE TEST
Through 100 tests you will get
right approach for
current affairs MCQs
and their relevance in
the UPSC exam

MENTORSHIP PROGRAMME
Individual doubt clearance
by faculties/experts to
increase confidence and
exposure on
different perspectives

COURSE VALIDITY
4 Years/3 Times Course
Validity will help to increase
your confidence and
preparation for your exam